भारतीय रिज़र्व बैंक

बुलेटिन

फरवरी 2023

खंड 77 अंक 2

अध्यक्ष
माइकल देबब्रत पात्र

संपादन समिति
अजित आर. जोशी
देब प्रसाद रथ
मुनिश कपूर
रेखा मिश्र
इन्द्रनील भट्टाचार्य
स्नेहल हेरवाडकर
पंकज कुमार
तुषार बरन दास
वी. धन्या
श्वेता कुमारी
सुजाता कुंडू

संपादक
जी. वी. नथनएल

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के
निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा
मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है।
इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए
बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है।
हस्ताक्षरित आलेखों में व्यक्त विचारों के लिए
लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2022

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
https://bulletin.rbi.org.in पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य 1

मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 7

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य 11

भाषण

भारत में वित्तीय बाजार : स्थिरता और विकास की यात्रा
शक्तिकान्त दास 13

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति 19

भारत के लिए पुनर्गठित त्रैमासिक पूर्वानुमान प्रतिरूप (क्यूपीएम 2.0) 59

केंद्रीय बजट 2023-24: एक आकलन 79

ईएसजी प्रकटीकरण और प्रदर्शन: अंतर-देशीय साक्ष्य 99

ऋण- मांग पर बैंकरों के रुख - महामारी के बाद सुधार 113

फेडरल रिज़र्व की कार्रवाइयों का दीर्घ प्रभाव: मौद्रिक नीति और
भारत में अनिश्चितता का प्रभाव-विस्तार 127

वर्तमान सांख्यिकी **141**

हाल के प्रकाशन **194**

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य

*गवर्नर का वक्तव्य**

शक्तिकान्त दास

नए वर्ष के प्रथम मौद्रिक नीति वक्तव्य को शुरू करते हुए मुझे भारतीय रिज़र्व बैंक हेतु वर्ष 2023 के ऐतिहासिक महत्व का स्मरण होता है। एक संयुक्त स्टॉक कंपनी से, भारतीय रिज़र्व बैंक को 1 जनवरी 1949[1] को सार्वजनिक स्वामित्व में लाया गया। इस प्रकार, वर्ष 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक के सार्वजनिक स्वामित्व और एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में इसके उद्भव का 75वां वर्ष है। इस अवधि में मौद्रिक नीति के विकास पर संक्षेप में विचार करने का यह एक उपयुक्त क्षण है। आज़ादी के बाद के दो दशकों में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की ऋण अपेक्षाओं को समर्थन प्रदान करने की थी। अगले दो दशक 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण, तेल के आघात, बड़े बजट घाटे के मुद्रीकरण तथा मुद्रा आपूर्ति और मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि के रूप में अभिलक्षित होते हैं। 1980 के दशक के मध्य में मुद्रा आपूर्ति में संवृद्धि को रोकने और मुद्रास्फीति के दबावों को कम करने हेतु मौद्रिक लक्ष्यीकरण को अपनाया गया। 1990 के दशक की शुरुआत से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाजार सुधारों और संस्था निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। अप्रैल 1998 में एक बहुसंकेतक दृष्टिकोण अपनाया गया जिसके अंतर्गत नीति निर्माण के लिए कई संकेतकों की निगरानी की गई। वैश्विक वित्तीय संकट और टेंपर टैंट्रम के बाद, भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति बिगड़ने के कारण, मौद्रिक नीति को एक विश्वसनीय मौद्रिक अवलंब प्रदान करने हेतु लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफ़आईटी) को औपचारिक रूप से जून 2016 में अपनाया गया। जैसा कि हम जानते हैं, एफआईटी ढांचे के अंतर्गत मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।

वर्तमान समय में, पिछले तीन वर्षों की अभूतपूर्व घटनाओं ने वैश्विक स्तर पर मौद्रिक नीति ढांचे को परीक्षण पर रख दिया है। बहुत ही कम अवधि में, विश्व भर में मौद्रिक नीतियां परस्परव्याप्त आघातों की एक श्रृंखला की प्रतिक्रिया में एक चरम से दूसरे चरम पर आ गई हैं। 1990 के दशक के महान संतुलन युग और इस सदी के शुरुआती वर्षों के विपरीत, मौद्रिक नीति को आर्थिक गतिविधियों में अभूतपूर्व संकुचन के साथ वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि का सामना करना पड़ा। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति की गतिशीलता में संरचनात्मक परिवर्तनों और मौद्रिक नीति के संचालन के लिए उनके निहितार्थों की गहरी समझ को आवश्यक बनाता है।

वर्तमान अस्थिर वैश्विक वातावरण में, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई) नीतिगत विश्वसनीयता को बनाए रखते हुए आर्थिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के बीच तीव्र समझौताकारी समन्वयन का सामना कर रही हैं। जैसे-जैसे व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश प्रवाह में वैश्विक खामियाँ उभरती हैं, वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता है। विश्व कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वैश्विक सहभागिता को क्रियाशील करने हेतु भारत, जो इस समय जी-20 का अध्यक्ष है, की ओर देख रही है। यह मुझे महात्मा गांधी की कही बात याद दिलाता है: "मुझे विश्वास है कि ... भारत ... दुनिया की शांति और ठोस प्रगति में स्थायी योगदान दे सकता है।"[2]

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय और विचार-विमर्श

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 6, 7 और 8 फरवरी 2023 को हुई। समष्टि आर्थिक स्थिति और इसकी संभावना के मूल्यांकन के आधार पर, एमपीसी ने 6 में से 4 सदस्यों के बहुमत से तत्काल प्रभाव से नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर संशोधित होकर 6.25 प्रतिशत; तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत प्रतिशत हो गई है। एमपीसी ने 6 में से 4 सदस्यों के बहुमत से निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

* गवर्नर का वक्तव्य – 8 फरवरी 2023

[1] भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वामित्व को "रिज़र्व बैंक (लोक स्वामित्व में अंतरण) अधिनियम, 1948" के अंतर्गत केंद्र सरकार की अधिसूचना के माध्यम से सरकार को हस्तांतरित किया गया था।

[2] यंग इंडिया, 1927-1928, विविधता में एकता, 11 अगस्त 1927।

गवर्नर का वक्तव्य

अब मैं नीतिगत दर और रुख पर इन निर्णयों के लिए एमपीसी के तर्क के बारे में बताता हूं। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अब उतना विकट नहीं दिखता जितना कुछ महीने पहले था। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में संवृद्धि की संभावनाओं में सुधार हुआ है, जबकि मुद्रास्फीति अधोगामी है, तथापि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में यह अभी भी लक्ष्य से काफी ऊपर है। स्थिति अस्थिर और अनिश्चित बनी हुई है। हाल की आशापूर्ण दृष्टि को दर्शाते हुए, आईएमएफ़ ने 2022 और 2023 के लिए वैश्विक संवृद्धि अनुमानों को ऊर्ध्वगामी संशोधित किया है।[3] मूल्य दबाव कम होने के कारण, कई केंद्रीय बैंकों ने धीमी दर वृद्धि या विराम का विकल्प चुना है। अमेरिकी डॉलर दो दशकों के अपने उच्चतम स्तर से तेजी से नीचे आया है। आक्रामक मौद्रिक नीति कार्रवाइयों, अस्थिर वित्तीय बाजारों, ऋण संकट, लंबी भू-राजनीतिक युद्धस्थिति और विखंडन के कारण सख्त वित्तीय स्थितियां वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावना को गंभीर अनिश्चितता प्रदान करती हैं।

इन अस्थिर वैश्विक घटनाक्रमों के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था आघात सहनीय बनी हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2022-23 में वास्तविक जीडीपी संवृद्धि 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उच्च रबी क्षेत्रफल, अविरत शहरी मांग, ग्रामीण मांग में सुधार, मजबूत ऋण विस्तार, उपभोक्ता और कारोबार प्रत्याशा में वृद्धि और केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे पर सरकार का बढ़ा हुआ जोर आने वाले वर्ष में आर्थिक गतिविधि का समर्थन करेगा। कमजोर बाह्य मांग और अनिश्चित वैश्विक वातावरण, तथापि, घरेलू संवृद्धि की संभावनाओं पर दबाव डालेंगे।

भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति नवंबर-दिसंबर 2022 के दौरान सब्जियों की कीमतों में भारी गिरावट के कारण ऊपरी सहन स्तर से नीचे आ गई। मूल मुद्रास्फीति, तथापि, स्थिर बनी हुई है।

आगे देखते हुए, जबकि 2023-24 में मुद्रास्फीति के कम होने की आशा है, इसके 4 प्रतिशत लक्ष्य से ऊपर रहने की संभावना है। संभावना पर भू-राजनीतिक तनावों, वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता, गैर-तेल कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से जारी अनिश्चितताओं के बादल छाए हुए हैं। वहीं, भारत में आर्थिक गतिविधियों के ठीक रहने की आशा है। मई 2022 से दरों में वृद्धि अभी भी प्रणाली के माध्यम से अपना काम कर रही है। समग्र रूप से, एमपीसी का विचार था कि मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने, मूल मुद्रास्फीति की सततता को तोड़ने और इस तरह मध्यम अवधि की संवृद्धि संभावनाओं को मजबूत करने के लिए आगे सुविचारित मौद्रिक नीति कार्रवाई की आवश्यकता है। तदनुसार, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। एमपीसी उभरती मुद्रास्फीति संभाना पर कड़ी निगरानी बनाए रखना जारी रखेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सहन-सीमा के भीतर बनी रहे और उत्तरोत्तर लक्ष्य के साथ संरेखित हो।

2023-24 की चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति के औसतन 5.6 प्रतिशत रहने की आशा है, जबकि नीतिगत रेपो दर 6.50 प्रतिशत है। मुद्रास्फीति के लिए समायोजित, नीतिगत दर अभी भी अपने महामारी पूर्व स्तर से कम है। जनवरी 2023 में एलएएफ के अंतर्गत ₹1.6 लाख करोड़ के औसत दैनिक अवशोषण के साथ चलनिधि अधिशेष है। अतः, समग्र मौद्रिक स्थिति निभावकारी बनी हुई है और इसलिए, एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

संवृद्धि

2022-23 की तीसरी और चौथी तिमाही के लिए उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में आर्थिक गतिविधि आघात-सह बनी हुई है। विशेष रूप से यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य जैसी सेवाओं पर विवेकाधीन व्यय में निरंतर बहाली के कारण शहरी खपत की मांग मजबूत हो रही है। यात्री वाहन बिक्री और घरेलू हवाई यात्री यातायात ने मजबूत वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) संवृद्धि दर्ज की। दिसंबर 2022 में पहली बार घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या महामारी से पहले के स्तर को पार कर गई। दिसंबर में ट्रैक्टर की बिक्री और दोपहिया वाहनों की बिक्री बढ़ने के कारण ग्रामीण मांग

[3] अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जनवरी 2023 की वैश्विक आर्थिक संभावना के अद्यतन के अनुसार, 2022 के लिए वैश्विक संवृद्धि को ऊर्ध्वगामी संशोधित कर 3.2 प्रतिशत से 3.4 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि 2023 के लिए वैश्विक संवृद्धि को अक्टूबर 2022 में अनुमानित 2.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.9 प्रतिशत कर दिया गया है।

गवर्नर का वक्तव्य

में सुधार के संकेत जारी हैं। कई उच्च आवृत्ति संकेतक[4] भी गतिविधि के मजबूत होने का संकेत दे रहे हैं।

निवेश गतिविधि में तेजी जारी है। 27 जनवरी 2023 को गैर-खाद्य बैंक ऋण में 16.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई। वाणिज्यिक क्षेत्र में संसाधनों के कुल प्रवाह में 2022-23 के दौरान अब तक 20.8 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जबकि एक वर्ष पहले यह 12.5 लाख करोड़ रुपये थी। नियत निवेश के संकेतकों - सीमेंट उत्पादन; स्टील की खपत; और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन और आयात में नवंबर और दिसंबर में मजबूत संवृद्धि दर्ज की गई। सीमेंट, स्टील, खनन और रसायन जैसे कई क्षेत्रों में निजी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता सृजित होने के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार, 2022-23 की दूसरी तिमाही में मौसमी रूप से समायोजित क्षमता उपयोग बढ़कर 74.5 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर, निवल बाह्य मांग में कमी, 2022-23 की तीसरी तिमाही में वाणिज्य वस्तु निर्यात के संकुचन के रूप में जारी रही।

आपूर्ति पक्ष पर, अच्छी रबी बुवाई, उच्च जलाशय स्तर, मिट्टी की अच्छी नमी, अनुकूल सर्दियों के तापमान और उर्वरकों की सहज उपलब्धता के साथ कृषि गतिविधि मजबूत बनी हुई है।[5] जनवरी 2023 में पीएमआई विनिर्माण और पीएमआई सेवाओं का विस्तार क्रमशः 55.4 और 57.2 रहा।

संभावना की ओर मुड़ते हुए, अपेक्षित उच्च रबी उत्पादन ने कृषि और ग्रामीण मांग की संभावनाओं में सुधार किया है। संपर्क-गहन क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि से शहरी खपत को समर्थन मिलना चाहिए। व्यापक-आधारित ऋण संवृद्धि, क्षमता उपयोग में सुधार, पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे में निवेश पर सरकार के जोर से, निवेश गतिविधि को बढ़ावा मिलना चाहिए। हमारे सर्वेक्षणों के अनुसार, विनिर्माण, सेवा और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनियां कारोबारी संभावना को लेकर आशावादी हैं। दूसरी ओर, दीर्घकालिक भू-राजनीतिक तनाव, सख्त वैश्विक वित्तीय स्थितियां और बाहरी मांग का धीमा होना घरेलू उत्पादन के लिए अधोगामी जोखिम के रूप में जारी रह सकता है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि दर पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 6.0 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत के साथ 6.4 प्रतिशत अनुमानित है। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

मुद्रास्फीति

हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति अक्तूबर 2022 में अपने 6.8 प्रतिशत के स्तर से नवंबर-दिसंबर 2022 के दौरान 105 आधार अंक कम हो गई। यह सब्जियों की कीमतों में तीव्र अपस्फीति से जनित खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी के कारण था, जो अनाज, प्रोटीन-आधारित खाद्य पदार्थों और मसालों से मुद्रास्फीति के दबावों की वृद्धि से कहीं अधिक था। सब्जियों की कीमतों में अनुमान से पहले और तेज मौसमी गिरावट के परिणामस्वरूप, 2022-23 की तीसरी तिमाही के लिए मुद्रास्फीति हमारे अनुमानों से कम हो गई। मूल सीपीआई मुद्रास्फीति (अर्थात, खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई), तथापि, उच्च बनी रही।

आगे बढ़ते हुए, गेहूं और तिलहन की प्रधानता में रबी की बंपर फसल की संभावना से खाद्य मुद्रास्फीति की संभावना में लाभ होगा। मंडी की आवक और खरीफ धान की खरीद अच्छी रही है, जिससे चावल के बफर स्टॉक में सुधार हुआ है। ये सभी घटनाक्रम 2023-24 में खाद्य मुद्रास्फीति की संभावना के लिए अनुकूल हैं।

कच्चे तेल की कीमत सहित वैश्विक कमोडिटी कीमतों के संभावित प्रक्षेपवक्र पर काफी अनिश्चितता बनी हुई है। दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों में ढील के साथ कमोडिटी की कीमतें स्थिर रह सकती हैं। इनपुट लागतों का निरंतर पास-थ्रू, विशेष रूप से सेवाओं में, मुख्य मुद्रास्फीति को ऊंचे स्तर पर रख सकता है। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय समेकन की प्रतिबद्धता और सकल राजकोषीय घाटे को कम करने के भविष्य के प्रक्षेपवक्र से समष्टिआर्थिक स्थिरता का वातावरण तैयार होगा। यह मुद्रास्फीति की संभावना के लिए अच्छा संकेत है। इसके अलावा, समकक्ष मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये की कम अस्थिरता, आयातित मूल्य दबावों और

[4] बंदरगाह माल ढुलाई; रेलवे माल यातायात; टोल संग्रह; ई-वे बिल; डीजल की खपत; और बिजली की खपत।

[5] रबी की बुवाई, 3 फरवरी 2023 को, एक वर्ष पहले की तुलना में 3.3 प्रतिशत अधिक थी (आज की तारीख के अनुसार सामान्य से 9.3 प्रतिशत अधिक)। 02 फरवरी 2023 को जलाशय का स्तर पूरी क्षमता के 63 प्रतिशत पर था जो दशकीय औसत 53 प्रतिशत से अधिक था।

अन्य वैश्विक स्पिलओवर के प्रभाव को सीमित करती है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए और 95 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की औसत कच्चे तेल की कीमत (भारतीय टोकरी) मानते हुए, 2022-23 में मुद्रास्फीति 6.5 प्रतिशत, चौथी तिमाही में 5.7 प्रतिशत के साथ होने का अनुमान लगाया गया है। सामान्य मानसून की आशा पर, 2023-24 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.3 प्रतिशत, पहली तिमाही में 5.0 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.6 प्रतिशत अनुमानित है। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

हेडलाइन मुद्रास्फीति नवंबर और दिसंबर 2022 में नकारात्मक गति के साथ कम हुई है, लेकिन मुख्य या अंतर्निहित मुद्रास्फीति की स्थिरता चिंता का विषय है। हमें मुद्रास्फीति में निर्णायक नरमी देखने की जरूरत है। हमें मुद्रास्फीति कम करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अटल रहना होगा। इस प्रकार, मौद्रिक नीति को टिकाऊ अवस्फीति प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। 25 आधार अंकों की दर वृद्धि को वर्तमान समय में उपयुक्त माना जाता है। दर वृद्धि के आकार में कमी से, मुद्रास्फीति की संभावना और बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था पर अब तक की गई कार्रवाइयों के प्रभावों का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। यह भविष्य में उचित कार्रवाई और नीतिगत रुख निर्धारित करने के लिए प्राप्त हो रहे सभी डेटा और पूर्वानुमानों का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त समय भी प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति के प्रक्षेपवक्र में आगे बढ़ने वाले हिस्सों के लिए चुस्त और सतर्क बनी रहेगी।

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति

जैसे हम 2022-23 के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, पिछले एक वर्ष के दौरान मौद्रिक नीति के मोर्चे पर प्रमुख गतिविधियों को दोहराना सार्थक होगा। यूरोप में युद्ध की शुरुआत के बाद, जिसने भारत सहित विश्वभर में संवृद्धि- मुद्रास्फीति की गतिशीलता को काफी हद तक बदल दिया, हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित में कई कदम उठाए हैं। हमने अप्रैल 2022 में संवृद्धि पर मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता दी; हमने स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) की शुरुआत के माध्यम से मौद्रिक नीति संचालन प्रक्रिया में एक बड़ा सुधार किया है; हमने नीतिगत कॉरिडोर की चौड़ाई को उसके पूर्व-महामारी स्तर पर बहाल कर दिया; हमने मई में ऑफ-साइकिल बैठक में रेपो दर में 40 बीपीएस और आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में 50 बीपीएस की बढ़ोत्तरी की; हमने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नीतिगत रुख में बदलाव किया; हमने एमपीसी की प्रत्येक बैठक में दरों में सख्ती का चक्र जारी रखा; और हमने आवश्यकता के अनुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) और परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) परिचालन दोनों का संचालन करके चलनिधि प्रबंधन के लिए एक फुर्तीला और लचीला दृष्टिकोण अपनाया। इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप, वास्तविक नीतिगत दर को सकारात्मक क्षेत्र में लाया गया है; बैंकिंग प्रणाली अतिरिक्त चलनिधि के *चक्रव्यूह*[6] से बाहर निकल चुकी है; मुद्रास्फीति कम हो रही है; और आर्थिक संवृद्धि लचीला बना हुआ है।

जब मैं यह वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं, अप्रैल 2022 की तुलना में क्रमिक रूप से कम होने के बावजूद, प्रणालीगत तरलता अधिशेष में बनी हुई है। आगे की अवधि में, जबकि उच्च सरकारी व्यय और विदेशी मुद्रा प्रवाह की प्रत्याशित वापसी से प्रणालीगत तरलता में वृद्धि होने की संभावना है, यह फरवरी से अप्रैल 2023 के दौरान एलटीआरओ और टीएलटीआरओ[7] निधियों के निर्धारित मोचन द्वारा संशोधित हो जाएगा। रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रति लचीला और उत्तरदायी बना रहेगा। हम चलनिधि की उभरती परिस्थितियों के आधार पर एलएएफ के दोनों ओर परिचालनों का संचालन करेंगे।

चलनिधि और बाजार परिचालनों को सामान्य करने की दिशा में हमारे क्रमिक कदम के हिस्से के रूप में, अब यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी प्रतिभूति बाजार के लिए बाजार के

6 चक्रव्यूह: दुश्मनों को घेरने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सैन्य गठन, जिसे भारतीय महाकाव्य महाभारत में दर्शाया गया है। यह कई रक्षात्मक दीवारों की भूलभुलैया जैसा दिखता है, जिसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है और यह केवल बहुत ही कुशल योद्धाओं के कार्य के लिए ही जाना जाता है।

7 रिज़र्व बैंक ने फरवरी से अप्रैल 2020 के दौरान बैंकों को 3 वर्ष तक की परिपक्वता वाली रेपो दर पर कम लागत वाली निधियां प्रदान कीं, ताकि मौद्रिक संचरण में सुधार हो सके, कोविड-महामारी के प्रभाव को कम किया जा सके और दीर्घकालिक रेपो परिचालन (एलटीआरओ) और लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) के अंतर्गत संस्थाओं/विशिष्ट क्षेत्रों में चलनिधि के तनाव को कम किया जा सके।

समय को पूर्व-महामारी का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे[8] तक बहाल किया जाए। इसके अलावा, सरकारी प्रतिभूति बाजार को और विकसित करने के हमारे चल रहे प्रयास के हिस्से के रूप में, हम जी-सेक को ऋण देने और उधार लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव करते हैं। यह निवेशकों को अपनी निष्क्रिय प्रतिभूतियों को लगाने, पोर्टफोलियो रिटर्न बढ़ाने और व्यापक सहभागिता की सुविधा प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। यह उपाय जी-सेक बाजार में गहराई और तरलता भी जोड़ेगा; कुशल मूल्य खोज में सहायता प्रदान करेगा; और केंद्र और राज्यों के बाजार उधारी कार्यक्रम को सुचारू रूप से पूरा करने की दिशा में काम करेगा।

वर्तमान कड़े चक्र में, उधार और जमा दरों के प्रति मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के संचरण की गति मजबूत हुई है। मई से दिसंबर 2022 के दौरान नए रुपया ऋण और बकाया ऋण पर भारित औसत उधार दर (डबल्यूएएलआर) में क्रमशः 137 बीपीएस और 80 बीपीएस की वृद्धि हुई। नए जमा और बकाया जमा पर भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर में क्रमश: 213 बीपीएस और 75 बीपीएस की वृद्धि हुई।

भारतीय रुपया कैलेंडर वर्ष 2022 में अपने एशियाई समकक्षों के बीच सबसे कम अस्थिर मुद्राओं में से एक रहा है और इस वर्ष भी ऐसा ही बना हुआ है।[9] इसी तरह, कई झटकों के मौजूदा चरण के दौरान भारतीय रुपये का मूल्यह्रास और अस्थिरता, वैश्विक वित्तीय संकट और टेपर टैंट्रम[10] की तुलना में बहुत कम है। एक मौलिक अर्थ में, रुपये का चलन भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है।

बाहरी क्षेत्र

2022-23 की पहली छमाही के लिए चालू खाता घाटा (सीएडी) सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत रहा। 2022-23 की तीसरी तिमाही में स्थिति में सुधार देखा गया है क्योंकि कमोडिटी कीमतों में गिरावट के चलते आयात में कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद व्यापार घाटा कम हुआ है। इसके अलावा, 2022-23 की तीसरी तिमाही में सेवाओं का निर्यात 24.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ा, जो सॉफ्टवेयर, करोबार और यात्रा सेवाओं द्वारा संचालित था। वैश्विक सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं पर व्यय 2023 में मजबूत रहने की उम्मीद है। 2022-23 की पहली छमाही में भारत के लिए विप्रेषण संवृद्धि लगभग 26 प्रतिशत थी - वर्ष के लिए विश्व बैंक के अनुमान से दोगुने से अधिक। खाड़ी देशों की बेहतर संवृद्धि संभावनाओं के कारण इसके मजबूत बने रहने की संभावना है। सेवाओं और विप्रेषण के अंतर्गत शुद्ध शेष बड़े अधिशेष में रहने की उम्मीद है, जो व्यापार घाटे को आंशिक रूप से कम कर देगा। 2022-23 की दूसरी छमाही में सीएडी मध्यम होने की उम्मीद है और यह प्रमुख रूप से प्रबंधनीय और व्यवहार्यता के मापदंडों के भीतर रहेगा।[11]

वित्तपोषण पक्ष पर, शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) प्रवाह अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान 22.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (पिछले वर्ष की इसी अवधि में 24.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पर मजबूत रहा। विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह ने इक्विटी प्रवाह(विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह, हालांकि, वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक नकारात्मक हैं) के नेतृत्व में जुलाई से 6 फरवरी के दौरान 8.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सकारात्मक प्रवाह के साथ सुधार के संकेत दिखाए हैं। अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान अनिवासी जमा के अंतर्गत शुद्ध अंतर्वाह एक वर्ष पहले के 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसे रिज़र्व बैंक के 6 जुलाई के उपायों से बल मिला। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 21 अक्तूबर 2022 को 524.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 27 जनवरी 2023

---

[8] हमने पहले दिसंबर 2022 में मुद्रा बाज़ार के कई खंड में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का बाज़ार का समय बहाल किया था।

[9] भिन्नता के गुणांक के संदर्भ में मापी गई अस्थिरता कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान भारतीय रुपये के लिए 3.5 प्रतिशत थी, जबकि मलेशियाई रिंगिट के लिए 3.7 प्रतिशत, थाई बहत के लिए 4.7 प्रतिशत और फिलीपीन पेसो के लिए 4.8 प्रतिशत थी।

[10] वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान, 1 अप्रैल 2008 और 3 मार्च 2009 के बीच अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष भारतीय रुपये में 23 प्रतिशत की गिरावट आई। इसी तरह, 01 मई 2013 और 28 अगस्त 2013 के बीच टेपर टैंट्रम के दौरान इसमें 22 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि, प्रतिकूल समय के बाद के प्रत्येक प्रकरण में रुपये के मूल्यह्रास की सीमा कम थी। महामारी के शुरुआती दिनों में, अर्थात्17 फरवरी 2020 और 21 अप्रैल 2020 के बीच रुपये में केवल 7 प्रतिशत की गिरावट आई। जबकि 2022 में यूक्रेन से उभर रहे भू-राजनीतिक तनाव की अवधि के दौरान भी, 24 फरवरी, 2022 और 19 अक्तूबर, 2022 के बीच अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष रुपये में 9 प्रतिशत की गिरावट आई, इसने सबसे उन्नत और कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं को पीछे छोड़ दिया। 10 अक्तूबर 2008 को वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान रुपये की 1 महीने की अंतर्निहित अस्थिरता 25 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गई और 29 अगस्त 2013 को टेंपर टैंट्रम अवधि के दौरान 20 प्रतिशत हो गई। हालांकि, कोविड-19 महामारी के दौरान, निहित अस्थिरता 24 मार्च, 2020 को 10% पर पहुंच गई।

[11] दास, शक्तिकान्त (2023); "भारत में वित्तीय बाजार: स्थिरता और विकास की खोज में"; 27 जनवरी 2023 को दुबई में 22वें FIMMDA-PDAI वार्षिक सम्मेलन में मुख्य भाषण।

को 576.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2022-23 के अनुमानित आयात के लगभग 9.4 महीनों को शामिल करता है। भारत का बाहरी ऋण अनुपात अंतरराष्ट्रीय मानकों से कम है।[12]

अतिरिक्त उपाय

अब मैं कतिपय अतिरिक्त उपायों की घोषणा करूंगा।

ऋणों पर दंडात्मक प्रभार

वर्तमान में, विनियमित संस्थाओं (आरई) के पास अग्रिमों पर दंडात्मक ब्याज लगाने के लिए एक नीति होना आवश्यक है। हालांकि, आरई ऐसे प्रभार लगाने पर अलग-अलग पद्धतियों का पालन करते हैं। कुछ मामलों में, ये शुल्क अत्यधिक पाए जाते हैं। पारदर्शिता, औचित्य और उपभोक्ता संरक्षण को और बढ़ाने के लिए, हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए दंड प्रभार लगाने पर मसौदा दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त

जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों, जिनमें वित्तीय स्थिरता निहितार्थ हो सकते हैं, के महत्व को स्वीकार करते हुए रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2022 में जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर एक चर्चा पत्र जारी किया था। प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि आरई को (i) हरित जमाराशि की स्वीकृति के लिए एक व्यापक रूपरेखा; (ii) जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण ढांचा; और (iii) जलवायु परिदृश्य विश्लेषण और तनाव परीक्षण पर मार्गदर्शन, संबंधी दिशानिर्देश जारी किए जाए।

ट्रेड्स के दायरे का विस्तार

एमएसएमई के लाभ के लिए, रिज़र्व बैंक ने 2014 में व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली (ट्रेड्स) के माध्यम से उनके व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के लिए एक रूपरेखा जारी की थी। अब (i) इन्वॉइस वित्तपोषण के लिए बीमा सुविधा प्रदान करके; (ii) फैक्टरिंग कारोबार करने वाली सभी संस्थाओं/संस्थानों को ट्रेड्स में वित्तपोषकों के रूप में भाग लेने की अनुमति देकर; और (iii) बीजक की पुनर्भुनाई की अनुमति (अर्थात, ट्रेड्स में द्वितीयक बाजार विकसित करना) देकर, ट्रेड्स के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इन उपायों से एमएसएमई के नकदी प्रवाह में सुधार की उम्मीद है।

भारत में आने वाले यात्रियों के लिए यूपीआई का विस्तार

यूपीआई भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान के लिए बेहद लोकप्रिय हो गया है। अब यह प्रस्ताव है कि भारत आने वाले सभी यात्रियों को देश में रहते हुए अपने व्यापारिक भुगतान (पी2एम) के लिए यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति दी जाए। शुरुआत में यह सुविधा चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर पहुंचने वाले जी-20 देशों के यात्रियों को दी जाएगी।

क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन – प्रायोगिक परियोजना

30. भारतीय रिज़र्व बैंक 12 शहरों में क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन (क्यूसीवीएम) पर एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करेगा। ये वेंडिंग मशीनें बैंकनोटों की भौतिक भुनाई के बजाय यूपीआई का उपयोग करके ग्राहक के खाते में होने वाले नामे के बदले सिक्के वितरित करेंगी। इससे सिक्कों की उपलब्धता में आसानी होगी। प्रायोगिक परियोजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर बैंकों को इन मशीनों के इस्तेमाल से सिक्कों के वितरण को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

निष्कर्ष

31. जैसा कि नववर्ष की शुरुआत हुई है, यह हमारी अब तक की यात्रा पर तथा आगे क्या करने वाले हैं, इस पर विचार करने का एक अच्छा समय है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो यह जानकर प्रसन्नता होती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले तीन वर्षों में कई बड़े झटकों का सफलतापूर्वक सामना किया और पहले से और अधिक मजबूत होकर उभरी है। भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के पास अंतर्निहित शक्ति, एक सक्षम नीतिगत माहौल और मजबूत समष्टि-आर्थिक आधार और बफर हैं। मुझे यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शब्द याद आ रहे हैं: "....... भारत की नियति पर अपना विश्वास कभी न खोएं"[13]।

धन्यवाद ! नमस्कार !

[12] भारत का बाह्य ऋण/जीडीपी अनुपात मार्च 2022 में 19.9 प्रतिशत से गिरकर सितंबर में 19.2 प्रतिशत हो गया। ऋण सेवा अनुपात 2021-22 में 5.2 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2022 में 5.0 प्रतिशत हो गया।

[13] "भारत आज़ाद होगा" - पूर्वी एशिया में भारतीयों के लिए 17 अगस्त 1945 का संदेश - सुभाष चंद्र बोस का चुनिंदा भाषण, प्रकाशन प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।

मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प फरवरी 6-8, 2023

*मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प**

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (8 फरवरी 2023) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया जाए।

परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत हो गई है।

- एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

ये निर्णय, संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है।

इस निर्णय में अंतर्निहित मुख्य विचार नीचे दिए गए विवरण में व्यक्त किए गए हैं।

आकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. प्रतिकूल भू-राजनीतिक परिस्थिति के बने रहने और विश्व भर में केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए मौद्रिक नीति सख्ती के प्रभाव के बावजूद, हाल के महीनों में वैश्विक संवृद्धि की संभावना में सुधार हुआ है। बहरहाल, 2023 के दौरान वैश्विक संवृद्धि में गिरावट आने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति, उच्च स्तरों से कुछ नरमी दिखा रही है, जो केंद्रीय बैंकों को दर संबंधी कार्रवाइयों के आकार और गति को कम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हालांकि, केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को अपने लक्ष्य के करीब लाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं। बॉण्ड प्रतिफल अस्थिर बनी हुई है। अमेरिकी डॉलर अपने हालिया उच्च स्तर से नीचे आ गया है, और पिछली एमपीसी बैठक के बाद से इक्विटी बाज़ारों में बढ़ोत्तरी हुई है। प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में कमजोर बाह्य मांग, संरक्षणवादी नीतियों की बढ़ती घटना, अस्थिर पूंजी प्रवाह और ऋण संकट, हालांकि, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

घरेलू अर्थव्यवस्था

3. 6 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी किए गए प्रथम अग्रिम अनुमान (एफ़एई) ने भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की संवृद्धि को 2022-23 के लिए 7.0 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) रखा, जो कि निजी उपभोग और निवेश द्वारा संचालित था। आपूर्ति पक्ष पर, योजित सकल मूल्य (जीवीए), 6.7 प्रतिशत पर अनुमानित था।

4. उच्च आवृत्ति संकेतक यह बताते हैं कि 2022-23 की तीसरी और चौथी तिमाही में आर्थिक गतिविधि मजबूत रही है। 3 फरवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार रबी बुवाई का क्षेत्रफल पिछले वर्ष के क्षेत्रफल से 3.3 प्रतिशत अधिक था। औद्योगिक उत्पादन में अक्तूबर में 4.2 प्रतिशत तक की गिरावट के बाद नवंबर में 7.1 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। विनिर्माण में क्षमता उपयोग अब अपने दीर्घकालिक औसत से ऊपर है। दिसंबर में बंदरगाह माल भाड़ा ट्रैफिक, ई-वे बिल और टोल कलेक्शन में तेजी रही। पिछले महीने की तुलना में कुछ नरमी के बावजूद जनवरी में विनिर्माण और सेवाओं के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) विस्तार में बना रहा।

5. मजबूत विवेकाधीन खर्च से घरेलू मांग को बनाए रखा गया है। जैसा कि बेहतर यात्री वाहनों की बिक्री और घरेलू हवाई यात्री यातायात में परिलक्षित होता है, शहरी मांग ने आघात-सहनीयता का प्रदर्शन किया है। ग्रामीण मांग में सुधार हो रहा है। निवेश गतिविधि धीरे-धीरे जोर पकड़ रही है। दिसंबर में तेल से इतर

* 8 फरवरी 2023 को जारी।

स्वर्ण से इतर आयात में बढ़ोत्तरी हुई। दूसरी ओर, कमजोर वैश्विक मांग के कारण वस्तुओं का निर्यात दिसंबर में संकुचित हुआ।

6. सब्जियों की कीमतों में दोहरे अंकों की अपस्फीति के कारण सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति, नवंबर में 5.9 प्रतिशत तक कम होने के बाद, दिसंबर 2022 में घटकर 5.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गया। दूसरी ओर, अनाज, प्रोटीन आधारित खाद्य पदार्थों और मसालों में मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा। मुख्य रूप से मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण ईंधन मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी हुई। स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभावों में निरंतर मूल्य दबाव के कारण मूल सीपीआई (अर्थात्, खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) मुद्रास्फीति दिसंबर में बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गई।

7. एलएएफ के अंतर्गत औसत दैनिक अवशोषण अक्तूबर-नवंबर में औसतन ₹1.4 लाख करोड़ से बढ़कर दिसंबर-जनवरी के दौरान ₹1.6 लाख करोड़ होने के कारण, समग्र चलनिधि अधिशेष में बनी हुई है। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, 27 जनवरी 2023 तक मुद्रा आपूर्ति (एम3) में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि गैर-खाद्य बैंक ऋण में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 27 जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 576.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर थीं।

संभावना

8. मुद्रास्फीति की संभावना मिश्रित है। जबकि रबी फसल, विशेष रूप से गेहूं और तिलहन के लिए, की संभावनाओं में सुधार हुआ है, लेकिन प्रतिकूल मौसमी घटनाओं का जोखिम बना हुआ है। कच्चे तेल सहित वैश्विक कोमोडिटी मूल्य संभावना, मांग की संभावनाओं से जुड़ी अनिश्चितताओं के साथ-साथ भू-राजनीतिक तनावों के कारण आपूर्ति में व्यवधान के जोखिमों के अधीन है। विश्व के कुछ हिस्सों में कोविड के कारण आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों में ढील के कारण कमोडिटी की कीमतों पर ऊर्ध्वगामी दबाव का प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। आउटपुट मूल्य में इनपुट लागतों का निरंतर प्रभाव-अंतरण, विशेष रूप से सेवाओं में, मूल मुद्रास्फीति पर दबाव जारी रख सकता है। रिज़र्व बैंक के उद्यम सर्वेक्षण, विनिर्माण में इनपुट लागत और आउटपुट मूल्य दबावों में कुछ नरमी का संकेत करते हैं। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए और कच्चे तेल की औसत कीमत (भारतीय टोकरी) 95 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल मानते हुए, चौथी तिमाही में 5.7 प्रतिशत के साथ 2022-23 में मुद्रास्फीति 6.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। सामान्य मानसून के अनुमान पर, सीपीआई मुद्रास्फीति 2023-24 के लिए 5.3 प्रतिशत अनुमानित है, जोकि पहली तिमाही में 5.0 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.6 प्रतिशत तथा जोखिम समान रूप से संतुलित रहना अनुमानित है (चार्ट 1)।

9. कृषि और संबद्ध गतिविधियों की मजबूत संभावनाओं से ग्रामीण मांग को बढ़ावा मिलने की संभावना है। संपर्क-गहन क्षेत्रों में वापसी और विवेकाधीन खर्च से शहरी खपत को समर्थन मिलने की उम्मीद है। रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि कारोबार और उपभोक्ता, संभावना के बारे में आशावादी हैं। मजबूत ऋण संवृद्धि, आघात-सहनीय वित्तीय बाजार और पूंजीगत व्यय तथा अवसंरचना पर सरकार का निरंतर बल, निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करता है। दूसरी ओर, निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ, वैश्विक गतिविधि में मंदी से बाह्य मांग में कमी आने की संभावना है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि 6.4 प्रतिशत अनुमानित है, जोकि पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.0 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत तथा जोखिम व्यापक रूप से संतुलित रहना अनुमानित है (चार्ट 2).

10. पिछले दो महीनों में मुद्रास्फीति में कमी, सब्जियों में मजबूत अपस्फीति से प्रेरित थी, जो गर्मी के मौसम में तेजी के साथ समाप्त हो सकती है। सब्जियों को छोड़कर हेडलाइन मुद्रास्फीति ऊपरी सहन-सीमा बैंड से काफी ऊपर बढ़ रही है और विशेष रूप से उच्च कोर मुद्रास्फीति दबावों के साथ उच्च बनी रह सकती है। इसलिए, मुद्रास्फीति, संभावना के लिए एक बड़ा जोखिम बनी हुई है। राजकोषीय समेकन जारी रहने से निजी निवेश के लिए अवसर मिलने के बावजूद, केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजी और अवसंरचना व्यय पर सतत ध्यान देने से घरेलू आर्थिक गतिविधि के आघात-सहनीय बने रहने की उम्मीद है। भले ही, मई 2022 से नीतिगत रेपो दर में की गई बढ़ोत्तरी, सिस्टम में अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन फिर भी मुद्रास्फीति पर सतर्क रहना अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सहन-सीमा बैंड के भीतर बनी रहे और लक्ष्य के साथ उत्तरोत्तर संरेखित हो।

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23

चार्ट 1 : सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) का तिमाही पूर्वानुमान

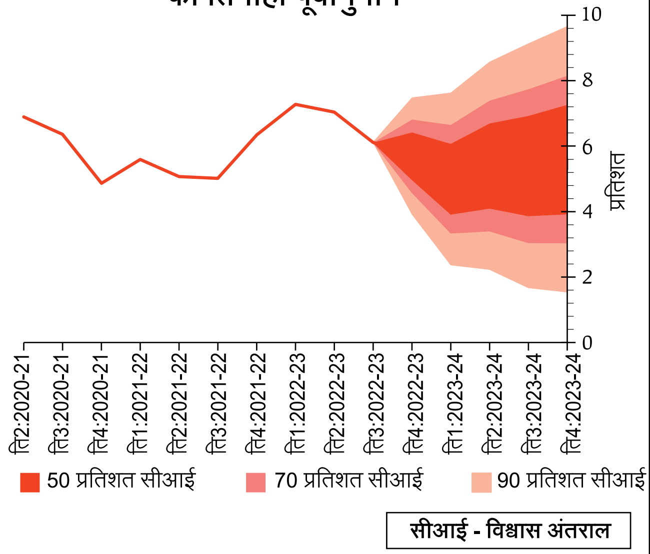

चार्ट 2 : वास्तविक जीडीपी संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) का तिमाही पूर्वानुमान

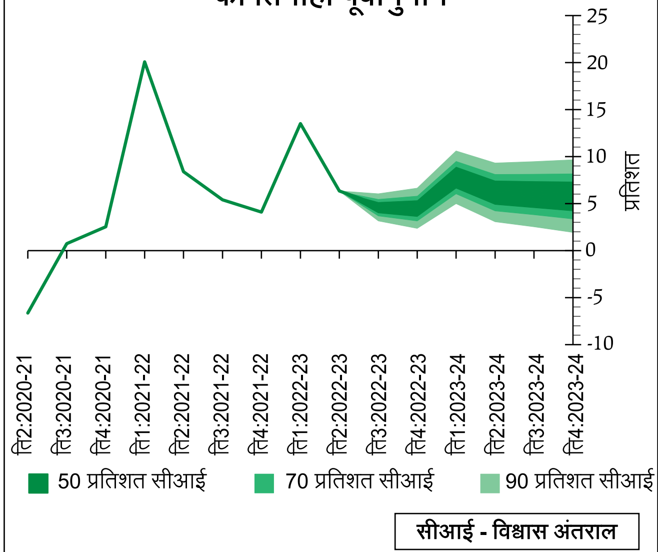

कुल मिलाकर, एमपीसी का यह विचार है कि मुद्रास्फीति के अनुमानों को नियंत्रित करने, मूल मुद्रास्फीति की सततता को रोकने और इस तरह मध्यम अवधि की संवृद्धि संभावनाओं को मजबूत करने के लिए आगे चलकर सुविचारित मौद्रिक नीति कार्रवाई आवश्यक है। तदनुसार, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

11. डॉ. शशांक भिडे, डॉ. राजीव रंजन, डॉ. माइकल देवब्रत पात्र और श्री शक्तिकान्त दास ने नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंकों तक बढ़ाने के लिए वोट किया। डॉ. आशिमा गोयल और प्रो. जयंत आर. वर्मा ने रेपो दर में वृद्धि के विरुद्ध वोट किया।

12. डॉ. शशांक भिड़े, डॉ. राजीव रंजन, डॉ. माइकल देवब्रत पात्र और श्री शक्तिकान्त दास ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए वोट किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे। डॉ. आशिमा गोयल, और प्रो. जयंत आर. वर्मा ने संकल्प के इस हिस्से के विरुद्ध वोट किया।

13. एमपीसी की बैठक का कार्यवृत्त 22 फरवरी 2023 को प्रकाशित किया जाएगा।

14. एमपीसी की अगली बैठक 3, 5 और 6 अप्रैल 2023 के दौरान निर्धारित है।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) वित्तीय बाजारों; (ii) विनियमन; (iii) भुगतान और निपटान प्रणाली और (iv) मुद्रा प्रबंधन, से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है।

I. वित्तीय बाजार

1. सरकारी प्रतिभूतियों में प्रतिभूतियां उधार देने और उधार लेने की शुरुआत

प्रतिभूतियां उधार देने और उधार लेने के लिए एक सुव्यवस्थित बाजार से, सरकारी प्रतिभूति बाजार में गहनता आएगी और चलनिधि की भी प्रचुरता होगी, जिससे कुशल मूल्य खोज में मदद मिलेगी। अतः, सरकारी प्रतिभूतियां उधार देने और उधार लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव है जो 'विशेष रेपो' के लिए मौजूदा बाजार को समृद्ध करेगा। आशा की जाती है कि यह प्रणाली, निवेशकों को निष्क्रिय प्रतिभूतियों को अभिनियोजित करने और पोर्टफोलियो रिटर्न बढ़ाने के लिए एक अवसर प्रदान करके प्रतिभूति उधार बाजार में व्यापक सहभागिता की सुविधा प्रदान करेगी। हितधारकों की प्रतिक्रियाओं के लिए निदेशों का मसौदा अलग से जारी किया जाएगा।

II. विनियमन

2. ऋणों पर दंडात्मक प्रभारों की वसूली

वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं (आरई) के पास अग्रिमों पर दंडात्मक ब्याज लगाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करने की परिचालनगत स्वायत्तता है, जो उचित और पारदर्शी होगी। दंडात्मक ब्याज का आशय अनिवार्य रूप से नकारात्मक प्रोत्साहनों के माध्यम से उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन की भावना उत्पन्न करना था, लेकिन इस तरह के प्रभारों का उपयोग ब्याज की संविदागत दर के ऊपर राजस्व वृद्धि उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। पर्यवेक्षी समीक्षाओं से पता चला है कि आरई के बीच दंडात्मक ब्याज लगाने के संबंध में अलग-अलग प्रणालियाँ प्रचलित हैं जो कतिपय मामलों में काफी अधिक थे, जिससे ग्राहकों की शिकायतें और विवाद उत्पन्न हुए।

उपरोक्त संदर्भ में दंडात्मक ब्याज लगाने पर वर्तमान विनियामकीय दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि ऋण की चुकौती में देरी/चूक या ऋणकर्ता द्वारा ऋण संबंधी करार के किसी अन्य महत्वपूर्ण नियम और शर्तों का पालन न करने पर उचित और पारदर्शी तरीके से 'दंडात्मक प्रभार' के रूप में दंड लगाया जाएगा और न कि 'दांडिक ब्याज' के रूप में, जोकि अग्रिमों पर लगाए जाने वाले ब्याज की दर में जोड़ा जाता है। इसके अलावा, दंडात्मक प्रभार का कोई पूंजीकरण नहीं होगा (अर्थात्, इसे अलग से वसूल किया जाएगा और बकाया मूलधन में नहीं जोड़ा जाएगा)। हालांकि, उधारकर्ता के ऋण जोखिम प्रोफाइल में किसी भी गिरावट के मामले में, आरई, ब्याज दर पर वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत ऋण जोखिम प्रीमियम को बदलने के लिए स्वतंत्र होंगे। उपरोक्त से संबंधित दिशानिर्देश का मसौदा, हितधारकों की प्रतिक्रियाओं के लिए शीघ्र ही भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा जाएगा।

3. जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त संबंधी विनियामकीय पहल

अपने अधिदेश के भाग के रूप में वित्तीय स्थिरता के साथ एक पूर्ण-सेवा वाला केंद्रीय बैंक होने के नाते, रिज़र्व बैंक यह मानता है कि जलवायु परिवर्तन, विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों में परिवर्तित हो सकता है, जिसके कारण वित्तीय स्थिरता से संबंधित व्यापक परिणाम हो सकते हैं। अतः, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रणालियों पर आधारित एक कार्यनीति तैयार करने के लिए, सार्वजनिक टिप्पणियों और प्रतिक्रिया के लिए 27 जुलाई 2022 को जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर एक चर्चा पत्र (डीपी) भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया था। इस संबंध में प्राप्त प्रतिक्रिया के विश्लेषण के आधार पर, आरई के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है:

(क) हरित जमाराशियों की स्वीकृति के लिए व्यापक रूपरेखा;

(ख) जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण ढांचा, और;

(ग) जलवायु परिदृश्य विश्लेषण और तनाव परीक्षण पर दिशानिर्देश।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

ये दिशानिर्देश, चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक के पास अपनी वेबसाइट पर एक समर्पित वेबपेज होगा जो जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर सभी अनुदेशों, प्रेस प्रकाशनियों, प्रकाशनों, भाषणों और संबंधित आरबीआई संचार को समेकित करेगा।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

4. व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली (ट्रेड्स) के दायरे का विस्तार

एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के उद्देश्य से दिसंबर 2014 में व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली (ट्रेड्स) संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद, तीन संस्थाओं ने ट्रेड्स प्लेटफार्मों का संचालन शुरू किया और दो अन्य संस्थाओं को सैद्धांतिक रूप से प्राधिकार प्रदान किया गया। ये संस्थाएं प्रतिवर्ष लगभग ₹60,000 करोड़ के लेनदेन प्रसंस्कृत करती हैं।

ट्रेड्स प्लेटफार्मों को और गति प्रदान करने के लिए, उनकी गतिविधि का दायरा निम्नानुसार बढ़ाने का प्रस्ताव है। इन उपायों से एमएसएमई के नकदी प्रवाह को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

(i) ट्रेड्स पर अब बीमा सुविधा की अनुमति दी जाएगी। यह क्रेताओं की क्रेडिट रेटिंग पर ध्यान दिए बिना उनकी देय राशियों के वित्तपोषण/ भुनाई को प्रोत्साहित करेगा। तदनुसार, एमएसएमई विक्रेताओं, खरीदारों और वित्तपोषकों के अलावा, बीमा कंपनियों को ट्रेड्स पर "चौथे सहभागी" के रूप में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

(ii) फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत फैक्टरिंग कारोबार करने के लिए पात्र सभी संस्थानों/ संस्थाओं को ट्रेड्स में वित्तपोषकों के रूप में भाग लेने की अनुमति होगी।

(iii) द्वितीयक बाजार परिचालन, अब ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। यह वित्तपोषकों को आवश्यकता पड़ने पर उसी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के भीतर अन्य वित्तपोषकों को अपने मौजूदा पोर्टफोलियो को भारी मात्रा में बिक्री करने की अनुमति देगा।

5. भारत में आने वाले यात्रियों के लिए यूपीआई उपलब्ध करवाना

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) भारत में खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के लिए एक सर्वव्यापी भुगतान साधन बन गया है। हाल ही में उन अनिवासी भारतीयों को यूपीआई एक्सेस प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिनके पास अपने एनआरई/एनआरओ खातों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर हैं। अब भारत आने वाले सभी यात्रियों को देश में रहने के दौरान उनके व्यापारिक भुगतान (पी2एम) के लिए यूपीआई एक्सेस करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। शुरुआत में, यह सुविधा चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर पहुंचने वाले जी-20 देशों के यात्रियों को दी जाएगी। आगे चलकर, यह सुविधा देश के अन्य सभी प्रवेश बिंदुओं पर सक्षम हो जाएगी। आवश्यक परिचालनगत अनुदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

IV. मुद्रा प्रबंधन

6. क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन – प्रायोगिक परियोजना

आम जनता के बीच सिक्कों के वितरण में सुधार करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक कुछ प्रमुख बैंकों के सहयोग से क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन (क्यूसीवीएम) पर एक प्रायोगिक परियोजना तैयार कर रहा है। क्यूसीवीएम एक नकदी रहित कॉइन वितरण मशीन है, जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करके ग्राहक के बैंक खाते से नामे किए गए राशि के बदले में सिक्कों का वितरण करेगी।

नकद-आधारित पारंपरिक कॉइन वेंडिंग मशीन के विपरीत, क्यूसीवीएम बैंकनोटों की भौतिक भुनाई और उनके प्रमाणीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। ग्राहकों के पास क्यूसीवीएम में आवश्यक मात्रा और मूल्यवर्ग में सिक्कों के आहरण का भी विकल्प होगा।

प्रायोगिक परियोजना को शुरू में देश भर के 12 शहरों में 19 स्थानों पर लागू करने की योजना है। इन वेंडिंग मशीनों को आसानी और पहुंच बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों, जैसे, रेलवे स्टेशनों, शॉपिंग मॉल, मार्केटप्लेस पर स्थापित किया जा सकता है। प्रायोगिक परीक्षणों से प्राप्त अनुभव के आधार पर, क्यूसीवीएम का उपयोग करके सिक्कों के बेहतर वितरण को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

भाषण

भारत में वित्तीय बाजार : स्थिरता और विकास की यात्रा

*भारत में वित्तीय बाजार : स्थिरता और विकास की यात्रा**

शक्तिकान्त दास

आज वार्षिक एफआईएमएमडीए[1]-पीडीएआई[2] सम्मेलन का हिस्सा बनकर मुझे खुशी हो रही है। रिज़र्व बैंक इस बात की सराहना करता है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में वित्तीय बाजारों के विकास में एफआईएमएमडीए और पीडीएआई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हाल ही में, कोविड-19 के उथल-पुथल भरे समय, यूक्रेन में युद्ध और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के बीच, आरबीआई के साथ साझेदारी करते हुए, बाजारों और अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन किया है।

चूंकि आज मैं बाजार के दक्ष खिलाड़ियों, दिग्गजों और विशेषज्ञों के सामने बोल रहा हूं, इसलिए मैंने सोचा कि यह हमारे वित्तीय बाजारों की पिछले एक दशक की यात्रा को फिर से देखने और इस बात पर विचार करने का सही समय होगा कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं और हम इसके आगे के सफर के बारे में क्या सोचते हैं। हम कह सकते हैं कि यह अतीत से सीखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास होगा।

वैश्विक वित्तीय संकट से लेकर यूरोजोन राष्ट्रिक ऋण संकट तक; टेपर टैंट्रम से लेकर ब्रेक्सिट तक; अभूतपूर्व मात्रात्मक शिथिलता से लेकर हालिया स्मृति में सबसे त्वरित मौद्रिक सख्ती तक; संपूर्ण मानव जाति को गतिशून्य कर देने वाली महामारी से लेकर पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए खतरा बन जाने वाले भू-राजनीतिक संकट तक- यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के वर्षों में दुनिया एक तूफान से दूसरे तूफान में फँसती चली गई है।

इस पृष्ठभूमि में, भारतीय वित्तीय बाजारों की यात्रा दो प्रमुख उद्देश्यों - स्थिरता और विकास से प्रेरित रही है। संकट प्रबंधन इस यात्रा का एक प्रमुख घटक रहा है। बहरहाल, वित्तीय बाजारों को विस्तृत करने और गहन बनाने के मुख्य उद्देश्य के साथ विकासात्मक सुधारों का सफर भीषण तूफानों के बीच भी जारी रहा।

अब तक का सफर

पिछले कुछ दशकों में भारतीय वित्तीय बाजारों की यात्रा पर मैं थोड़ी चर्चा करता हूं। 1980 के दशक के अंत तक, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक प्रशासित ब्याज दर व्यवस्था, निश्चित विनिमय दर, एक आबद्ध (कैप्टिव) सरकारी प्रतिभूति बाजार और चालू एवं पूंजी खाता प्रतिबंधों से जाना जाता था। 1990 के दशक के दौरान नीतिगत उपायों के जरिये बाजार-निर्धारित ब्याज दर एवं विनिमय दर, बहुसंकेतक दृष्टिकोण और अंततः मौद्रिक नीति के संचालन में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, चालू खाते में परिवर्तनीयता और पूंजी खाते के क्रमशः उदारीकरण की ओर बढ़ने की दिशा में कदम उठाए गए। कई प्रमुख विधायी परिवर्तनों से नीतिगत उपायों को बल मिला: विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999; सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006; सरकारी प्रतिभूतियों, डेरिवेटिवों और मुद्रा बाजार के लिखतों पर रिज़र्व बैंक को स्पष्ट विनियामक शक्तियां प्रदान करने के लिए 2006 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन; और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007। मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव बाजारों को समाशोधन और गारंटीकृत निपटान प्रदान करने के लिए 2001 में क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) और एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म का संचालन आरंभ किया गया था। डेरिवेटिवों के लिए एक ट्रेड रिपॉजिटरी स्थापित की गई थी। 2009 के पिट्सबर्ग शिखर सम्मेलन में जी-20 द्वारा अपने सुधार एजेंडे को लागू करने के बाद ही इनमें से कुछ पहलें वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण हो गई थीं।

वैश्विक वित्तीय संकट (2008) के बाद, भारतीय वित्तीय बाजार नवजात अवस्था में थे लेकिन बढ़ रहे थे। अधिकांश बाजार क्षेत्रों में विदेशी भागीदारी के प्रति दृष्टिकोण संभल-संभल कर आगे बढ़ने वाला था। डेरिवेटिव बाजार, जो जोखिमों की हेजिंग के लिए बाजार थे, प्रतिभागियों और उत्पादों की संख्या के लिहाज से

* दुबई में 27 जनवरी 2023 को आयोजित 22वें एफआईएमएमडीए-पीडीएआई वार्षिक सम्मेलन में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तुत मुख्य उद्बोधन।

[1] फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए)

[2] प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई)

सीमित थे। इस बीच, 2013 में प्रकाशित बीआईएस त्रैवार्षिक सर्वेक्षण से पता चला कि विदेशों में भारतीय रुपये में रुचि बढ़ रही थी। हालांकि, तटीय और अपतटीय विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दरों में अंतर ज्यादा के कारण, रुपये के लिए तटीय और अपतटीय बाजार संवर्गीकृत (सेगमेंटेड) रहे।

प्रतिकूलताएँ और अनुकूलताएँ

कुछ अधिक हाल का समय देखें तो पिछले दशक में हमारी कई नीतियां संकट प्रबंधन से मिली सीखों के साथ-साथ, उन विकासात्मक उद्देश्यों से निर्देशित रही हैं, जिन्हें हमारा देश हासिल करना चाहता है। जैसे-जैसे दुनिया एक के बाद एक तूफानों को पार करते हुए आगे बढ़ती गई, वैसे-वैसे हम प्रमुख वैश्विक प्रतिकूलताओं के प्रभाव-प्रसार से बचने की भरसक कोशिश करते गए।

अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएँ भी हमारी नीति को निर्देशित करने में समान रूप से बाध्यकारी थीं। पिछले दशक में जैसे-जैसे वास्तविक/वस्तु क्षेत्र का विकास हुआ, वित्तीय बाजारों से अपेक्षाएं भी बढ़ीं। अर्थव्यवस्था की जरूरतें इन प्रगतियों को दर्शाती हैं। इस बात के परिप्रेक्ष्य में, आइए कुछ आंकड़ों पर गौर करें। नॉमिनल जीडीपी वित्त वर्ष 2010 के ₹64 लाख करोड़ से चार गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में ₹273 लाख करोड़ हो गया।[3] इसी अवधि के दौरान बाहरी व्यापार भी ₹29 लाख करोड़ से चार गुना बढ़कर ₹137 लाख करोड़ हो गया।[4] जीडीपी में व्यापार का अनुपात 2000 में रहे 25% से बढ़कर 2021 में 45% हो गया है।[5] देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)[6] 2010 के बाद तेजी से बढ़कर ढाई गुना हो गया है। भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र में संसाधनों का प्रवाह वित्त वर्ष 2012 में रहे ₹12 लाख करोड़ से लगभग दुगुना बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में ₹22 लाख करोड़ हो गया।[7] यद्यपि बैंक वित्तपोषण का एक प्रमुख स्रोत बने हुए हैं, वाणिज्यिक क्षेत्र की बाजार उधारी[8] वित्तीय वर्ष 2012 में रहे ₹74,000 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में ₹3,16,000 करोड़ हो गई। जैसे-जैसे हमारी अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाज़ारों का विकास हुआ, वैसे-वैसे विश्व अर्थव्यवस्था और वैश्विक वित्तीय बाज़ारों के साथ इसका एकीकरण भी बढ़ा है। बढ़ती अर्थव्यवस्था और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बने रहने की हमारी आकांक्षाओं ने हमारी फंडिंग जरूरतों का विस्तार किया है। इन सभी के लिए बड़े और सघन वित्तीय बाजारों की आवश्यकता है।

प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति नीतिगत प्रतिक्रिया

हाल ही में हमारी कुछ नीतिगत प्रतिक्रियाओं को देखना प्रासंगिक होगा, विशेष रूप से प्रमुख वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के संदर्भ में। पिछले दशक में उथल-पुथल के एक के बाद एक एपिसोड नें अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियों के ढेर खड़े कर दिए थे। इन चुनौतियों के लिए अलग-अलग जवाबी कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत थी।

2008 में नीतिगत कार्रवाईयों का उद्देश्य प्रणाली में चलनिधि की सहज स्थिति, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना सुनिश्चित करना और एक संकट प्रबंधन ढांचा बनाए रखना था जो विश्व स्तर पर होने वाले वित्तीय संकट के प्रति अर्थव्यवस्था को संभाले रख सके। इसके लिए पारंपरिक उपकरण जैसे कि नीतिगत ब्याज दरें और प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात(सीआरआर) का इस्तेमाल किया गया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन के उपाय के रूप में अन्य बातों के साथ-साथ अनिवासी भारतीयों द्वारा कार्पोरेट्स के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) हेतु विदेशी मुद्रा जमाराशियों पर ब्याज दर की सीमा में छूट दिया जाना रहा है। अपरंपरागत उपायों में ये उपाय शामिल थे – भारतीय बैंकों के लिए रुपया-डालर स्वैप सुविधा, म्युचुअल फंडों के लिए एक पुनर्वित्त विंडो और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सहायता प्रदान करने केलिए एक विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) की व्यवस्था की गई।

2013 में फेडरल रिज़र्व द्वारा मात्रात्मक सहजता के प्रारंभिक टेपर की घोषणा के बाद बाज़ार सहभागियों के विश्वास को बहाल रखने तथा रुपए पर दबाव को नियंत्रित करने के प्रयोजनों ने रिज़र्व बैंक की नीतिगत जवाबी कार्रवाइयों का मार्दर्शन किया। मौद्रिक स्थितियों को अपरंपरागत साधनों के माध्यम से कठोर बनाया गया। पूंजी प्रवाह का प्रबंधन करने के लिए विदेशी मुद्रा बाज़ार के लिए किए गए उपायों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और प्रशासनिक

[3] स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

[4] स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आरबीआई भुगतान संतुलन सांख्यिकी

[5] स्रोत: विश्व बैंक

[6] स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

[7] स्रोतः भारतीय रिज़र्व बैंक सांख्यिकी पुस्तिका

[8] बाजार उधारी में गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक और अधिकार मुद्दे, गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा सकल निजी स्थानन और गैर-बैंकों द्वारा अभिदत्त वाणिज्यिक पत्रों का निवल निर्गम शामिल है।

उपाय दोनों शामिल हैं। इन उपायों में गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध, पीएसयू कंपनियों के तेल के लिए एक विशेष डालर स्वैप विंडो खोलना, विदेशी मुद्रा अनिवासी-बैंक (एफसीएनआर-बी) जमाराशियों के लिए एक रियायती स्वैप विंडो, बैंकों की विदेशी उधार सीमा में वृद्धि, सरकारी ऋण में विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि और बाहरी निवेश प्रवाह पर प्रतिबंध , उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) पात्रता के साथ-साथ एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स शामिल हैं।

मार्च, 2020 में कोविड-महामारी के प्रकोप ने जरूरी कर दिया था कि उभरते या संभाव्य बाज़ार में अत्यधिक अव्यवस्था उत्पन्न होने की स्थिति के पहले समाधान के लिए तेज और केंद्रित नीतिगत जवाबी कार्रवाई की जाए। पहले की तरह नीतिगत दरें कम की गई और प्रणालीगत चलनिधि का विस्तार किया गया। लेकिन, इस बार नीतिगत गलियारे को असमान रूप से बढ़ाया गया था और निश्चित रिवर्स रेपो दर अल्प एवं दीर्घकालिक ब्याज दरों के उभार को नियंत्रित करने का प्रभावी उपकरण बन गई। नीतिगत दरों के प्रसारण को बेहतर बनाने तथा प्रभावित क्षेत्रों को क्रेडिट के प्रवाह के बने रहने को सुनिश्चित करने के लिए अपरंपरागत उपायों का इस्तेमाल किया गया जैसे-दीर्घकालिक रेपो परिचालन (एलटीआरओ), लक्ष्यित एलटीआरओ तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए विशेष पुनवित्त सुविधाएं। म्यूचुअल फंड के लिए एक विशेष चलनिधि सुविधा लागू की गई ताकि मोचन संबंधी दबाव को कम किया जा सके। पहली बार ऐसा हुआ कि रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम(जी-सैप) के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बहाली लाने के लिए अपने तुलन पत्र को गिरवी रख दिया जिसमें क्रय की जाने वाली राशि के लिए सर्वाधिक अग्रिम वचनबद्धता प्रदान की गई थी। विशेष खुले बाज़ार परिचालन किए गए जिसमें प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद और फरोख्त की गई ताकि प्रतिफल वक्र की स्थिति को सही दिशा में बनाए रखा जा सके तथा चलनिधि का प्रबंधन हो सके। उभरते समय के साथ-साथ आगे के लिए तथा स्थिति-प्रज्ञ मार्गदर्शन को प्रमुखता प्राप्त हुई जिसमें रिजर्व बैंक की वचनबद्धता का आश्वासन था कि वित्तीय स्थिति को सौहार्दपूर्ण बनाए रखा जाएगा। यह संप्रेषण हमारे मौद्रिक नीति टूल- किट का महत्वपूर्ण हिस्सा साबित हुआ।

यूक्रेन में दुबारा युद्ध छिड़ जाने से जोखिम- भावना और भी क्षीण हो गई है जिसमें वस्तुओं की कीमतें और मुद्रास्फीति कई दशकों के सबसे उच्च स्तर पर पहुच गई। ज्यों ही प्रमुख केंद्रीय बैंकों में मुद्रास्फीति संबंधी दबावों को दूर करने के लिए नीतिगत दरों को बढ़ाना शुरू किया और चलनिधि की स्थिति को कड़ा कर दिया, वित्तीय बाज़ार में अस्थिरता का एक दुष्चक्र पैदा हो गया और इसके कारण रुपये पर काफी दबाव बना गया। इस बार नीतिगत जवाबी कार्रवाई ने बाहरी प्रवाहों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक उपायों का सहारा नहीं लिया बल्कि आनेवाली जमाराशियों, ऋण-लिखतों तथा ईसीबी में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करके आवक प्रवाह को बढ़ाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया। निर्यात को बढ़ाने तथा रुपए में विश्व की बढ़ती हुई रुचि को सहारा देने के लिए रुपए में किए गए निर्यात/ आयात की इनवाइसिंग, भुगतान तथा निपटान के संबंध में अतिरिक्त व्यवस्था लागू की गई।

मैं यहां जिस बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ वह यह है कि उथल-पुथल के विभिन्न प्रकरणों के प्रति रिज़र्व बैंक की जवाबी कार्रवाई स्पष्ट, सामान्य स्वरूप की थी जिसमें जवाबी कार्रवाई प्रत्येक प्रकरण के अनुरूप की गई थी, चाहे वह नीतिगत प्रयोजन तथा विकल्प को लेकर हो और चाहे टूल-किट के उपयोग के संबंध में हो। प्रत्येक जवाबी कार्रवाई अंतर्निहित व्यापक आर्थिक स्थितियों का प्रकार्य थी जिससे पिछले संकटों से ली गई सीख परिलक्षित होती थी। इस संदर्भ में, मैं हमारी नीतिगत प्रतिक्रियाओं की तीन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना चाहूँगा। पहली, रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए सभी चलनिधि संबंधी प्रबंध परिचालन जिसमें म्यूचुअल फंडों तथा एनबीएफसी भी शामिल हैं, हमेशा बैंकों के माध्यम से किए गए जो रिज़र्व बैंक के लिए चलनिधिक प्रवाह माने जाते हैं,यहां तक कि शांति काल में थी। दूसरी,ऐसे उपाय जिसमें संपार्श्विक मानकों में कोई कमी नहीं की गई तथा यह सुनिश्चित किया गया कि केंद्रीय बैंक, प्रतिपक्षी जोखिमों से सुरक्षित बने रहें। तीसरी, इस बार जितने उपाय किए गए वे सभी समयबद्ध थे और वे उसी समय समाप्त हुए जो मूल रूप से परिपक्व होने के लिए परिभाषित किए गए थे। उदाहरण के तौर पर, जी-सैप को बंद कर दिया गया था, सीआरआर के संबंध में छूट उसे सामान्य बनाए रखने के लिए दी गई तथा चलनिधि प्रबंध ढांचे में अप्रैल 2022 में बदलाव किए गए ताकि स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) को क्रियान्वित रखा जा सके। इन उपायों ने हमें संभावित चलनिधि शिकंजे, जिसे चक्रव्यूह कहते हैं, से बाहर निकालने में सक्षम बनाया है।

यह दिलचस्प और संभवत: विरोधाभासी बात है कि एक दशक की अभूतपूर्व चुनौतियों के दौरान वित्तीय बाजारों में सुधार

और विकास के उपाय अप्रत्याशित गति से हुए हैं। सुधारों का उद्देश्य तटीय वित्तीय बाजारों को बढ़ाना और कीमत उपाय की दक्षता में वृद्धि करना था। हाल के सुधार संबंधित हैं (i) घरेलू बाजारों में अनिवासियों की पहुंच को आसान बनाने और निवासियों को अपतटीय बाजारों तक पहुंचने की अनुमति देकर समानांतर बाजार विभाजन को दूर करना; (ii) आसान पहुंच के प्रावधान के माध्यम से वित्तीय बाजारों और खुदरा भागीदारी में अनिवासी भागीदारी को प्रोत्साहित करके सहभागिता आधार का विस्तार करना, उदाहरण के लिए रिटेल डायरेक्ट और एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म के माध्यम से; (iii) अधिक प्रबुद्ध उपयोगकर्ताओं को उनकी हेजिंग जरूरतों के लिए बाजारों तक पहुंचने और बाजार के उतार-चढ़ाव पर अपने विचार व्यक्त करने की सुविधा प्रदान करना; (iv) उत्पादों के एक बड़े सूट(समूह) की शुरुआत के माध्यम से नवोन्मेष को बढ़ावा देना जिसे वैयक्तिक बाजार सहभागियों की जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सकता है;[9] और (v) खुदरा उपयोगकर्ता की सुरक्षा और एक ठोस, स्वीकार्य और ग्राहक उपयुक्तता फ्रेमवर्क के माध्यम से उचित उपयोगकर्ता आचरण को सुनिश्चित करते हैं। प्रभावी समाशोधन और निपटान व्यवस्था, बेंचमार्क सुधार, पारदर्शी आवश्यकताओं और बाजार दुरुपयोग पर नियम, अन्य के अतिरिक्त से एक मजबूत बुनियादी फ्रेमवर्क और प्रवर्तन फ्रेमवर्क स्थापित किया गया है।

भारत पूंजी खाता संपरिवर्तनीयता के उच्च स्तर को प्राप्त करने की दिशा में भी एक लंबा सफर तय कर चुका है। कुछ संवेदनशील/रणनीतिक क्षेत्रों के अतिरिक्त एफडीआई अप्रतिबंधित होने के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह का उदारीकरण पिछले दशक में जारी रहा। घरेलू बाजार बाजारों में अनिवासी निवेश की सीमाओं को उदार बनाया गया। सरकारी और कॉर्पोरेट बांड में अनिवासी निवेश की सुविधा के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) की शुरुआत की गई। एक संपूर्ण सुलभ मार्ग (एफएआर) को पोर्टफोलियो ऋण प्रवाह के उपरांत उदारीकरण के हिस्से के रूप में पेश किया गया था, जो निर्दिष्ट बेंचमार्क सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासी निवेश पर कोई सीमा नहीं रखता है। ईसीबी फ्रेमवर्क को व्यापक रूप से उदारीकृत किया गया था और अब यह केवल एक समग्र सुलभ सीमा और कुछ "अंतिम उपयोग" प्रतिबंधों के अधीन है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) के लिए विनियमों को भी युक्तिसंगत और उदार बनाया गया है। वर्तमान में एलआरएस चालू और पूंजी खाता लेनदेन दोनों के लिए उपलब्ध है।

आज हम कहां हैं?

कई आघातों के उपरांत, वर्ष 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के अत्यधिक संकुचित रहने का अनुमान है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संवृद्धि और मुद्रास्फीति दोनों ही मामलों में सबसे खराब समय पीछे रह गया है ऐसा प्रतीत होता है। हाल में, विभिन्न देशों में कोविड संबंधी प्रतिबंधों और मुद्रास्फीति में कमी के साथ, हालांकि जो अभी भी अधिक है, केंद्रीय बैंकों ने कम दर वृद्धि अथवा विराम की शुरुआत की है। साथ ही, उन्होंने मुद्रास्फीति को लक्ष्य के करीब लाने के अपने संकल्प को जोरदार ढंग से दोहराया। भविष्य में, लंबी अवधि के लिए उच्च नीतिगत दरों की संभावना स्पष्ट दिखती है। संवृद्धि के मोर्चे पर, कुछ महीने पहले तक अनुमानित एक गंभीर और अधिक व्यापक मंदी की तुलना में वर्तमान में यह एक नरम मंदी के आसपास घूम रही है ।

इस प्रतिकूल और अनिश्चित अंतरराष्ट्रीय माहौल में, भारतीय अर्थव्यवस्था आघात-सह बनी हुई है, जो अपने समष्टि आर्थिक आधार से मजबूती हासिल कर रही है। हमारी वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ और स्थिर बनी हुई है। बैंक और कॉरपोरेट संकट से पहले की तुलना में अधिक मजबूत हैं। बैंक क्रेडिट में द्विअंकीय वृद्धि देखी गई है। भारत को व्यापक रूप से धुंधली दुनिया में एक उज्ज्वल सितारे के रूप में देखा जा रहा है। हमारी मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है, लेकिन नवंबर और दिसंबर 2022 के दौरान इसमें स्वागत योग्य नरमी देखी गई है। हालांकि, मूल मुद्रास्फीति जड़ और उच्च बनी हुई है।

बाहरी मोर्चे पर, प्रतिवैश्वीकरण और संरक्षणवाद जोर पकड़ रहे हैं जैसा कि हाल में वैश्विक आपूर्ति-शृंखला के आघात के दौरान देखा गया है। इस प्रकार ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए द्विपक्षीय व्यापार संबंधों का होना और सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। हाल ही में, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के

[9] जनवरी 2022 से लागू हुए ओटीसी डेरिवेटिव्स में मार्केट मेकिंग के दिशा-निर्देशों ने मार्केट मेकर्स को रेजिडेंट्स को विभिन्न प्रकार के डेरिवेटिव उत्पादों की पेशकश करने की अनुमति दी ताकि वे अपने जोखिमों को कम करने के लिए कुशलतापूर्वक रणनीति तैयार कर सकें। इसके बाद, कई नए उत्पाद, जैसे, एफएक्स बैरियर ऑप्शन, बाइनरी ऑप्शन, फॉरेक्स मार्केट में लक्षित रेंज फॉरवर्ड और ब्याज दर बाजार में स्वैपशन और कुल रिटर्न स्वैप पेश किए गए हैं।

साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और इस तरह के और समझौतों की बात प्रगति पर हैं। वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में औसत चालू खाता घाटा 3.3 प्रतिशत रहा। माल निर्यात पर धीमी वैश्विक मांग की मार पड़ रही है; परंतु हमारी सेवाओं का निर्यात और विप्रेषण मजबूत बना हुआ है। सेवाओं और विप्रेषण के तहत निवल शेष में बड़ा अधिशेष बना रहा है, जो आंशिक रूप से व्यापार घाटा का समायोजन करता है। परिणामत:, चालू खाता घाटा प्रमुख रूप से प्रबंधनीय है और व्यवहार्यता के मापदंडों के अंतर्गत है।

वित्तपोषण पक्ष की ओर देखा जाए तो निवल एफ़डीआई प्रवाह मज़बूत बने रहे तथा विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह जुलाई 2022 से फिर से शुरू हो गया है, जिसमें समय समय पर बीच में कुछ बहिर्वाह भी हुए हैं। विदेशी मुद्रा भंडार का आकार सहज बना हुआ है तथा 21 अक्तूबर 2022 के 524 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 13 जनवरी 2023 को बढ़कर 572 बिलियन अमरीकी डालर हो गया था। इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से भारत का बाह्य ऋण अनुपात भी कम ही है। इस स्थिति में रिज़र्व बैंक को, पूंजी का प्रवाह नियंत्रित करने तथा अत्यधिक पूंजी बहिर्वाह के प्रकरणों के समय में भी घरेलू मुद्रा को और अधिक अंतरराष्ट्रीयकृत बनाने के लिए कदम उठाने पड़े।

विश्व के प्रत्येक जोखिम-रहित प्रकरण के दौरान अमरीकी डालर मज़बूत हुआ है जिससे अधिकांश करेंसियों के मूल्य गिरने का दबाव बढ़ता रहा है। संकट के क्रमिक प्रकरणों के दौरान रुपये का तुलनात्मक प्रदर्शन[10] अपनी अलग कहानी बयान करता है। वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान रुपए में बदतरीन मूल्यह्रास हुआ था– 1 अप्रैल 2008 और 3 मार्च 2009 के बीच रुपए ने अमरीकी डालर की तुलना में अपना 23% मूल्य खो दिया था। इसी प्रकार से 01मई 2013 और 28 अगस्त 2013 के मध्य टेपर टैंट्रम के दौरान रुपए में 22% मूल्यह्रास हुआ था। लेकिन, बाद के उथल-पुथल के प्रत्येक प्रकरण में रुपये में मूल्यह्रास अपेक्षाकृत कम था। महामारी के प्रारंभिक दिनों में अर्थात 17 फरवरी 2020 और 21 अप्रैल 2020 के बीच रुपये में केवल 7% का मूल्यह्रास हुआ था। यहां तक कि वर्ष 2022 में यूक्रेन से उत्पन्न भू-राजनैतिक तनवों के दौरान भी जहां 24 फरवरी 2022 और 19 अक्तूबर 2022 के बीच अमरीकी डालर की तुलना में रुपए में 9% का मूल्यह्रास हुआ था, इस प्रकार रुपए का प्रदर्शन अधिकांश उन्नत एवं उसके उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं की करेंसियों की तुलना में कहीं बेहतर था।

महत्वपूर्ण रूप से, अस्थिरता के समय में रुपये का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। उदाहरण के लिए 1- महीने की अंतर्निहित अस्थिरता सहित वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान रुपए ने 10 अक्तूबर 2008 को 25% के उच्च स्तर को छू लिया था तथा टेपर टैंट्रम अवधि के दौरान 29 अगस्त 2013 को 20% के स्तर पर पहुँच गया था। हालांकि, कोविद-19 महामारी के दौरान अंतर्निहित अस्थिरता 24 मार्च 2020 को 10% के सर्वाधिक उच्च स्तर पर थी तथा उसके बाद युद्ध से जुड़ी अनिश्चितताओं एवं प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक सख्ती किए जाने के बावजूद सुनियंत्रित स्थिति में बनी रही।[11] सरकारी बांड-बाज़ार समुत्थानशील बने रहे, जिसमें समान समूह के राष्ट्रों के औसत बिड-आस्क स्प्रेड न्यूनतम बने रहे। प्रतिफल वक्र भी अत्यधिक उच्च सरकारी उधारी के बावजूद बिना किसी अनावश्यक अस्थिरता के सही क्रम में बनी रही।

आगे की राह

आज, जब हम आगे की ओर निगाह डालते हैं तो अभी भी हमें चुनौतियां नज़र आती हैं, किंतु उनके प्रति हम पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ तैयारी कर सकते हैं। भारतीय वित्तीय बाज़ार पिछले वर्षों में काफी हद तक विकसित हुआ है। सरकारी प्रतिभूति बाज़ार और रात्रिपर्यन्त (ओवरनाइट) मुद्रा बाज़ार में चलनिधि का स्तर बढ़ा हुआ है। बिड-आस्क स्प्रेड संकीर्ण बना रहा है जो मूल्य-निर्धारण की क्षमता को प्रदर्शित करता है। विदेशी मुदा बाज़ार में समग्र व्यापारित मात्रा बढ़ी है और हेजिंग उत्पादों का एक सुइट उत्पन्न हो गया है। ब्याज दर स्वैप बाज़ारों में भी व्यापारित मात्रा लगातार बढ़ी है और इन बाज़ारों में नए उत्पाद भी विकसित हो रहे हैं। सभी बाज़ारों में विदेशी मुद्रा बाज़ार और ब्याज दरों में फासला घटने के साथ तटवर्ती और अपतटीय बाज़ार ज्यादा से

[10] स्रोतः ब्लूमबर्ग के डेटा का इस्तेमाल रुपए के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है।

[11] 01 जनवरी 2022 और 20 जनवरी 2023 के बीच रुपये की दैनिक औसत 1-महीने की अंतर्निहित अस्थिरता 5% थी और 7 मार्च, 2022 को यह 8% के उच्च स्तर पर पहुंच गई।

स्रोत: ब्लूमबर्ग

ज्यादा जुडते जा रहे हैं। इन बाज़ारों में अनिवासी की सहभागिता यद्यपि धीरे-धीरे ही सही, बढ़ रही है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी झटकों और अनिश्चितताओं से ग्रस्त है। वित्तीय बाज़ार अस्थिर बने हुए हैं और भू-राजनैतिक तनावपूर्ण बनी रहने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य, ऊर्जा और वस्तुओं की कीमतें कम हुई हैं लेकिन इसमें भी अनिश्चितता बनी हुई है। मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है और सभी देशों में व्यापक आधार पर फैली हुई है। आईएमएफ ने विश्व अर्थव्यवस्था के एक-तिहाई हिस्से में इसमें कमी आने का अनुमान लगाया है।

भारत में, हम वित्तीय बाज़ार के विकास में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं लेकिन अभी भी यह कार्य प्रगति पर है। रिज़र्व बैंक और फिमड़ा (एफआईएमएमडीए) तथा पीड़ीएआई जैसे हितधारकों को मिलकर काम करने और कतिपय विशेष क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। सरकारी- प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाज़ार की चलनिधि कुछ ही प्रतिभूतियों और अवधियों तक ही केंद्रित है। ब्याज दर डेरेवेटिव बाज़ार में मिबोर-आधारित ओआईएस ही एक मात्र प्रमुख चलनिधीय उत्पाद बना हुआ है। अनेक सुविधाजनक नीतिगत उपायों के होते हुए भी मीयादी मुद्रा बाज़ार अनुपस्थित रहता है। बाज़ारों में खुदरा खंड की पहुंच, खासकर डेरेवेटिव बाज़ारों में और ज्यादा सुधार की जरूरत है। विदेशी मुद्रा बाज़ार में,जहां कार्पोरेट्स सख्त बिड-आस्क स्प्रेड से लाभान्वित होते हैं, वहीं छोटे उपयोगकर्ताओं को निष्पक्ष एवं पारदर्शी मूल्य-निर्धारण हेतु विनियामकीय अपेक्षाओं के बावजूद मूल्य-निर्धारण संबंधी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार, सरकारी प्रतिभूति बाज़ारों में खुदरा निवेशकों के लिए चलनिधि सुनिश्चित करने हेतु सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।

निष्कर्ष

पिछले दशक में भारतीय वित्तीय बाज़ारों की यात्रा स्थिरता के साथ निरंतर प्रगति की कहानी कह रही है। हमने इस जहाज़ को स्थिर रखकर आगे बढ़ाने के अपने दृष्टिकोण के प्रति दृढ़ता और प्रतिबद्धता बनाए रखी है। आगे देखें तो हम यह पाएंगे की ज्यों ज्यों भारतीय बैंकों की उपस्थिति अपतटीय बाज़ारों में बढ़ेगी, उत्पादों की संख्या बढ़ेगी, घरेलू बाज़ारों में अनिवासी सहभागिता में वृद्धि होगी और पूंजी खाता परिवर्तनीयता बढ़ेगी, वैसे-वैसे और अधिक चुनौतियाँ पैदा होती जाएंगी। बाज़ार सहभागियों को विश्व स्तर पर एकीकृत बाज़ारों में होने वाले परिवर्तनों और जोखिमों के प्रति स्वयं को तैयार रखना होगा। मनोवांछित परिणाम प्राप्त करना वित्तीय संस्थाओं और बाज़ार सहभागियों यह निर्भर करेगा कि वे सुधार के इस एजेंडे को आगे ले जाएं ताकि हमारे पास अधिक गतिमान और समुत्थानशील वित्तीय बाज़ार उपलब्ध हो।

धन्यवाद !

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

भारत के लिए पुनर्गठित त्रैमासिक पूर्वानुमान प्रतिरूप (क्यूपीएम 2.0)

केंद्रीय बजट 2023-24: एक आकलन

ईएसजी प्रकटीकरण और प्रदर्शन: अंतर-देशीय साक्ष्य

ऋण- मांग पर बैंकरों के रुख - महामारी के बाद सुधार

फेडरल रिज़र्व की कार्रवाइयों का दीर्घ प्रभाव: मौद्रिक नीति और भारत में अनिश्चितता का प्रभाव-विस्तार

*अर्थव्यवस्था की स्थिति**

वर्ष 2023 संभवतः पहले के अनुमान की तुलना में मामूली वैश्विक मंदी से विशेष होगा, लेकिन प्रक्षेपवक्र अप्रत्याशित बना हुआ है। भारत में, घरेलू खपत और निवेश को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए मजबूत संभावनाओं, व्यापार और उपभोक्ता विश्वास के सुदृढ़ीकरण और मजबूत ऋण वृद्धि से लाभ होगा। भले ही, जनवरी में मुद्रास्फीति में वापसी देखी गई हो, लेकिन आपूर्ति प्रतिक्रियाओं और लागत की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजीगत व्यय पर जोर देने से निजी निवेश में आधिक्य, रोजगार सृजन और मांग में मजबूती और भारत की संभावित वृद्धि में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

हम पूर्ण अनिश्चितता के युग में रहते हैं - हम जो कुछ भी जानते हैं वह सभी अच्छी तरह से जानते हैं - विस्फोटक सूचना क्रांति इसे सुनिश्चित करती है। जैसा कि जॉन केनेथ गालब्रेथ ने लगभग तीन दशक पहले लिखा था, "दो प्रकार के पूर्वानुमानकर्ता हैं: एक वे जो नहीं जानते हैं, और दूसरे वे जो नहीं जानते हैं कि वे नहीं जानते हैं। [1] फिर भी, जब हर कोई एक ही दिशा में अनुमान लगाता है, तो यह आमतौर पर सच हो जाता है।

एक अच्छा उदाहरण जनवरी 2023 का अंतिम सप्ताह है, जिसके दौरान तथाकथित प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों[2] द्वारा मौद्रिक नीति के कदमों को कम नापने का पूरी तरह से हावी वित्तीय बाजारों द्वारा अनुमान लगाया गया था। दर वृद्धि के निचले क्रम के लिए एक पीरूएट निष्पादित करके, उन्होंने हमें वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण की एक झलक दी जैसा कि उनके नजरिए से देखा गया था। फरवरी के पहले सप्ताह में, दोनों उन्नत लेकिन ज्यादातर उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाली दस से अधिक केंद्रीय बैंकों की गति धीमी हुई या रुकी, इसके बाद दूसरे सप्ताह में पांच और केंद्रीय बैंकों ने इस विचार को मजबूती दी कि वर्ष 2023 शायद पहले के अनुमान की तुलना में हल्की वैश्विक मंदी से विशेष होगा।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 30 जनवरी को जारी अपने विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में भी भविष्य के बारे में कुछ अधिक आशावादी दृष्टिकोण की पुष्टि की, जैसा कि निम्नलिखित खंड में निर्धारित किया गया है। आईएमएफ के पूर्वानुमान की एक उल्लेखनीय विशेषता उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की ताकत है, जिसमें एशिया अग्रणी है। चीन और भारत 2023 में वैश्विक विकास का आधा हिस्सा उत्पन्न करेंगे।

आईएमएफ के अनुसार, वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 में 8.8 प्रतिशत से घटकर 2023 में 6.6 प्रतिशत हो सकती है, क्योंकि रि-ओपनिंग, कमोडिटी की कीमतों में कमी और आपूर्ति श्रृंखलाओं की बहाली से मांग बढ़ती है - लेकिन फिर भी 2024 में 4.3 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष ऊंची रह सकती है। जोखिम नीचे की ओर चला गया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड बीत चुका है[3], और केंद्रीय बैंक इसे जानते हैं। फिर भी, उनमें से कोई भी वित्तीय बाजारों द्वारा उनके खिलाफ दांव लगाने के बावजूद कम होने के मूड का खुलासा नहीं कर रहा है कि वे इस साल के अंत में न केवल रोकेंगे बल्कि दरों में कटौती भी करेंगे।

केंद्रीय बैंक जानते हैं कि मुद्रास्फीति नीचे आ रही है, लेकिन वे इस बात से सतर्क हैं कि वित्तीय कीमतों को बढ़ाने में बाजारों का तर्कहीन उत्साह वास्तव में मांग और मुद्रास्फीति के पुनरुत्थान को फिर से बढ़ावा दे सकता है। इसलिए, जीओएटी की महंगी नीति त्रुटि[4] को याद करते हुए, केंद्रीय बैंक सावधानी बरतने के पक्ष में

* इस आलेख को जी. वी. नथनएल, मधुरेश कुमार, कुणाल प्रियदर्शी, हर्षिता केशन, रमेश के गुप्ता, पंकज कुमार, हरेंद्र बेहेरा, अर्जित शिवहरे, राशिका अरोड़ा, अनूप के. सुरेश, लव के. शांडिल्य, रोहन बंसल, सुधांशु गोयल, प्रियंका सचदेवा, सत्यम कुमार, अक्षरा अवस्थी, युवराज कश्यप, अंशु कुमारी, आशीष एस खोब्रागडे, राजेश कावेडिया, सुप्रिया मजूमदार, विवेक कुमार, सौरभ कुमार, सौरभी सरदार ने तैयार किया है। निवेदिता बैनर्जी, बिचित्रानंद सेठ, सुजाता कुंडू, शेषाद्री बैनर्जी, इप्सिता पाढ़ी, सक्षम सूद, विनीत कुमार श्रीवास्तव, समीर रंजन बेहरा, देब प्रसाद रथ और माइकल देबब्रत पात्रा। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं।

[1] जॉन केनेथ गालब्रेथ, वॉल स्ट्रीट जर्नल, 22 जनवरी 1993।

[2] अमेरिकी फेडरल रिजर्व; यूरोपीय सेंट्रल बैंक; बैंक ऑफ इंग्लैंड।

[3] पियरे-ओलिवियर गौरिनचास, आईएमएफ, विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट कार्यवाही, 31 जनवरी, 2023। https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/01/31/tr-13123-world-economic-outlook-update।

[4] पॉल वोल्कर को अब तक का सबसे महान (जीओएटी) केंद्रीय बैंकर माना जाता है। हालांकि, कम ज्ञात, लेकिन उन्होंने 1980 में गंभीर नीतिगत गलती की थी। मंदी शुरू होने के बाद मई में बेरोजगारी दर एक प्रतिशत से अधिक बढ़कर 7 प्रतिशत से अधिक हो गई, फेड ने रिवर्स कोर्स करने और संघीय निधि दर को 7 प्रतिशत अंक से अधिक कम करने का फैसला किया। यह कार्रवाई इस तथ्य के बावजूद की गई कि मुद्रास्फीति अप्रैल में 14.7 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई थी। फेड ने हस्तक्षेप किया था और मुद्रास्फीति सेनानी के रूप में वोल्कर की विश्वसनीयता को झटका लगा था। मुद्रास्फीति की उम्मीदें उच्च बनी रहीं और वास्तविक मुद्रास्फीति 1980 के अंत तक 12 प्रतिशत से ऊपर रही। जुलाई 1980 में मंदी समाप्त होने के साथ, फेड मुद्रास्फीति से लड़ने वाले व्यवसाय में वापस आ गया और संघीय निधि दर को फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार, अपनी विश्वसनीयता को फिर से स्थापित करने के लिए, फेड को 1981 के मध्य तक संघीय निधि दर को लगभग 20 प्रतिशत के क्रशिंग स्तर तक बढ़ाना पड़ा। जुलाई 1981 में शुरू हुई आगामी मंदी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे गंभीर मंदी बन गई। (फ्रेडरिक मिश्किन, फाइनेंशियल टाइम्स, 14 सितंबर 2022)।

गलती करेंगे और कम के बजाय अधिक करेंगे। यदि सॉफ्ट लैंडिंग लगभग सुनिश्चित है, तो दरों में हमेशा कटौती की जा सकती है यदि विकास उम्मीद से अधिक धीमा हो जाता है, एक बार कम मुद्रास्फीति टिकाऊ आधार पर हासिल हो जाती है। जैसे-जैसे मुद्रास्फीति का दबाव कम होता है, वित्तीय स्थितियों में सुधार की संभावना होगी, और इससे विकास को सहायता मिलेगी।

दूसरी ओर, वित्तीय बाजार इस दांव से प्रेरित हैं कि मुद्रास्फीति का पतन एक पीढ़ी में एक बार आने वाली गिरावट होगी, जैसा कि मुद्रास्फीति के बाजार-आधारित गेज जैसे ब्रेक-ईवन दरों और स्वैप कर्व्स में पता चलता है। इक्विटी स्थिर हैं और बॉन्ड में तेजी आई है जबकि मुद्रास्फीति सकारात्मक जोखिम वाली आस्तियों में फैल गई है। अमेरिकी डॉलर बुनियाद खो चुका है और शेष विश्व में व्यापक आर्थिक स्थितियों में सुधार के साथ इसमें और गिरावट की संभावना है।

क्या आने वाला डेटा अपेक्षाओं अपूर्ण रखना जारी रख सकता है? 2022 तक मौद्रिक नीति को सख्त बनाने से सबसे भारी दबाव अभी तक पकड़ में नहीं आया है। मंदी के मुहाने पर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित बनी हुई है। 2023 अभी भी एक चुनौतीपूर्ण वर्ष होगा। केंद्रीय बैंकों के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि कहां रुकना और ठहरना है। यदि वास्तव में वैश्विक विकास धीमा हो जाता है लेकिन मुद्रास्फीति ऊंची बनी रहती है। उनकी सबसे बुरी आशंका सच हो सकती है।

लचीलेपन की आवश्यकता है, जिसमें आने वाले आंकड़ों की व्याख्या करना शामिल है, विशेष रूप से श्रम बाजार - अभी भी कमजोर श्रम भागीदारी, इस्तीफे, अंशकालिक काम की अधिक घटनाओं और हाल ही में बड़े पैमाने पर कामबंदी के लिए समायोजित, यह उतना गर्म नहीं हो सकता है जितना कि बेरोजगारी दर और आय के आंकड़ों से पता चलता है। जैसे-जैसे दृष्टिकोण अधिक स्थिर होता है, मुद्रास्फीति की संरचनात्मक विशेषताओं पर महामारी और भू-राजनीति के बार-बार के झटके के निशान का वास्तविक रूप से आकलन करना महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या स्वर्णिम अर्थ बिखर गया है, जिससे मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है? क्या विकसित अर्थव्यवस्थाओं को 4 प्रतिशत के मुद्रास्फीति लक्ष्यों को स्वीकार करना होगा, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं को और भी अधिक मुद्रास्फीति लक्ष्यों को अपनाना होगा।

व्यापार, वाणिज्य, वित्तीय और प्रौद्योगिकी प्रवाह के लिए अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में गंभीर जोखिम बढ़ रहे हैं। विश्व व्यापार संरक्षणवाद या फ्रेंड शोरिंग की ओर बलपूर्वक उठाए गए कदमों से खंडित हो सकता है, जिसमें प्रत्येक देश सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहनों के उपयोग के माध्यम से रणनीतिक सामग्री और उद्योगों के उत्पादन पर नियंत्रण चाहता है। समय के साथ, अन्य क्षेत्र रणनीतिक हो सकते हैं क्योंकि बलपूर्वक व्यापार, औद्योगिक और प्रौद्योगिकी नीतियां शुरू की जाती हैं।

आईएमएफ का अनुमान है कि सीमित विखंडन परिदृश्य में वैश्विक उत्पादन के 0.2 प्रतिशत के बीच इन विकासों की लागत एक गंभीर परिदृश्य में लगभग 7 प्रतिशत के बीच - लगभग जर्मनी और जापान के संयुक्त वार्षिक उत्पादन के बराबर है । यदि तकनीकी अलगाव को इस उलझन में जोड़ा जाता है, तो कुछ देशों को सकल घरेलू उत्पाद के 12 प्रतिशत तक का नुकसान हो सकता है। आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि माल और पूंजी का वैश्विक प्रवाह कम हो रहा है और प्रतिबंधों में वृद्धि दुनिया को बहुत छोटी जगह बना रही है। वित्तीय क्षेत्रीयकरण और खंडित वैश्विक भुगतान प्रणाली व्यापार प्रतिबंधों से होने वाले नुकसान को बढ़ा सकती है। कम अंतरराष्ट्रीय जोखिम-साझाकरण के साथ, समष्टि आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है, और अधिक गंभीर संकट न केवल राष्ट्रीय बफर पर अधिक दबाव डाल सकते हैं, बल्कि ऋणग्रस्तता सहित संकट में देशों का समर्थन करने के लिए वैश्विक समुदाय की क्षमता को भी कमजोर कर सकते हैं। [5]

जैसा कि केंद्रीय बैंक के भाषण से पता चलता है, समष्टि आर्थिक संभावनाओं को देखने की परंपरा को ध्यान में रखते हुए, भारत की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पिछली बैठक 8 फरवरी, 2023 को 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानों की सार्वजनिक विज्ञप्ति के साथ हुई थी। अपने फॉरवर्ड गाइडेंस[6] के डेल्फिक भाग में, एमपीसी ने कृषि और संबद्ध

[5] क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, विखंडन का सामना करना जहां यह सबसे ज्यादा मायने रखता है: व्यापार, ऋण और जलवायु कार्रवाई, आईएमएफ ब्लॉग। 16 जनवरी, 2023।

[6] ओडिसन फॉरवर्ड गाइडेंस के बीच एक अंतर तैयार किया गया है, जो सार्वजनिक रूप से और स्पष्ट रूप से केंद्रीय बैंक को भविष्य की कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध करता है, और डेल्फिक फॉरवर्ड गाइडेंस, जो उनमें निहित संभावित मौद्रिक नीति कार्यों के साथ समष्टि आर्थिक प्रदर्शन का पूर्वानुमान लगाता है (कैंपबेल)। जे.आर., चार्ल्स ई इवांस, जोनास डी एम फिशर और एलेजांद्रो जस्टिनियानो, फेडरल रिजर्व फॉरवर्ड गाइडेंस के समष्टि आर्थिक प्रभाव, आर्थिक गतिविधि पर ब्रुकिंग्स पेपर्स, स्प्रिंग 2012)।

गतिविधियों के लिए मजबूत संभावनाओं, संपर्क-गहन क्षेत्रों और विवेकाधीन खर्च में वापसी, व्यापार और उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करने, मजबूत ऋण वृद्धि, लचीला वित्तीय बाजार, और घरेलू उपभोग और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने वाले कारकों के रूप में पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे पर सरकार के निरंतर जोर की ओर इशारा किया। उनके दृष्टिकोण से, ये कारक वैश्विक मंदी के कारण निर्यात के लिए प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई करेंगे।

तदनुसार, 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था। मुद्रास्फीति के परिदृश्य के बारे में एमपीसी ने प्रतिकूल मौसम की घटनाओं, वैश्विक पण्य मूल्य परिदृश्य को लेकर अनिश्चितताओं और उत्पादन मूल्यों, विशेष रूप से सेवाओं में इनपुट लागत के निरंतर पास-थ्रु को पहचानते हुए फसल की संभावनाओं में सुधार का हवाला देते हुए 2023-24 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति को 5.3 प्रतिशत पर अनुमानित किया, जो 2022-23 में 6.5 प्रतिशत से कम है। एमपीसी की राय में, मुद्रास्फीति उस दृष्टिकोण के लिए एक बड़ा जोखिम बनी हुई है जिसमें घरेलू आर्थिक गतिविधि लचीली रहने की उम्मीद है। तदनुसार, इसने निर्णय लिया कि मुद्रास्फीति पर सतर्क रहना अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सहिष्णुता बैंड के भीतर रहे और उत्तरोत्तर लक्ष्य के साथ संरेखित हो। इसलिए मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को बनाए रखने, कोर मुद्रास्फीति की दृढ़ता को तोड़ने और उससे मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं को मजबूत करने के लिए और अधिक जांची-परखी मौद्रिक नीति कार्रवाई की आवश्यकता है।[7]

इस बैठक में एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का फैसला किया और समायोजन वापस लेने के रुख को बरकरार रखा। एमपीसी के फैसले को 2021-22 की दूसरी छमाही में महामारी से प्रेरित चलनिधि अंत:क्षेपण की समाप्ति, महामारी सुविधाओं को बंद करने, परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी के माध्यम से चलनिधि का मॉड्यूलेशन और नकदी आरक्षित अनुपात में वृद्धि के साथ शुरू हुई यात्रा के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिनमें से सभी ने सामान्य चलनिधि प्रबंधन संचालन और बाजार के समय की बहाली के लिए बुनियाद तैयार की।

शुरुआत में नीतिगत दरों में वृद्धि फ्रंट लोडेड थी, लेकिन घरेलू आर्थिक गतिविधियों को अस्थिर करने से बचने के लिए प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों के कार्यों की विशेषता वाली 75 आधार अंकों की बड़ी वृद्धि को टाल दिया गया था। मुद्रास्फीति जून 2022 में चरम पर थी और उसके बाद इसमें कमी आई। दिसंबर 2022 से, दर वृद्धि के निचले स्तरों को ठीक करने के लिए स्थितियां अनुकूल हो गई और फरवरी 2023 तक, मुद्रास्फीति से पहले चार तिमाहियों के लिए समायोजित होने पर नीतिगत दर ने सकारात्मक स्थान हासिल कर लिया। महत्वपूर्ण रूप से, कोई बैकस्लाइड या रिवर्सल नहीं हुआ है और दर परिवर्तन का आकार फॉरवर्ड गाइडन्स का सबसे अच्छा रूप रहा है।

एमपीसी मुद्रास्फीति को लक्ष्य तक लाने के अपने संकल्प को व्यक्त करने में दक्ष रही है। गवर्नर श्री शक्तिकांत दास के 8 फरवरी, 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के हवाले से, "हमें मुद्रास्फीति में निर्णायक कमी देखने की आवश्यकता है। हमें मुद्रास्फीति को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अटल रहना होगा। इस प्रकार, मौद्रिक नीति को एक स्थिर अवस्फीति प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए....। दर वृद्धि के आकार में कमी मुद्रास्फीति दृष्टिकोण और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था पर अब तक किए गए कार्यों के प्रभावों का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करती है। यह आगे बढ़ने के लिए उचित कार्यों और नीतिगत रुख को निर्धारित करने के लिए सभी आने वाले डेटा और पूर्वानुमानों को तौलने के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करती है। मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था के समक्ष आनेवाली चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मुद्रास्फीति के पथ में गतिशील हिस्सों के प्रति चुस्त और सतर्क बनी रहेगी।"

मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों का प्रभाव प्रसारण के चैनलों में परिलक्षित हो रहा है, लेकिन आगे की राह चुनौतीपूर्ण है। आने वाले वर्ष में, मुद्रास्फीति की वापसी जिद्दी होने और आपूर्ति के झटके से घिरे होने की उम्मीद है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लगभग हर दूसरे घटक - सांख्यिकीय और अपवाद-आधारित उपाय - मूल्य दबाव में वृद्धि दिखा रहे हैं। परिवारों की मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं फ्लैट- लाईंड हैं और विनिर्माण निगमों को बिक्री और

[7] मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6-8 फरवरी, 2023।

राजस्व की वृद्धि में कमी का सामना करना पड़ रहा है। लाभ पर दबाव बढ़ने के साथ, पूंजीगत व्यय नियंत्रित रहता है। इसलिए, मौद्रिक नीति के रुख को स्थायी आधार पर उपभोक्ता खर्च और व्यावसायिक निवेश के लिए अवस्फीतिकारी बने रहने की आवश्यकता होगी और विकास में तेजी के लिए एक ठोस आधार प्रदान करना होगा।

भारत की उत्पादक क्षमता के विस्तार के लिए मध्यम अवधि की नीतियां घरेलू विनिर्माण और व्यापार नीतियों पर जोर दे रही हैं जो घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करती हैं और मूल्य श्रृंखलाओं या जिसे 'उत्पादवाद'[8] कहां जाता है, को पुनर्जीवित करती हैं। गतिविधि का पुनरुद्धार पहले से ही भीतरी इलाकों में रात की रोशनी में स्पष्ट है। भारत के जी-20 की अध्यक्षता में डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के बुनियादी ढांचे के केंद्र में आने के साथ, देश डिजिटल नवाचारों में नेतृत्व करने और भारत के तकनीकी कार्यों को साकार करने के लिए तैयार है। ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम, इलेक्ट्रिक वाहनों और सेमी-कंडक्टर उत्पादन की योजनाओं, और बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा के साथ संप्रभु ग्रीन बॉन्ड की पहली पेशकश के मुद्दे के साथ अर्थव्यवस्था को हरा-भरा करने की प्रक्रिया गति पकड़ रही है। अधिक आत्मविश्वास से भरा भारत 2047 के दृष्टिकोण के साथ उच्च लक्ष्य लेकर चल रहा है। समापन खंड में, हम इस बात को रेखांकित करते हैं कि केंद्रीय बजट 2023-24 इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक निश्चित कदम उठाता है।

इस पृष्ठभूमि पर निर्धारित, लेख के शेष भाग को चार खंडों में संरचित किया गया है। खंड II वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे विकास को रेखांकित करता है। घरेलू अर्थव्यवस्था का विकास खंड III में रखा गया है। खंड IV घरेलू वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करता है, जबकि अंतिम खंड समापन टिप्पणी निर्धारित करता है।

II. वैश्विक सेटिंग

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए परिदृश्य कम निराशाजनक हो गया क्योंकि मुद्रास्फीति में नरमी ने आगे आक्रामक मौद्रिक सख्ती की आशंकाओं को कम कर दिया। महामारी प्रतिबंधों से दुनिया के कुछ हिस्सों के फिर से खुल जाने से, पहले के अनुमान की तुलना में मामूली मंदी की संभावनाओं में सुधार हुआ है। हालांकि, काफी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि आने वाले डेटा को पार्स किया जाता है।

विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) के जनवरी 2023 के अपडेट में आईएमएफ ने अक्टूबर के अपने अनुमानों की तुलना में 2023 के लिए वैश्विक वृद्धि दर को 20 आधार अंक (बीपीएस) बढ़ाकर 2.9 प्रतिशत कर दिया। इस संशोधन में नियंत्रित की गई मांग से मजबूत वृद्धि, मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट और वित्तीय स्थितियों में नरमी जैसे सकारात्मक अप्रत्याशित बातों को ध्यान में रखा गया है। विशेष रूप से, एक वैश्विक मंदी अब आधारभूत मूल्यांकन नहीं है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के लिए, 2023 के लिए विकास को 10 आधार अंकों से बढ़ाकर 1.2 प्रतिशत कर दिया गया था, जबकि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के

सारणी 1: जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान – चुनिंदा एई और ईएमई

(प्रतिशत)

अवधि के लिए पूर्वानुमान	2023		2024	
पूर्वानुमान के माह	जनवरी 2023	अक्टूबर 2022	जनवरी 2023	अक्टूबर 2022
विश्व	2.9	2.7	3.1	3.2
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं				
यूएस	1.4	1.0	1.0	1.2
यूके	-0.6	0.3	0.9	0.6
यूरो क्षेत्र	0.7	0.5	1.6	1.8
जापान	1.8	1.6	0.9	1.3
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं				
ब्राजील	1.2	1.0	1.5	1.9
रूस	0.3	-2.3	2.1	1.5
भारत	6.1	6.1	6.8	6.8
चीन	5.2	4.4	4.5	4.5
दक्षिण अफ्रीका	1.2	1.1	1.3	1.3

स्रोत: आईएमएफ।

[8] दानी रॉड्रिक, 5 जुलाई, 2022, प्रोजेक्ट सिंडिकेट।

चार्ट 1: वैश्विक जीडीपी तात्कालिक अनुमान (नाउकास्ट)

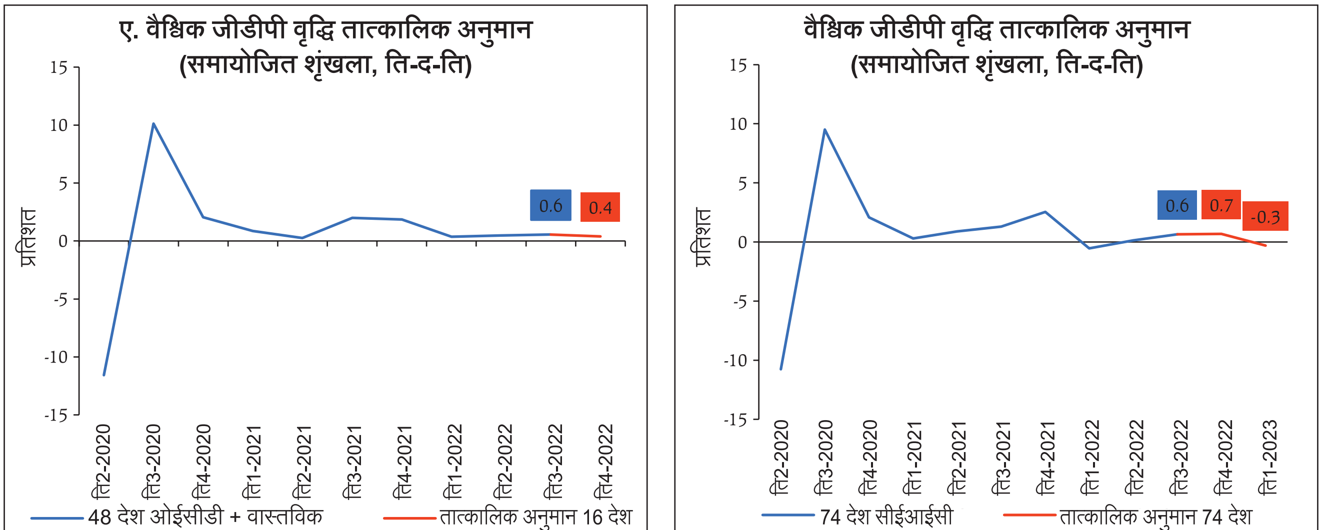

स्रोत: ओईसीडी; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

स्रोत: सीईआईसी; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

लिए, यह 2023 में 4.0 प्रतिशत पर 30 आधार अंक अधिक होने का अनुमान है (डब्ल्यूईओ अक्टूबर 2022 के अनुमानों की तुलना में) [सारणी1]।

इस पृष्ठभूमि में, हमारे मॉडल आधारित नाउकास्ट, जिसमें 74 देशों के डेटा शामिल हैं, ने 2023 की पहली तिमाही में वैश्विक विकास की गति में -0.3 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है (चार्ट: 1ए और 1बी)।

उच्च आवृत्ति संकेतकों में, जनवरी 2023 में 49.8 पर वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) ने तेजी दर्ज की, लेकिन लगातार छठे महीने संकुचन क्षेत्र में रहा (चार्ट 2)। वैश्विक विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक जनवरी में 49.1 पर लगातार पांचवें महीने तटस्थ चिह्न से नीचे रहा, हालांकि संकुचन ने उत्पादन और नए स्तर दोनों में कमी के संकेत दिखाए, रोजगार में मामूली वृद्धि दर्ज की। सेवा पीएमआई छह महीने बाद विस्तारवादी मोड में लौट आया।

नवंबर 2022 में विश्व व्यापार की मात्रा में तीव्र नकारात्मक गति और प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण 1.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई (चार्ट 3 ए)। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स - शुष्क थोक वस्तुओं के लिए शिपिंग शुल्क का एक नाप - जनवरी 2023 में अपने मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक गिर गया क्योंकि सभी पोत खंडों में कमजोर मांग के साथ कैपसाइज मांग कम रही (चार्ट 3 बी)। आईएमएफ का अनुमान है कि वस्तुओं और सेवाओं में वैश्विक व्यापार 2022 में 5.4 प्रतिशत से घटकर 2023 में 2.4 प्रतिशत रह जाएगा।

चार्ट 2: वैश्विक पीएमआई

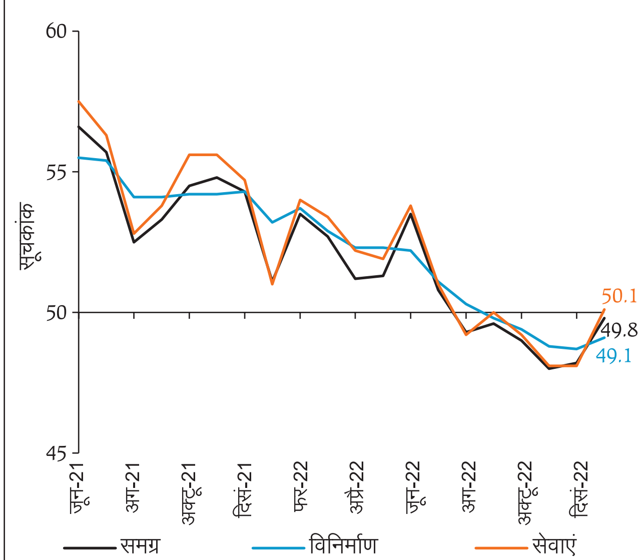

स्रोत: आईएचएस मार्किट।

चार्ट 3: विश्व व्यापार और नौ-परिवहन लागत

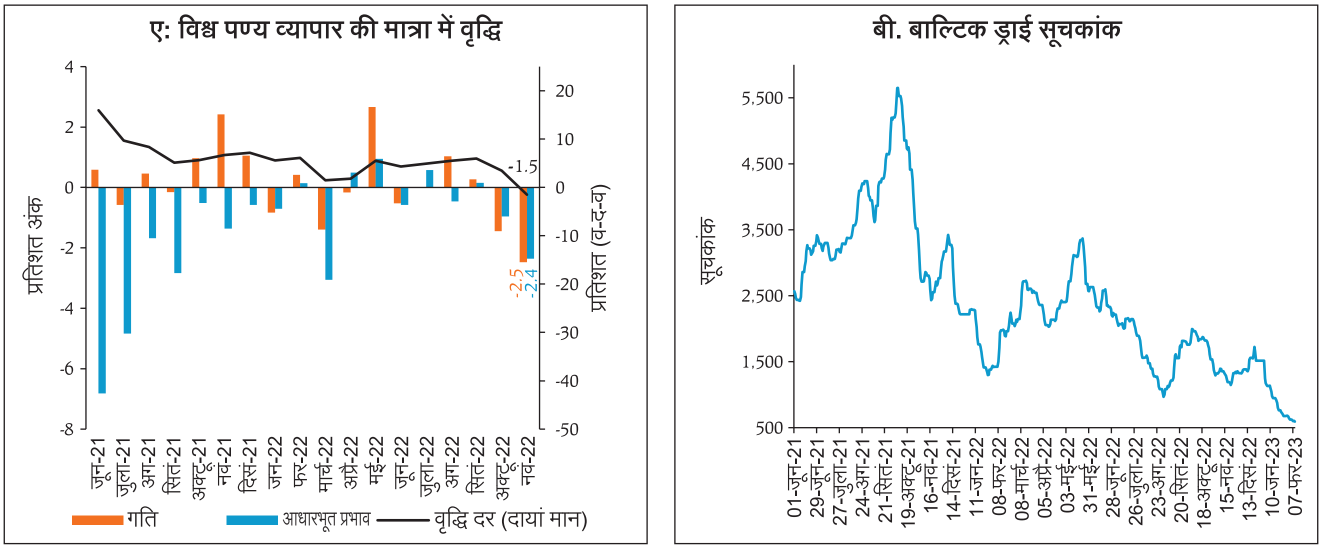

स्रोत: सीपीबी नीदरलैंड; और ब्लूमबर्ग।

अभी भी कमजोर वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण ने मांग पर दबाव जारी रखा है जिसके कारण (चार्ट 4 ए) वैश्विक पण्य कीमतों ने अस्थिरता का प्रदर्शन जारी रखा है (चार्ट 4 ए)। तुर्की में भूकंप के बाद उभरती भू-राजनीतिक चिंताएं, आपूर्ति की कमी और एक

चार्ट 4: पण्य और खाद्य कीमतें

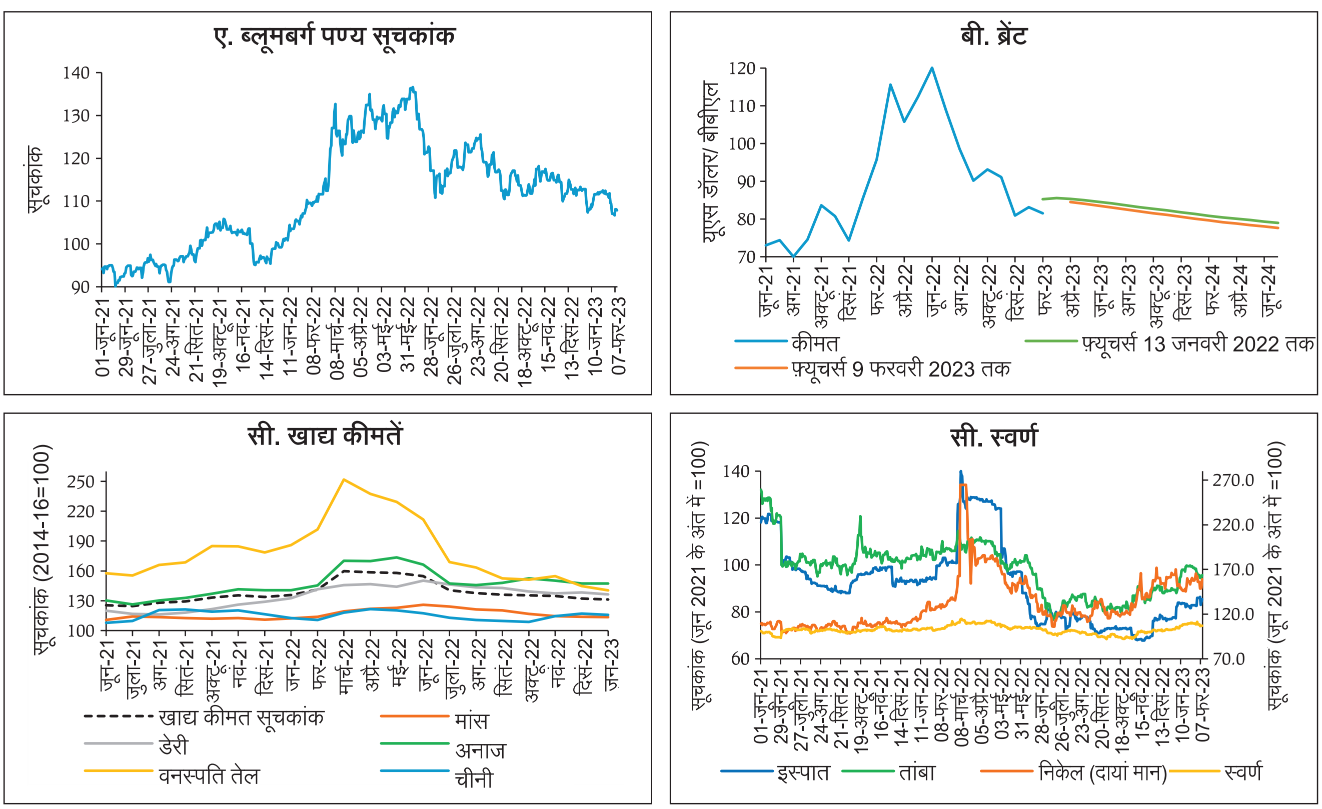

स्रोत: ब्लूमबर्ग; विश्व बैंक पिंक शीट; और एफएओ।

प्रमुख निर्यात टर्मिनल के बंद होने के आसपास घुमती अनिश्चितता के बाद जनवरी और फरवरी (15 फरवरी, 2023 तक) में कच्चे तेल की कीमतों ने औसतन 83 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार किया (चार्ट 4 बी)। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) खाद्य मूल्य सूचकांक[9] में जनवरी में लगातार दसवें महीने गिरावट आई, जो वनस्पति तेलों, डेयरी और चीनी से प्रेरित थी, जबकि अनाज और मांस की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं (चार्ट 4 सी)।

महामारी के प्रतिबंधों में ढील और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में उच्च वृद्धि के कारण दुबारा खुली योजनाओं और उच्चतर मांग की अपेक्षाओं पर धातु की कीमतों में वृद्धि हुई। सुरक्षित निवेश मांग के कारण जनवरी में सोने की कीमतों में तेजी आई (चार्ट 4 डी)। सभी प्रमुख हितधारकों से सोने की मांग बढ़ रही है, 1967 के बाद से केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीद 2022 की चौथी तिमाही में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है (चार्ट 5ए और 5बी) ।

अधिकांश एई और ईएमई में हेडलाइन मुद्रास्फीति कम हो गई। हालांकि वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति 2022 की तीसरी तिमाही में चरम पर है, आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में मुख्य मुद्रास्फीति महामारी से पहले के स्तर से ऊपर बनी हुई है। अमेरिका में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जनवरी 2023 में मामूली घटकर 6.4 प्रतिशत रही जो एक महीने पहले 6.5 प्रतिशत थी। व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में स्पष्ट रूप से घटकर 5.0 प्रतिशत हो गई (चार्ट 6 ए)। जनवरी में यूरो क्षेत्र और ब्रिटेन में मुद्रास्फीति घटकर क्रमश: 8.5 प्रतिशत और 10.1 प्रतिशत पर आ गई। जापान में सीपीआई (ताजा खाद्य पदार्थ से इतर सभी वस्तुएं) मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में 4.0 प्रतिशत के साथ 41 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। ईएमई में, दिसंबर 2022 में ब्राजील (5.8 प्रतिशत), रूस (11.9 प्रतिशत), और दक्षिण अफ्रीका (7.2 प्रतिशत) में मुद्रास्फीति में और कमी आई (चार्ट 6 बी)। हालांकि, चीन ने दिसंबर में सीपीआई मुद्रास्फीति में 20 आधार अंकों की वृद्धि दर्ज की और यह 1.8 प्रतिशत हो गई।

वैश्विक इक्विटी बाजारों ने 2023 की शुरुआत नए आशावाद के साथ की क्योंकि आने वाले आंकड़ों ने मुद्रास्फीति में कमी और कम आक्रामक दर वृद्धि की उम्मीदों का सुझाव दिया, जिसमें ईएमई एई की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे (चार्ट 7 ए)। हालांकि, फरवरी की शुरुआत में बाजार में गिरावट आई, विशेष रूप से ईएमई में, क्योंकि निवेशकों ने जोखिम से परहेज किया, विशेष रूप से, अमेरिका में मजबूत गैर-कृषि पेरोल और कम बेरोजगारी दर के आंकड़ों के जारी होने के बाद, जो एई में उच्च ब्याज दरों की अपेक्षाओं को दर्शाता है।

चार्ट 5: सोने की बढ़ती मांग

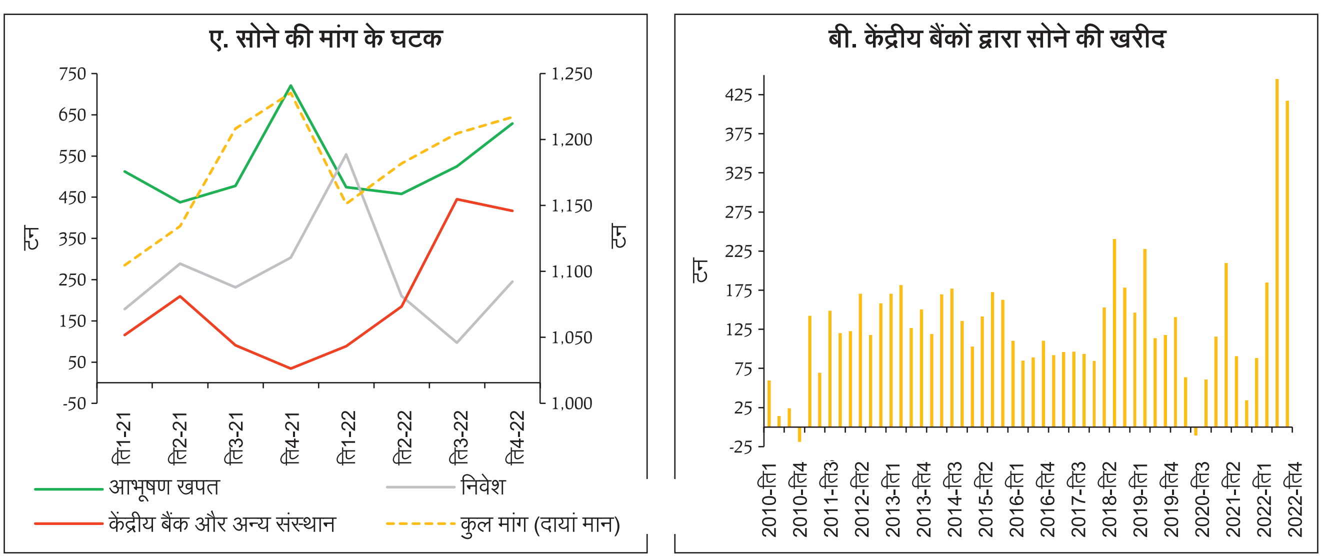

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

[9] उप-सूचकांकों में अनाज, वनस्पति तेल, डेयरी, मांस और चीनी मूल्य सूचकांक शामिल हैं।

चार्ट 6: मुद्रास्फीति

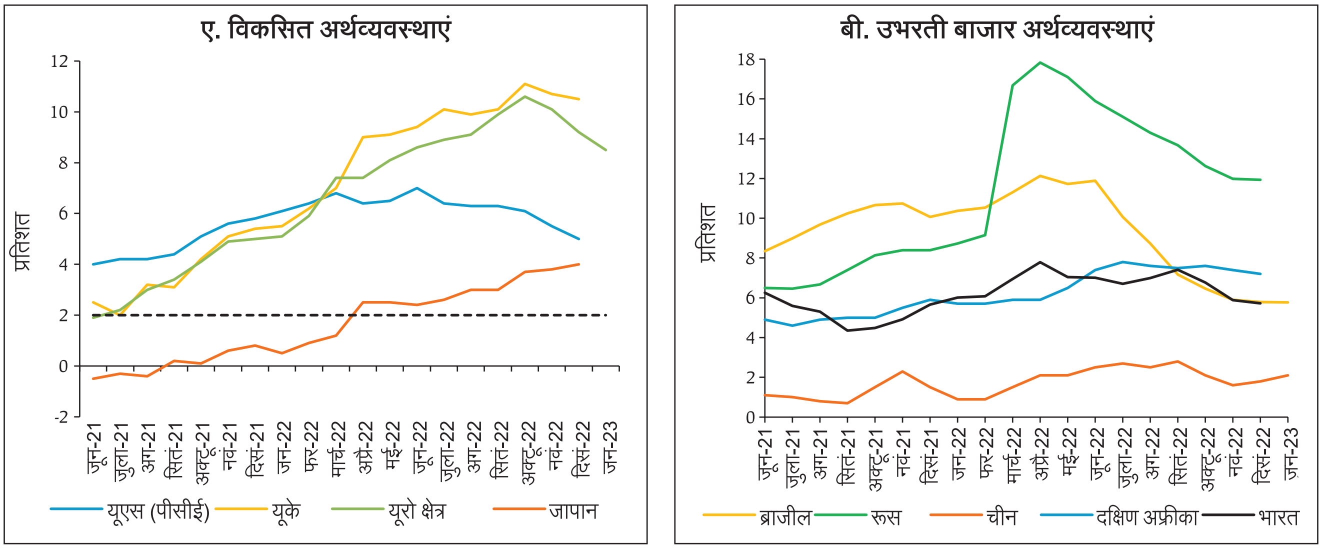

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और ओईसीडी।

जनवरी 2023 के दौरान, अमेरिका सहित अधिकांश देशों में उम्मीद से कम मुद्रास्फीति के कारण प्रमुख एई में 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल कम हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में 37 आधार अंकों की गिरावट आई और

चार्ट 7: वित्तीय बाजार

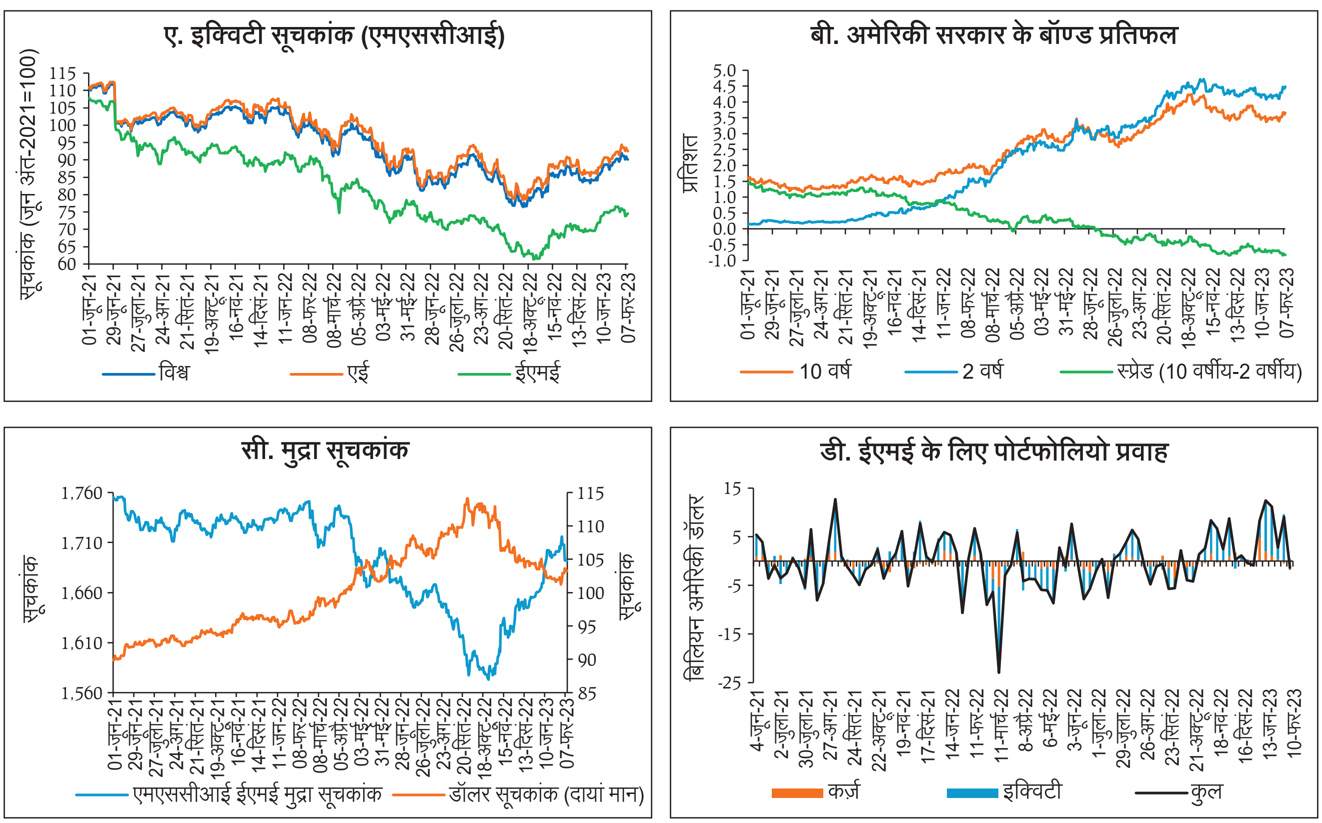

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आईआईएफ।

चार्ट 8: प्रमुख नीतिगत दर में उतार-चढ़ाव

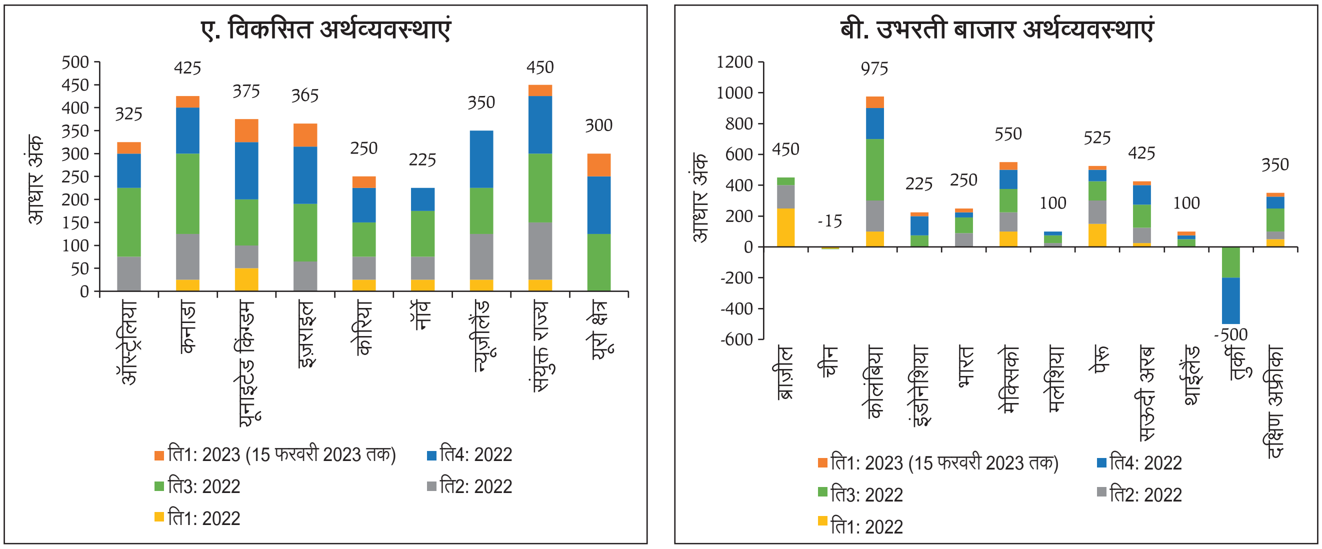

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

2-वर्षीय जी-सेक यील्ड में 22 बीपीएस की कमी आई। इससे उपज वक्र व्युत्क्रमण का परिमाण बढ़ गया (चार्ट 7बी)। हालांकि, फरवरी में अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल अनुमान से अधिक अमेरिकी गैर-कृषि पेरोल आंकड़ों के कारण मजबूत हुआ और 2 साल के जी-सेक प्रतिफल में 20 आधार अंकों (08 फरवरी, 2023 तक) की वृद्धि हुई। अमेरिकी डॉलर ने सितंबर 2022 में चरम पर पहुंचने के बाद अपनी तेजी को उलट दिया और जनवरी में कम आक्रामक नीतिगत दरों में वृद्धि की उम्मीद में 1.4 प्रतिशत गिर गया। इसके साथ-साथ, ईएमई के लिए एमएससीआई मुद्रा सूचकांक ने गति प्राप्त की, पूंजी प्रवाह (चार्ट 7 सी और 7 डी) के कारण 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अधिकांश एई और ईएमई के केंद्रीय बैंकों ने हाल के महीनों में सख्ती की गति को धीमा कर दिया (चार्ट 8 ए)। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने फेडरल फंड्स रेट की लक्ष्य सीमा 25 आधार अंक बढ़ाकर 4.50-4.75 प्रतिशत कर दी है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) और बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) ने फरवरी 2023 में अपनी प्रमुख दरों में 50 बीपीएस की वृद्धि करने का फैसला किया। कनाडा ने जनवरी में अपनी नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि की और ऑस्ट्रेलिया ने फरवरी की बैठक में अपनी दर में 25 बीपीएस की वृद्धि जारी रखी। जापान ने उदार रुख बनाए रखते हुए अलग रहना जारी रखा है; हालांकि, इसने 10 साल के सरकारी बॉन्ड प्रतिफल में उतार-चढ़ाव के लिए अपनी सीमा का विस्तार किया।

अधिकांश ईएमई केंद्रीय बैंकों ने भी नीतिगत सख्ती जारी रखी है, जबकि कुछ अन्य रुक गए हैं (चार्ट 8 बी)। दिसंबर में, दक्षिण अफ्रीका ने अपनी नीतिगत दर में वृद्धि की गति को 75 बीपीएस से 25 बीपीएस तक कम कर दिया और सऊदी अरब ने अपनी जनवरी की बैठक में 50 बीपीएस से 25 बीपीएस तक धीमा कर दिया। इंडोनेशिया और थाईलैंड ने जनवरी में अपनी नीतिगत दरों में 25-25 आधार अंकों की वृद्धि की थी। ब्राजील ने फरवरी में और मलेशिया, चिली और हंगरी ने जनवरी में अपनी प्रमुख दरों को अपरिवर्तित रखा। इसके विपरीत, चीन ने मौद्रिक समायोजन जारी रखा।

III. घरेलू घटनाक्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था में आपूर्ति प्रतिक्रियाओं और समग्र लागत की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। आपूर्ति श्रृंखला दबाव कम होता रहा जैसा कि भारत के लिए आपूर्ति श्रृंखला दबाव के हमारे सूचकांक द्वारा इंगित किया गया है (आईएसपीआई) [चार्ट 9] ।

चार्ट 9: भारत के लिए आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक

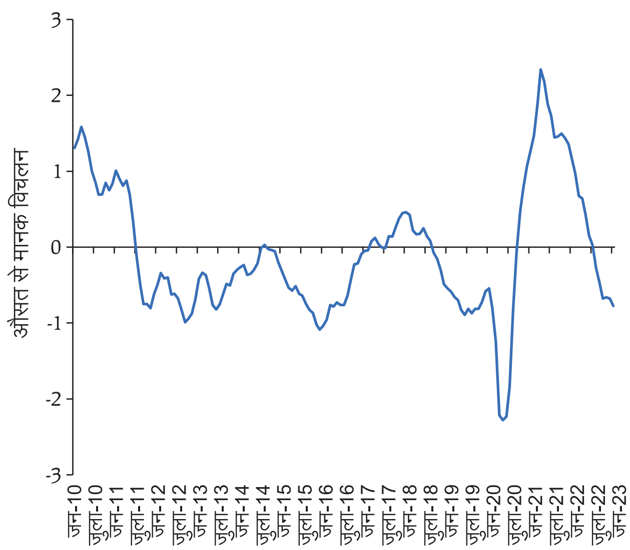

स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) ने नवंबर और दिसंबर 2022 में गतिविधि में तेजी दिखाई (चार्ट 10 ए)। तदनुसार, 2022-23 की तीसरी तिमाही के लिए हमारे सकल घरेलू उत्पाद का अब का अनुमान 4.4 प्रतिशत पर रखा गया है (चार्ट 10 बी)।

कुल मांग

प्रमुख संकेतक आर्थिक गतिविधियों में निरंतर गति की ओर इशारा करते हैं। हालांकि ई-वे बिल की मात्रा और टोल संग्रह में मध्यम गति से वृद्धि जारी रही। (चार्ट 11)।

मौसमी कारकों के कारण ईंधन की खपत दिसंबर में दर्ज नौ महीने के उच्च स्तर से नीचे आ गई। उच्च मांग के कारण ऑटोमोबाइल (यात्री और वाणिज्यिक वाहनों), दोपहिया वाहनों की बिक्री और वाहन पंजीकरण (परिवहन और गैर-परिवहन वाहन) में तेजी आई। फसल की बेहतर कीमतों ने ट्रैक्टर की बिक्री में तेजी लाने में मदद की है। मोटरसाइकिल और तिपहिया वाहनों की बिक्री में भी तेजी आई, जो बाद में जनवरी 2022 की तुलना में दोगुनी से अधिक हो गई (चार्ट 12)।

पर्यटन क्षेत्र में, कमरे की औसत दरों में वृद्धि जारी रही, भले ही होटल रिहाइश दरें सपाट रहीं। नवंबर में गिरावट दर्ज करने के

चार्ट 10: आर्थिक गतिविधि और जीडीपी तात्कालिक अनुमान

ए: आर्थिक गतिविधि सूचकांक

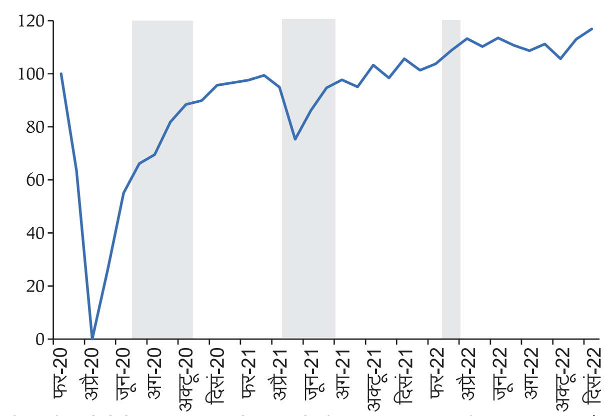

टिप्पणी: गतिविधि सूचकांक का निर्माण गतिशील कारक मॉडल (डीएफएम) का उपयोग करके आर्थिक गतिविधि के चयनित उच्च आवृत्ति संकेतकों के एक समूह के अंतर्गत सामान्य प्रवृत्ति की पहचान कर किया गया है। ईएआई के लिए मान फरवरी 2020 के लिए 100 और अप्रैल 2020 के लिए 0 तक पहुंचा है। छायांकित क्षेत्र उन अवधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब दैनिक नए पुष्ट मामले 50,000 से अधिक हो गए।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

बी: जीडीपी- वास्तविक और तात्कालिक अनुमान

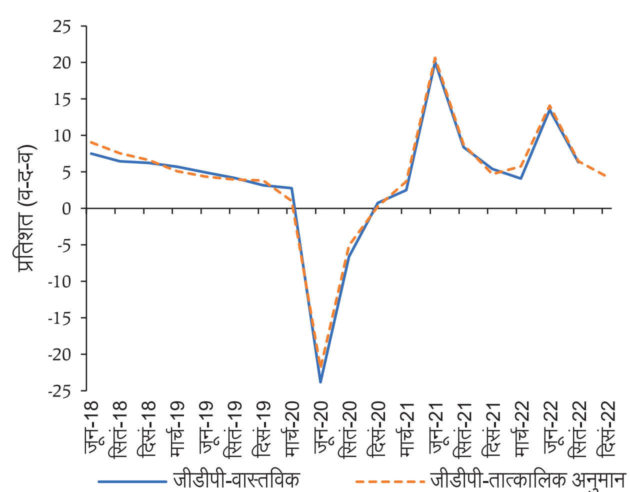

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट 11: ई-वे बिल और टोल संग्रह

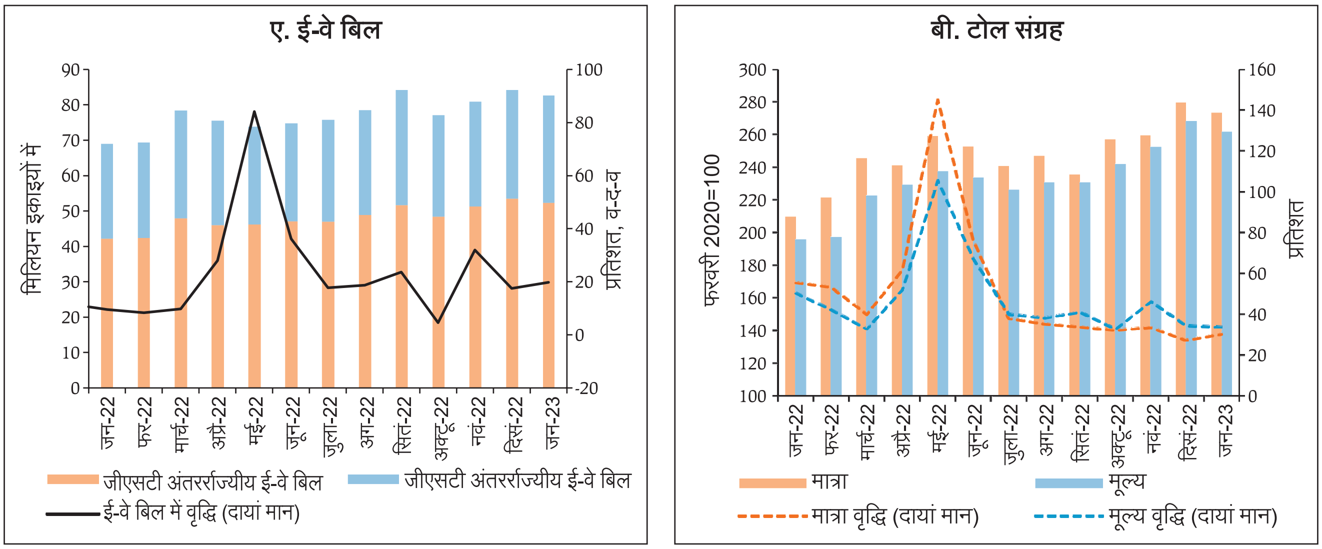

स्रोत: जीएसटीएन; आरबीआई; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

बाद, प्रति उपलब्ध कमरे (आरईवीपीएआर) राजस्व में वृद्धि हुई (चार्ट 13)।

रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) में रिपोर्ट की गई आर्थिक स्थितियों के लिए परिवारों का आकलन और

चार्ट 12: ऑटोमोबाइल क्षेत्र के संकेतक

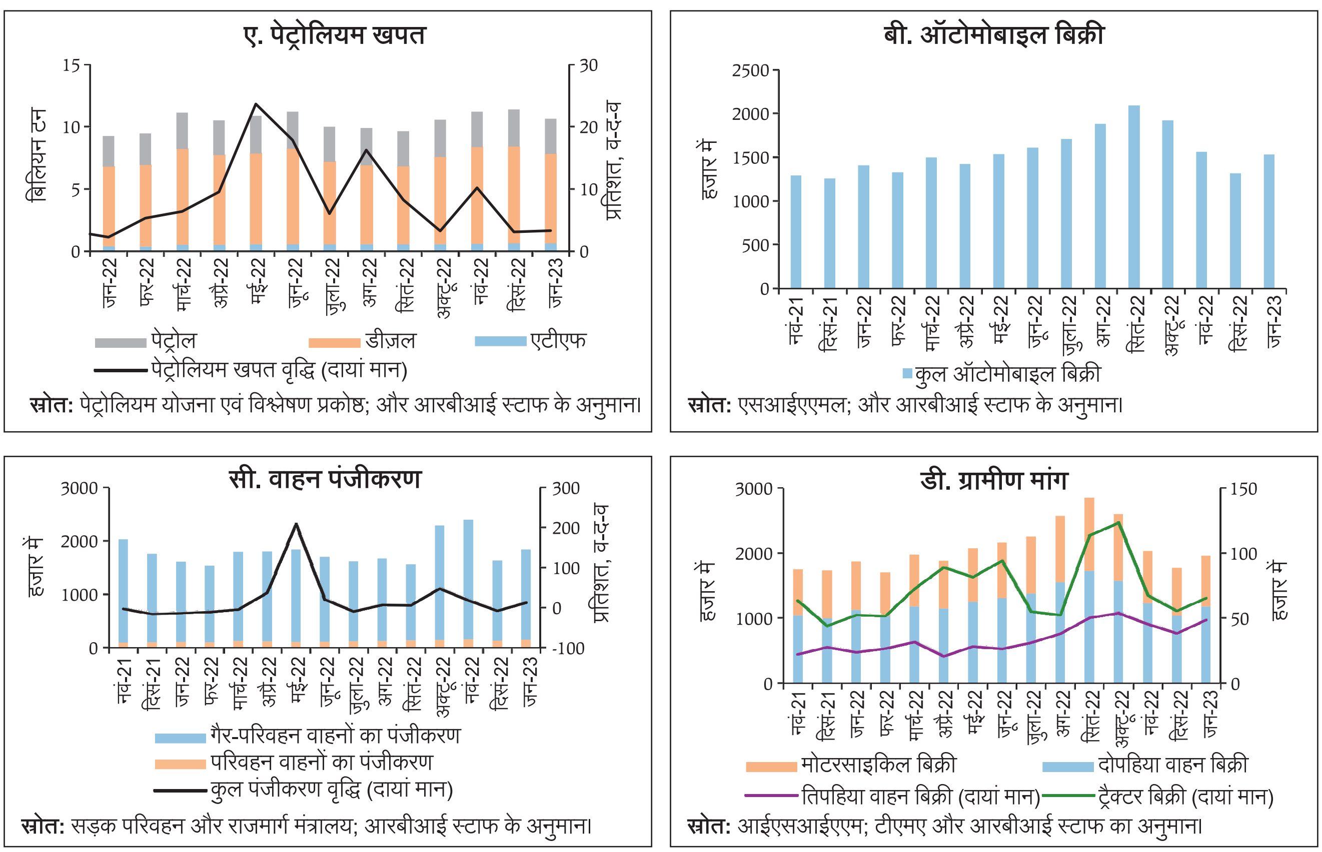

चार्ट 13: होटल क्षेत्र के संकेतक

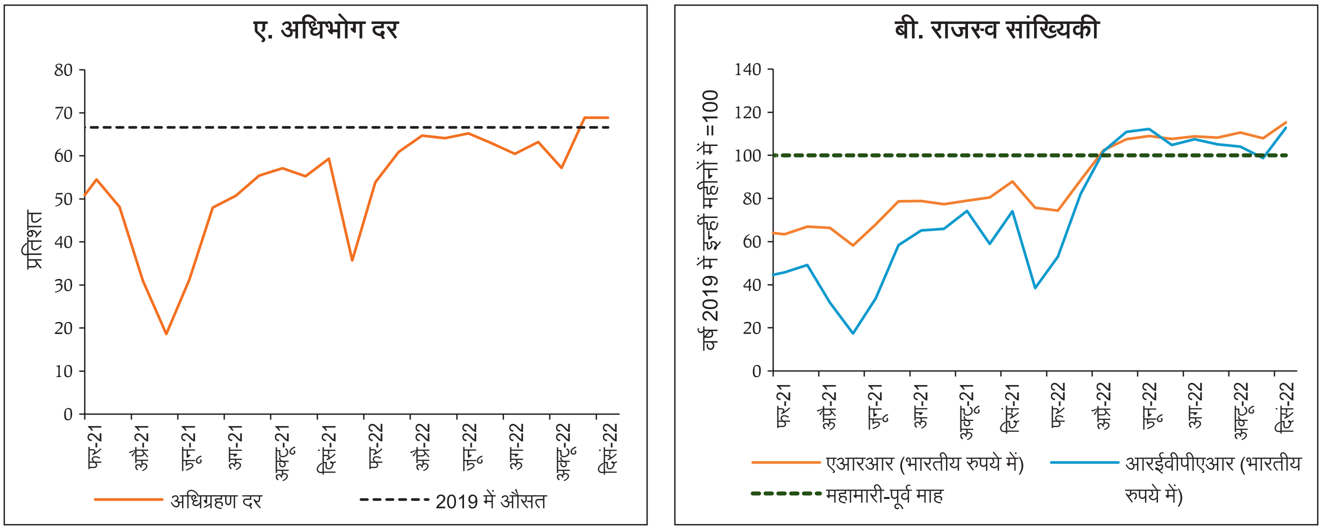

टिप्पणी: एआरआर; कमरे की औसत दर।
स्रोत: एचवीएस एनारॉक; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

दृष्टिकोण वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई) के साथ-साथ एक साल की अवधि में भविष्य की अपेक्षा सूचकांक (एफईआई) में परिलक्षित बढ़ते विश्वास की ओर इशारा करता है (चार्ट 14)।

शहरी बेरोजगारी में अपेक्षाकृत बड़ी गिरावट के कारण, अखिल भारतीय बेरोजगारी दर दिसंबर 2022 में 8.3 प्रतिशत से घटकर जनवरी 2023 में 7.1 प्रतिशत हो गई (चार्ट 15 ए)। हालांकि, श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) जनवरी में पिछले महीने के 40.5 प्रतिशत से घटकर 39.8 प्रतिशत हो गई, जिसमें रोजगार दर (ईआर) काफी हद तक सपाट रही (चार्ट 15 बी)।

चार्ट 14: उपभोक्ता विश्वास सूचकांक

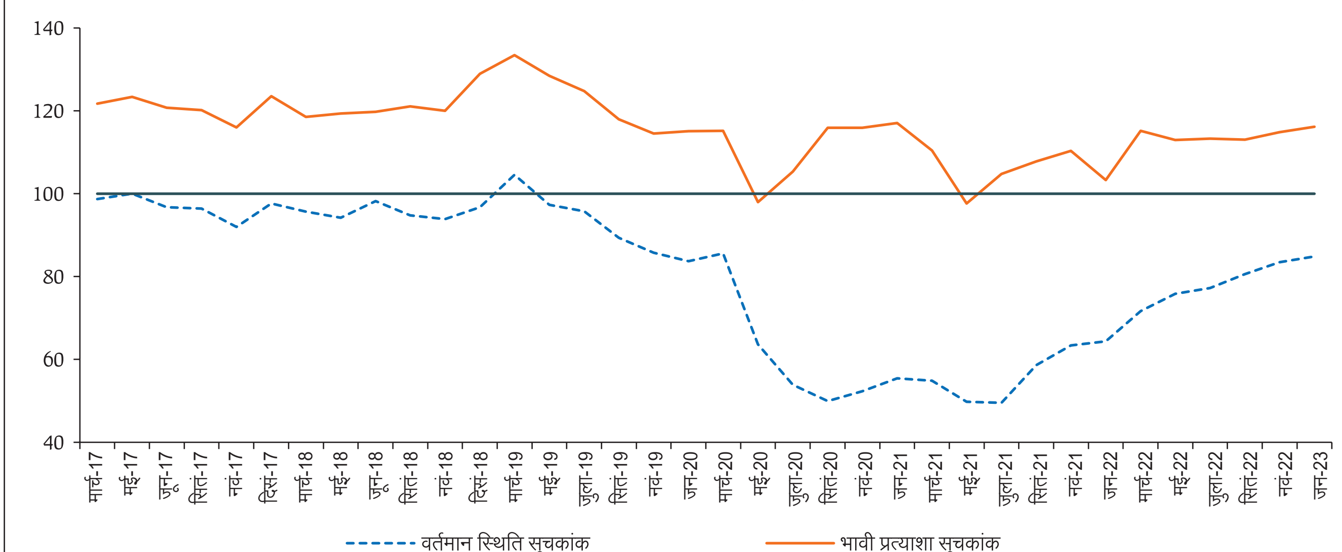

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट 15: श्रम बाजार स्थितियां

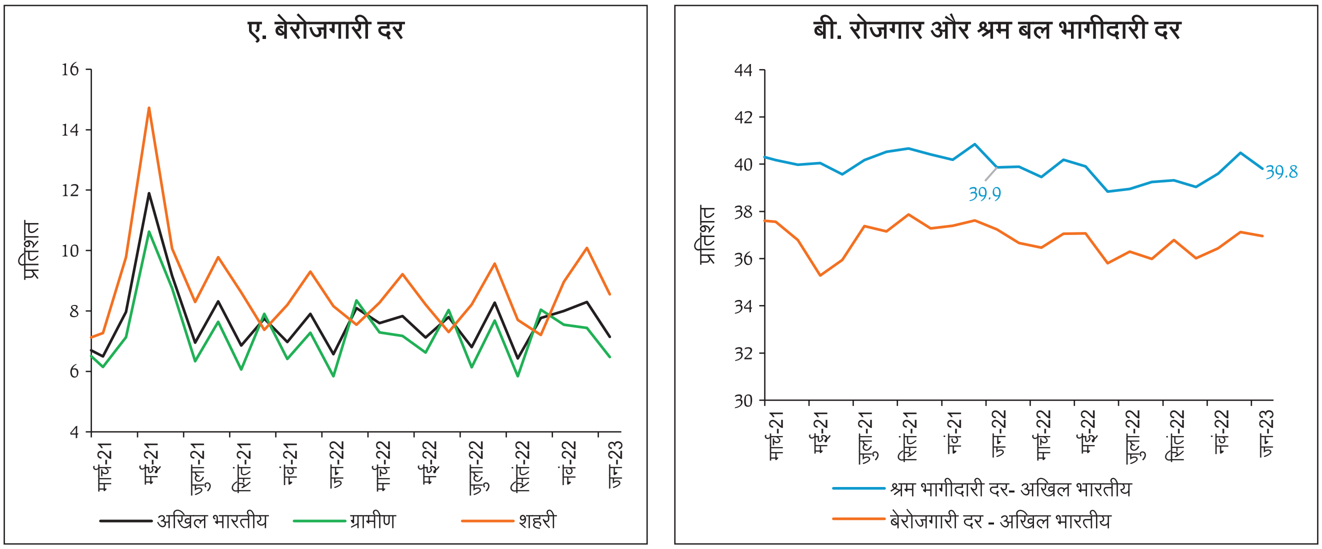

स्रोत: सीएमआईई।

पीएमआई रोजगार सूचकांक जनवरी 2023 में मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहा (चार्ट 16)।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत कार्य की मांग में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर गिरावट आई है, जो अन्य गतिविधियों विशेष रूप से रबी बुवाई में श्रम मांग में वृद्धि को दर्शाती है (चार्ट 17)।

जनवरी 2023 में भारत का व्यापारिक निर्यात 32.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें सालाना आधार पर 6.6 प्रतिशत और

चार्ट 16: पीएमआई रोज़गार सूचकांक

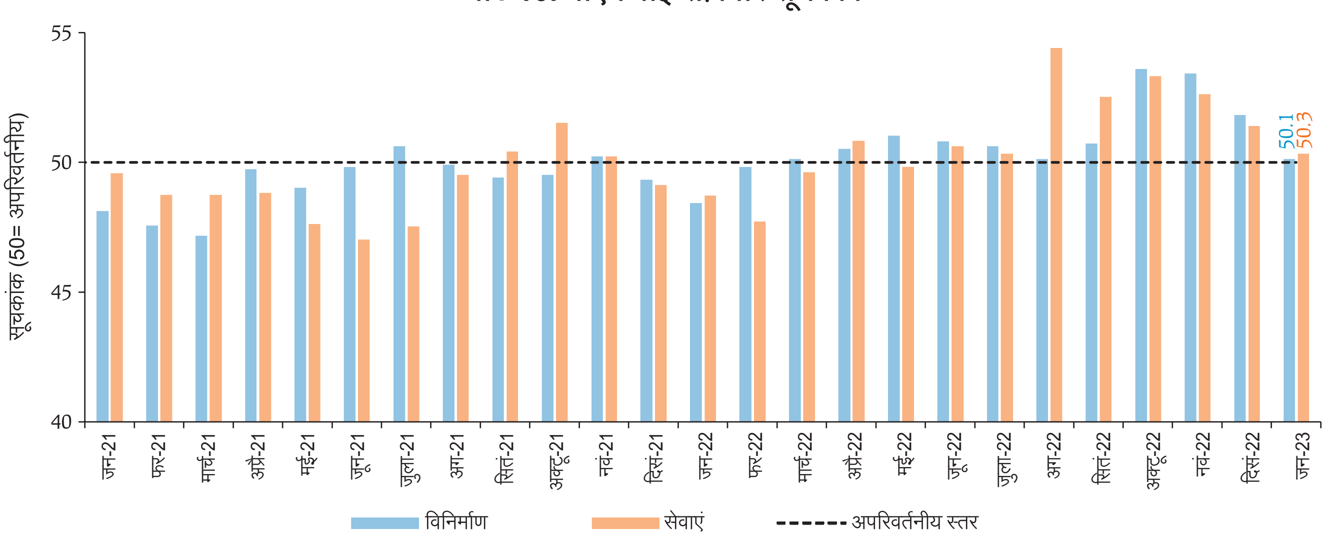

टिप्पणी: क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) का 50 से अधिक का मान, विस्तार दर्शाता है।

स्रोत: एसएंडपी ग्लोबल।

चार्ट 17: मनरेगा के अंतर्गत काम की मांग

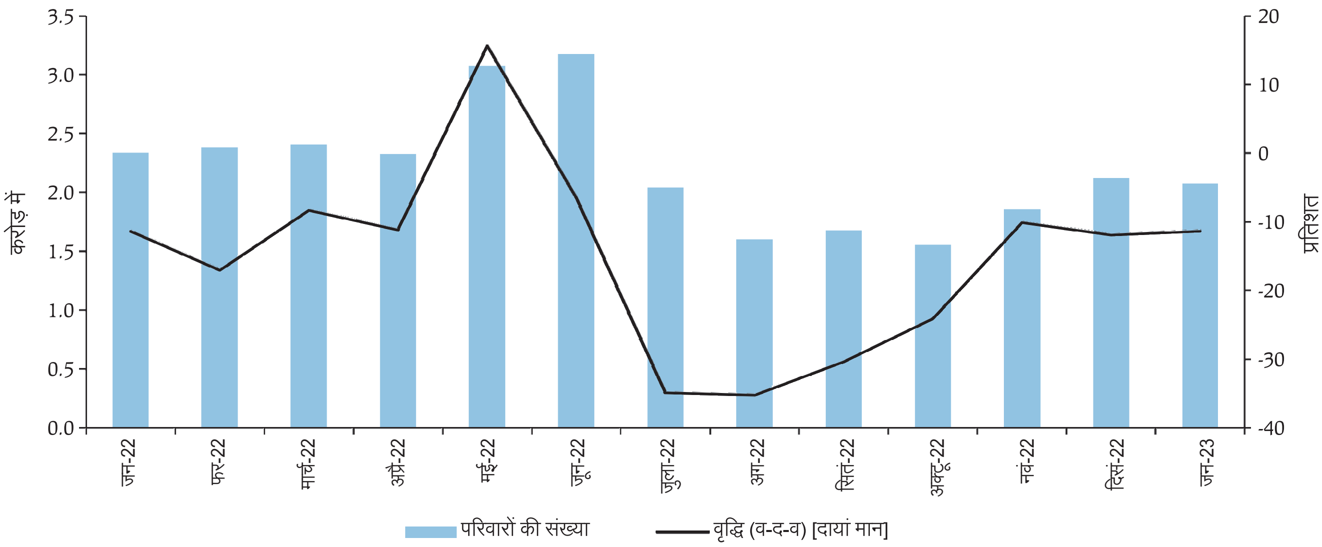

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

क्रमिक आधार पर 13.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 18)। अप्रैल-जनवरी 2022-23 के दौरान, संचयी व्यापारिक निर्यात 8.5 प्रतिशत बढ़कर 369.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

जनवरी 2023 में गैर-तेल निर्यात में सालाना आधार पर 8.7 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसमें इंजीनियरिंग सामान, रत्न और आभूषण, और सूती धागे और कपड़े में गिरावट आई (चार्ट 19)। दूसरी ओर, पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक सामान और चावल ने समग्र निर्यात में सकारात्मक योगदान दिया।

सॉफ्टवेयर और यात्रा सेवाओं से होने वाली कमाई के कारण भारत का सेवा निर्यात जो 31.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, उसमें दिसंबर 2022 में 20.4 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि हुई (दिसंबर 2021 में 26.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर)।

जनवरी 2023 में 50.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापारिक आयात में 3.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई, जो आंशिक रूप से कच्चे तेल, कुछ उर्वरकों और वनस्पति तेलों

चार्ट 18: भारत के पण्य वस्तु निर्यात में रुझान

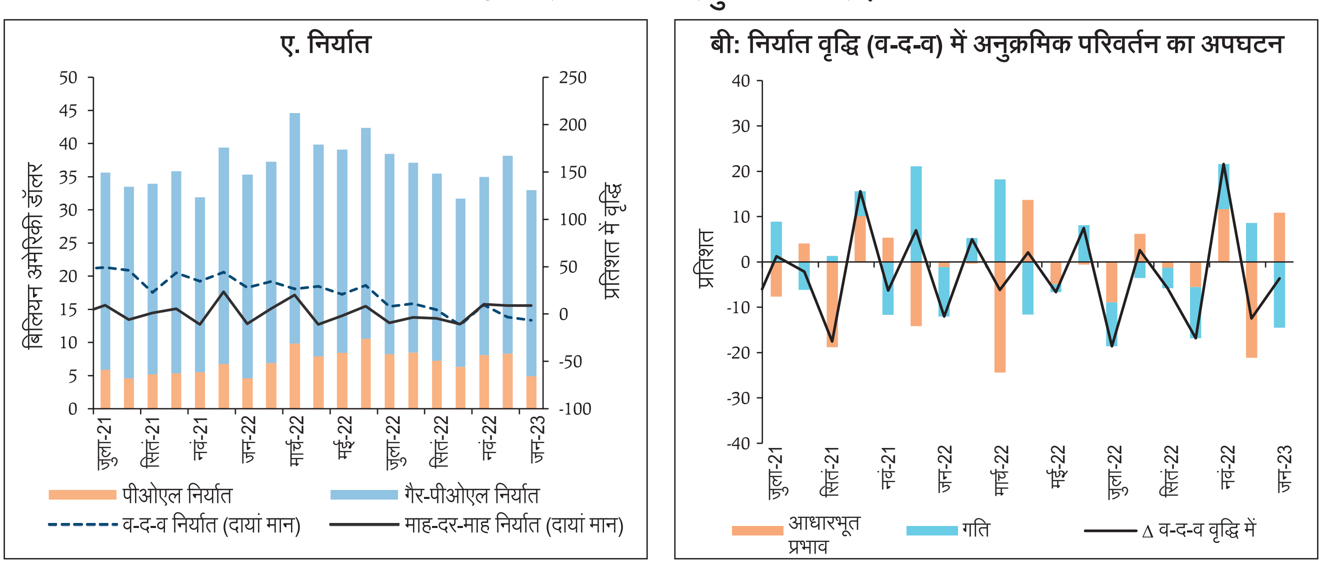

स्रोत: डीजीसीआईएस।

चार्ट 19: भारत का पण्य निर्यात – सापेक्ष योगदान (दिसंबर 2021 की तुलना में दिसंबर 2022 में)

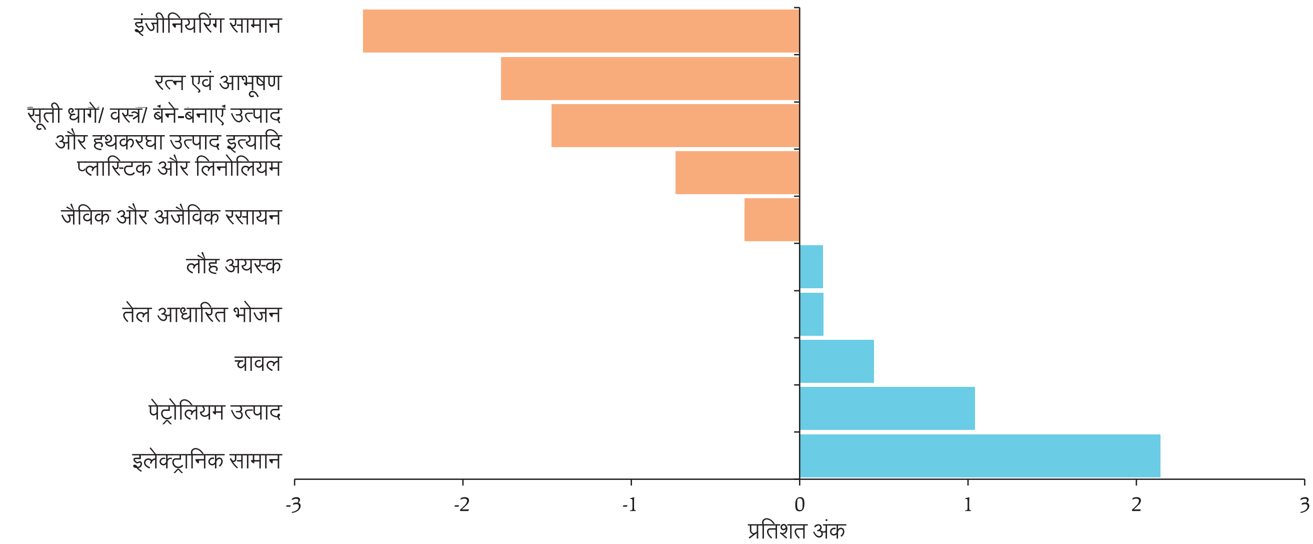

स्रोत: डीजीसीआईएस।

की कीमतों में गिरावट को दर्शाती है। क्रमिक आधार पर, आयात में गिरावट 15.8 प्रतिशत (चार्ट 20) पर और भी तेज थी। सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोती और कीमती पत्थर वे मुख्य वस्तुएं थीं जिन्होंने आयात को नीचे खींच लिया, जबकि पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल), लोहा और इस्पात और परियोजना के सामान जैसी वस्तुओं ने सकारात्मक योगदान दिया (चार्ट 21)।

जनवरी 2023 में अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतें 9 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ, भारत का सोने का आयात 70.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट के साथ 20 महीने के निचले स्तर 697 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गया। लगातार 25 महीनों तक विस्तारक्षेत्र में रहने के बाद, गैर-तेल गैर-सोना (एनओजी) आयात जनवरी 2023 में 6.7 प्रतिशत घट गया।

चार्ट 20: भारत के पण्य वस्तु आयात में रुझान

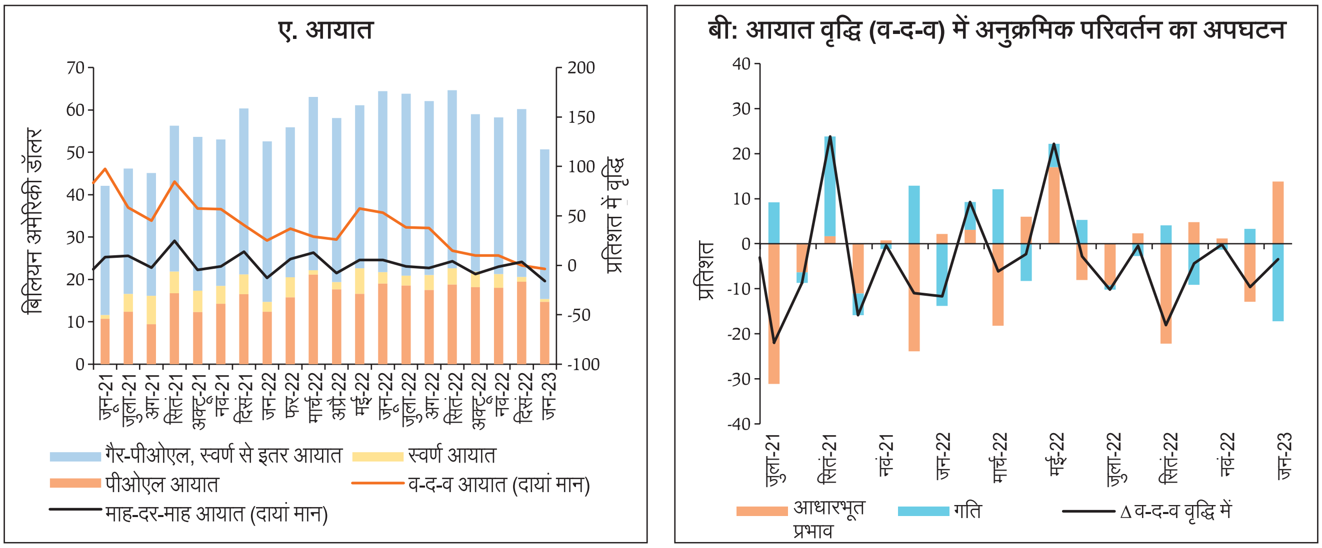

स्रोत: डीजीसीआईएस।

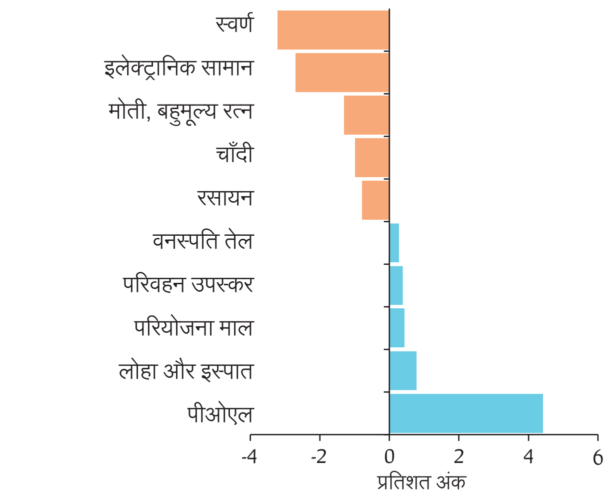

स्रोत: डीजीसीआईएस।

खाद्य तेल - जिसके लिए भारत आयात[10] पर बहुत अधिक निर्भर है - ने दिसंबर 2022[11] में मात्रा में 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और 15.6 लाख मीट्रिक टन (एमटी) तक पहुंच गया। जबकि पाम तेल खाद्य तेल आयात का 71 प्रतिशत था, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल शेष थे (चार्ट 22)। हालांकि, दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक इंडोनेशिया द्वारा कुछ निर्यात परमिट निलंबित किए जाने के संकेत के बाद फरवरी के दूसरे सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय पाम तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया।[12] नवंबर-दिसंबर 2022 के दौरान, इंडोनेशिया परिष्कृत ब्लीच्ड डिओडोराइज्ड (आरबीडी) पामोलीन और कच्चे पाम तेल का भारत का प्रमुख आपूर्तिकर्ता था।[13]

सकारात्मक बात यह है कि फसल वर्ष 2022-23 में सरसों के बीज का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है क्योंकि 98 लाख हेक्टेयर में अब तक की सबसे अधिक बुआई कवरेज और प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में मौसम अनुकूल है। चूंकि सरसों के तेल की घरेलू खाद्य तेल उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, इसलिए फसल का ज़्यादा उत्पादन अन्य खाद्य तेलों के आयात को कम करने में मदद कर सकता है।[14] इसके अलावा, 2021 में शुरू किए गए सरकार के 'खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम' का उद्देश्य घरेलू कच्चे पाम तेल उत्पादन

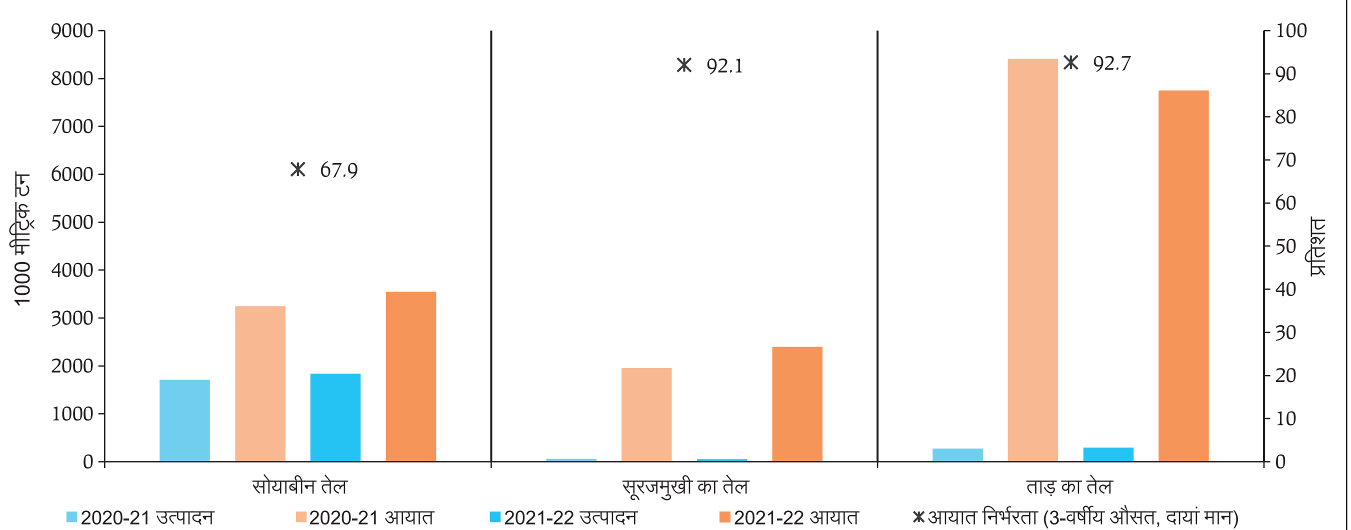

टिप्पणी: भारत का खाद्य तेल उत्पादन और आयात, विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के लिए हैं।
स्रोत: अमेरिकी कृषि विभाग, विदेशी कृषि सेवा।

[10] खाद्य तेल के लिए भारत की घरेलू मांग का लगभग 55 प्रतिशत आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।

[11] सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया।

[12] https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-suspend-some-palm-oil-export-permits-senior-official-2023-02-06/

[13] सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया।

[14] https://www.agriwatch.com/newsdetails.php?st=NEWS&commodity_id=11&sid=631435

को 2019-20 में 0.27 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2025-26 तक 11.20 लाख मीट्रिक टन करके पाम तेल पर आयात निर्भरता को कम करना है। आयात में तेज गिरावट के कारण, जनवरी 2023 में पण्य व्यापार घाटा 17.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 12 महीने के निचले स्तर पर आ गया।

उच्च आधार और परिवहन सेवाओं में गिरावट के कारण 15.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सेवा आयात में कमी आई। तदनुसार, दिसंबर 2022 के लिए निवल सेवा आय 15.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है (चार्ट 23)।

अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) संशोधित अनुमानों (आरई) का 56.6 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक (47.7 प्रतिशत) था। पूंजीगत परिव्यय में 17.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में 9.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जिससे खर्च की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ (चार्ट 24)।

अप्रैल-दिसंबर के दौरान उत्पाद शुल्क को छोड़कर (मई 2022 में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के कारण) सभी क्षेत्रों में संग्रहण में सुधार के साथ सकल कर राजस्व में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में क्रमशः 17.6 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट 25)। हालांकि गैर-कर राजस्व में 17.4 प्रतिशत की गिरावट आई है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सफल आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के कारण गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 93.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई।

चार्ट 23: सेवाओं का निर्यात और आयात

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट 24: सरकारी व्यय में रुझान

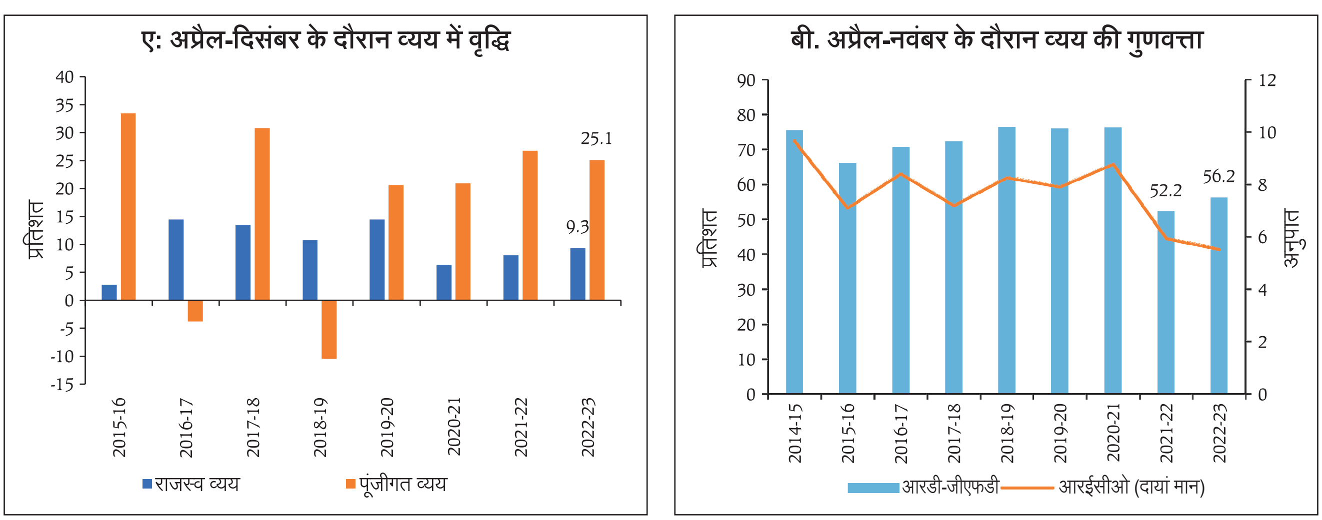

टिप्पणी: 1. आरडी-जीएफडी: सकल राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटा अनुपात (प्रतिशत के संदर्भ में उल्लेखित)।
2. आरईसीओ: पूंजीगत परिव्यय की तुलना में राजस्व व्यय अनुपात।

स्रोत: महालेखा नियंत्रक (सीजीए) और केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

चार्ट 25: अप्रैल-दिसंबर के दौरान कर राजस्व

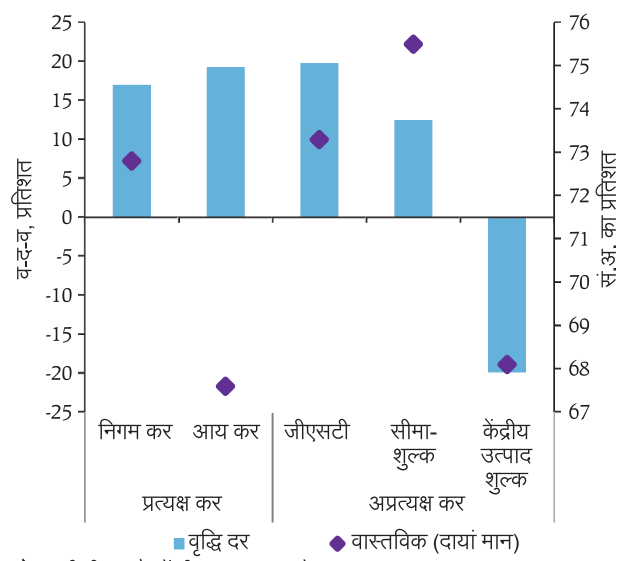

स्रोत: सीजीए; और केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

जनवरी 2023 में जीएसटी संग्रहण (केंद्र और राज्य) 10.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 1.55 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो अप्रैल 2022 के बाद से सबसे अधिक संग्रहण है (चार्ट 26)।

राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार जारी है, जैसा कि अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान बजटीय घाटे में गिरावट से परिलक्षित होता है (चार्ट 27)।[15]

एसजीएसटी संग्रहण में उच्च वृद्धि और केंद्र से कर हस्तांतरण के कारण राजस्व प्राप्तियों में ठोस वृद्धि बनी हुई है। राजस्व व्यय में गति भी बनी हुई है। संबंधित अवधि में पूंजीगत व्यय में 9.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट 28)। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2022-23 के तहत कर हस्तांतरण में वृद्धि और उठाव में वृद्धि के साथ पूंजीगत व्यय में यह गति 2022-23 की चौथी तिमाही में बनी रहने की उम्मीद है।

केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है, जिससे निजी निवेश में भरमार और रोजगार सृजन तथा मांग के मजबूत होने की उम्मीद है। सरकार ने 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 प्रतिशत के बजटीय राजकोषीय लक्ष्य का पालन किया (संशोधित अनुमान, आरई के अनुसार)। हालांकि, पूर्ण रूप से, जीएफडी ने बजट अनुमानों (बीई) को 94,123 करोड़ रुपये से पार कर लिया क्योंकि राजस्व व्यय में वृद्धि प्राप्तियों में वृद्धि से अधिक थी। 2023-24 (बजट अनुमान) में जीएफडी का बजट जीडीपी के 5.9 प्रतिशत पर रखा गया है, जो 2025-26 तक जीएफडी को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने के मध्यम अवधि के लक्ष्य के अनुरूप है।

चार्ट 26: मासिक जीएसटी राजस्व

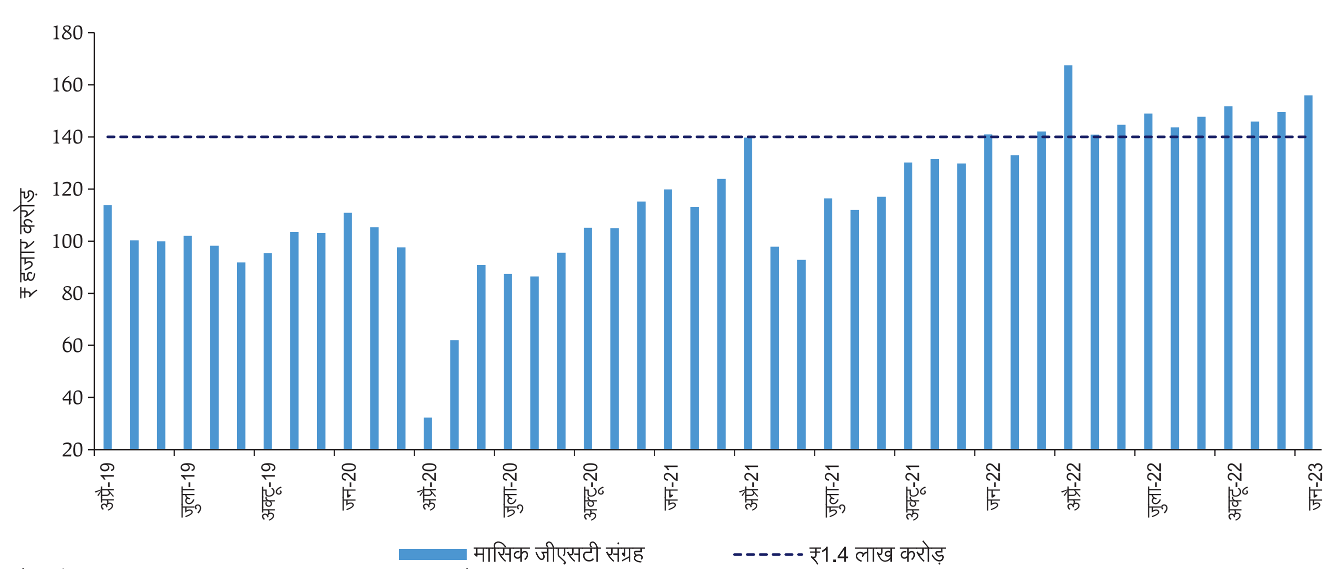

स्रोत: प्रेस सूचना कार्यालय (पीआईबी), भारत सरकार (जीओआई)।

[15] आंकड़े 24 राज्यों से संबंधित हैं।

चार्ट 27: अप्रैल-नवंबर की अवधि के दौरान राज्यों का बजटीय घाटा

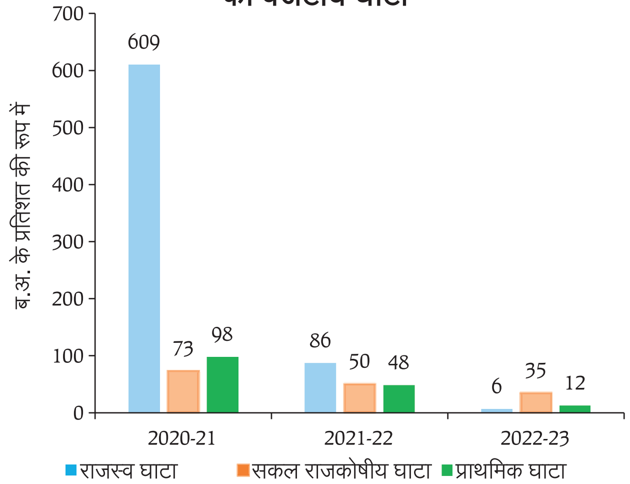

टिप्पणी: ये डेटा 24 राज्यों से संबंधित है।
स्रोत: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी); और राज्यों के बजट दस्तावेज़।

चार्ट 28: अप्रैल-नवंबर की अवधि के दौरान राज्यों के राजस्व और व्यय के रुझान

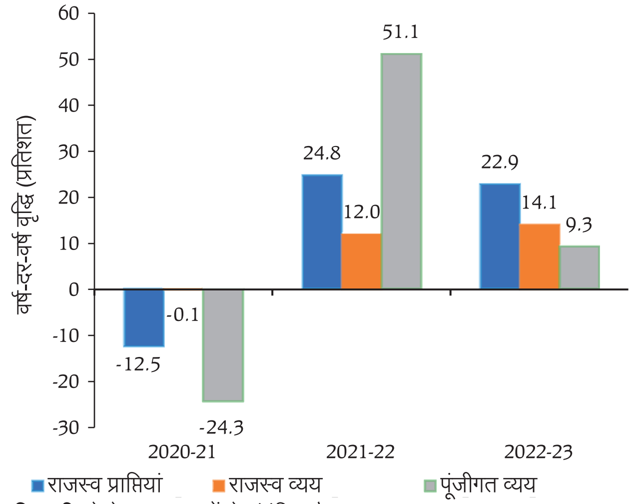

टिप्पणी: ये डेटा 24 राज्यों से संबंधित है।
स्रोत: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी)।

वित्त वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपये रखा गया है जो जीडीपी का 3.3 प्रतिशत है। प्रभावी पूंजीगत व्यय, जिसमें केंद्र का पूंजीगत व्यय और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए राज्यों को सहायता अनुदान शामिल है, का बजट 2023-24 (बीई) में सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत है। इसके विपरीत राजस्व व्यय में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। 2023-24 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाजार उधार 8.6 प्रतिशत बढ़कर 15.4 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि 2023-24 के दौरान 11.8 लाख करोड़ रुपये पर निवल बाजार उधार 6.6 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

केंद्रीय बजट 2023-24 में राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3.5 प्रतिशत तय की गई है, जिसमें से 0.5 बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा होगा। केंद्र ने राज्यों को उनके पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए 2023-24 के दौरान 1.3 ट्रिलियन रुपये के बढ़े हुए आवंटन के साथ ब्याज मुक्त 50 साल के ऋण प्रदान करना जारी रखने का भी फैसला किया है।

कुल आपूर्ति

कृषि फसल उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमानों (एई) के अनुसार, भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 में 323.6 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2021-22 के अंतिम अनुमानों की तुलना में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। रबी फसलों की 6.2 प्रतिशत की वृद्धि ने खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में 1.2 प्रतिशत की गिरावट की भरपाई कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। खाद्य फसल श्रेणी में गेहूं (एक रबी स्टेपल), मक्का और दालों के साथ-साथ वाणिज्यिक फसलों के बीच तिलहन और गन्ने के लिए नया उत्पादन रिकॉर्ड का अनुमान लगाया गया है। कपास उत्पादन ने एई के अनुसार उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की है।(चार्ट 29)

चार्ट 29: 2022-23 में कृषि उत्पादन (दूसरे अग्रिम अनुमान)

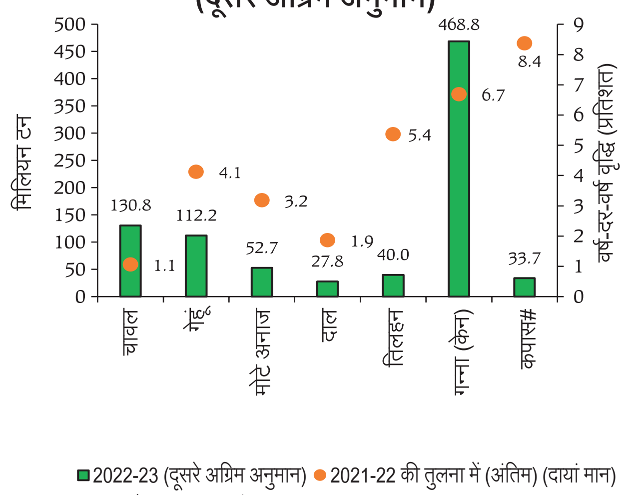

प्रति 170 किलो मिलियन गांठें।
स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

चार्ट 30: *रबी* मौसम संचयी बुवाई और जलाशय की स्थिति

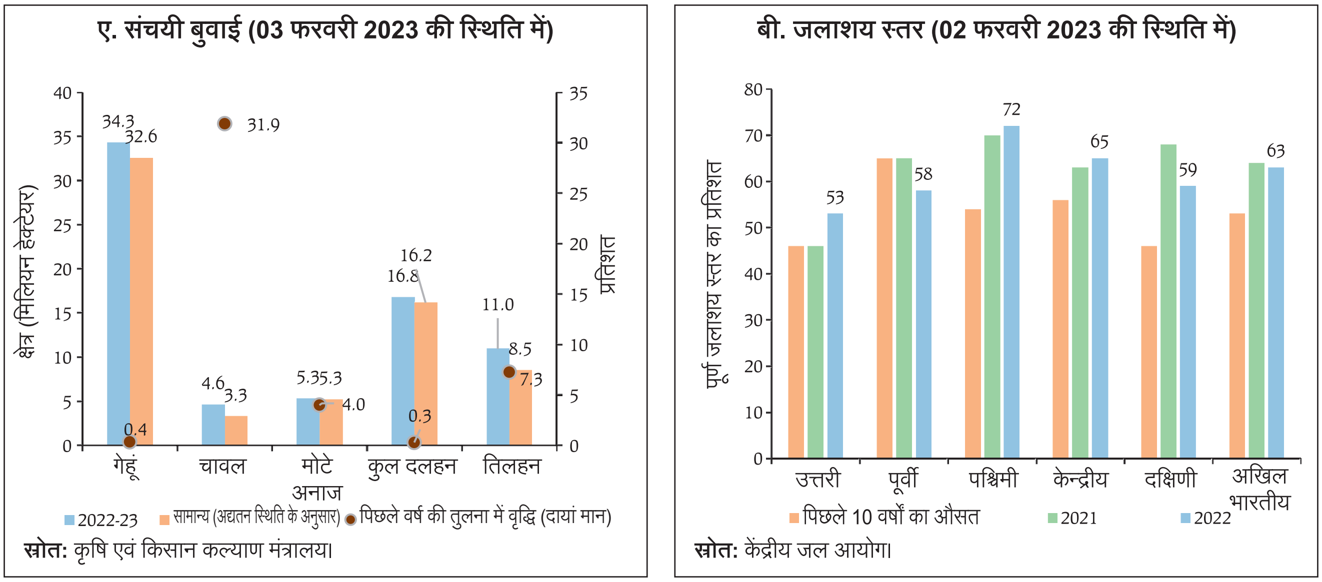

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

स्रोत: केंद्रीय जल आयोग।

रबी फसल की बुवाई का मौसम 72.1 मिलियन हेक्टेयर के रिकॉर्ड क्षेत्रफल के साथ समाप्त हुआ, जिसमें सभी फसलों के तहत पर्याप्त वृद्धि हुई (चार्ट 30 ए)। जलाशय का स्तर सुखद रहा (चार्ट 30 बी)।

09 फरवरी, 2023 तक संचयी चावल खरीद (अनमिल्ड धान सहित) एक साल पहले की तुलना में मामूली रूप से कम थी, लेकिन चालू खरीफ विपणन सत्र में धान की मंडी आवक वर्ष-दर-वर्ष (09 फरवरी, 2023 तक) 36.9 प्रतिशत अधिक रही है। 01 फरवरी, 2023 तक चावल और गेहूं का सार्वजनिक स्टॉक बफर मानदंडों के क्रमशः 6.2 और 1.1 गुना पर संतोषजनक रहा। 25 जनवरी, 2023 को सरकार ने केंद्रीय पूल से विभिन्न चैनलों के माध्यम से 3 मिलियन टन गेहूं की खुले बाजार में बिक्री की घोषणा की। सबसे पहले, 16 फरवरी, 2023 को । यह पहले ही दो ई-नीलामी के माध्यम से 1.3 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं बेच चुका है। दूसरा, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों/परिसंघों, केन्द्रीय भंडार और एनसीसीएफ/नैफेड को रियायती दर पर 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आबंटन भी किया है।

केंद्रीय बजट 2023-24 कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक सुधारों और नीतियों पर केंद्रित है, जिनमें: (i) बाजरा के उत्पादन और खपत में वृद्धि; (ii) संबद्ध क्षेत्रों का विविधीकरण और संवर्धन; (iii) अंतिम छोर तक संपर्क के लिए संभार तंत्र अवसंरचना को बढ़ावा देना; (iv) कृषि निर्यातों पर जोर देना; (v) सहकारी आधारित विकास और वृद्धि; और (vi) डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से कृषि विस्तार को सुदृढ़ करना शामिल हैं। सरकार नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कृषि गतवर्धक निधि के माध्यम से एक कृषि-तकनीकी स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करने का भी इरादा रखती है।

अनुक्रमिक ब्लिप के बावजूद जनवरी 2023 में विनिर्माण और सेवाओं के लिए हेडलाइन पीएमआई क्रमशः 55.4 और 57.2 पर, विस्तारवादी क्षेत्र में रहा (चार्ट 31 ए और 31 बी)। विनिर्माण और सेवाओं के लिए दृष्टिकोण उत्साहजनक बना हुआ है, और ऐतिहासिक औसत से ऊपर है। क्रॉस-कंट्री तुलना से पता चलता है कि भारत में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक पीएमआई रीडिंग थी (चार्ट 31 सी)।

विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग 2022-23 की दूसरी तिमाही में अपने दीर्घकालिक औसत को पार कर गया। विनिर्माताओं को बाद की तिमाहियों में और सुधार की उम्मीद है। विनिर्माण, बुनियादी ढांचा और सेवा क्षेत्रों की कंपनियों ने 2023-24 की

चार्ट 31: क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)

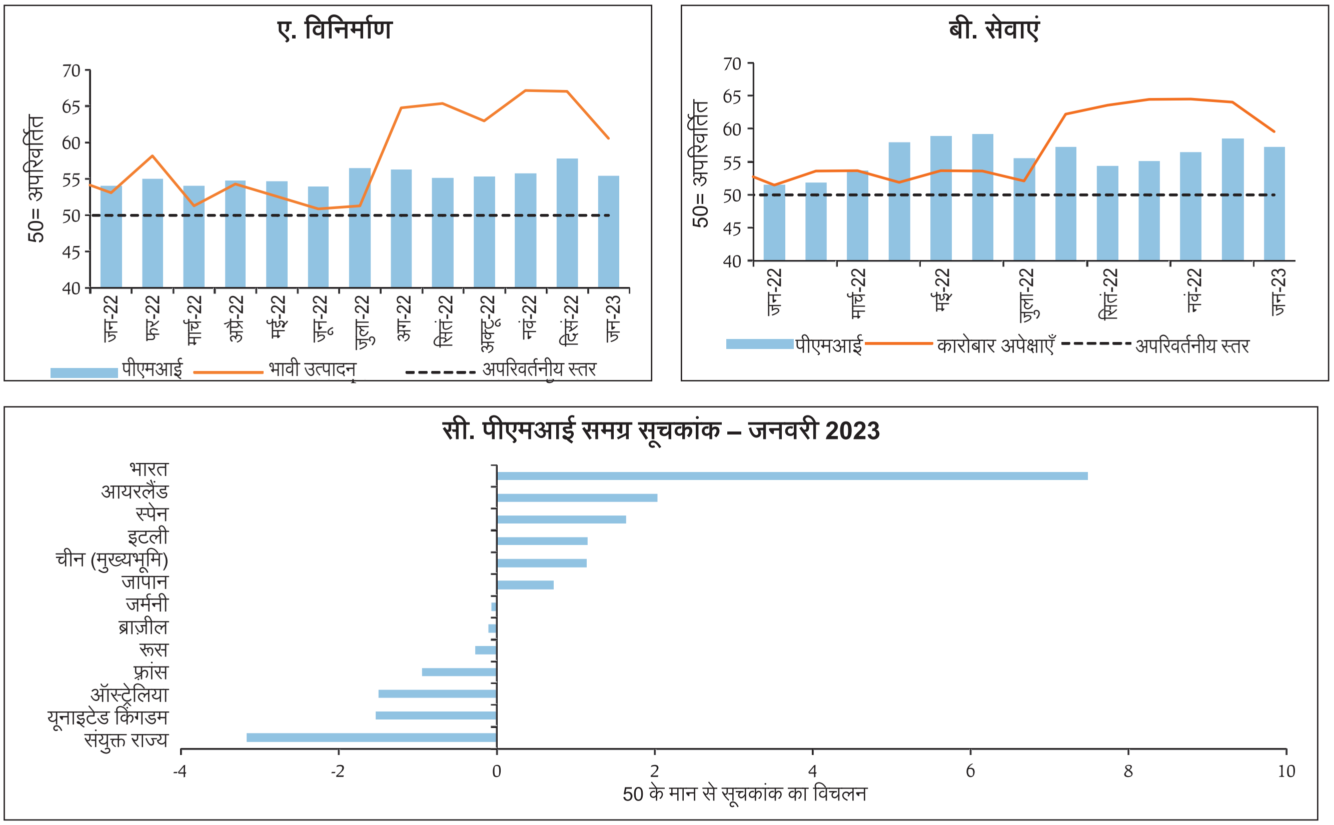

स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

पहली छमाही तक मांग की स्थिति को लेकर बहुत अधिक आशावाद दिखाया है, जैसा कि रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण सर्वेक्षण (अनुबंध 1) में परिलक्षित होता है।

सेवा क्षेत्र में, परिवहन संकेतकों में विस्तार दर्ज किया गया, जिसमें रेलवे माल ढुलाई आय जनवरी 2023 में महीने-दर-महीने (एम-ओ-एम) और साल-दर-साल आधार पर बढ़ी, जो भारतीय रेलवे की हंगर फॉर कार्गो पहल द्वारा समर्थित है (चार्ट 32 ए) । कोकिंग कोल और कंटेनराइज्ड कार्गो के पोतभार में वृद्धि के कारण जनवरी में प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो यातायात में तेजी आई (चार्ट 32 बी) ।

निर्माण क्षेत्र में इस्पात की खपत जनवरी 2023 में सालाना आधार पर 2.7 प्रतिशत बढ़ी जबकि एक साल पहले इसी महीने में इसमें 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। सीमेंट उत्पादन में वृद्धि एक उच्च आधार पर कम हो गई (चार्ट 33)।

सेवा क्षेत्र में उच्च आवृत्ति संकेतक अंतरराष्ट्रीय यात्री आंदोलन और हवाई कार्गो यातायात को छोड़कर आम तौर पर सकारात्मक गति जारी रहने की ओर इशारा करते हैं (सारणी 2)।

राज्य स्तर पर प्रमुख नीतिगत पहलों के संदर्भ में, तमिलनाडु ने तमिलनाडु इमर्जिंग सेक्टर सीड फंड (टीएनईएसएफ) शुरू किया है जिसका उद्देश्य उभरते/सनराइज क्षेत्रों में स्टार्ट-अप के लिए निवेश प्रदान करना है। पश्चिम बंगाल ने कपड़ा क्षेत्र को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने वाली एक योजना शुरू की। ओडिशा ने ओडिशा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन (ओपीजीसी)

चार्ट 32: रेलवे और कार्गो यातायात

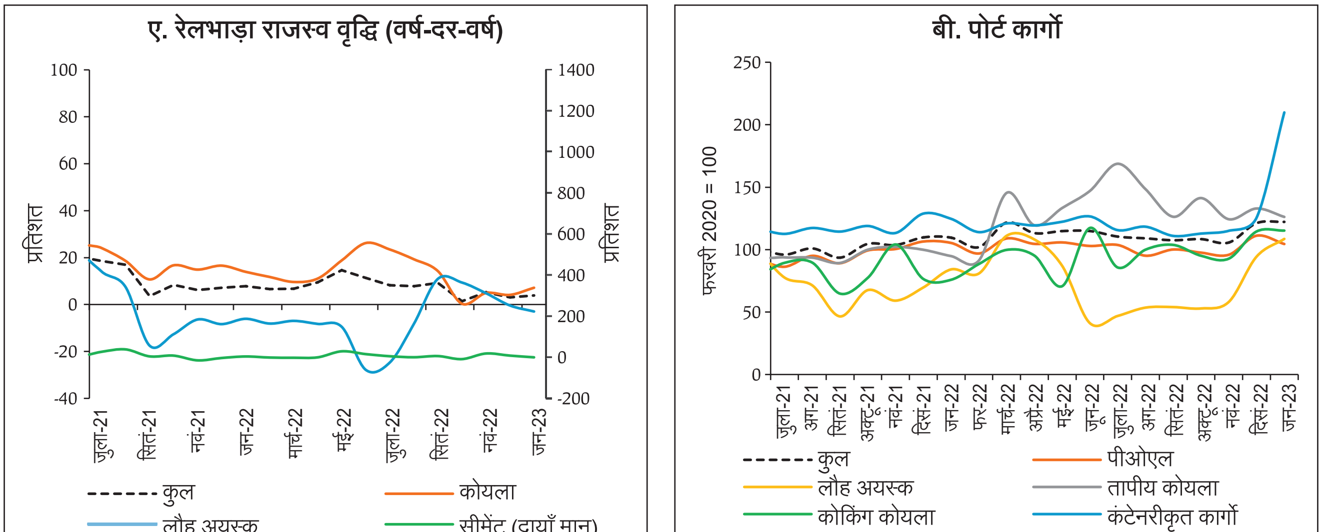

स्रोत: रेल दृष्टि।

स्रोत: इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन।

में अपनी 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए एक वैश्विक निविदा जारी की। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निजी औद्योगिक पार्क के विकास की सुविधा के लिए एक नई योजना को मंजूरी दे दी है।

चार्ट 33: इस्पात खपत और सीमेंट उत्पादन

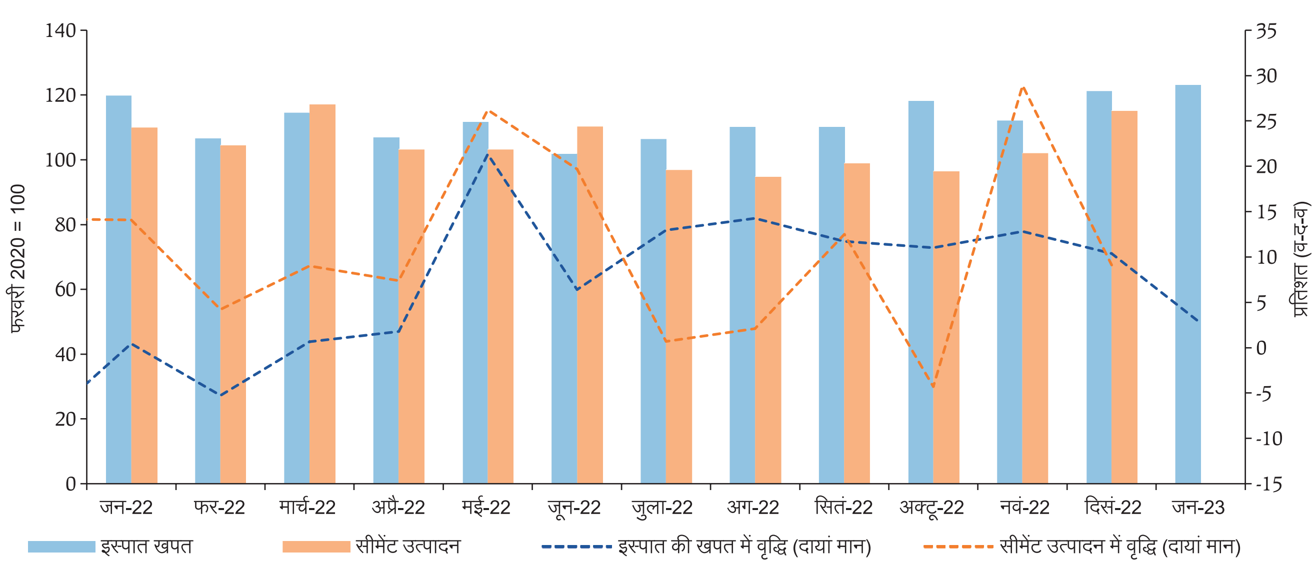

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

सारणी 2: उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाएं

सेवाओं में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

क्षेत्र	संकेतक	अक्टू-22	नवं-22	दिसं-22	जन-23
शहरी मांग	यात्री वाहन बिक्री	28.6	28.1	7.2	17.2
ग्रामीण मांग	दुपहिया वाहन बिक्री	2.3	16.5	3.9	5.0
	तिपहिया वाहन बिक्री	70.4	103.2	37.6	103.0
	ट्रैक्टर बिक्री	6.8	6.5	25.6	24.4
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार	वाणिज्यिक वाहन बिक्री	16.6			
	रेलवे माल ढुलाई यातायात	1.4	5.2	3.1	3.8
	पोर्ट कार्गो यातायात	3.1	1.8	10.3	
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात	-8.3	3.7	-3.6	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात	-18.7	-6.0	-7.4	
	घरेलू हवाई यात्री यातायात	30.4	12.6	14.6	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	115.0	97.5	85.9	
	जीएसटी ई-वे बिल (कुल)	4.6	32.0	17.5	19.7
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतर्राज्यीय)	12.0	37.7	23.2	24.1
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतर-राज्यीय)	-5.9	23.1	8.6	12.8
	पर्यटक आगमन	243.2	191.3	204.2	
निर्माण	इस्पात खपत	11.0	12.8	10.3	2.7
	सीमेंट उत्पादन	-4.3	28.9	9.1	
पीएमआई सूचकांक	सेवाएं	55.1	56.4	58.5	57.2

स्रोत: सीएमआईई; सीईआईसी आंकड़े; आईएचएस मार्किट; एसआईएएम; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; और संयुक्त प्लांट समिति।

मुद्रास्फीति

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति – जैसा कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में साल-दर-साल परिवर्तनों द्वारा मापा जाता है – दिसंबर 2022 में 5.7 प्रतिशत से बढ़कर जनवरी 2023 में 6.5 प्रतिशत हो गया (चार्ट 34 ए)। सूचकांक में 46 बीपीएस की वृद्धि हुई, जिसके साथ-साथ प्रतिकूल आधार

चार्ट 34: सीपीआई मुद्रास्फीति के रुझान और वाहक

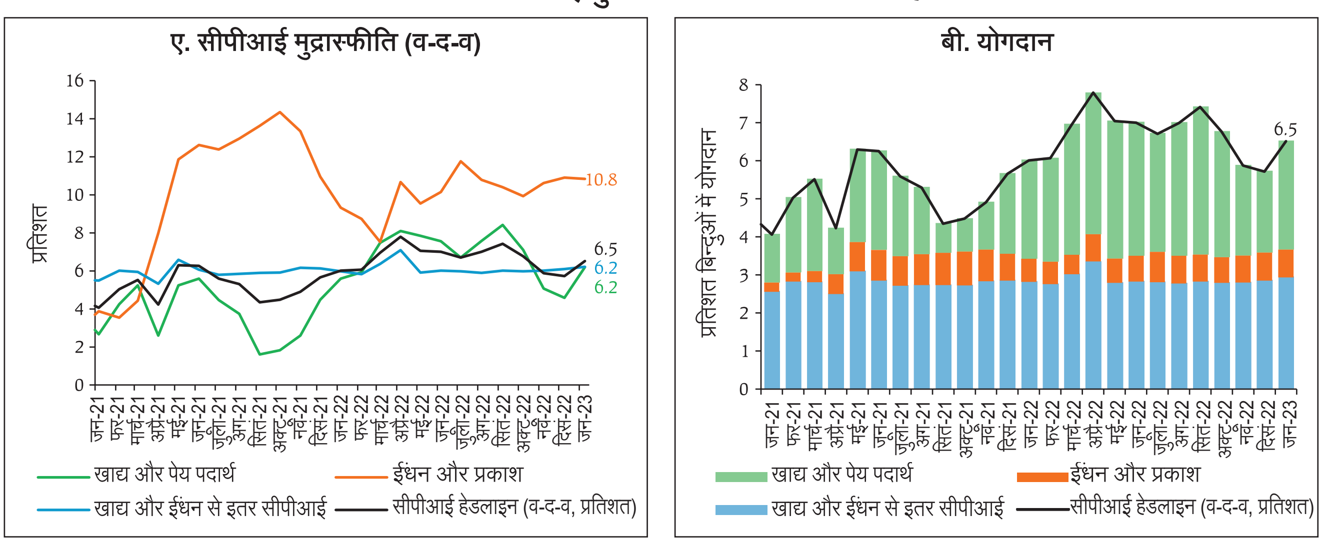

टिप्पणी: अप्रैल-मई 2021 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति की गणना, अप्रैल-मई 2020 के लिए अनुमानित सीपीआई सूचकांकों के आधार पर की गई थी।
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

प्रभाव (एक साल पहले कीमतों में एम-ओ-एम परिवर्तन) 30 बीपीएस के साथ, जिसके परिणामस्वरूप दिसंबर और जनवरी के बीच हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगभग 80 बीपीएस की वृद्धि हुई।

मूल्य दबाव मुख्य रूप से खाद्य और पेय समूह (45 बीपीएस) और 'कोर' (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) समूह (52 बीपीएस) में एम-ओ-एम वृद्धि से उत्पन्न होता है। हालांकि ईंधन समूह का सूचकांक संबंधित महीने में अपरिवर्तित रहा।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खाद्य मुद्रास्फीति जनवरी में तेजी से बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई, जो एक महीने पहले 4.6 प्रतिशत थी (चार्ट 34बी)। खाद्य समूह के भीतर, अनाज में मुद्रास्फीति काफी बढ़कर 16.1 प्रतिशत - जून 2013 के बाद से सबसे अधिक - और मसालों में, 21.1 प्रतिशत - वर्तमान सीपीआई श्रृंखला में सबसे अधिक हो गई (चार्ट 35)। फल, खाद्य तेल, चीनी, प्रोटीन आधारित खाद्य (दालें, अंडे, मांस, मछली और दूध) और गैर-मादक पेय जैसे अन्य उप-समूहों ने महीने के दौरान मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज की। सब्जियों ने दिसंबर 2022 की तुलना में जनवरी 2023 में कम अपस्फीति दर्ज की (चार्ट 36)।

ईंधन और बिजली समूह की मुद्रास्फीति जनवरी में मामूली रूप से कमी आकर वह 10.8 प्रतिशत रही जो दिसंबर में 10.9 प्रतिशत थी। केरोसीन-पीडीएस और बिजली की मुद्रास्फीति में कुछ कमी दर्ज की गई, जबकि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) ने एक महीने पहले की तुलना में मूल्य वृद्धि का उच्च स्तर दर्ज किया। सीपीआई बास्केट में 6.8 प्रतिशत के भारांश वाले ईंधन समूह ने जनवरी में हेडलाइन मुद्रास्फीति में 11.3 प्रतिशत का योगदान दिया।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में बढ़कर 6.2 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो दिसंबर में 6.1 प्रतिशत थी। दूसरी ओर कपड़े और जूते-चप्पल, घरेलू सामान एवं सेवाएं, परिवहन एवं संचार तथा शिक्षा उप-समूहों में जनवरी में मुद्रास्फीति में नरमी देखी गई।

चार्ट 35: वार्षिक मुद्रास्फीति (व-द-व) और उप-समूहों में गति (माह-दर-माह)

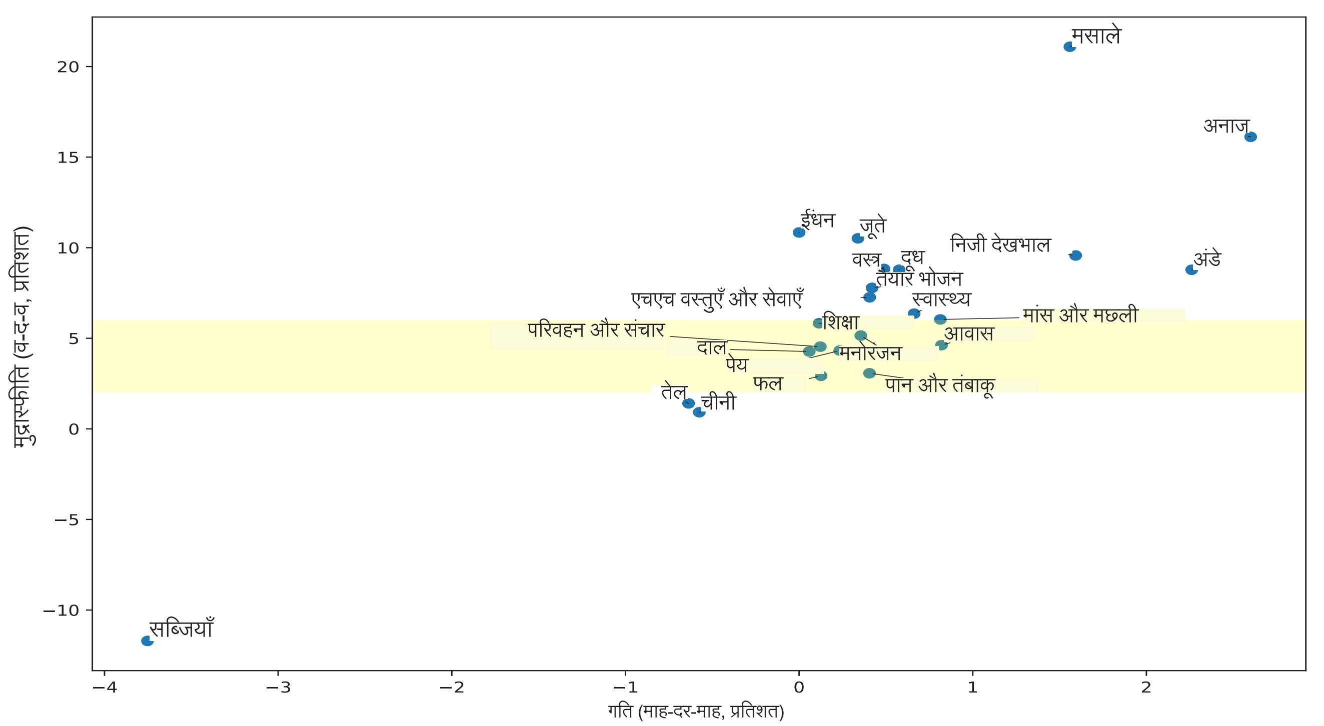

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट 36: उप-समूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (दिसंबर 2022 की तुलना में जनवरी 2023)

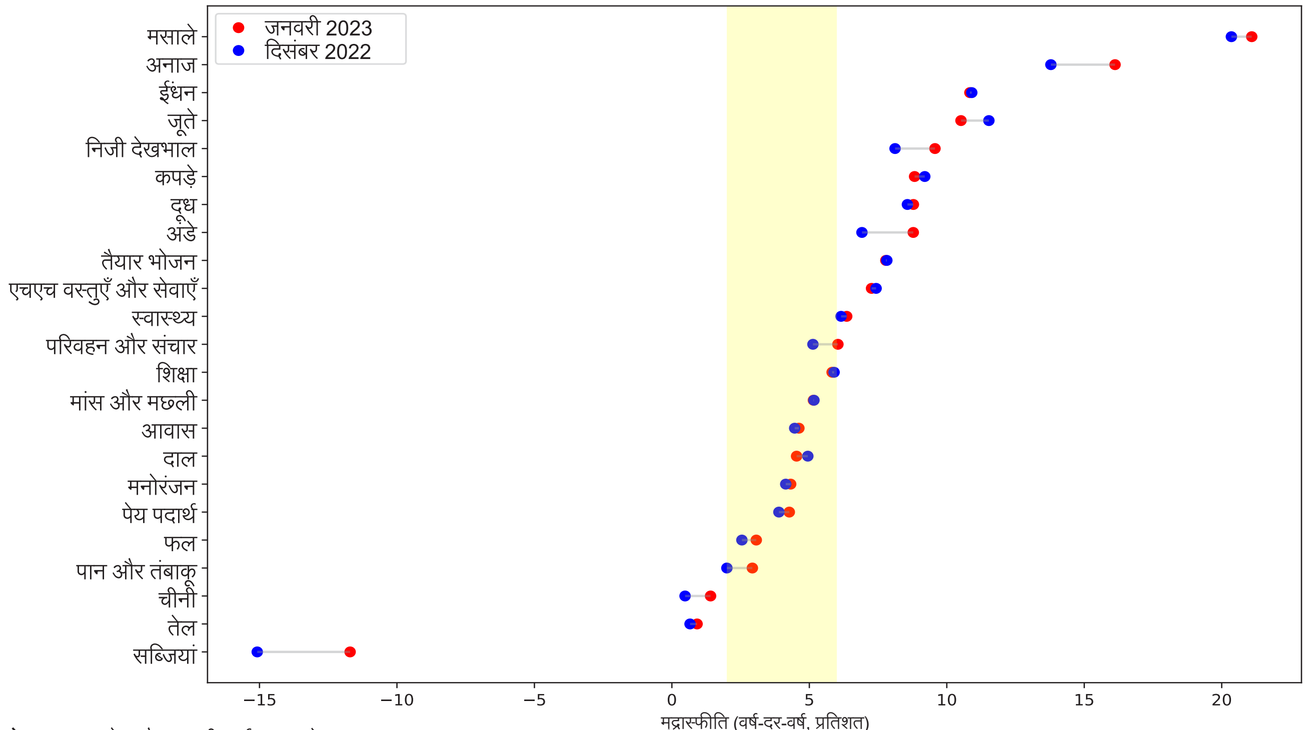

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

जनवरी 2023 में ग्रामीण मुद्रास्फीति 6.85 प्रतिशत रही जो शहरी मुद्रास्फीति (6.00 प्रतिशत) से अधिक है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज, फल, कपड़े की मुद्रास्फीति अधिक थी, दूध, अंडे, मांस और ईंधन और प्रकाश में शहरी केंद्रों में उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की गई (चार्ट 37)।

राज्यों में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना ने 8 प्रतिशत से अधिक मुद्रास्फीति का अनुभव किया, जबकि छत्तीसगढ़, दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय ने मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से नीचे दर्ज की (चार्ट 38)।

फरवरी 2023 (13 फरवरी तक) के लिए खाद्य कीमतों पर उच्च आवृत्ति डेटा से पता चलता है कि चावल और गेहूं के लिए कीमतों में वृद्धि जारी रही। मूंग को छोड़कर दालों की कीमतों में गिरावट आई है। खाद्य तेल और सब्जियों की कीमतों में फरवरी में गिरावट जारी रही (चार्ट 39)।

चार्ट 37: चुनिंदा मदों में मुद्रास्फीति (ग्रामीण बनाम शहरी)

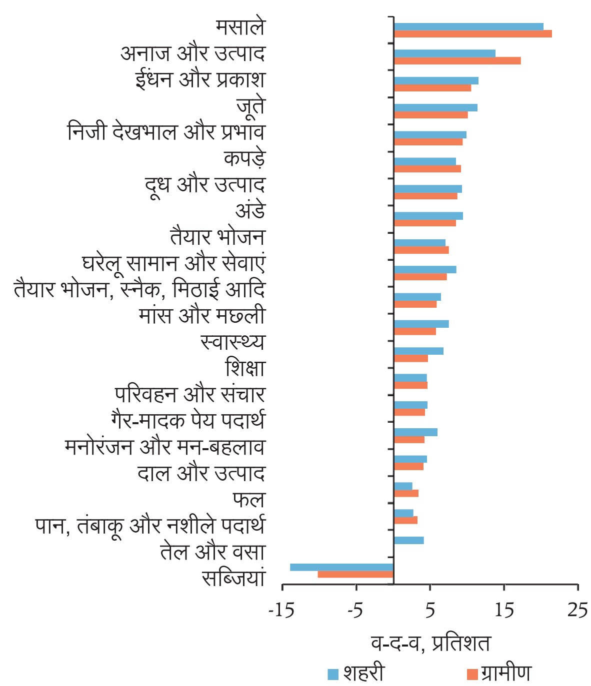

स्रोत: एनएसओ।

चार्ट 38: जनवरी 2023 में मुद्रास्फीति का स्थानिक वितरण (सीपीआई- संयुक्त, वर्ष-दर-वर्ष)

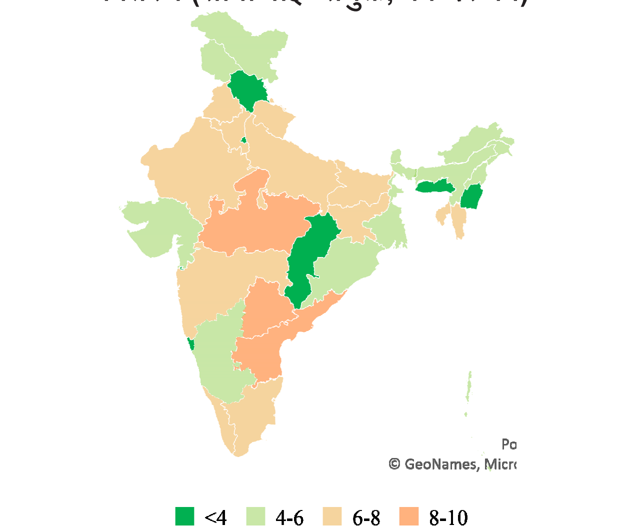

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

सारणी 3: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

मदें	इकाई	घरेलू कीमतें			माह की तुलना (प्रतिशत)	
		फर-22	जन-23	फर-23^	जन-23	फर-23
पेट्रोल	₹/लीटर	102.87	102.92	102.92	0.0	0.0
डीजल	₹/लीटर	90.51	92.72	92.72	0.0	0.0
केरोसिन (सहायकी सहित)	₹/लीटर	42.11	53.67	55.79	-9.0	4.0
एलपीजी (सहायकी रहित)	₹/सिलेंडर	910.13	1063.25	1063.25	0.0	0.0

^: 1-13 फरवरी 2023 की अवधि के लिए।

टिप्पणी: मिट्टी के तेल के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में औसत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मिट्टी के तेल के लिए कीमतें, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में रियायती कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल); पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); तथा आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री कीमतें फरवरी में अब तक स्थिर रही हैं। जबकि एलपीजी की कीमतों को अपरिवर्तित रखा गया था, जनवरी में तेजी से गिरावट के बाद मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि हुई (सारणी 3)।

चार्ट 39: डीसीए आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

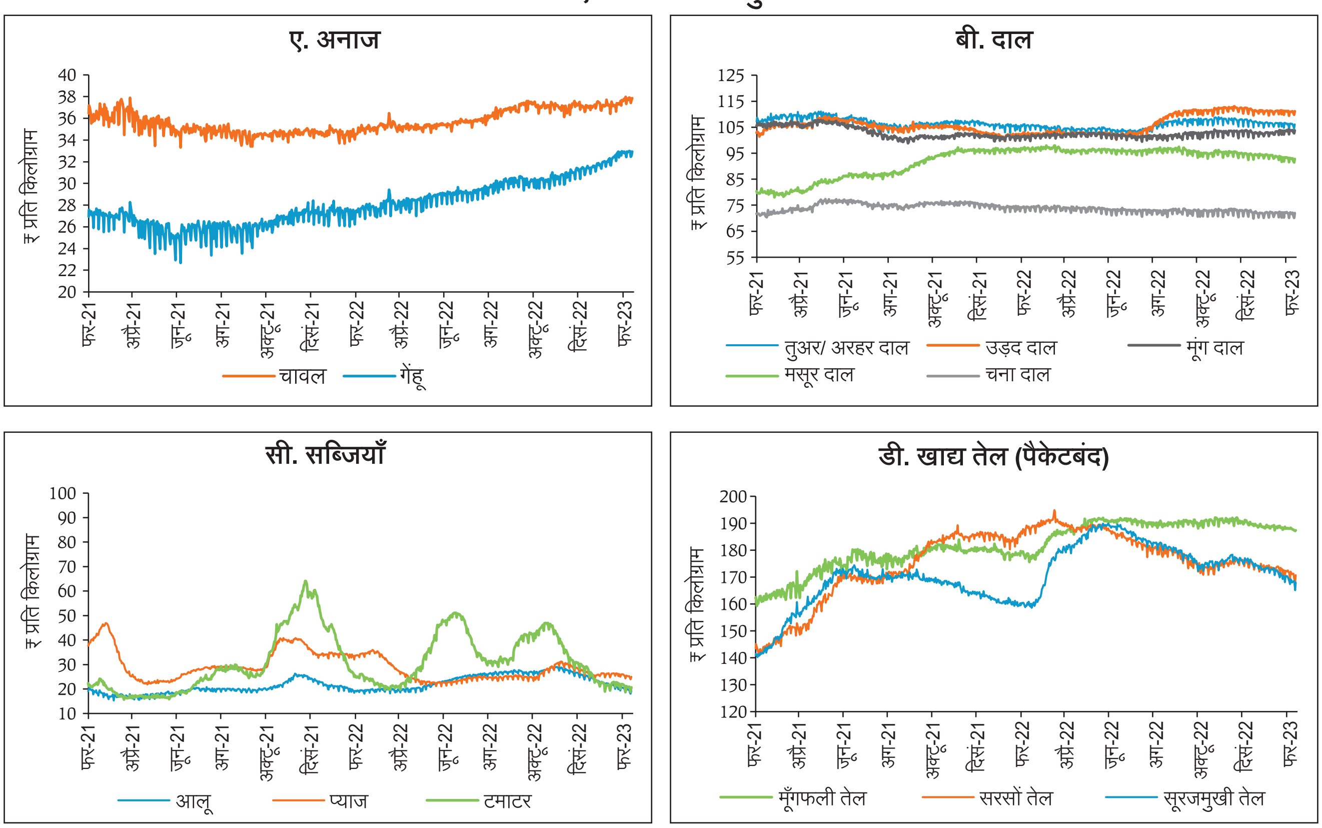

स्रोत : उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट 40: पीएमआई: इनपुट और आउटपुट कीमतें

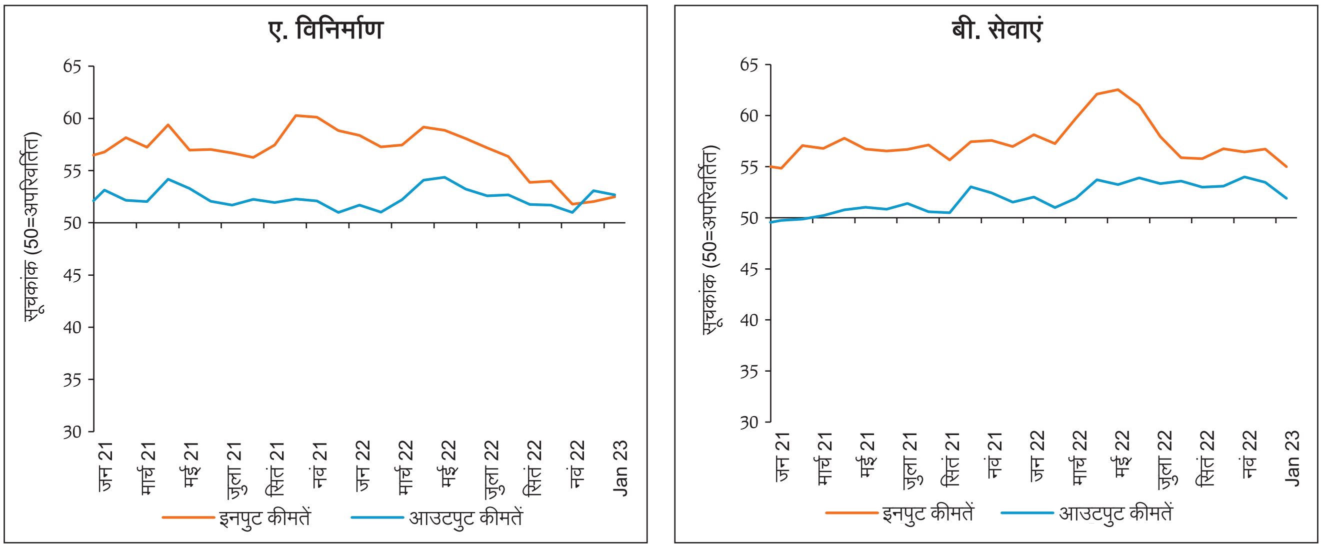

स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

इनपुट लागत और बिक्री मूल्य, जैसा कि पीएमआई में परिलक्षित होता है, विनिर्माण और सेवाओं दोनों के लिए विस्तारवादी मोड में रहा (चार्ट 40), बाद में वृद्धि की गति में क्रमिक कमी देखी गई।

4. वित्तीय स्थिति

जनवरी 2023 की दूसरी छमाही में जीएसटी संग्रह [16] के कारण बहिर्वाह की वजह से अधिशेष चलनिधि कम हो गई, लेकिन फरवरी की शुरुआत में सरकारी खर्च ने प्रणाली चलनिधि को फिर से बढ़ा दिया। कुल मिलाकर, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक अवशोषण 16 जनवरी से 8 फरवरी, 2023 के दौरान 1.3 लाख करोड़ रुपये तक कम हो गया, जो दिसंबर के मध्य से 15 जनवरी, 2023 के दौरान 1.5 लाख करोड़ रुपये था (चार्ट 41)। इस अवधि के दौरान दैनिक औसत अधिशेष चलनिधि में से 0.4 लाख करोड़ रुपये रात्रिकालीन स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के माध्यम से अवशोषित किए गए थे, जबकि शेष को परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामी के माध्यम से जुटाया गया था।

अधिशेष चलनिधि में गिरावट ने कुछ बैंकों को सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया, जो इसी अवधि के दौरान औसतन ₹ 0.06 लाख करोड़ था। एसडीएफ के तहत अधिशेष निधियों के बड़े पैमाने पर जमावट की पृष्ठभूमि में बैंकों द्वारा एमएसएफ का सहारा लेना प्रणाली में विषम चलनिधि

चार्ट 41: चलनिधि स्थितियां

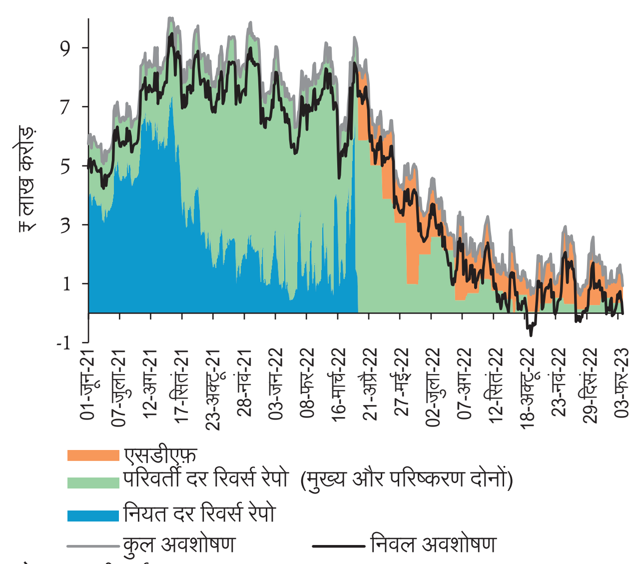

स्रोत : आरबीआई।

[16] जनवरी 2023 का मासिक जीएसटी संग्रह 1.56 लाख करोड़ रुपये था, जो अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपये के बाद दूसरा सबसे अधिक संग्रह था।

चार्ट 42: नीतिगत कॉरीडोर और मुद्रा बाज़ार दरें

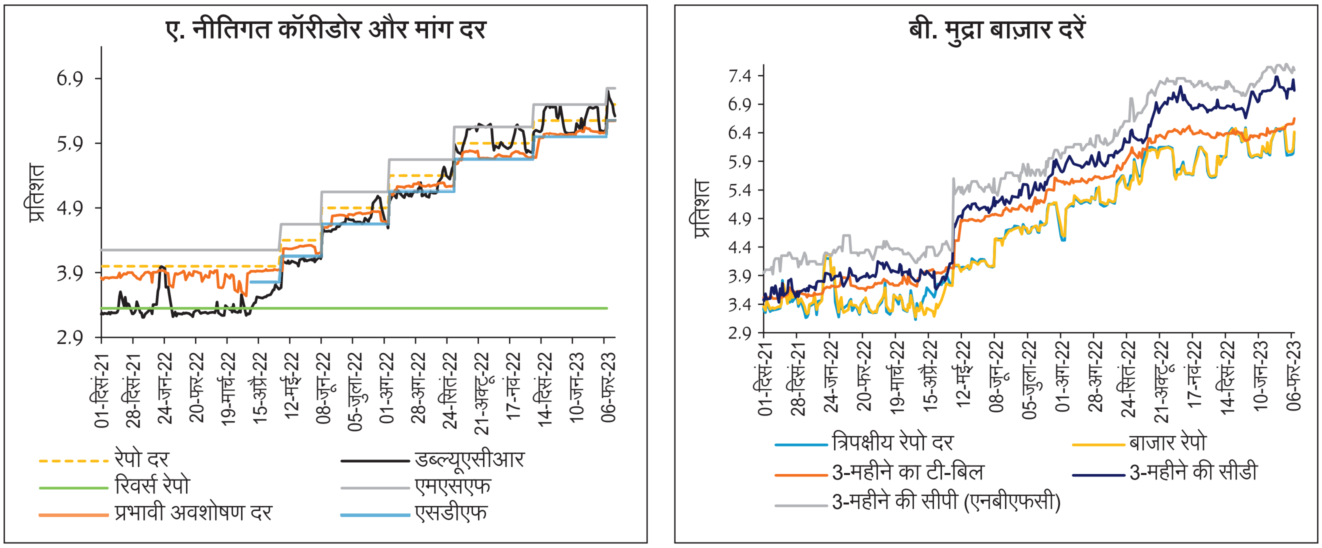

स्रोत: आरबीआई; ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

वितरण को दर्शाता है। निवल आधार पर (रेपो और एमएसएफ के माध्यम से अंत:क्षेपण के लिए समायोजित) समीक्षाधीन अवधि में औसत अवशोषण घटकर 0.34 लाख करोड़ रुपये रह गया, जो पिछली अवधि में 0.51 लाख करोड़ रुपये था। पाक्षिक वीआरआरआर नीलामी के तहत रखी गई राशि भी 27 जनवरी, 2023 से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए 0.35 लाख करोड़ रुपये (पिछली नीलामी के दौरान 0.52 लाख करोड़ रुपये) से कम थी।

अधिशेष चलनिधि की स्थिति में कमी और दीर्घकालिक रेपो परिचालन की आगामी परिपक्वता के बीच, रिजर्व बैंक ने संशोधित चलनिधि ढांचे के तहत पहली बार 10 फरवरी, 2023 को 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) संचालन किया, जिसके लिए 0.50 लाख करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के सामने 1.34 लाख करोड़ रुपये की बोली प्राप्त हुई। केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रस्तुत 2022-23 के संशोधित अनुमानों से स्पष्ट सरकारी खर्च में संभावित वृद्धि से फरवरी-मार्च के दौरान संचलन में मुद्रा में सामान्य विस्तार और मार्च-अप्रैल 2023 के दौरान एलटीआरओ और टीएलटीआरओ (आंशिक रूप से) की परिपक्वता से अपेक्षित चलनिधि निकासी की भरपाई करने में मदद मिलेगी।[17]

भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) ने जनवरी 2023 के अंत में एलएएफ कॉरिडोर की ऊपरी सीमा को कुछ समय के लिए छुआ, लेकिन बाद में उसमे कमी आई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, डब्ल्यूएसीआर का औसत 6.28 प्रतिशत था, जो नीतिगत रेपो दर के करीब (औसतन) कारोबार कर रहा था (चार्ट 42 ए)। मांग बाजार में गतिविधियों में तेजी आई और 16 जनवरी से 8 फरवरी, 2023 के दौरान औसत दैनिक मात्रा 14,420 करोड़ रुपये रही, जो 13 दिसंबर, 2022 से 15 जनवरी, 2023 के दौरान 11,343 करोड़ रुपये थी।

इसके साथ ही, संपार्श्विक खंड में दरें भी मजबूत हुई - जबकि त्रिपक्षीय रेपो दर नीति रेपो दर से 4 बीपीएस नीचे कारोबार करती है, बाजार रेपो दरें नीति रेपो दर के करीब कारोबार करती हैं। मियादी मुद्रा खंड में, 3 महीने के ख़जाना बिल (टी-बिल) पर दर एमएसएफ दर से 7 बीपीएस नीचे कारोबार करती है, जबकि एनबीएफसी के लिए जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) के लिए 3 महीने की दरें एमएसएफ दर से ऊपर क्रमशः 67 बीपीएस और 102 बीपीएस थीं (चार्ट 42 बी)।

वर्ष के दौरान अब तक (13 जनवरी तक) प्राथमिक बाजार में सीडी निर्गम के जरिये 5.2 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रहा जो पिछले साल की संबंधित अवधि के 1.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक है जो बैंकों की बढ़ते ऋण उठाव के कारण धन

[17] 13,517 करोड़ रुपये फरवरी-मार्च 2023 में परिपक्व होंगे और 61,131 करोड़ रुपये अप्रैल 2023 में परिपक्व होंगे।

चार्ट 43: जी-सेक बाजार में घटनाक्रम

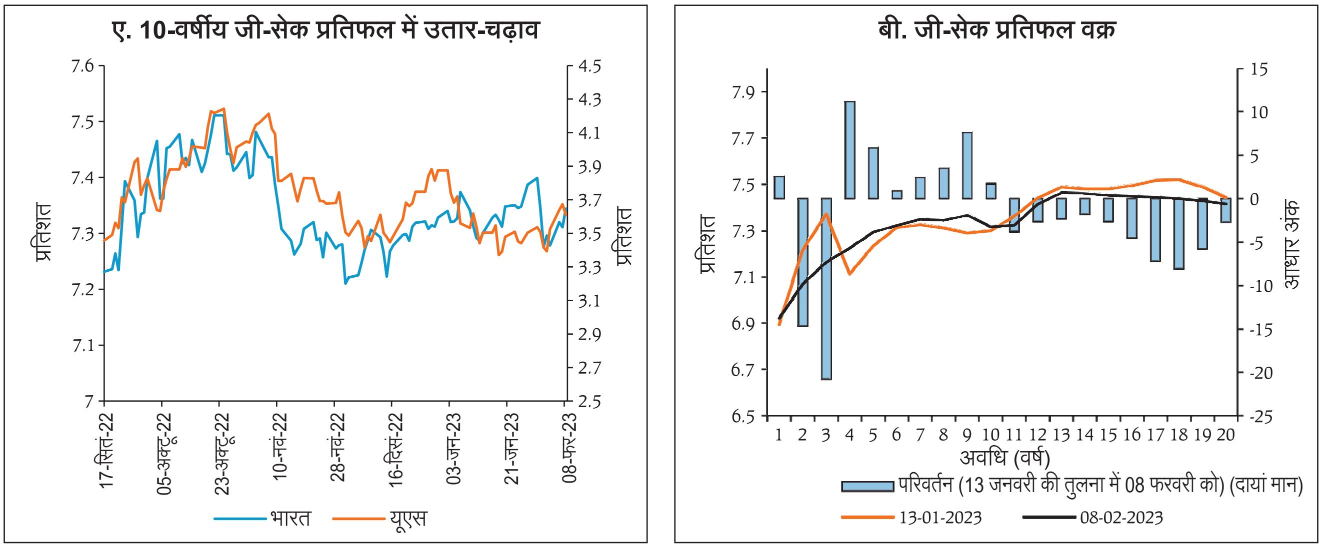

स्रोत: ब्लूमबर्ग; सीसीआईएल; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

की अतिरिक्त मांग को दर्शाता है। । सीपी निर्गम वर्ष के दौरान अब तक (15 जनवरी तक) घटकर 10.9 लाख करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल की संबंधित अवधि में 17.2 लाख करोड़ रुपये था, बैंक ऋण की सहायता से धन जुटाने के पसंदीदा साधन के रूप में उभर रहा है। मुद्रा बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (3 महीने का सीपी माइनस 91-दिन ट्रेजरी बिल) इस अवधि के दौरान 110 बीपीएस पर ऊंचा रहा, जो अधिशेष चलनिधि में कमी को दर्शाता है।

केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय समेकन की प्रतिबद्धता और अनुमानित सकल बाजार उधारी से कम की घोषणा के जवाब में 10-वर्षीय बेंचमार्क जी-सेक यील्ड में कमी आई (चार्ट 43 ए)। कारोबार के दौरान 7.40 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद बजट घोषणा के दिन यानी एक फरवरी, 2023 को कारोबारी सत्र के अंत तक बेंचमार्क प्रतिफल घटकर 7.28 प्रतिशत पर आ गया। इसके बाद जी-सेक यील्ड ने अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड के साथ मिलकर सख्त पूर्वाग्रह का प्रदर्शन किया और 7.34 फीसदी पर बंद हुआ। इस मियादी संरचना में, जी-सेक प्रतिफल में उपज वक्र के छोटे छोर पर तेजी से नरमी आई, जो आगे चलकर कम दर वृद्धि की उम्मीदों का संकेत है (चार्ट 43 बी)।

कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल और स्प्रेड रेटिंग श्रेणियों में कठोर हो गया है, विशेष रूप से 3-5 साल की परिपक्वता के लिए जहां निर्गम ज्यादातर केंद्रित होते हैं (सारणी 4)। कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने के जरिये जुटाया गया धन दिसंबर में बढ़कर 1.37 लाख

सारणी 4: वित्तीय बाजार - दरें और स्प्रेड

लिखत	ब्याज दर (प्रतिशत)			स्प्रेड (आधार अंक) (तदनुरूपी जोखिम-मुक्त दर की तुलना में)		
	13 दिसं 2022-15 जन 2023	16 जन 2023-07 फर 2023	उतार-चढ़ाव (आधार अंकों में)	13 दिसं 2022-15 जन 2023	16 जन 2023-07 फर 2023	उतार-चढ़ाव (आधार अंकों में)
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉरपोरेट बॉण्ड						
(i) एएए (1-वर्ष)	7.87	7.87	0	91	88	-3
(ii) एएए (3- वर्ष)	7.77	7.79	2	59	62	3
(iii) एएए (5- वर्ष)	7.76	7.86	10	40	52	12
(iv) एए (3- वर्ष)	8.49	8.49	0	130	132	2
(v) बीबीबी- (3- वर्ष)	12.14	12.13	-1	496	497	1

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना मासिक औसत के रूप में की जाती है।
स्रोत: एफआईएमएमडीए; और ब्लूमबर्ग।

करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो नवंबर, 2022 में 0.77 लाख करोड़ रुपये था। बॉन्ड बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (5 साल एएए माइनस 5 साल जी-सेक) 16 जनवरी से 8 फरवरी, 2023 के दौरान 52 बीपीएस तक बढ़ गया, जो 13 दिसंबर, 2022 से 15 जनवरी, 2023 के दौरान 40 बीपीएस था।

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर आरक्षित धन (आरएम) 10 फरवरी, 2023 को 8.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) (एक साल पहले 7.7 प्रतिशत) बढ़ा [चार्ट 44 ए]। आरएम के सबसे बड़े घटक संचलन में मुद्रा (सीआईसी) में 8.15 फीसदी (पिछले साल 8.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। मुद्रा आपूर्ति (एम3) में 27 जनवरी, 2023 को 9.8 प्रतिशत (पिछले साल 8.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से बैंकों के साथ इसके सबसे बड़े घटक - कुल जमा - से प्रेरित थी, जिसमें 10.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि 27 जनवरी, 2023 को 16.3 प्रतिशत (पिछले साल 8.2 प्रतिशत) पर बनी रही। जमा संग्रहण में तेजी के साथ, दिसंबर 2022 के मध्य से वृद्धिशील सी-डी अनुपात में कमी आई है (चार्ट 44 बी)।

बैंकों ने मई 2022 से जनवरी 2023 के दौरान अपनी बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दरों (ईबीएलआर) को 225 बीपीएस के परिमाण तक संशोधित किया है। एससीबी की 1 साल की औसत सीमांत लागत आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) में 120 बीपीएस की वृद्धि हुई है। नतीजतन, एससीबी के नए और बकाया रुपये के ऋणों पर भारित औसत उधार दरें (डब्ल्यूएएलआर) मई-दिसंबर 2022 के दौरान क्रमशः 137 बीपीएस और 80 बीपीएस तक बढ़ गईं। इसी अवधि के दौरान अनुसूचित बैंकों की बकाया जमाराशियों पर भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में 75 आधार अंकों की वृद्धि हुई (सारणी 5)।

भारत सरकार ने 30 दिसंबर, 2022 को 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की दरों को 20 से 110 बीपीएस की सीमा में संशोधित किया, जिसमें सावधि जमा में सबसे अधिक वृद्धि हुई (चार्ट 45)। 3 साल तक की अवधि की पोस्ट ऑफिस सावधि जमा पर ब्याज दरें अब फॉर्मूला-आधारित दरों के साथ निकटता से संरेखित हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में एक नई योजना, यानी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की घोषणा की गई थी, जो महिला जमाकर्ताओं के लिए 7.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर पर 2 साल की अवधि के लिए 2 लाख रुपये तक की जमा सुविधा प्रदान करेगी। बैंकों द्वारा दी जाने वाली सावधि जमा दरें सामान्य रूप से, 3 साल तक की परिपक्वता अवधि के लिए समान परिपक्वता वाली छोटी बचत जमाओं की तुलना में कम हैं।

चार्ट 44: मौद्रिक और ऋण स्थितियां

ए. मौद्रिक और ऋण समुच्चय में रुझान

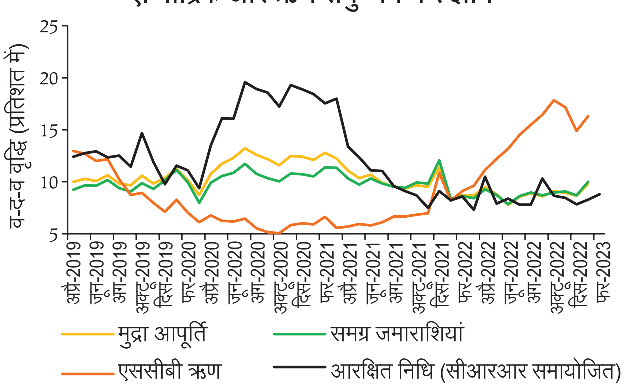

टिप्पणी: 1. डेटा मुद्रा आपूर्ति, समग्र जमाराशियों और बैंक ऋण के लिए हर महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार; और आरक्षित निधि के लिए हर महीने के अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
2. आरक्षित निधि के नवीनतम आंकड़े 10 फरवरी 2023; जबकि मुद्रा आपूर्ति के लिए 27 जनवरी 2023 से से संबंधित हैं।

स्रोत: आरबीआई।

बी. वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात

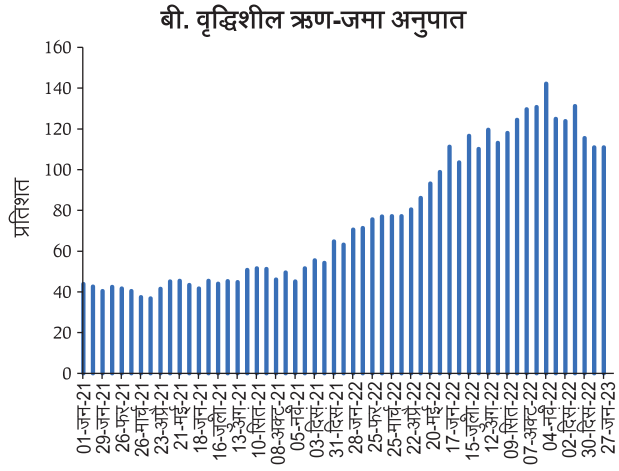

टिप्पणी: वृद्धिशील सी-डी अनुपात की गणना 26 पखवाड़ों (1 वर्ष) में की गई है।

स्रोत: आरबीआई।

सारणी 5: बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार अंकों में भिन्नता)

अवधि	रेपो दर (आधार अंक)	मीयादी जमा दरें (आधार अंक)		उधार दरें (आधार अंक)		
		माध्यिका अवधि जमाराशि दरें (कार्ड दर)	डब्ल्यूएडीटीडी-आर - बकाया जमाराशियां	1-वर्षीय एमसीएलआर (माध्यिका)	डब्ल्यूएएलआर – नया रुपया ऋण	डब्ल्यूएएलआर - बकाया रुपया ऋण
सहजता का दौर फरवरी 2019 से मार्च 2022	-250	-208	-188	-155	-232	-150
सख़्ती का दौर मई 2022 से जनवरी 2023*	+225	78	75	120	137	80

टिप्पणी: *: डब्ल्यूएएलआर और डब्ल्यूएडीटीडीआर पर अद्यतन डेटा दिसंबर 2022 से संबंधित है;
2. डब्ल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर; डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर; एमसीएलआर: निधि-आधारित उधार दर की सीमांत लागत।
स्रोत: आरबीआई।

जनवरी 2023 की पहली छमाही में सीमित रहने के बाद, कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर में कमी के बाद, घरेलू इक्विटी बाजार शुरू में दूसरी छमाही में ऊपर चले गए। एक व्यापारिक समूह के शेयरों में असामान्य मूल्य उतार-चढ़ाव के बाद महीने के अंत में भावनाएं नकारात्मक हो गईं। कुल मिलाकर, एफपीआई के शुद्ध विक्रेता बनने के साथ, बीएसई सेंसेक्स में जनवरी 2023 के दौरान 2.1 प्रतिशत की गिरावट आई (चार्ट 46)। फिर भी, केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजीगत व्यय में वृद्धि और चुनिंदा प्रत्यक्ष कर राहत[18] से संबंधित घोषणाएं, वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा घरेलू वित्तीय और व्यापक आर्थिक स्थितियों की सुदृढ़ता की पुन: पुष्टि करने वाले बयानों ने बाजार की भावनाओं को बढ़ावा देने में मदद की। बीएसई सेंसेक्स फरवरी 2023 (15 फरवरी, 2023 तक) के दौरान 2.9 प्रतिशत ऊपर उठा।

चार्ट 45: अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज दरें

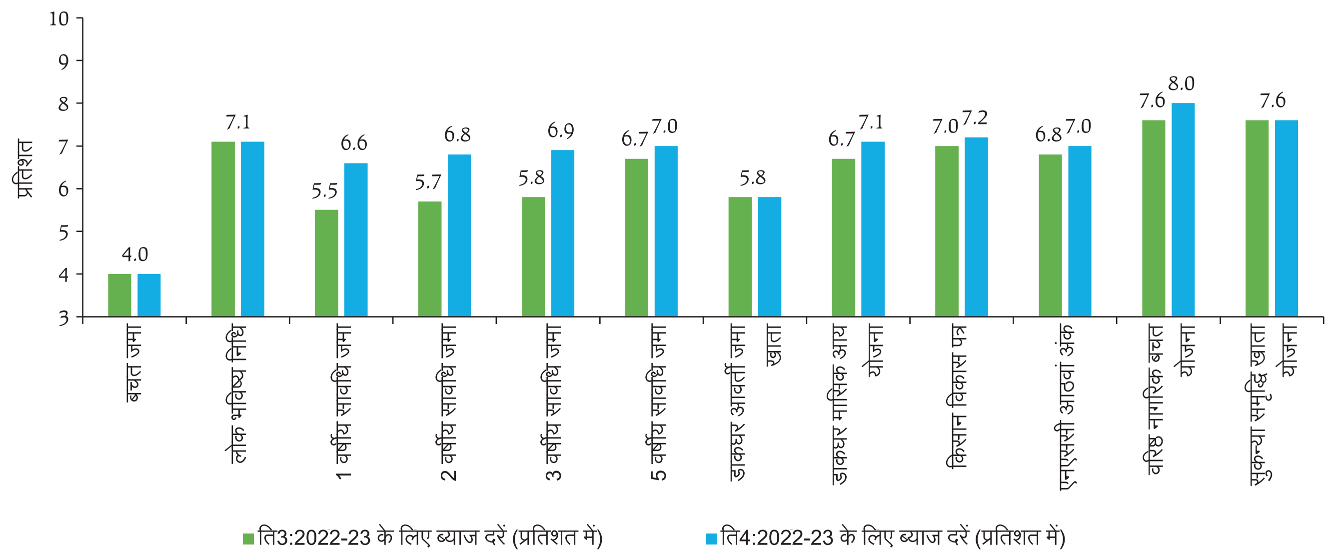

स्रोत: भारत सरकार।

[18] वित्त मंत्री ने नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कई बदलावों का प्रस्ताव किया, जैसे एमएसएमई, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप के लिए कर लाभ के साथ आयकर में छूट के लिए आय सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करना, कर स्लैब को युक्तिसंगत बनाना, वेतनभोगी वर्ग के लिए मानक कटौती का प्रावधान, उच्चतम अधिभार दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करना,आदि। इन उपायों से प्रत्यक्ष कर राजस्व में 37,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने की उम्मीद है।

चार्ट 46: बीएसई सेंसेक्स और संस्थागत प्रवाह

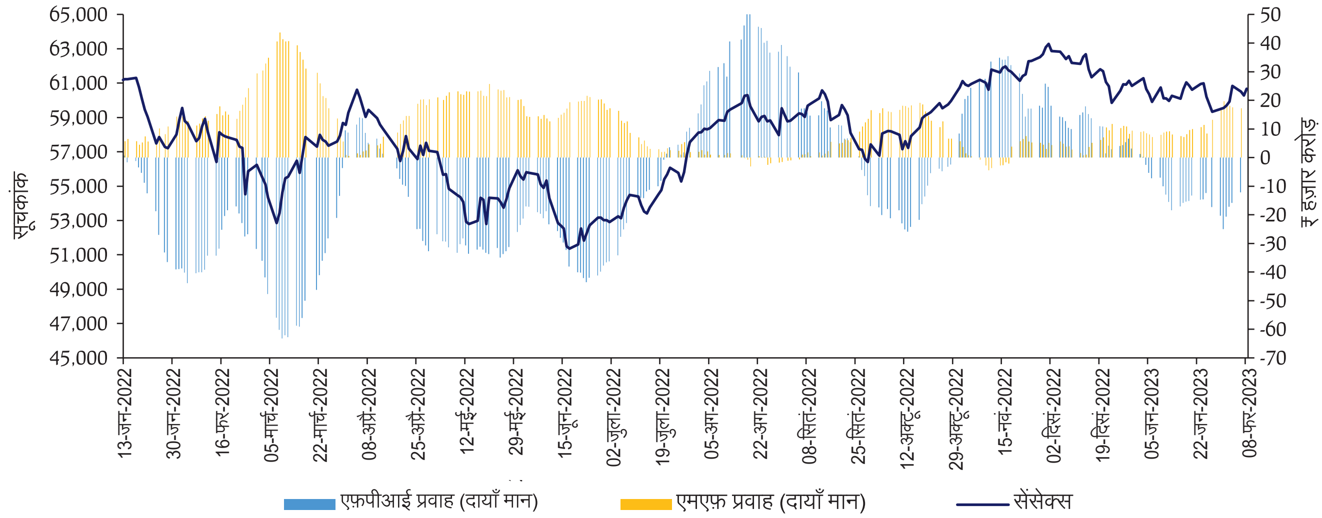

टिप्पणी: एफपीआई और एमएफ प्रवाह को 15-दिनों के रोलिंग सम आधार पर दर्शाया गया है।
स्रोत: सेबी; एनएसडीएल; और ब्लूमबर्ग।

भारतीय इक्विटी बाजार ने 27 जनवरी, 2023 को तेजी से निपटान व्यवस्था में अपना संक्रमण पूरा किया, जिसमें इक्विटी खंड की सभी प्रतिभूतियां टी + 1 निपटान में चली गईं। यह सितंबर 2021 में शुरू हुई एक प्रक्रिया की परिणति का प्रतीक है, जिससे भारत सबसे छोटे निपटान चक्रों के साथ वैश्विक नेताओं में से एक बन गया है जो निपटान, प्रतिपक्ष और संचालन से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद करेगा और व्यापर मात्रापर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

2022-23 की तीसरी तिमाही के लिए 1,109 गैर-वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों[19] द्वारा घोषित कॉर्पोरेट आय परिणामों से पता चला है कि कंपनियों की राजस्व वृद्धि में कमी देखी गई (चार्ट 47 ए)। व्यय में वृद्धि के बावजूद, अन्य आय द्वारा समर्थित वर्ष-दर-वर्ष आधार पर परिचालन लाभ में मामूली सुधार हुआ। इनपुट लागत दबाव कम होने से परिचालन लाभ मार्जिन में क्रमिक आधार पर सुधार देखा गया। अन्य आय, जिसमें कॉर्पोरेट्स की ख़जाना प्रबंधन गतिविधियों से आय शामिल है, ने वृद्धि दर्शायी। कुल मिलाकर गैर-वित्तीय कंपनियों की निवल लाभ वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) लगातार दूसरी तिमाही में नकारात्मक रही। सेवा क्षेत्र ने बिक्री और परिचालन लाभ में ठोस वृद्धि दर्ज की। उच्च ब्याज लागत और मुख्य रूप से लोहा और इस्पात उद्योग में अन्य खर्च से विनिर्माण कंपनियों के शुद्ध मुनाफे में 18.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई [चार्ट 47 बी]।

बैंकों और अन्य वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों[20] की आय ठोस बनी हुई है और ऋण वृद्धि द्वारा समर्थित राजस्व (वर्ष-दर-वर्ष) में ठोस दो अंकों की वृद्धि हुई है (चार्ट 48)। अन्य आय, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षा लेनदेन, शुल्क और कमीशन से लाभ/हानि शामिल है, में भी तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। टॉप-लाइन की तुलना में व्यय धीमी गति से बढ़ने के साथ, परिचालन मुनाफे में वृद्धि हुई। प्रावधान लागत सालाना आधार पर समतल पर रही और बदले में बैंकों और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के कुल निवल मुनाफे में ठोस वृद्धि दर्ज की गई।

---

[19] प्रारंभिक परिणाम 2021-22 की तीसरी तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट व्यवसाय क्षेत्र के प्रदर्शन' पर आरबीआई के अध्ययन में शामिल कुल बिक्री आकार का 74.3 प्रतिशत कवर करते हैं।

[20] 862 बैंकों और अन्य वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के परिणामों के आधार पर, जो बाजार पूंजीकरण का लगभग 89 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं।

चार्ट 47: कॉरपोरेट प्रदर्शन

ए. सूचीबद्ध गैर-वित्तीय कंपनियों का प्रदर्शन

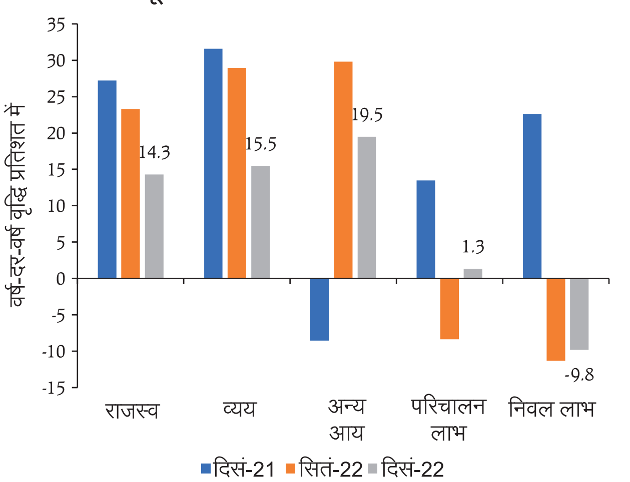

स्रोत: कैपिटलाइन; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

बी. ति3:2022-23 में क्षेत्रवार प्रदर्शन

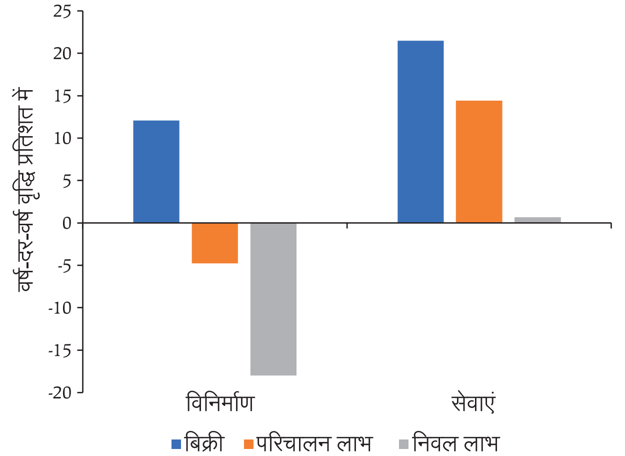

* 726 विनिर्माण और 274 सेवा कंपनियों के तिमाही परिणामों के आधार पर।

स्रोत: कैपिटलाइन; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) एक साल पहले के 61.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 55.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया (चार्ट 49)। इस अवधि के दौरान निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक वर्ष पूर्व के 248 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 223 बिलियन अमरीकी डालर रहा, जो मुख्य रूप से इक्विटी अंतर्वाह में गिरावट को दर्शाता है। अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं, कंप्यूटर सेवाओं, खुदरा और थोक व्यापार और संचार सेवाओं द्वारा एफडीआई इक्विटी प्रवाह का बड़ा हिस्सा प्राप्त किया गया था। अमेरिका, सिंगापुर और मॉरीशस इस अवधि के दौरान एफडीआई के प्रमुख स्रोत देश थे।

चार्ट 48: सूचीबद्ध वित्तीय कंपनियों का प्रदर्शन

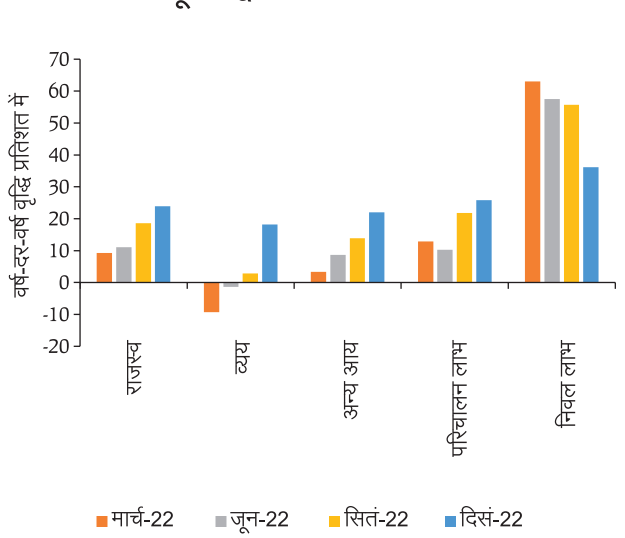

टिप्पणी: असाधारण मदें शामिल नहीं हैं।

स्रोत: सीएमआईई प्रोवेस और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट 49: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

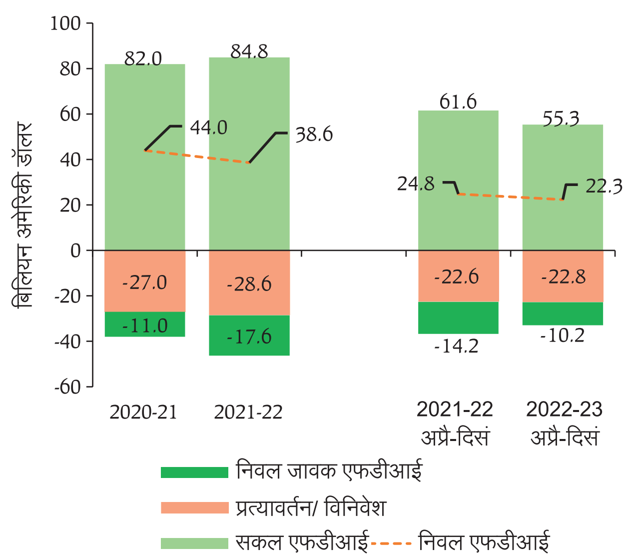

स्रोत: आरबीआई।

2023-24 में एफडीआई दृष्टिकोण के लिए केंद्रीय बजट का 'बुनियादी ढांचा और निवेश' और 'हरित विकास' का विषय अच्छा संकेत है। भारत 'एफडीआई स्टैंडआउट वॉचलिस्ट' में दूसरे स्थान पर है जो दुनिया के शीर्ष 50 एफडीआई गंतव्यों के एफडीआई प्रक्षेपवक्र का आकलन करता है।[21]

एफपीआई जनवरी 2023 में घरेलू पूंजी बाजारों में निवल विक्रेता बन गए (चार्ट 50)। इक्विटी खंड की अगुवाई में जनवरी 2023 में भारत से निवल एफपीआई बहिर्वाह 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। हालांकि, जनवरी 2023 के दौरान ऋण खंड में 0.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश देखा गया। वित्तीय सेवाओं, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों, और धातु और खनन क्षेत्रों ने इक्विटी बाजार में पोर्टफोलियो निवेश का बड़ा हिस्सा आकर्षित किया। दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोग्य ईंधन और पूंजीगत सामान शेयरों में विनिवेश की सूचना मिली।

अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) पंजीकरण राशि[22] 20.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 24.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। वर्ष के दौरान के संचालनों से पता चलता है कि 2022-23 की पहली तिमाही में गिरावट के बाद, पंजीकरण राशि में तेजी आई, जो आंशिक रूप से 6 जुलाई, 2022 को रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित उदारीकरण उपायों द्वारा समर्थित थी। हालांकि अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान भारत को ईसीबी का सकल संवितरण 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, लेकिन उच्च पुनर्भुगतान के कारण निवल ईसीबी ऋणात्मक हो गया, और हाल ही में, ईसीबी पंजीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बाद में तैयार किया जाना निर्धारित किया गया (चार्ट 51)।

चार्ट 50: निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश

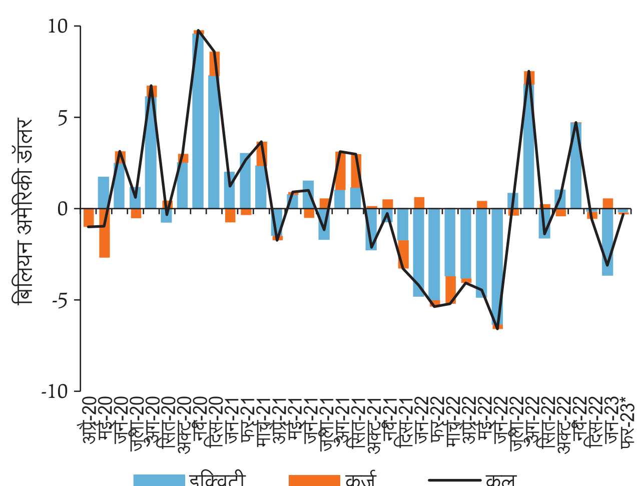

*: 13 फरवरी 2023 तक।
टिप्पणी: कर्ज में स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) और संकर (हाइब्रिड) लिखतों के तहत निवेश शामिल हैं।
स्रोत: नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड।

चार्ट 51: ईसीबी - पंजीकरण, अंतर्वाह और बहिर्वाह

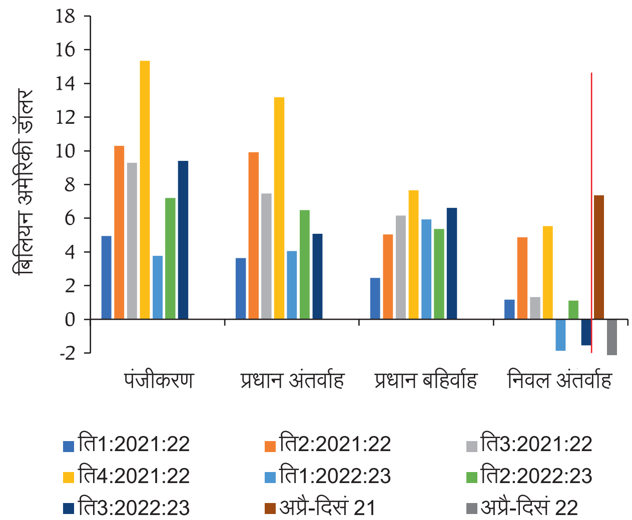

स्रोत: आरबीआई।

अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान ईसीबी समझौते की राशि के तीन-चौथाई से अधिक प्रभावी रूप से हेजिंग रहे और शेष में स्वाभाविक हेज के साथ ऋण शामिल थे (यानी, उधारकर्ताओं की आय विदेशी मुद्रा में है) [चार्ट 52]।

सितंबर 2022 के अंत से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 42.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गया और 3 फरवरी, 2023 को 575.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें 2022-23 के लिए अनुमानित नौ महीने से अधिक आयात शामिल है (चार्ट 53)।

[21] एफडीआई आउटलुक 2023, एफडीआई इंटेलिजेंस।

[22] पंजीकरण राशि ईसीबी मार्ग के माध्यम से स्वीकृत उधार राशि को ले लेती है।

चार्ट 52: ईसीबी करार – बचाव-व्यवस्था की स्थिति

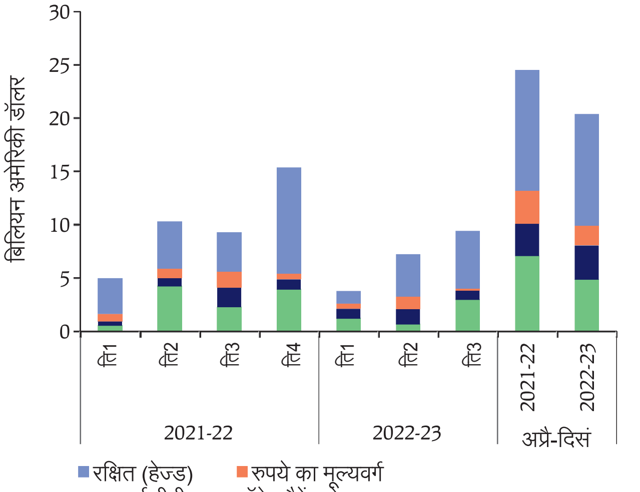

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट 53: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

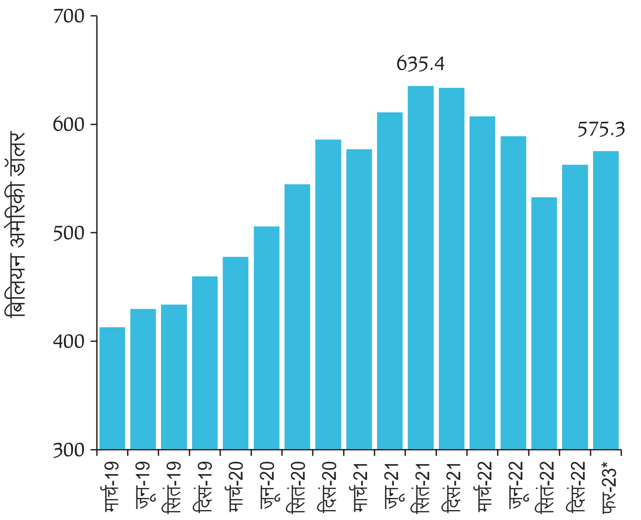

*: 03 फरवरी 2023 तक।
स्रोत: आरबीआई।

विदेशी मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपया (आईएनआर) जनवरी 2023 में अमेरिकी डॉलर (एम-ओ-एम) की तुलना में 0.7 प्रतिशत बढ़ गया, क्योंकि अमेरिकी फेड ने कम आक्रामक रुख अपनाया और अमेरिकी डॉलर में 1.7 प्रतिशत की गिरावट आई (चार्ट 54)। रुपये का प्रदर्शन कई अन्य ईएमई और आरक्षित मुद्राओं के अनुरूप था।

40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में, जनवरी 2023 में आईएनआर में 0.4 प्रतिशत की गिरावट आई (एम-ओ-एम) (चार्ट 55)।

चार्ट 54: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले प्रमुख मुद्राओं में उतार-चढ़ाव (जनवरी 2023, माह-दर-माह)

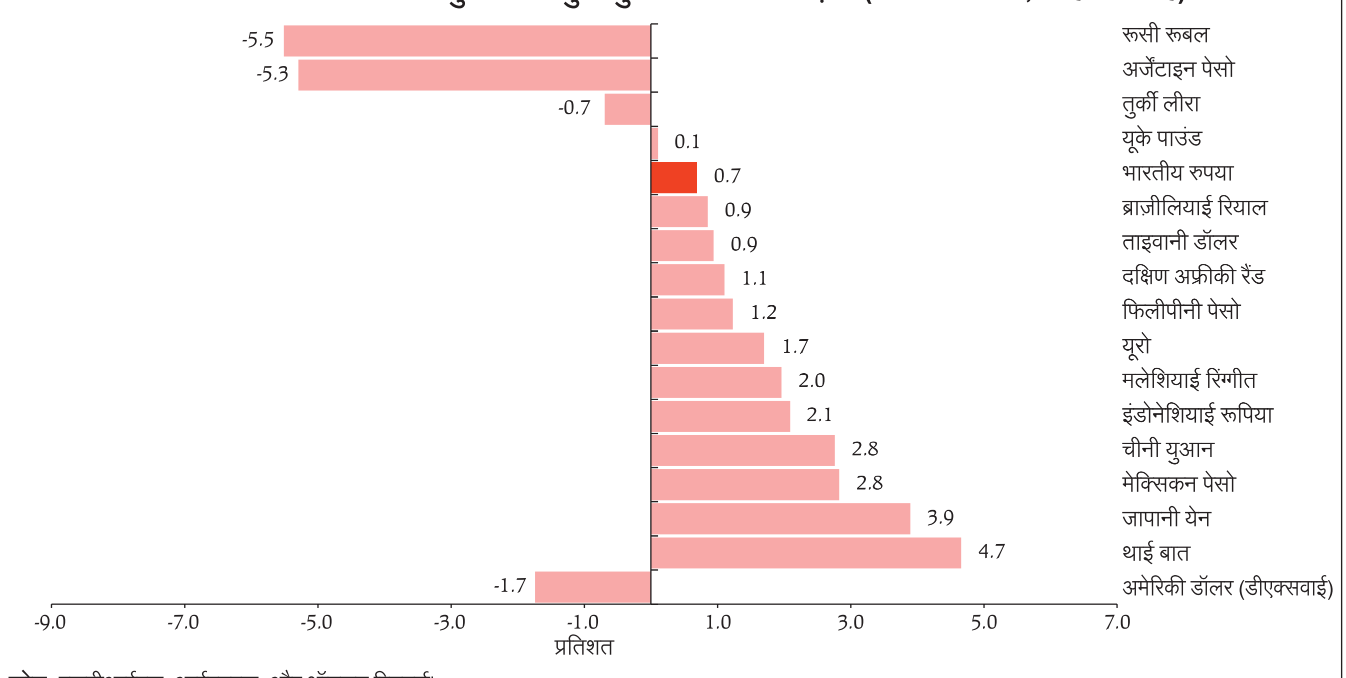

स्रोत: एफबीआईएल; आईएमएफ; और थॉमसन रियूटर्स।

चार्ट 55: 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव

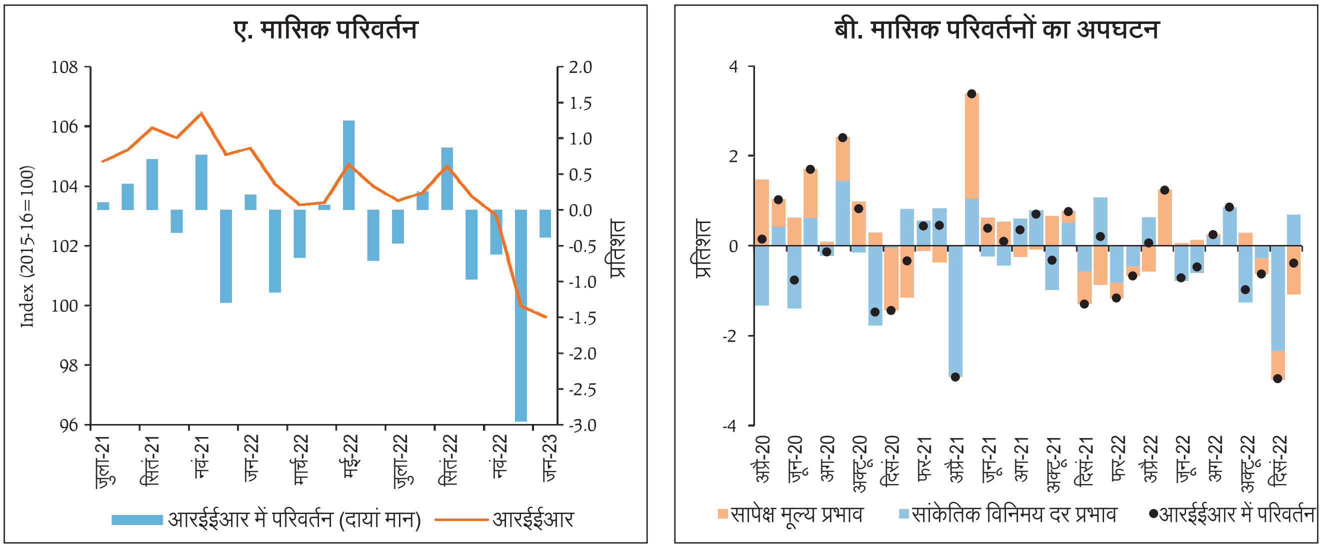

स्रोत: आरबीआई।

भुगतान प्रणाली

डिजिटल लेनदेन विभिन्न तरीकों से उन्नत हुआ और एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) के नेतृत्व में खुदरा क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनी रही [सारणी 6]। आपूर्ति पक्ष में, भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना के तहत परिनियोजित भुगतान स्वीकृति उपकरणों की संख्या अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान 59 प्रतिशत बढ़ी।

8 फरवरी, 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में बीमा कंपनियों और फैक्टरिंग व्यवसाय करने वाली एजेंसियों की भागीदारी की अनुमति देकर और टीआरईडीएस प्लेटफार्मों पर द्वितीयक बाजार संचालन को सक्षम करके व्यापार प्राप्ति छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) से संबंधित गतिविधि के दायरे का विस्तार करने के उपायों का प्रस्ताव किया गया है। इसमें भारत आने वाले सभी यात्रियों के लिए यूपीआई (मर्चेंट भुगतान के लिए) के विस्तार का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने 10 देशों के अनिवासी भारतीयों को यूपीआई प्लेटफॉर्म पर शामिल करने में समर्थ बनाया है।[23] डिजिटल प्रणाली के बढ़ते अंगीकरण के प्रमाण के रूप में, हाल ही में, जारी रिज़र्व बैंक के डिजिटल भुगतान सूचकांक

सारणी 6: चुनिंदा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि दरें

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत में)

भुगतान प्रणाली संकेतक	लेन-देन की मात्रा				लेन-देन के मूल्य			
	दिसं-21	दिसं-22	जन-22	जन-23	दिसं-21	दिसं-22	जन-22	जन-23
आरटीजीएस	17.9	11.5	15.7	12.6	21.7	5.9	13.9	20.1
एनईएफटी	22.3	29.0	26.2	32.2	6.5	9.4	12.8	15.0
यूपीआई	104.4	71.4	100.5	74.1	98.7	55.0	93.0	56.1
आईएमपीएस	24.5	9.7	27.0	7.8	35.6	22.7	34.1	23.4
एनएसीएच	-2.7	10.5	28.8	-10.4	5.1	34.5	26.4	14.4
एनईटीसी	74.9	27.2	54.8	30.2	59.7	34.3	50.0	33.6
बीबीपीएस	137.0	60.4	130.2	59.8	165.2	63.6	148.8	66.6

स्रोत: आरबीआई।

[23] एनपीसीआई परिपत्र, जनवरी 2023।

(आरबीआई-डीपीआई) ने सितंबर 2022 में 24.1 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) दिखाई। 2023 में, भारत में डिजिटल भुगतान की उपयोगकर्ता प्रवेश दर दुनिया की तुलना में अधिक होने की उम्मीद है।[24]

केंद्रीय बजट 2023-24 में मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए विभिन्न उपायों की भी घोषणा की गई है। इनमें डिजिटल भुगतान मोड को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 1500 करोड़ रुपये का राजकोषीय समर्थन जारी रखना, एक कृषि त्वरक निधि की स्थापना करना, राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस नीति के माध्यम से अनाम डेटा तक सुरक्षित पहुंच को सक्षम करना, डिजीलॉकर[25] के माध्यम से उपलब्ध दस्तावेजों के दायरे का विस्तार करना, व्यवसायों द्वारा जानकारी संग्रहीत करने और साझा करने के लिए एक 'एंटिटी डिजीलॉकर' बनाना, डिजिटल क्षमताओं को विकसित करने के लिए एमएसएमई को प्रशिक्षित करना शामिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, 5 जी सेवाओं का उपयोग करके एप्लिकेशन विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना और अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) प्रक्रिया को सरल बनाना।

निष्कर्ष

हमारा मानना है कि भारत मौजूदा पुराने और शेष विश्व के वृहद आर्थिक अनुमानों से अलग हो जाएगा। हमारे विचार में, (क) 2023-27 की अवधि में भारत की विकास संभावनाओं और (ख) भारत के संभावित विकास को बढ़ाते हुए अलगीकरण का साधन केंद्रीय बजट होगा।

तात्कालिक विकास संभावनाओं को देखें, तो केंद्रीय बजट को कई मामलों में सभी पक्षों से सराहना मिली है। समेकन और पूंजीगत व्यय पर किए गए वादों के अलावा, बजट में प्रस्तावित कर परिवर्तनों से परिवारों के हाथों में कम से कम 35,000 करोड़ रुपये आएंगे। विकास के दृष्टिकोण पर इन तीन पहलुओं के निहितार्थ गहरे हैं। सबसे पहले, करों पर बचत से उपभोग पर परिवारों द्वारा खर्च को बढ़ावा मिलेगा। भारत की उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति (एमपीसी) 0.54 होने का अनुमान है, कर गुणक 1.16 है। इसलिए, भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 2023-24 में अकेले कर कटौती से 15 आधार अंकों की वृद्धि मिलेगी।

दूसरा, 2023-24 में पूंजीगत व्यय के लिए आवंटन में वृद्धि (राज्यों को ऋण सहायता, रेलवे, रसद और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान सहित, जिन्हें प्रभावी राजस्व घाटे के तहत बाहर रखा गया है और इसलिए पूंजी खाते में जोड़ा गया है) 3.2 लाख करोड़ रुपये है।[26] यह बढ़ा हुआ पूंजीगत व्यय 2023-27 के दौरान 10.3 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन उत्पन्न करेगा - कर गुणक के विपरीत जिसका अल्पकालिक प्रभाव पड़ता है, गतिशील पूंजीगत व्यय गुणक पहले वर्ष में 1 से बढ़कर दूसरे वर्ष में 2.45, तीसरे वर्ष में 3.14 और 2026-27 में 3.25 चरम पर पहुंच जाता है। रेलवे पर पूंजीगत व्यय और राज्यों को ऋण सहायता इस बढ़ी हुई आय का 43 प्रतिशत योगदान देगी, जबकि रसद में निवेश (60,000 करोड़ रुपये) से 2023-27 में 1.95 लाख करोड़ रुपये या बढ़ी हुई आय का 19 प्रतिशत उत्पन्न होने की उम्मीद है।

तीसरा, राजकोषीय समेकन निजी क्षेत्र के लिए उत्पादक संसाधनों को मुक्त कर सकता है और पूंजी की लागत को कम करने में भी योगदान दे सकता है। केंद्रीय बजट में कुल व्यय में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 0.41 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया है।[27] इससे निजी निवेश के लिए संसाधन मुक्त होंगे। व्यय गुणक के संयोजन के साथ, यह 2023-24 में अर्थव्यवस्था की विकास दर को 10 आधार अंकों तक बढ़ा सकता है।[28]

इन सभी को एक साथ रखने और आर्थिक सर्वेक्षण के 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के अनुमान को आधार के रूप में लेते हुए, केंद्रीय बजट के कर, पूंजीगत व्यय और राजकोषीय समेकन प्रस्तावों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर, वे 2023-24 में भारत

[24] स्रोत: स्टेटिस्टा डेटाबेस 03 फरवरी, 2023 तक एक्सेस किया गया।

[25] डिजीलॉकर नागरिकों के दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म है।

[26] केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 2022-23 (संशोधित अनुमान) के 10.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 (बीई) में 13.7 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।

[27] 2023-24 (बजट अनुमान) में कुल व्यय पिछले वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 15.33 प्रतिशत से घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 14.92 प्रतिशत होने का अनुमान है, जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद के 0.41 प्रतिशत की गिरावट आई है।

[28] कारोबार चक्र के विस्तारवादी चरण में व्यय गुणक का अनुमान चार तिमाहियों में (-) 0.22 है, जबकि मंदी की अवधि में सकारात्मक व्यय गुणक होता है जब निजी क्षेत्र की ऋण की मांग आम तौर पर कमजोर हो जाती है (मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट, 2022)।

की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 7.0 प्रतिशत के करीब ले जा सकते हैं।

भारत की क्षमता को देखें, तो केंद्रीय बजट (क) पूंजीगत व्यय पर जोर देकर; (ख) डिजिटलीकरण और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने जैसी नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके; और (ग) जनसांख्यिकीय लाभांश जो एक साथ मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना सीमा का विस्तार कर सकता है, को जब्त करके अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता का विस्तार करेगा। सबसे पहले, पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर देने के अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस नीति और केवाईसी मानदंडों के सरलीकरण से उत्पादकता को सकारात्मक झटका लग सकता है और कुल कारक उत्पादकता (टीएफपी) में वृद्धि हो सकती है जो प्रति वर्ष 10 आधार अंकों की संभावित वृद्धि को बढ़ा सकती है।

दूसरा, केंद्रीय बजट भाषण में हरित विकास प्राथमिकता के तहत 12 योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें चार योजनाओं के तहत पहले से ही उल्लिखित 85 हजार करोड़ रुपये का ठोस परिव्यय है।[29] इससे 2030 तक 1.7 लाख करोड़ रुपये के निजी निवेश (2 का क्राउड-इन फैक्टर लेते हुए)[30] में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे कुल हरित निवेश को 2.6 लाख करोड़ रुपये तक ले जाया सकता है और जीडीपी में 3.3 लाख करोड़ रुपये या संभावित उत्पादन के लगभग 100 आधार अंकों की वृद्धि हो सकती है। भौतिक और डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना के साथ-साथ युवाओं और शिक्षकों को कुशल बनाकर जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने से संभावित जीडीपी वृद्धि 5 आधार अंकों से बढ़कर 15 आधार अंक प्रति वर्ष हो सकती है।[31]

राजकोषीय समेकन से उत्पन्न व्यापक आर्थिक स्थिरता का माहौल और इसलिए ऋण में कमी से मध्यम अवधि में मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक आर्थिक अस्थिरता और देश के जोखिम प्रीमियम में कमी आएगी, जिससे एक अच्छे चक्र की शुरुआत होगी। अनुमानों से पता चलता है कि एकल आधार पर, यानी मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को ध्यान में रखे बिना, इससे अगले पांच वर्षों में मुद्रास्फीति में प्रति वर्ष औसतन 26 आधार अंकों की कमी हो सकती है[32], जो बदले में, संभावित विकास को और 10 आधार अंक तक बढ़ा देगी।[33]

इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, संभावित वृद्धि 6.0 प्रतिशत (2022-23 में आईएमएफ द्वारा अनुमानित[34]) से बढ़कर 6.8 प्रतिशत होने की उम्मीद है।[35] बजट में घोषित उपायों के कारण भारत की संभावित वृद्धि में बढ़ोतरी के साथ, 2027-28 तक सकल घरेलू उत्पाद के 54.3 प्रतिशत तक केंद्र सरकार के ऋण का तेजी से समेकन होने की संभावना है।

सभी संस्कृतियो की पौराणिक कथाओं में, सूर्य को आमतौर पर चार घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ की सवारी के रूप में चित्रित किया गया है। उदाहरण के लिए, ग्रीस में अपोलो के लिए ऐसा है; मिस्र में रा; रोम में सोल। भारतीय पौराणिक कथाओं में, हालांकि, सूर्य का रथ सात घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। घोड़ों के अर्थ बारे में कई व्याख्याएं उपलब्ध हैं –विभिन्न शास्त्र उन्हें इंद्रधनुष के सात रंग प्रदान करते हैं; सात वैदिक मान या छंद; और इसी तरह अन्य । सातवां घोड़ा सपनों, आकांक्षाओं और भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है कि अगर अन्य छह घोड़े घायल या थक भी जाते हैं, तो भी सातवां घोड़ा सूर्य के रथ को उसके गंतव्य तक ले जा सकता है। यह डॉ. धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध पुस्तक का विषय है और श्याम बेनेगल की इसी नाम की फिल्म का विषय भी है, जिसका नाम सूरज का सातवां घोड़ा है। हमारे विचार में, केंद्रीय बजट 2023-24 सूर्य का सातवां घोड़ा है।

[29] बजट में हरित हाइड्रोजन मिशन, ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा निकासी, हरित ऋण कार्यक्रम, पीएम-प्रणाम, गोबरधन योजना, भारतीय प्रकृतिक खेती जैव-इनपुट संसाधन केंद्र, तटरेखा पर्यावासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी), अमृत धरोहर, तटीय शिपिंग और वाहन प्रतिस्थापन सहित 12 प्रस्तावों को रेखांकित किया गया है।

[30] आईईए (2012), आईएमएफ (2021), अंतर-अमेरिकी विकास बैंक (2006), यूरोपीय आयोग (2013) देखें ।

[31] कुछ संदर्भों में तिलक (1989) शामिल हैं; तबर एट अल, (2016); जेमेल एट अल, (2016); और डी रिडर एट अल, (2020)।

[32] वान बॉन, एन (2015) पर आधारित आंतरिक अनुमान।

[33] मोहदेस और रायसी (2014) पर आधारित 33 आंतरिक अनुमान।

[34] अनुच्छेद IV परामर्श, दिसंबर 2022।

[35] उच्च संभाव्यता विकास मूल्यांकन बजट में अलग-अलग विकास सहायक उपायों के प्रभाव के आकलन पर आधारित होता है, जो बाद में एकत्रित होते हैं, न कि इन सभी प्रमुख उपायों के बीच क्रॉस इफेक्ट्स को पकड़ने के लिए एक गतिशील मॉडल ढांचे में। संभावित वृद्धि में आकलित वृद्धि भी अगले कुछ वर्षों में होने की संभावना है, न कि 2023-24 में क्योंकि कुछ उपायों का पूर्ण प्रभाव, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 2026-27 तक और यहां तक कि 2030 तक भी होगा।

अनुबंध 1: आरबीआई के उद्यम सर्वेक्षण से प्रमुख निष्कर्ष

2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान किए गए रिज़र्व बैंक के उद्यम सर्वेक्षणों[36] के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- कंपनियां समग्र कारोबारी स्थितियों को लेकर उत्साहित हैं, जिनके 2023-24 की पहली छमाही (चार्ट ए1 और ए2) तक विस्तार जारी रहने की उम्मीद है।
- पूर्णकालिक और अंशकालिक कर्मचारियों (चार्ट ए3) दोनों के लिए नौकरी के अवसरों का विस्तार होने की संभावना है।
- व्यवसाय उत्पादन, ऑर्डर बुक, रोजगार की स्थिति, क्षमता उपयोग और समग्र व्यावसायिक स्थिति पर आशावादी रहते हैं।
- क्षमता उपयोग (सीयू) और मौसमी रूप से समायोजित सीयू 2022-23 कि दूसरी तिमाही में दीर्घकालिक औसत सीयू को पार कर लिया; सुधार जारी रहने की संभावना है (चार्ट ए 4 और ए 5)।

चार्ट ए1: उत्पादन/ कारोबार पर रुख

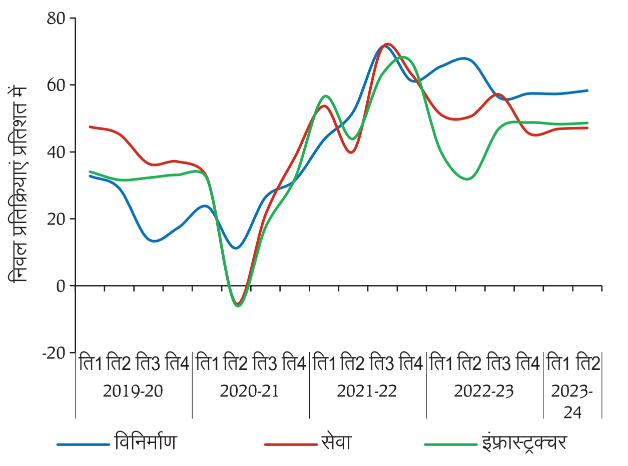

चार्ट ए2: समग्र कारोबार स्थिति पर रुख

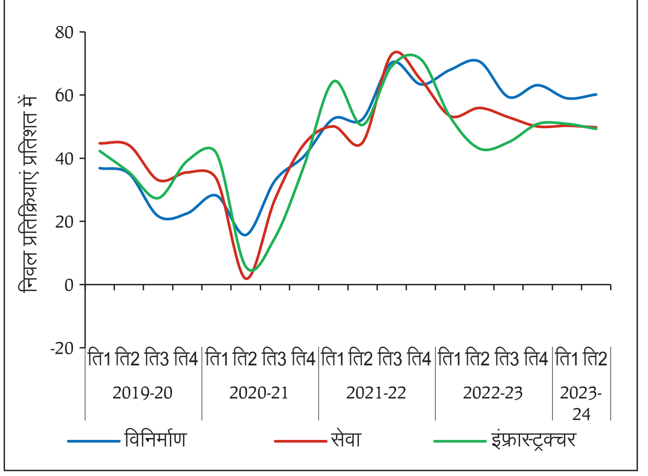

चार्ट ए3: रोजगार की स्थिति पर रुख

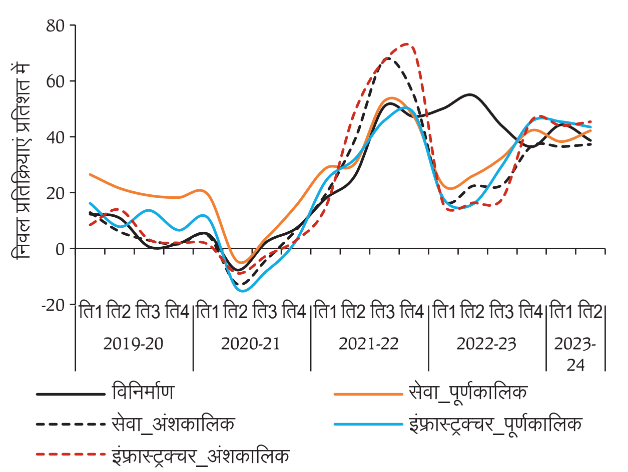

चार्ट ए4: विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग*

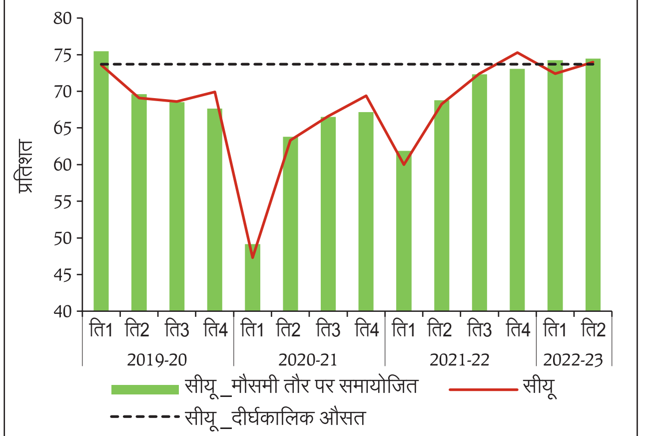

*: दीर्घकालिक सीयू में 2020-21 की पहली तिमाही शामिल नहीं है, जिसमें राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अवधि शामिल है।

स्रोत: आरबीआई।

[36] https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=55184

अनुबंध 1: आरबीआई के उद्यम सर्वेक्षण से प्रमुख निष्कर्ष *(जारी)*

- वरिष्ठ ऋण अधिकारियों को उम्मीद है कि 2023-24 की पहली छमाही के दौरान बैंकों से ऋण मांग में हालिया वृद्धि बनी रहेगी (चार्ट ए 6)।

- उच्च इनपुट लागत दबाव और मूल्य निर्धारण शक्ति की वापसी के कारण, अधिक कंपनियों को बिक्री मूल्यों (चार्ट ए 7 और ए 8) में वृद्धि की उम्मीद है।

चार्ट ए5: क्षमता उपयोग पर विनिर्माताओं के रुख

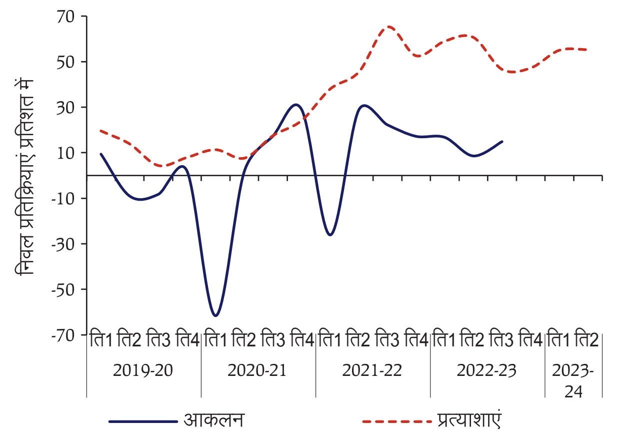

चार्ट ए6: वरिष्ठ ऋण अधिकारियों की ऋण मांग पर प्रत्याशाएं

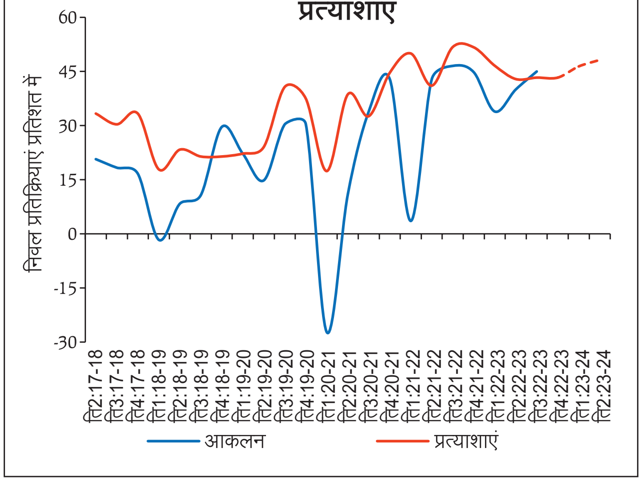

चार्ट ए7: इनपुट लागत पर रुख

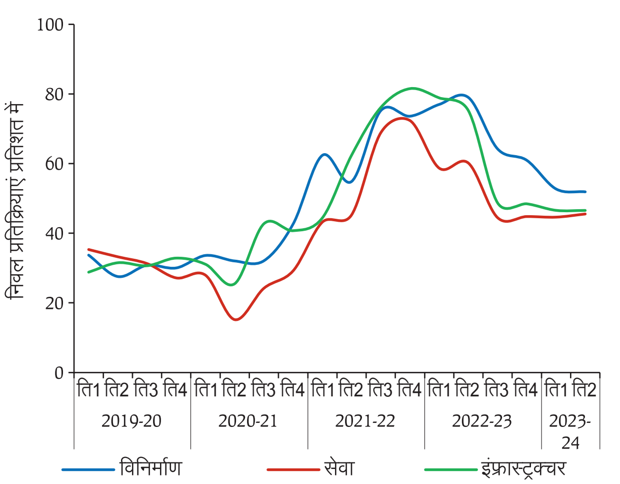

चार्ट ए8: विक्रय मूल्य पर रुख

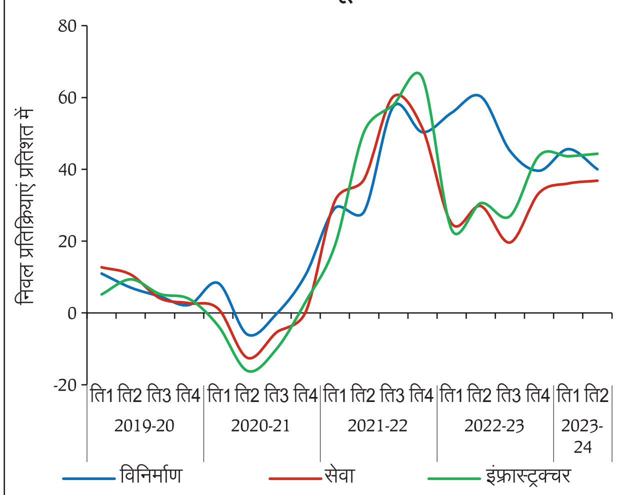

टिप्पणी: "निवल प्रतिक्रिया" सकारात्मक रिपोर्ट करने वाले उत्तरदाताओं और नकारात्मक की रिपोर्ट करने वाले उत्तरदाताओं के प्रतिशत के बीच का अंतर है। यह -100 और 100 के बीच है; शून्य से अधिक कोई भी मान, विस्तार/ सकारात्मक को इंगित करता है और शून्य से कम मान संकुचन/ नकारात्मक को इंगित करता है।

स्रोत: आरबीआई।

*भारत के लिए पुनर्गठित त्रैमासिक पूर्वानुमान प्रतिरूप (क्यूपीएम 2.0)**

जॉइस जॉन, दीपक कुमार, आशीष थॉमस जॉर्ज, प्रतिक मित्रा, मनीष कपूर और माइकल देबब्रत पात्र द्वारा

इस लेख में प्रस्तुत पुन: सुविचारित त्रैमासिक अनुमान मॉडल (क्यूपीएम 2.0) एक अग्रगामी खुली अर्थव्यवस्था अंतर मॉडल है जिसे पूर्वानुमान करने, जोखिम मूल्यांकन करने और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नीति विश्लेषण प्रदान करने के लिए कैलिब्रेट किया गया है। क्यूपीएम 2.0 राजकोषीय-मौद्रिक नीति इंटरैक्शन, घरेलू ईंधन मूल्य निर्धारण गतिशीलता, पूंजी प्रवाह, विनिमय दर गतिशीलता और अधिक सूचित निर्णय के लिए केंद्रीय बैंक के विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप के अधिक सूक्ष्म मॉडलिंग के साथ क्यूपीएम 1.0 को बढ़ाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का त्रैमासिक प्रक्षेपण मॉडल (क्यूपीएम) एक सुविचारित, अग्रगामी, खुली अर्थव्यवस्था, नया कीनेसियन गैप मॉडल है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की विशिष्ट विशेषताओं को शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढांचे के तहत निर्धारित लक्ष्यों / अधिदेश को प्राप्त करने के अनुरूप मध्यम अवधि के अनुमान और नीति विश्लेषण उत्पन्न करना है। इसके पूर्ववर्ती का प्रलेखन, यानी, क्यूपीएम संस्करण 1 (क्यूपीएम 1.0) 2016 में प्रकाशित किया गया था (बेनेस एट अल, 2016 ए ; बी)। अनुभव के सबक से लैस, तब से, मॉडल संरचना और मापदंडों को अधिक भारत-केंद्रित विशेषताओं के साथ मॉडल को बढ़ाने के लिए फिर से तैयार किया गया था ताकि इसके प्रदर्शन और प्रासंगिकता को समृद्ध किया जा सके। [1]

संस्करण 2 (क्यूपीएम 2.0) में लाए गए प्रमुख सुधार निम्नानुसार हैं:शेष लेख को छह खंडों में व्यवस्थित किया गया है।

ए राजकोषीय-मौद्रिक नीति बातचीत;

बी घरेलू ईंधन मूल्य निर्धारण गतिशीलता (तेल की कीमतें, विनिमय दरें और ईंधन कर);

सी पूंजी प्रवाह और विनिमय दर गतिशीलता; और

डी 2019 की चौथी तिमाही (कोविड-पूर्व अवधि)[2] तक के आंकड़ों को शामिल करते हुए पुन: परमेट्राइजेशन।

बाकी के आलेख को छ: खंडों में लिखा गया है। खंड II मॉडल संरचना प्रदान करता है। अंशांकन के लिए समीकरण और दृष्टिकोण खंड III में समझाया गया है। आवेग प्रतिक्रिया कार्यों (आईआरएफ) के संदर्भ में मॉडल गुणों को खंड IV में वर्णित किया गया है। प्रमुख मैक्रोइकॉनॉमिक चर के ऐतिहासिक अपघटन पर खंड V में चर्चा की गई है। खंड VI पूर्वानुमान प्रदर्शन प्रस्तुत करता है और खंड VII समाप्त होता है।

II. मॉडल संरचना

क्यूपीएम 2.0 मानक नए-कीनेसियन लघु ओपन-इकोनॉमी फ्रेमवर्क का प्रतीक है। इसमें 6 ब्लॉक हैं, अर्थात्, i) एक समग्र मांग ब्लॉक जिसमें आउटपुट अंतर और क्रेडिट स्थितियां शामिल हैं; (ii) मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति अपेक्षाओं और केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता का मॉडलिंग करने वाला एक समग्र आपूर्ति ब्लॉक; iii) अल्पकालिक ब्याज दरें (नीति प्रतिक्रिया कार्य और परिचालन लक्ष्य) और दीर्घकालिक ब्याज दरों में संचरण; iv) राजकोषीय ब्लॉक; v) संशोधित जोखिम-समायोजित कवर नहीं की गई ब्याज समानता की स्थिति, पूंजी प्रवाह और विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप के माध्यम से विनिमय दर; और vi) विदेशी क्षेत्र ब्लॉक (चार्ट 1)।

II.1. राजकोषीय-मौद्रिक नीति बातचीत

राजकोषीय नीति की गतिशीलता का उत्पादन और मुद्रास्फीति पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, मूल्य स्थिरता और निरंतर विकास प्राप्त करने के संदर्भ में उत्पादन और मुद्रास्फीति व्यवहार की समझ में सुधार के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीति बातचीत का उचित मॉडलिंग महत्वपूर्ण है (वुडफोर्ड, 2001; वुडफोर्ड, 2001) कैनज़ोनेरी एट अल। इसलिए, समग्र राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान में विघटित हो जाता है। प्राथमिक घाटे में संरचनात्मक

^लेखक भारतीय रिज़र्व बैंक से हैं। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं।

[1] यह परियोजना आरबीआई की मध्यम अवधि की रणनीति रूपरेखा, 'उत्कर्ष 2022' के तहत शुरू की गई थी।

[2] 2019 के बाद की अवधि के डेटा का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि कोविड-19 जन्य अत्यधिक अस्थिरता और अन्य घटनाक्रम औसत मॉडल गुणों को प्रभावित कर सकते हैं।

चार्ट 1: ओपीएम 2.0 - संरचना

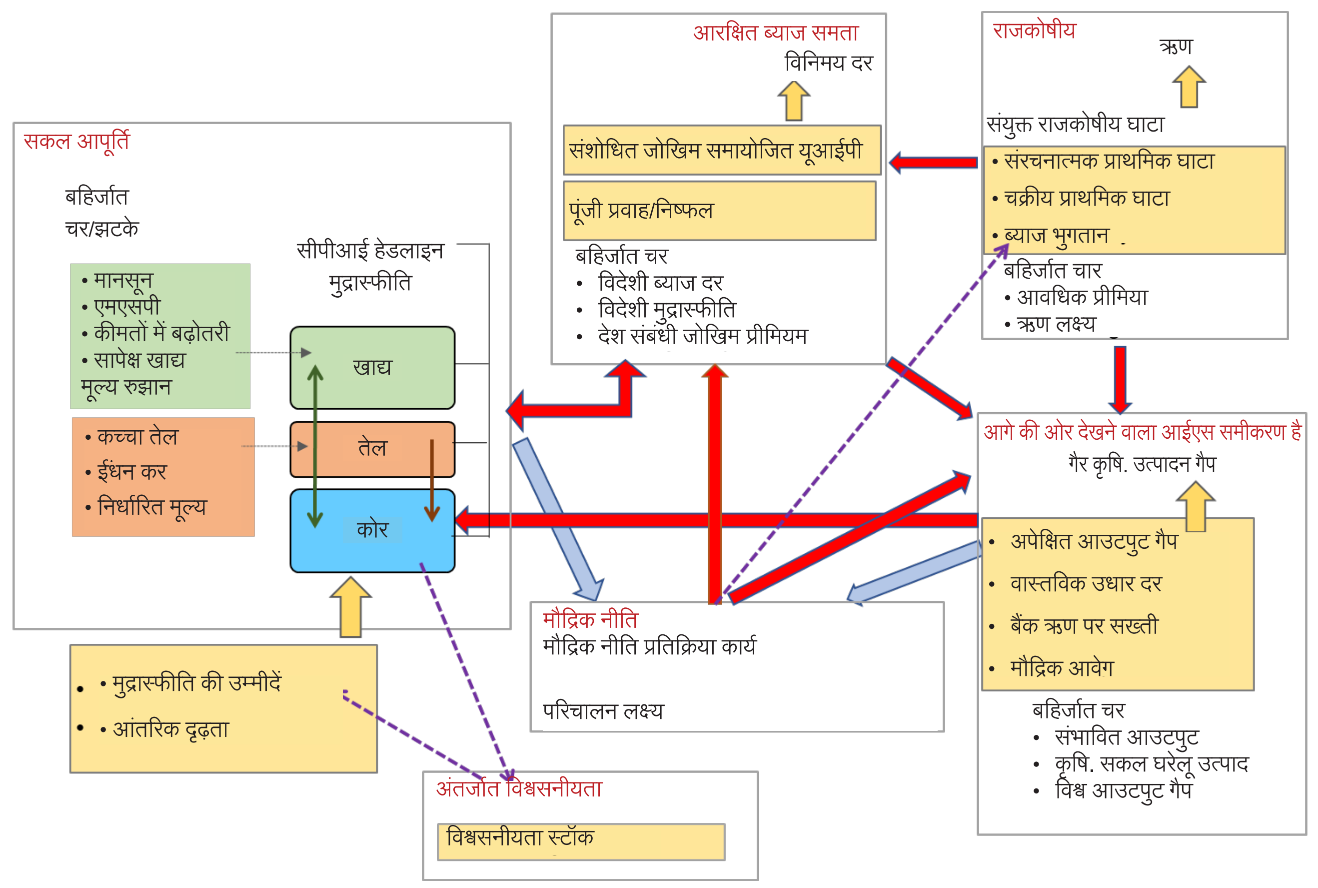

स्रोत: जॉन एट अल., 2022; बेन्स एट अल., 2016बी

(चक्रीय रूप से समायोजित) और चक्रीय (स्वचालित स्टेबलाइज़र) घटक होते हैं। चक्रीय घटक को आउटपुट गैप के फ़ंक्शन के रूप में मॉडल किया गया है। सरकारी खपत के रूप में संरचनात्मक घाटे में अप्रत्याशित परिवर्तन निजी खपत को प्रभावित करते हैं और इस तरह घरेलू आर्थिक चक्र राजकोषीय आवेगों का निर्माण करते हैं (ब्लैंचर्ड और पेरोट्टी, 2002)। ऋण गतिशीलता में ए) ऋण और समग्र राजकोषीय घाटे के बीच संबंध और बी) समग्र घाटा शामिल है जो ऋण के स्थायी स्तर (एस्कोलानो, 2010) के साथ संगत है। स्थिर राज्य संरचनात्मक घाटा स्थिर राज्य ऋण स्तर और नाममात्र उत्पादन वृद्धि से जुड़ा हुआ है। दीर्घकालिक ऋण लक्ष्य से विचलन संशोधित जोखिम-समायोजित कवर नहीं की गई ब्याज समानता (एमएमयूआईपी) स्थिति के माध्यम से देश के जोखिम प्रीमियम और विनिमय दर को प्रभावित करता है। कुल मांग और विनिमय दर में परिवर्तन मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं, जिससे मौद्रिक नीति में बदलाव होता है। इसी समय, मौद्रिक नीति ब्याज भुगतान के माध्यम से राजकोषीय घाटे को प्रभावित करती है - अल्पकालिक ब्याज दर दीर्घकालिक दर को प्रभावित करती है।

II.2. ईंधन की कीमत

भारत में ईंधन मूल्य निर्धारण की एक विशिष्ट प्रणाली है। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन खपत के कुछ घटकों की कीमत बाजार चर के आधार पर की जाती है - अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें और विनिमय दरें। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और केरोसिन जैसी कुछ वस्तुएं बाजार के लिए निर्धारित हैं, लेकिन उनके पास-पास नहीं है। बिजली जैसी ईंधन वस्तुओं के एक अन्य सेट की कीमतें प्रशासित की जाती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गैर-यथामूल्य करों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, जो मुद्रास्फीति में कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव के पूर्ण पारित होने में बाधा डालता है। इन कारकों को ध्यान में रखते

हुए, ईंधन अनुभाग में तीन अलग-अलग घटक हैं: क) 'बाजार ईंधन 1', जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतें शामिल हैं, कच्चे तेल की कीमतों, विनिमय दरों और ईंधन करों (उत्पाद शुल्क और वैट) में बदलाव से निर्धारित होती हैं; (ख) एलपीजी और मिट्टी के तेल से युक्त 'बाजार ईंधन 2' जिसके लिए कीमतें अंतर्राष्ट्रीय ईंधन कीमतों और विनिमय दरों द्वारा निर्धारित की जाती हैं, लेकिन एक अंतराल के साथ; और सी) सीपीआई के ईंधन और प्रकाश उपसमूह में 'प्रशासित ईंधन' यानी बिजली और अन्य आइटम। अर्थव्यवस्था में इनपुट लागत दबावों को निर्धारित करने में ईंधन की कीमतों की पर्याप्त भूमिका है, जो मुद्रास्फीति के ईंधन से गैर-ईंधन घटकों तक स्पिलओवर के माध्यम से मॉडल किए जाते हैं।

II.3. पूंजी प्रवाह और विनिमय दर गतिशीलता

पूंजी प्रवाह, विनिमय दरों और मौद्रिक नीति की गतिशीलता के लिए मानक दृष्टिकोण 'ट्राइलेममा' पर आधारित है (मुंडेल, 1963; 2006)। फ्लेमिंग, 1962)। इसे आगे नए-कीनेसियन ओपन इकोनॉमी फ्रेमवर्क में विकसित किया गया था, जिसमें वैश्विक वित्तीय चक्र और प्रमुख मुद्रा प्रतिमान (ऑब्स्टफेल्ड और रोगोफ, 2000) के निहितार्थ शामिल थे। गैली और मोनासेली, 2005; गोपीनाथ और अन्य 2020; मिरांडा-एग्रीपिनो और रे, 2022)। पूंजी प्रवाह और विनिमय दरों में अस्थिरता का व्यापक आर्थिक प्रबंधन पर प्रभाव पड़ता है। रूढ़िवादी दृष्टिकोण का मानना है कि सफल मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (आईटी) के लिए उच्च स्तर के विनिमय दर लचीलेपन की आवश्यकता होती है। हालांकि, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के संदर्भ में, यह देखा गया है कि पूंजी प्रवाह में अचानक वृद्धि या उलटफेर के कारण विनिमय दरों में अस्थिरता से जुड़ी लागतों को अनदेखा करना उप-इष्टतम है। इसने कई ईएमई को आईटी ढांचे (आरबीआई, 2021) के तहत भी विनिमय दर की अस्थिरता के प्रबंधन के लिए विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप जैसे नीतिगत साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है।

III. मुख्य व्यवहार समीकरण और अंशांकन

क्यूपीएम 2.0 में 154 समीकरण (पहचान सहित) हैं, जिनमें से 57 व्यवहार समीकरण हैं (तालिका 1)।

III.1. कुल मांग: एक अग्रगामी आईएस वक्र

घरेलू मांग को गैर-कृषि उत्पादन अंतर ($\hat{y}_t^{nag}$) द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे प्राकृतिक लघुगणक में व्यक्त गैर-कृषि उत्पादन (y_t^{nag}) और इसकी क्षमता ($\bar{y}_t^{nag}$) के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है।[4]

$$\hat{y}_t^{nag} = \alpha_1 * E_t(\hat{y}_{t+1}^{nag}) + \alpha_2 * \hat{y}_{t-1}^{nag} - \alpha_3 * \hat{r}_t^m + \alpha_4 * \hat{y}_t^f + \alpha_5 * \hat{Z}_t - \alpha_6 * \eta_t^{BL} + \alpha_7 * FIMP_t - \alpha_8 * \widehat{rfuel}_t + \varepsilon_t^{\hat{y}nag}$$

$$\alpha_1 = 0.1; \alpha_2 = 0.5; \alpha_3 = 0.25; \alpha_4 = 0.25;$$
$$\alpha_5 = 0.06; \alpha_6 = 0.4; \alpha_7 = 0.25; \alpha_8 = 0.01. \quad ...(1)$$

जहां $\hat{y}_t^{nag}$ को इसके पिछड़े मूल्यों ($\hat{y}_{t-1}^{nag}$) और मॉडल-आधारित तर्कसंगत अपेक्षाओं ($E_t(\hat{y}_{t+1}^{nag})$) दीर्घकालिक बाजार वास्तविक ब्याज दर अंतर ($\hat{r}_t^m$) विदेशी आउटपुट अंतर ($\hat{y}_t^f$) के द्वारा देखी गई गई वैश्विक मांग, वास्तविक विनिमय दर अंतर (η_t^{BL}), क्रेडिट शर्तों ($\widehat{rfuel}_t$) के आधार पर बैंक ऋण (बीएल), वास्तविक ईंधन मूल्य अंतर ($\widehat{rfuel}_t$), राजकोषीय आवेग (एफआईएमपीटी) और कुल मांग के आघात ($\varepsilon_t^{\hat{y}nag}$) (परिशिष्ट और बेन्स एट अल, 2016बी)।

सारणी 1: क्यूपीएम 2.0 - आयाम

समीकरणों की संख्या	154
जिनमें से	
व्यवहार समीकरणों की संख्या	57
पहचान की संख्या	97
चर की संख्या	154
स्टोकेस्टिक झटकों की संख्या	57
माप समीकरणों की संख्या	33
देखे गए चर की संख्या	33
पैरामीटर्स की संख्या	116

स्रोत: लेखकों की गणना।

[3] पूंजी प्रवाह के आघातों के सामने, विनिमय दर अपने दीर्घकालिक संतुलन से काफी दूर चली जाती है, जिससे विनिमय दर का प्रभाव अंतरण, मुद्रास्फीति और आर्थिक अव्यवस्था में प्रसारित हो जाता है। इसलिए, केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति के अलावा विनिमय दर की भी परवाह करते हैं। हालांकि, मौद्रिक नीति साधनों का उपयोग करके विनिमय दर पर ध्यान देना, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था में विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है जिससे मौद्रिक नीति कार्रवाई महंगी पड़ेगी (ब्लैंचर्ड और अन्य, 2016, घोष और अन्य, 2016)।

[4] सभी वास्तविक रुझान प्रणाली-अनुरूप हैं, जिन्हें कलमैन फ़िल्टर का उपयोग करके फ़िल्टर किया गया है। क्यूपीएम 2.0 में, समग्र मांग समीकरण (समीकरण 1) में ईंधन की कीमतों को शामिल करने के साथ, विश्व उत्पादन अंतराल गुणांक केवल प्रत्यक्ष प्रभाव को दर्शाता है और तदनुसार सुनियंत्रित किया गया है। क्यूपीएम 1.0 में, यह कच्चे तेल की कीमतों के प्रत्यक्ष प्रभाव के साथ-साथ अप्रत्यक्ष प्रभाव को भी दर्शाता है।

III.2. कुल आपूर्ति: मुद्रास्फीति

भारत में मुद्रास्फीति की गतिशीलता की अनूठी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, भोजन, ईंधन और कोर[5] घटकों (क्यूपीएम 1.0 की संरचना के अनुरूप) के लिए अलग-अलग समीकरण तैयार किए जाते हैं (बेनेस एट अल।

खाद्य मुद्रास्फीति (π_t^{food}) अपने अतीत (π_{t-1}^{food}), पर निर्भर करती है। शर्तें $(\pi 4_{t-1}^{headline} - \pi 4_{t-1}^{food})$ और $(p_{t+4}^{food} - p_{t+4}^{core} - \overline{rp}_{t+4}^{food})$ सुनिश्चित करती हैं कि खाद्य मुद्रास्फीति लंबे समय में समग्र मुद्रास्फीति में परिवर्तित हो जाती है। अल्पावधि में, खाद्य मुद्रास्फीति तीन झटकों से प्रेरित होती है: मानसून आघात ($\varepsilon_t^{monsoon}$); न्यूनतम समर्थन मूल्य (ε_t^{MSP}) को आघात ; और सब्जियों ($\varepsilon_t^{vegetables}$) की कीमतों को आघात , प्रत्येक के अलग-अलग अल्पकालिक प्रभाव होते हैं। इन आघातों की गतिशीलता चलती औसत बहुपद $\Gamma_{monsoon}(L)$, $\Gamma_{MSP}(L)$, and $\Gamma_{vegetables}(L)$.

$$\pi_t^{food} = \pi_{t-1}^{food} + \varphi_1(\pi 4_{t-1}^{headline} - \pi 4_{t-1}^{food}) - \varphi_2(p_{t+4}^{food} - p_{t+4}^{core} - \overline{rp}_{t+4}^{food}) + \Gamma_{monsoon}(L)\varepsilon_t^{monsoon} + \Gamma_{MSP}(L)\varepsilon_t^{MSP} + \Gamma_{vegetables}(L)\varepsilon_t^{vegetables} + \varepsilon_t^{\pi^{food}}$$

$$\varphi_1 = 0.025; \ \ \varphi_2 = 0.75 \qquad ...(2)$$

कोर मुद्रास्फीति (π_t^{core}) अपेक्षित मुद्रास्फीति ($E_t{}^h(\pi 4_{t+1}^{core})$) , मुद्रास्फीति में निरंतरता, घरेलू उत्पादन अंतर (π_{t-1}^{core}) और वास्तविक विनिमय दर ($\hat{y}_t^{nag}$) को पकड़ने के लिए अपने स्वयं के अतीत ($\hat{z}_t$). $(p_t^{energy,mkt} - p_t^{core} - \overline{rp}_t^{energy,mkt})$,

पर निर्भर करती है। (ऊर्जा) $(p_{t+4}^{food} - p_{t+4}^{core} - \overline{rp}_{t+4}^{food})$ -छिद्र-पूड क्रमशः ईंधन और खाद्य घटकों से स्पिलओवर का प्रतिनिधित्व करता है।"

$$\pi_t^{core} = \beta_1 * E_t{}^h(\pi 4_{t+1}^{core}) + (1-\beta_1) * \pi_{t-1}^{core} + \beta_2 * (\hat{y}_t^{nag} + \beta_3 * \hat{z}_t) + \beta_4 * (\pi 4_{t-1}^{headline} - \pi 4_{t-1}^{core}) + \beta_5(p_t^{energy,mkt} - p_t^{core} - \overline{rp}_t^{energy,mkt}) + \beta_6(p_{t+4}^{food} - p_{t+4}^{core} - \overline{rp}_{t+4}^{food}) + \varepsilon_t^{\pi^{core}}$$

$$\beta_1 = 0.33; \ \beta_2 = 0.15; \ \beta_3 = 0.05; \ \beta_4 = 0.01; \ \beta_5 = 0.02; \ \beta_6 = 0.04. \qquad ...(3)$$

ईंधन ब्लॉक में, मुद्रास्फीति (π_t^{fuel}) को पेट्रोल और डीजल मुद्रास्फीति ($\pi_t^{fuel,mkt1}$), एलपीजी और केरोसीन मुद्रास्फीति ($\pi_t^{fuel,mkt2}$) और प्रशासित ईंधन मुद्रास्फीति ($\pi_t^{fuel,adm}$) के भारित औसत के रूप में निर्धारित किया जाता है।[7]

$$\pi_t^{fuel} = wt_{fuel,mkt1}\,\pi_t^{fuel,mkt1} + wt_{fuel,mkt2}\,\pi_t^{fuel,mkt2} + (1 - wt_{fuel,mkt1} - wt_{fuel,mkt2})\,\pi_t^{fuel,adm}$$

$$wt_{fuel,mkt1} = 0.25; \ wt_{fuel,mkt2} = 0.20. \qquad ...(4)$$

पेट्रोल और डीजल की मुद्रास्फीत किच्चे तेल की कीमतों की भारतीय टोकरी (Δp_t^{oil}) वनिमिय दर (ΔS_t) में बदलाव और ईधन करों ($\pi_t^{fuel,tax}$) में बदलाव से नर्धिारति होती है।

$$\pi_t^{fuel,mkt1} = \beta_1^{fm1}\pi_{t-1}^{fuel,mkt1} + \beta_2^{fm1}\pi_t^{fuel,tax} + (1 - \beta_1^{fm1} - \beta_2^{fm1})4(\Delta S_t + \Delta p_t^{oil} - \Delta\bar{Z}_t) + \varepsilon_t^{\pi^{fuel,mkt1}}$$

$\beta_1^{fm1} = 0.00$ तत्काल और पूर्ण पासथ्रू के लिए और > 0.00 विलंबित पासथ्रू के लिए

$$\beta_2^{fm1} = 0.47.^8 \qquad ...(5)$$

कर में परिवर्तन बहिर्जात कारकों द्वारा संचालित माना जाता है, अर्थात्,

$$\pi_t^{fuel,tax} = \pi_{t-1}^{fuel,tax} + \varepsilon_t^{\pi^{fuel,tax}} - \varepsilon_{t-1}^{\pi^{fuel,tax}} \qquad ...(6)$$

एलपीजी और मिट्टी के तेल की मुद्रास्फीति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? कच्चे तेल (Δp_t^{oil}) की कीमतों के भारतीय बास्केट में बदलाव और विनिमय दर में परिवर्तन (ΔS_t)।

$$\pi_t^{fuel,mkt2} = \beta_1^{fm2}\pi_{t-1}^{fuel,mkt2} + (1 - \beta_1^{fm2})4(\Delta S_t + \Delta p_t^{oil} - \Delta\bar{Z}_t) + \varepsilon_t^{\pi^{fuel,mkt2}}$$

5 मूल मुद्रास्फीति को भोजन, ईंधन, पेट्रोल और डीजल घटकों को छोड़कर मुद्रास्फीति के रूप में परिभाषित किया गया है।

6 मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं का गठन और एक अंतर्जात विश्वसनीयता निर्माण प्रक्रिया को क्यूपीएम 1.0 के समान तैयार किया गया है (परिशिष्ट और बेन्स और अन्य, 2016 बी)। π तिमाही-दर-तिमाही (वार्षिक) मुद्रास्फीति को दर्शाता है, जबकि π4 वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) मुद्रास्फीति को दर्शाता है। सांकेतिक (S_t) और वास्तविक (Z_t) विनिमय दरों में वृद्धि मूल्यह्रास और इसके विलोमतः दर्शाती है। सापेक्ष खाद्य कीमत प्रवृत्ति को क्यूपीएम 1.0 के समान तैयार किया गया है (परिशिष्ट और बेन्स और अन्य, 2016बी)।

7 क्यूपीएम 1.0 में, ईंधन मुद्रास्फीति में दो प्रकार के ईंधन शामिल थे, यथा बाजार और प्रशासित। बाजार ईंधन मुद्रास्फीति भारतीय समूह के कच्चे तेल की कीमतों और विनिमय दर द्वारा निर्धारित की गई थी, जबकि ईंधन मूल्य निर्धारण में प्रशासित घटक को बड़े पैमाने पर एक बहिर्जात प्रक्रिया के रूप में तैयार किया गया था (बेन्स और अन्य, 2016बी)।

8 गुणांक 0.47, लगभग 80 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कच्चे तेल की कीमत से मेल खाता है।

$\beta_1^{fm2} = 0.00$ तत्काल और पूर्ण पासथ्रू के लिए और > 0.00 विलंबित पासथ्रू के लिए .... (7)

प्रशासित ईंधन मुद्रास्फीति बहिर्जात रूप से है दृढ।

$$\pi_t^{fuel,adm} = \pi_{t-1}^{fuel,adm} + \beta_1^{fa}\left(\pi_{t-1}^{core} - \pi_{t-1}^{fuel,adm}\right) + \varepsilon_t^{\pi^{fuel,adm}}$$

$$\beta_1^{fa} = 0.05. \quad ...(8)$$

III.3. ब्याज दरें

ब्लॉक मौद्रिक नीति रेपो दर समीकरण एक ब्याज दर स्मूथिंग पैरामीटर (बेनेस एट) के साथ मुद्रास्फीति पूर्वानुमान-आधारित टेलर-प्रकार की प्रतिक्रिया फ़ंक्शन का अनुसरण करता है। अल., 2016 बी)।

$$i_t = \lambda_1 i_{t-1} + (1-\lambda_1)\{\bar{r}_t + \pi4_t^* + \lambda_2 * [E_t(\pi4_{t+3}^{core}) - \pi4_t^*] + \lambda_3[E_t(\pi4_{t+3}^{headline}) - \pi4_t^*] + \lambda_4 \hat{y}_t{}^{nag}\} + \varepsilon_t^i$$

$$\lambda_1 = 0.88;\ \lambda_2 = 1.50;\ \lambda_3 = 0.50;\ \lambda_4 = 0.50. \quad ...(9)$$

नीति रेपो दर कहां है, प्राकृतिक दर है ब्याज की मात्रा, मुद्रास्फीति लक्ष्य है, और तीन तिमाहियों से आगे क्रमशः कोर और हेडलाइन मुद्रास्फीति पूर्वानुमान हैं और आउटपुट अंतर है। प्रतिक्रिया फलन में कोर और हेडलाइन दोनों शामिल होते हैं, अर्थात, मौद्रिक नीति न केवल मांग पक्ष के विकास और अंतर्निहित मुद्रास्फीति के दबावों पर प्रतिक्रिया करती है जैसा कि मुख्य मुद्रास्फीति पूर्वानुमानों में परिलक्षित होता है, बल्कि मुख्य मुद्रास्फीति पर खाद्य और ईंधन की कीमतों के दूसरे दौर के प्रभावों को रोकने के लिए पहले से ही आपूर्ति पक्ष के दबावों पर भी प्रतिक्रिया करती है। यह विनिर्देश मौद्रिक नीति को क्षणिक आपूर्ति पक्ष के झटकों के माध्यम से देखने में सक्षम बनाता है।

क्यूपीएम 2.0 मौद्रिक नीति के परिचालन लक्ष्य के लिए एक अतिरिक्त समीकरण शामिल करता है - भारित औसत कॉल मनी दर (डबल्यूएसीआर) - निम्नानुसार:

$$\breve{i}_t = i_t + Spread_t \quad ...(10)$$

डबल्यूएसीआर जहां $\breve{i}_t$ है और $Spread_t$ परिचालन लक्ष्य और नीति दर इसके बीच की खाई है। $Spread_t$ के लिए स्टीडी स्टेट मूल्य को 0 मान लिया गया है जो की इसे दीर्घावधि में दर्शाता है। दीर्घकाल में, नीतिगत दर और परिचालन लक्ष्य प्रशासित ईंधन मुद्रास्फीति बहिर्जात रूप से है दृढ। अल्पकालिक दर से दीर्घकालिक ब्याज दर तक संचरण - निजी ऋण के लिए प्रासंगिक - ब्याज दरों की अवधि संरचना के साथ-साथ टर्म प्रीमियम (परिशिष्ट और बेनेस एट अल। 2016 बी)।

III.4 राजकोषीय ब्लॉक

राजकोषीय घाटा (नॉमिनल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में), (FD_t) प्राथमिक राजकोषीय घाटे (PD_t) और ब्याज भुगतान (IP_t) का योग है, यानी,

$$FD_t = PD_t + IP_t \quad ...(11)$$

प्राथमिक घाटे को संरचनागत $(PD^s{}_t)$ और चक्रीय $(PD^c{}_t)$ घटकों में विघटित किया गया है अर्थात ,

$$PD_t = PD^s{}_t + PD^c{}_t \quad ...(12)$$

चक्रीय प्राथमिक राजकोषीय घाटा $(PD^c{}_t)$, स्वचालित स्थिरकर्ता, को किस के कार्य के रूप में मॉडल किया गया है जिसे आउटपुट गैप के रूप में मापा जाता है $(\hat{y}^{nag})$

$$PD^c{}_t = -\xi_1 * \hat{y}_t^{nag} + \varepsilon^{PD^c}{}_t$$

$$\xi_1 = 0.2. \quad ...(13)$$

फिस्कल डेफिसिट $(PD^s{}_t)$ के संरचनात्मक घटक को संरचनात्मक प्राथमिक डिफी सिट और प्राथमिक डिफी सिट लक्ष्य $(\overline{PD}_t^s)$ के एक चौथाई अंतराल के भारित औसत के रूप में तैयार किया गया है। ईंधन कर परिवर्तन राजस्व में परिवर्तन के माध्यम से प्राथमिक घाटे को प्रभावित करते हैं, अर्थात

$$PD_t^s = \rho^{PD^s} * PD^s{}_{t-1} + \left(1-\rho^{PD^s}\right) * \overline{PD}_t^s - \xi_2(\pi_t^{fuel,tax} - \pi4_t^*) + \varepsilon^{PD^s}{}_t$$

$$\rho^{PD^s} = 0.80;\ \xi_2 = 0.002. \quad ...(14)$$

प्राथमिक घाटे के लक्ष्य को राजकोषीय समेकन के रास्ते के रूप में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) के अनुरूप कैलिब्रेट किया जाता है:

$$\overline{PD}_t^s = \rho^{\overline{PD}^s} * \overline{PD}^s{}_{t-1} + \left(1-\rho^{\overline{PD}^s}\right) * \overline{PD}_t^s + \varepsilon^{\overline{PD}^s}{}_t$$

$$\rho^{\overline{PD}^s} = 0.70. \quad ...(15)$$

संरचनात्मक प्राथमिक घाटे का अपने लक्ष्य से विचलन राजकोषीय आवेग ($FIMP_t$):

$$FIMP_t = PD_t^s - \overline{PD}_t^s \quad ...(16)$$

ऋण संचय गतिशीलता निम्नानुसार मॉडल किया गया है:

$$B_t = FD_t + B_{t-1}\left(\frac{1}{\left(1+\frac{\pi 4_t^* + Y4_t^*}{100}\right)}\right) \quad ...(17)$$

जहां वर्तमान ऋण (नाममात्र जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) (B_t) वर्तमान वित्तीय घाटे (FD_t) द्वारा निर्धारित किया जाता है और ऋण के पिछले स्तर (B_{t-1}) को नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि ($\pi 4_t^* + Y4_t^*$) के लिए समायोजित किया जाता है|

स्थिर राज्य राजकोषीय घाटा (एफडी*) स्थिर ऋण गतिशीलता (बी*) से निम्नानुसार संबंधित है:

$$FD^* = B^*\left(1 - \frac{1}{\left(1+\frac{(\pi 4_t^*+Y4_t^*)}{100}\right)} - \frac{i_t^n}{\left(1+\frac{(\pi 4_t^*+Y4_t^*)}{100}\right)} h^{3M} - \frac{i_t^n + prem^{10y^*}}{\left(1+\frac{(\pi 4_t^*+Y4_t^*)}{100}\right)}(1 - h^{3M})\right)$$

$$h^{3M} = 0.05. \quad ...(18)$$

ब्याज की नाममात्र प्राकृतिक दर कहां है, जो ... (23) यह वास्तविक प्राकृतिक ब्याज दर और मुद्रास्फीति लक्ष्य के बराबर है। मॉडलिंग में आसानी के लिए, हम मानते हैं कि सरकार दो प्रकार के बॉन्ड जारी करके राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करती है, एक अल्पकालिक परिपक्वता (91-दिन) ट्रेजरी बिल) और दूसरा दीर्घकालिक परिपक्वता के साथ।

अंत में, ऋण लक्ष्य ($\overline{B_t}$) सरकार के व्यवहार को सहारा देता है और निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है

$$\overline{B_t} = \rho^{\bar{B}}\overline{B_{t-1}} + (1 - \rho^{\bar{B}})B^* + \varepsilon^{\bar{B}}{}_t$$

$$\rho^{\bar{B}} = 0.99. \quad ...(19)$$

समग्र ब्याज भुगतान (IP_t) अल्पावधि (IP_t^{3M}) और दीर्घावधि (IP_t^{10Y}) बोंड्स का योग होते हैं।

$$IP_t = IP_t^{3M} + IP_t^{10Y} \quad ...(20)$$

अल्पकालिक बॉन्ड पर ब्याज भुगतान पिछली अवधि ($h^{3M} * B_{t-1}$), की अल्पकालिक दर ($\breve{\imath}_{t-1}$) का उत्पाद है और पिछली अवधि में अल्पकालिक बांड के रूप में रखे गए बकाया ऋण का हिस्सा है, जिसे नाममात्र जीडीपी वृद्धि में बदलाव के लिए समायोजित किया गया है।

$$IP_t^{3M} = \breve{\imath}_{t-1}\, h^{3M} B_{t-1} \frac{1}{\left(1+\frac{(\pi 4_t^*+Y4_t^*)}{100}\right)} \quad ...(21)$$

लंबी अवधि के बॉन्ड पर ब्याज भुगतान पिछली अवधि की ब्याज दर (i_{t-1}^{10y}) का उत्पाद है और लंबे समय तक रखे गए बकाया ऋण का हिस्सा- पिछली अवधि (($1 - h^{3M}) * B_{t-1}$) में टर्म बॉन्ड को नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में बदलाव के लिए एडजस्ट किया गया था।

$$IP_t^{10Y} = i_{t-1}^{10y} * (1 - h^{3M})B_{t-1} \frac{1}{\left(1+\frac{(\pi 4_t^*+Y4_t^*)}{100}\right)} \quad ...(22)$$

दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दर (i_t^{10y}) को अग्रगामी अल्पकालिक ब्याज दरों के औसत और टर्म प्रीमियम ($prem_t^{10y}$) के रूप में दर्शाया जा सकता है

$$i_t^{10y} = \frac{1}{40}\sum_{i=0}^{39} \widetilde{\imath_{t+\imath}} + prem_t^{10y} \quad ...(23)$$

टर्म प्रीमियम ($prem_t^{10y}$) को अल्पकालिक और दीर्घकालिक ब्याज दरों के बीच दीर्घकालिक ($prem^{10y^*}$) औसत प्रसार में परिवर्तित माना जाता है किसी भी सदमे की अनुपस्थिति।

$$prem_t^{10y} = \rho^{prem^{10y}} prem_{t-1}^{10y} + (1 - \rho^{prem^{10y}})prem^{10y^*} + \varepsilon_t^{prem^{10y}}$$

$$\rho^{prem^{10y}} = 0.75. \quad ...(24)$$

III.5 संशोधित जोखिम समायोजित कवर नहीं की गई ब्याज समानता (एमआरयूआईपी)

कवर नहीं की गई ब्याज दर समानता (यूआईपी) स्थिति, जिसमें ब्याज दर अंतर अपेक्षित विनिमय दर निर्धारित करते हैं, मौद्रिक नीति विश्लेषण के लिए छोटी खुली अर्थव्यवस्था मॉडल में लोकप्रिय रूप से उपयोग किया गया है। हालांकि, यूआईपी संबंध को डेटा में लगातार और निर्णायक रूप से खारिज कर दिया गया है (देखें फ्रूट एंड थेलर, 1990; लुईस, 1995 और एंगेल, 1996 व्यापक सर्वेक्षण के लिए)। इस अनुभवजन्य डिस्कनेक्ट को प्रतिबिंबित करने के लिए, विनिमय दरों पर ब्याज दरों के प्रभाव को कम करने के लिए समय-अलग देश जोखिम प्रीमियम और

क्रय शक्ति समता स्थितियों को पेश किया जाता है (बेनेस एट अल।

एमआरयूआईपी समीकरण के माध्यम से कैप्चर की गई विनिमय दर गतिशीलता को बाहरी क्षेत्र की विशेषताओं को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है: ए) पूंजी प्रवाह के लिए एक समायोजन प्रक्रिया; ख) चालू खाते के निर्धारक; ग) चालू और पूंजी खातों से संबंधित भुगतान संतुलन की पहचान भंडार के संचय से संबंधित है; और, डी) विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप।

$$K_t = \varsigma_1 K_{t-1} + \varsigma_2 (rr_t - rr_t^{rw}) - \varsigma_3 \Delta S_t + \varsigma_4 (\hat{y}_t^{nag} - \hat{y}_t^{f}) + \varepsilon_t^K$$

$$\varsigma_1 = 0.55;\ \varsigma_2 = 0.05;\ \varsigma_3 = 0.20;\ \varsigma_4 = 0.08. \quad ...(25)$$

जहां पूंजी प्रवाह (नाममात्र जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) का प्रतिनिधित्व करता है, जो वास्तविक ब्याज दर अंतर से प्रेरित होते हैं $(rr_t - rr_t^{rw})$; नाममात्र विनिमय दर में परिवर्तन (ΔS_t); और घरेलू और वैश्विक उत्पादन अंतराल के बीच अंतर $(\hat{y}_t^{nag} - \hat{y}_t^{f})$:

$$CA_t = \tau_1 CA_{t-1} + \tau_2 \widehat{Z}_t - \tau_3 \hat{y}_t^{nag} - \tau_4 \widehat{Oil}_t + \varepsilon_t^{CA}$$

$$\tau_1 = 0.50;\ \tau_2 = 0.07;\ \tau_3 = 0.10;\ \tau_4 = 0.015. \quad ...(26)$$

जहां CA चालू खाता शेष राशि (नाममात्र जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) है, जो $\widehat{Oil}$ द्वारा निर्धारित की जाती है जो कच्चे तेल की कीमत में अंतर 9, घरेलू मांग की स्थिति $(\hat{y}_t^{nag})$और वास्तविक विनिमय दर अंतर $(\hat{Z}_t)$ को दर्शाती है।

भंडार में परिवर्तन (जीडीपी (ΔRes)) के प्रतिशत के रूप में) भुगतान संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है जो विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप (Int) द्वारा अनुकूलित हैं वह बदले में , विनिमय दर पर पूंजी प्रवाह के प्रभाव को निर्धारित करता है।

$$Int(CA_t + K_t) = \Delta Res_t$$

$$Int = 0\ for\ no\ intervention\ and\ 1\ for\ full\ intervention. \quad ...(27)$$

[9] कच्चे तेल की कीमत का दीर्घकालिक रुझान से विचलन।

अतिरिक्त सुविधाओं को शामिल करते हुए, एमआरयूआईपी समीकरण निम्नानुसार व्यक्त किया गया है:

$$\gamma_1 * [\breve{\iota}_t - (i_t^f + \sigma_t + \gamma_2 * BIMP_t + \gamma_3 * FIMP_t)] + (1-\gamma_1) * [4\Delta\bar{Z}_{t-1} + (\pi 4_{t-1}^{core} - \pi 4_{t-1}^{f})] + (1 - Int) * \gamma_4 * K_t = 4 * (E_t S_{t+1} - S_t) + \varepsilon_t^S$$

$$\gamma_1 = 0.55;\ \gamma_2 = 2.0;\ \gamma_3 = 2.0;\ Int = 0\ to\ 1;\ \gamma_4 = 3.33. \quad ...(28)$$

$$E_t S_{t+1} = \delta_1 * S_{t+1} + (1-\delta_1) * \{S_{t-1} + 2 * [\Delta\bar{Z}_t + (\pi 4_t^* - \pi 4_t^{*f})/4]\}$$

$$\delta_1 = 0.63. \quad ...(29)$$

जहां, S_t विनिमय दर है, $E_t S_{t+1}$ अपेक्षित विनिमय है दर, $\breve{\iota}_t$ अल्पकालिक नाममात्र ब्याज दर है, i_t^f विदेशी नाममात्र ब्याज दर है[10], σ_t समय-भिन्न देश जोखिम प्रीमियम है, $\pi 4_t^f$ विदेशी मुद्रास्फीति है, $\pi 4_t^{core}$ घरेलू है मुख्य मुद्रास्फीति, $\Delta\bar{Z}_t$ वास्तविक विनिमय दर की प्रवृत्ति में परिवर्तन है, $\pi 4_t^*$ and $\pi 4_t^{*f}$ घरेलू और विदेशी अर्थव्यवस्थाओं के लक्ष्य हैं, $FIMP_t$राजकोषीय आवेग है $BIMP_t$ ऋण आवेग और K_t पूंजी प्रवाह है।

III.6. विदेशी ब्लॉक

क्यूपीएम में विदेशी ब्लॉक के दो भाग हैं - यूनाइटेड स्टेट्स (यूएस) ब्लॉक और बाकी दुनिया (आरओडब्ल्यू) ब्लॉक। यूएस ब्लॉक तीन व्यवहार समीकरणों के साथ एक नए-कीनेसियन मॉडल है - आईएस वक्र, फिलिप्स वक्र और टेलर नियम:

$$\hat{y}_t^{US} = a_1 * E_t(\hat{y}_{t+1}^{US}) + a_2 * \hat{y}_{t-1}^{US} - \alpha_3 * \hat{r}_t^{US} + \varepsilon_t^{\hat{y}^{US}}$$

$$a_1 = 0.25;\ a_2 = 0.55;\ a_3 = 0.20. \quad ...(30)$$

$$\pi_t^{US} = b_1 * E_t^{\,h}(\pi_{t+1}^{US}) + (1-b_1) * \pi_{t-1}^{US} + b_2 * \hat{y}_t^{\,US} + \varepsilon_t^{\pi^{US}}$$

$$b_1 = 0.75;\ b_2 = 0.10. \quad ...(31)$$

$$i_t^{\,US} = c_1 i_{t-1}^{\,US} + (1-c_1) * \{\bar{r}_t^{\,US} + \pi 4_t^{*US} + c_2 * [E_t(\pi 4_{t+3}^{US}) - \pi 4_t^{*US}] + c_3 * \hat{y}_t^{\,US}\} + \varepsilon_t^{i^{US}}$$

$$c_1 = 0.70;\ c_2 = 1.50;\ c_3 = 0.20. \quad ...(32)$$

[10] विदेशी ब्याज दर (i_t^f) का अनुमान फेडरल निधि दर (यूएस) का उपयोग करके लगाया जाता है।

जहां $\hat{y}_t^{US}$यूएस आउटपुट गैप है, $\hat{r}_t^{US}$ यूएस वास्तविक ब्याज दर अंतर, π_t^{US} यूएस मुद्रास्फीति, $i_t{}^{US}$ फेड फंड्स दर है, $\pi 4_t^{*US}$ यूएस मुद्रास्फीति लक्ष्य है और $\bar{r}_t{}^{US}$ यूएस की ब्याज दर की वास्तविक प्राकृतिक दर है।

विदेशी ब्लॉक के आरओडब्ल्यू खंड में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के लिए एक बहिर्जात समीकरण शामिल है। विदेशी चर के पूर्वानुमान बहिर्जात रूप से प्रदान किए जाते हैं, जो संयुक्त राज्य फेडरल रिजर्व (यूएस फेड), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संघ (आईईए) जैसी एजेंसियों से उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं।

III.7. अंशांकन

क्यूपीएम 2.0 के मापदंडों का अंशांकन कई पुनरावृत्तियों (चार्ट 2) के माध्यम से किया गया है। इस प्रक्रिया में ए) रैखिक प्रतिगमन मॉडल, गैर-रैखिक प्रतिगमन मॉडल और वेक्टर ऑटो रिग्रेशन (वीएआर) मॉडल का उपयोग करके अर्थमितीय अनुमान उत्पन्न करना शामिल है; (ख) अन्य अनुभवजन्य अध्ययनों (खुंद्राक्पम और जैन, 2012) के अनुमानों का उपयोग करना; मिश्रा और त्रिवेदी, 2016; बेहरा और अन्य 2017; पात्रा और अन्य, 2018; कपूर, 2018; आरबीआई, 2018; गोयल और परब, 2019; राज और अन्य, 2018; आरबीआई, 2019; पात्रा और अन्य, 2021; पटनायक और अन्य, 2022); और (ग) मॉडल जनित आईआरएफ, ऐतिहासिक अपघटन और रोलिंग पूर्वानुमानों का उपयोग करके फिट का मूल्यांकन करना।

मॉडल समाधान, सिमुलेशन, ऐतिहासिक अपघटन और पूर्वानुमान निम्नलिखित चरणों के माध्यम से एमएटीएलएबी में आईआरआईएस टूलबॉक्स का उपयोग करके किए जाते हैं। सबसे पहले, मॉडल को एक स्थिर स्थिति के आसपास रैखिक करने की

चार्ट 2: फ़्लो चार्ट - क्यूपीएम 2.0 अंशांकन

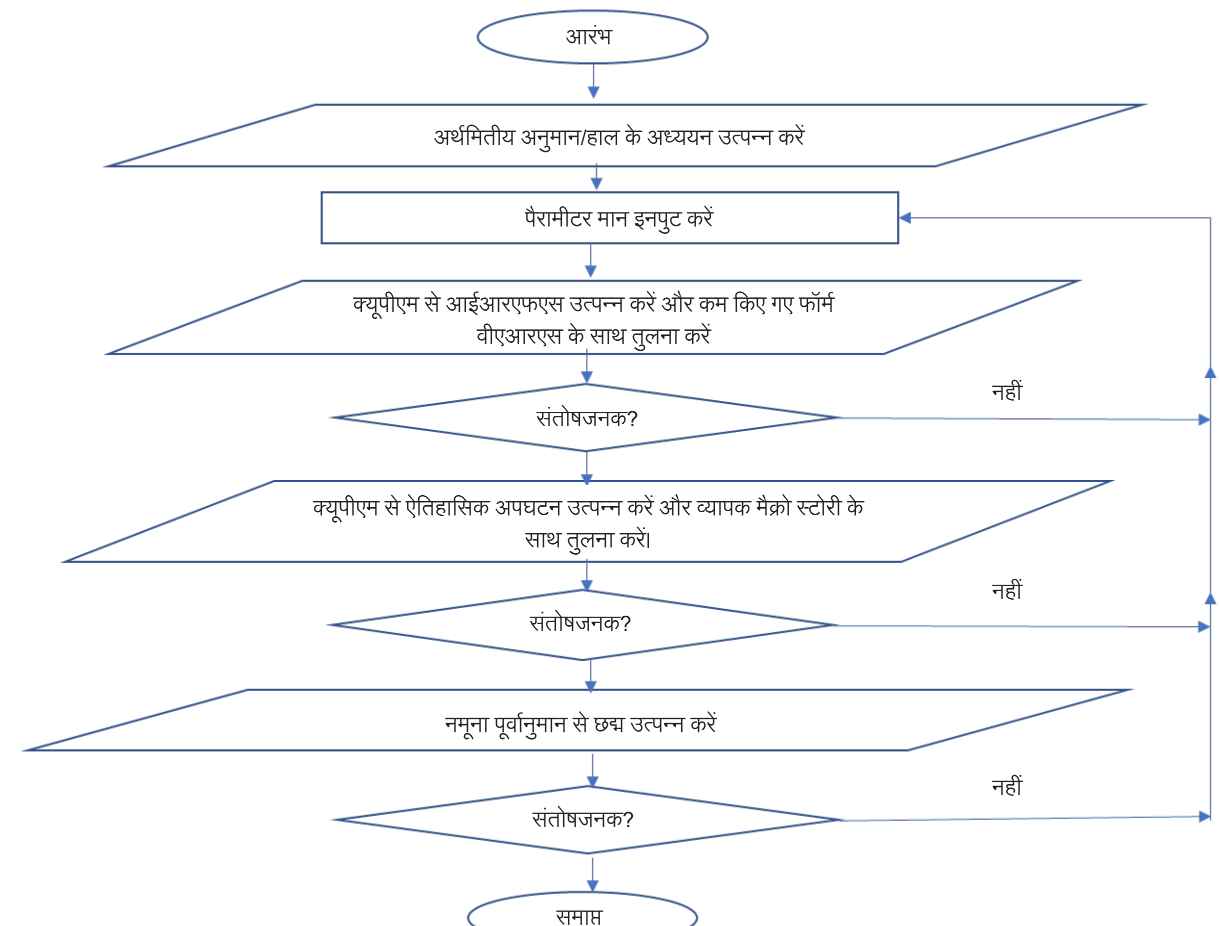

स्रोत: लेखकों का चित्रण।

आवश्यकता है। दूसरा, अग्रगामी चर को शामिल करने वाले गतिशील समाधान प्राप्त किए जाने चाहिए। तीसरा, अनदेखे चर को राज्य-स्थान प्रतिनिधित्व से फ़िल्टर किया जाना है। चौथा, पूर्वानुमान और नीति सिमुलेशन उत्पन्न किया जाना चाहिए।

स्थिर अवस्थाओं की गणना एक नॉनलाइनियर न्यूटन-प्रकार एल्गोरिथ्म का उपयोग करके की जाती है। गतिशील मॉडल समाधान एक नॉनलाइनियर कण झुंड ऑप्टिमाइज़र (पीएसओ) से प्राप्त किया जाता है, और भविष्य की अपेक्षाओं को एकीकृत करने के लिए एक सामान्यीकृत स्चुर अपघटन का उपयोग किया जाता है। एक सटीक नॉनलाइनियर पूर्वानुमान चरण के साथ एक बहुभिन्नरूपी कलमैन फिल्टर (एमवीकेएफ) को नियोजित करके अनदेखे चर को फ़िल्टर किया जाता है। मॉडल से उत्पन्न सिमुलेशन स्थिर अवस्था के आसपास गणना किए गए पहले क्रम के अनुमानित समाधान पर आधारित हैं। शंख त्वरण के साथ समीकरण-चयनात्मक नॉनलाइनर सिम्युलेटर लागू करके पूर्वानुमान उत्पन्न किए जाते हैं।

IV. मॉडल सिमुलेशन

IV.1. आउटपुट गैप (मांग) आघात

1 प्रतिशत अंक (पीपीटी) के सकारात्मक मांग झटके से कोर मुद्रास्फीति अपने चरम पर 20 आधार अंक (बीपीएस) बढ़ जाती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति लगभग 20 बीपीएस बढ़ी। आउटपुट अंतर और अपने लक्ष्य से मुद्रास्फीति के विचलन दोनों के लिए वास्तविक ब्याज दर में वृद्धि की आवश्यकता होती है, जिसे नीतिगत ब्याज दर में वृद्धि के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ये परिवर्तन मांग को कम करते हैं और मध्यम अवधि में, आउटपुट अपने संभावित स्तर पर लौटता है। अतिरिक्त मांग के उन्मूलन के साथ, मुद्रास्फीति लक्ष्य पर लौटती है और सभी वास्तविक चर अपने दीर्घकालिक संतुलन (चार्ट 3) में लौट आते हैं।

IV.2. कोर मुद्रास्फीति (लागत-धक्का) आघात

मुख्य मुद्रास्फीति के लिए लागत-धक्का आघात मौद्रिक नीति को एक कठिन व्यापार-बंद के साथ प्रस्तुत करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत दर में वृद्धि की जानी चाहिए कि मुद्रास्फीति मध्यम अवधि में लक्ष्य पर लौट आए, लेकिन यह एक नकारात्मक आउटपुट अंतर खोलता है (चार्ट 4)। मुद्रास्फीति के लक्ष्य तक गिरने के साथ ब्याज दर में कमी आने से उत्पादन अंतर समाप्त हो जाता है और उत्पादन अपने संभावित स्तर पर लौट आता है।

चार्ट 3: उत्पादन अंतराल में 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि पर प्रतिक्रिया

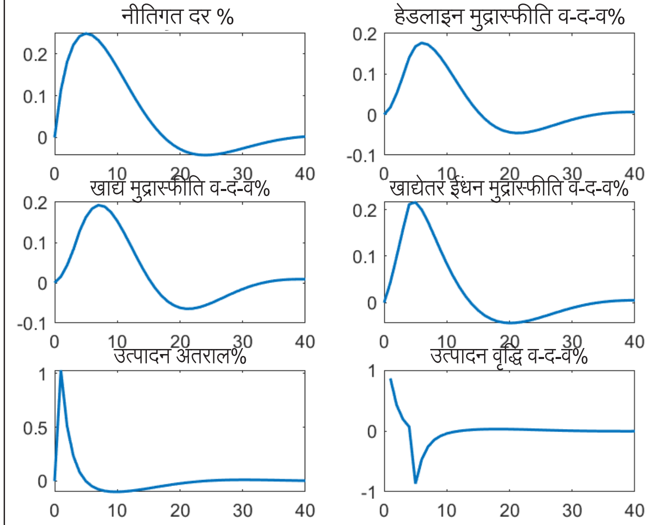

टिप्पणी: एक्स-अक्ष तिमाही हैं; वाई-अक्ष प्रतिशत अंक हैं।
स्रोत: लेखकों के अनुमान।

IV.3. नीतिगत दर का आघात

नीतिगत ब्याज दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू मांग में लगभग 20 बीपीएस की गिरावट आती है और एक नकारात्मक आउटपुट अंतर खुल जाता है (चार्ट 5)। मुद्रास्फीति

चार्ट 4: मूल मुद्रास्फीति में 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि पर प्रतिक्रिया

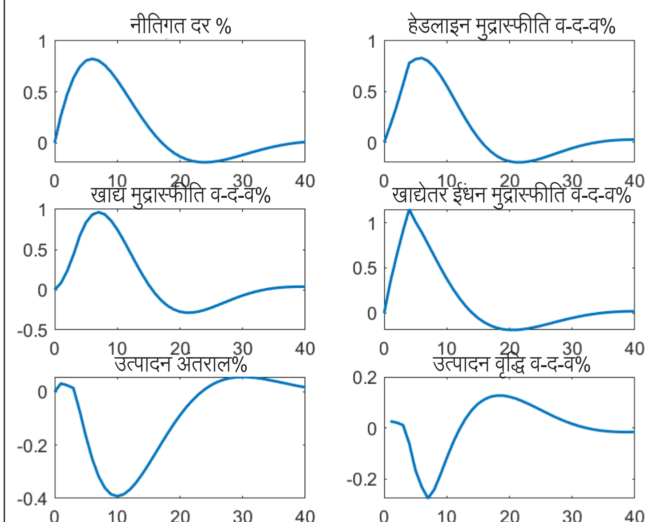

टिप्पणी: एक्स-अक्ष तिमाही हैं; वाई-अक्ष प्रतिशत अंक हैं।
स्रोत: लेखकों के अनुमान।

चार्ट 5: नीतिगत दर में 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि पर प्रतिक्रिया

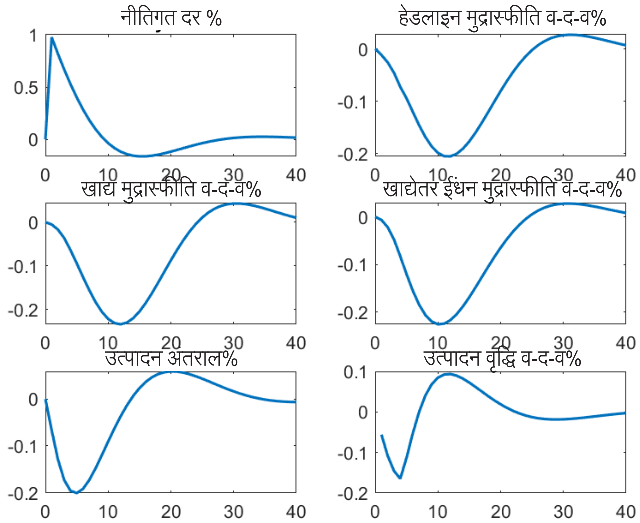

टिप्पणी: एक्स-अक्ष तिमाही हैं; वाई-अक्ष प्रतिशत अंक हैं।
स्रोत: लेखकों के अनुमान।

चार्ट 6: विनिमय दर में 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि पर प्रतिक्रिया

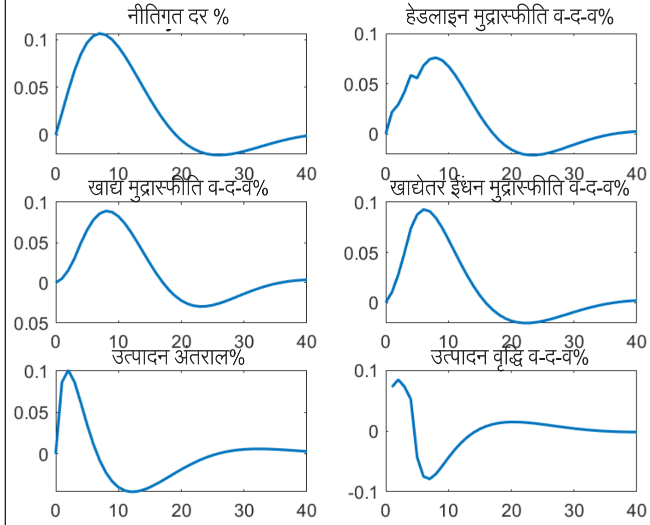

टिप्पणी: एक्स-अक्ष तिमाही हैं; वाई-अक्ष प्रतिशत अंक हैं।
स्रोत: लेखकों के अनुमान।

की उम्मीदों को कम करने और केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता में वृद्धि के साथ, इससे मुख्य मुद्रास्फीति में लगभग 25 बीपीएस और हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगभग 20 बीपीएस की गिरावट आती है। हालांकि, ये प्रभाव केवल अल्पावधि में रहते हैं। समय के साथ, जैसे-जैसे मुद्रास्फीति लक्ष्य पर लौटती है, ब्याज दर कम हो जाती है, जो आउटपुट अंतर को बंद कर देती है और प्रारंभिक ब्याज दर में वृद्धि के विघटनकारी प्रभाव को बेअसर कर देती है।

IV.4. विनिमय दर का आघात

विनिमय दर में 1 प्रतिशत की गिरावट से 7 प्रतिशत की विनिमय दर पास-थ्रू (ईआरपीटी) के माध्यम से मुद्रास्फीति में लगभग 7 बीपीएस की वृद्धि होती है (चार्ट 6)। आउटपुट अंतर शुरू में बाहरी प्रतिस्पर्धा में लाभ के परिणामस्वरूप बढ़ता है। मुद्रास्फीति में वृद्धि और उत्पादन अंतर मौद्रिक सख्ती की मांग करता है। इससे आउटपुट गैप कम हो जाता है, जिससे मध्यम अवधि में नकारात्मक विकास प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं।

IV.5. कच्चे तेल की कीमत में उछाल

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और केरोसिन की कीमतों पर पड़ता है। बाजार ईंधन की कीमतों में वृद्धि लागत को धक्का देती है और मुख्य मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भी भारतीय रुपये (आईएनआर) के अवमूल्यन को प्रेरित करती हैं। इससे मुद्रास्फीति पर दूसरे दौर का अतिरिक्त प्रभाव पड़ेगा। साथ में, कच्चे तेल की कीमत में 10 प्रतिशत की वृद्धि के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति अपने चरम पर 30 बीपीएस तक बढ़ जाती है (चार्ट 7)।

चार्ट 7: कच्चे तेल की कीमतों में 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि पर प्रतिक्रिया

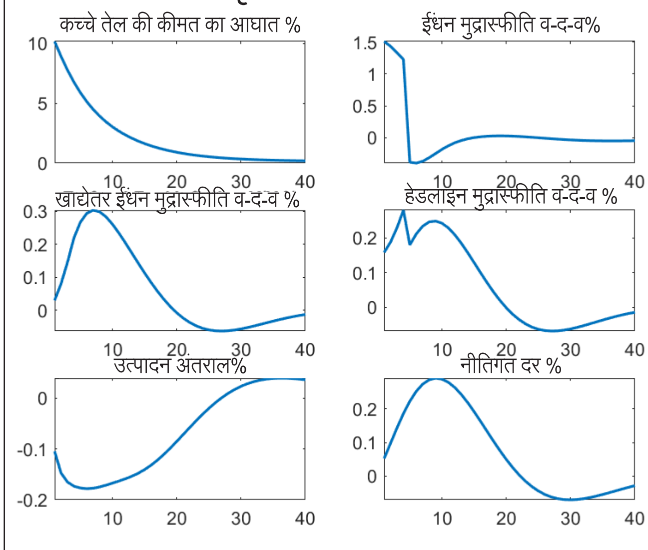

टिप्पणी: एक्स-अक्ष तिमाही हैं; वाई-अक्ष प्रतिशत अंक/ प्रतिशत हैं।
स्रोत: लेखकों के अनुमान।

कुल मांग धीमी हो जाती है क्योंकि कंपनियां अपने लाभ मार्जिन, नकदी प्रवाह और निवेश पर असर डालती हैं। तथापि, मुद्रास्फीतिक दबावों में वृद्धि मुद्रास्फीति को लक्ष्य पर वापस लाने के लिए मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

IV.6. विश्व उत्पादन अंतर (मांग) आघात

विश्व मांग में 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि से घरेलू मांग में 30 बीपीएस की वृद्धि होती है (चार्ट 8), जो मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। विश्व मांग में वृद्धि से अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ती हैं। भारत कच्चे तेल का आयातक होने के कारण, कच्चे तेल की उच्च कीमतें हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं। घरेलू मांग और मुद्रास्फीति में वृद्धि मौद्रिक नीति को कड़ा करने की मांग करती है।

IV.7. ईंधन कर आघात

ईंधन कर में वृद्धि छिटपुट और गैर-मतलबी प्रत्यावर्तन है। इसलिए, क्यूपीएम 2.0 में, ईंधन करों के झटके को उनके मूल मूल्यों पर वापस नहीं माना जाता है जब तक कि उन्हें बहिर्जात रूप से उलट नहीं किया जाता है। ईंधन कर में 10 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि से ईंधन की कीमतों में वृद्धि होती है और इसलिए लागत पुश चैनल के माध्यम से मुख्य मुद्रास्फीति होती है।

चार्ट 8: विश्व उत्पादन अंतराल में 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि पर प्रतिक्रिया

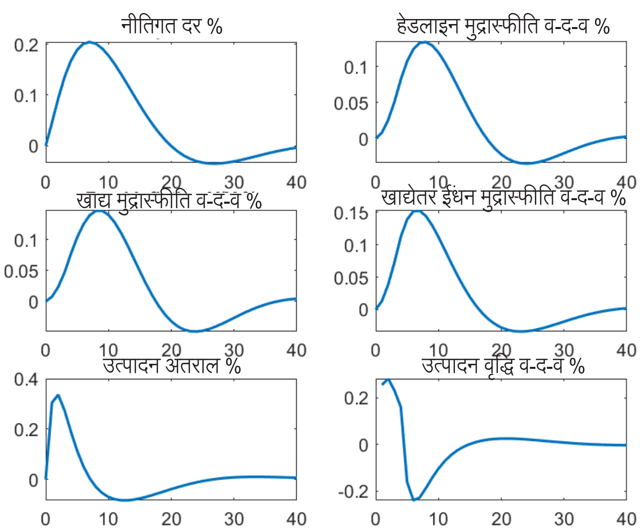

टिप्पणी: एक्स-अक्ष तिमाही हैं; वाई-अक्ष प्रतिशत अंक हैं।
स्रोत: लेखकों के अनुमान।

चार्ट 9: ईंधन करों में प्रति लीटर 10 की वृद्धि पर प्रतिक्रिया

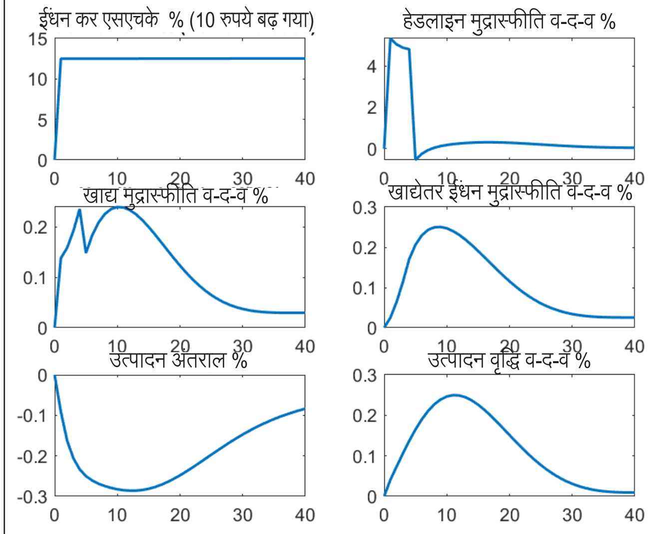

टिप्पणी: एक्स-अक्ष तिमाही हैं; वाई-अक्ष प्रतिशत अंक/ प्रतिशत हैं।
स्रोत: लेखकों के अनुमान।

मुद्रास्फीति 25 बीपीएस तक बढ़ जाती है (चार्ट 9)। वृद्धि यों को वापस न लिए जाने के कारण प्रणाली में मुद्रास्फीति क दबाव बना हुआ है। इसी कारण से मांग की स्थिति भी लंबी अवधि के लिए कम रहती है। मुद्रास्फीति की उम्मीदों को कम करने और दूसरे दौर के प्रभावों को बेअसर करने के लिए नीतिगत दर में वृद्धि की आवश्यकता है।

IV.8. संरचनात्मक प्राथमिक राजकोषीय घाटा आघात

संरचनात्मक प्राथमिक राजकोषीय घाटे में जीडीपी के 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि, मांग में योगदान देती है और धनात्मक उत्पादन अंतराल लाती है (चार्ट 10)। कुल राजकोषीय घाटा समान राशि तक बढ़ जाता है, जिससे कर्ज का संचय होता है, जो देश जोखिम प्रीमियम के माध्यम से भारतीय रुपये (आईएनआर) के मूल्यह्रास में योगदान देता है। धनात्मक उत्पादन अंतराल और मुद्रा मूल्यह्रास, उच्च मुद्रास्फीति में परिणत होता है, जिससे मौद्रिक नीति कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

IV.9. पूंजीगत प्रवाह आघात

पूंजीगत प्रवाह आघात (जीडीपी का एक प्रतिशत अंक) का प्रभाव, आरबीआई के मध्यक्षेप और शोधन करने के फैसले पर सशर्त है। पूंजी बहिर्वाह आघात के मामले में, अगर आरबीआई

चार्ट 10: संरचनात्मक प्राथमिक घाटा में 1 प्रतिशत अंक की कमी पर प्रतिक्रिया

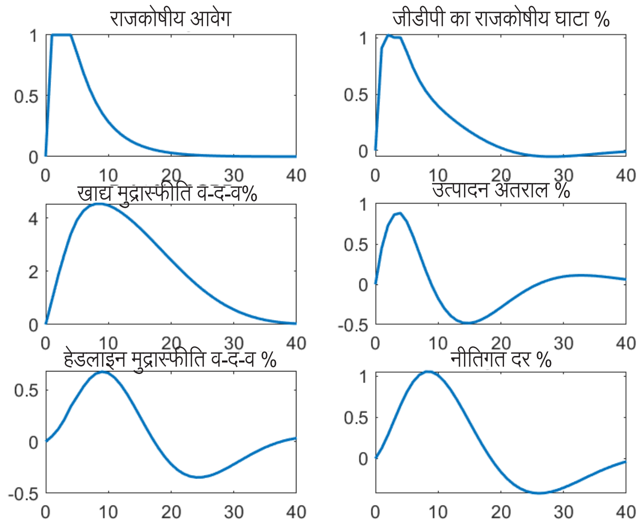

टिप्पणी: एक्स-अक्ष तिमाही हैं; वाई-अक्ष प्रतिशत अंक हैं।
स्रोत: लेखकों के अनुमान।

हस्तक्षेप करता है और 70 प्रतिशत को स्टेरलाइज़ करता है, तो आरक्षित निधियां सांकेतिक जीडीपी के 0.7 प्रतिशत अंक तक कम हो जाएंगी। इस परिदृश्य में, विनिमय दर में लगभग 1 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है, जिससे लगभग 10 आधार अंकों की मुद्रास्फीति जनित हो सकती है (चार्ट 11)।

चार्ट 11: पूंजी प्रवाह में 1 प्रतिशत अंक की गिरावट पर प्रतिक्रिया

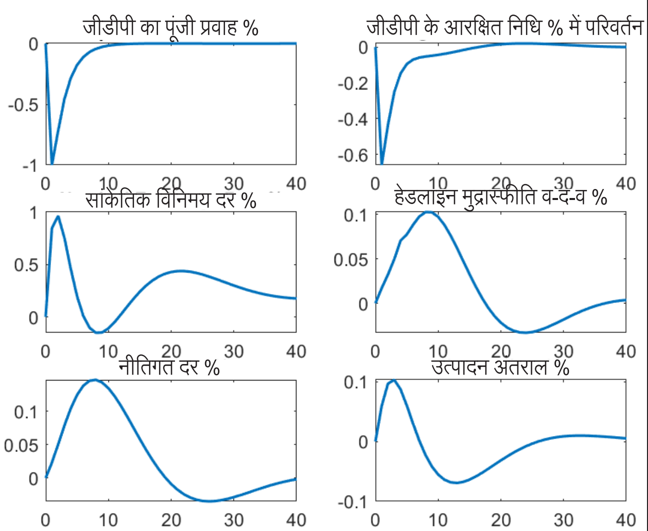

टिप्पणी: एक्स-अक्ष तिमाही हैं; वाई-अक्ष प्रतिशत अंक/ प्रतिशत हैं।
स्रोत: लेखकों के अनुमान।

यदि केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप नहीं करने का निर्णय लेता है, तो आरक्षित निधियों में कोई कमी नहीं होगी; हालांकि, मूल्यह्रास अधिक हो सकता है, जो उच्च मुद्रास्फीति और उच्च नीतिगत दरों में परिणत हो सकती है तथा विनिमय दर, मुद्रास्फीति और नीतिगत दर में अस्थिरता आ सकती है। दूसरी ओर, यदि केंद्रीय बैंक पूरी तरह से हस्तक्षेप करने का विकल्प चुनता है, तो आरक्षित निधियों की समान मात्रा समाप्त हो जाएगी और मौद्रिक नीति दर में परिवर्तन नहीं होने का आश्वासन देते हुए, लेकिन आरक्षित निधियों में अस्थिरता के साथ विनिमय दर कमोबेश अपरिवर्तित रहेगी।

V. ऐतिहासिक अपघटन

2011-2022 की अवधि के लिए प्रमुख समष्टि चरों का एक ऐतिहासिक अपघटन (एचडी), समष्टि-आर्थिक घटनाक्रमों के पथ को चालित करने में विभिन्न आघातों और नीतियों की भूमिका को समझने में मदद करता है।

V.1. हेडलाइन मुद्रास्फीति

2014 से पहले की अवधि में एफआईटी की प्रारंभिक शर्तें निर्धारित की गई थीं – तब हेडलाइन मुद्रास्फीति दहाई अंकों में थी। मानसून और एमएसपी से उत्पन्न होने वाले खाद्य कीमतों के आघात, नॉमिनल एंकर की कमी, विनिमय दर मूल्यह्रास और ईंधन की उच्च कीमतों के कारण उस अवधि के दौरान मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई (चार्ट 12)। 2014 से 2016 के दौरान, जब एक वास्तविक एफआईटी फ्रेमवर्क का अनुसरण किया गया था, तो 2014 से पूर्व की अवधि के दौरान उच्च मुद्रास्फीति में योगदान देने वाले कारक समाप्त हो गए। अनुकूल वैश्विक पण्य कीमतों के बल पर लागत प्रेरित आघात अवस्फीतिकारी हो गए और बाहरी वातावरण के अनुकूल होने पर विनिमय दर स्थिरता बहाल हो गई। 2014 के बाद से, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के ऋणात्मक प्रभाव को दूर करते हुए, ईंधन करों ने मुद्रास्फीति में धनात्मक योगदान देना शुरू कर दिया। इन कारकों के कारण, 2016 में एफआईटी के संस्थागत होने तक मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के करीब पहुंच गई।

2016 के बाद से, एफआईटी द्वारा निर्धारित नॉमिनल एंकर ने मुद्रास्फीति में अनुकूल योगदान दिया। राजकोषीय विवेक ने भी अवस्फीतिकारी प्रक्रिया में योगदान दिया। 2019 की तीसरी तिमाही तक, खाद्य कीमतों के आघातों के कारण मुद्रास्फीति में गिरावट आई। इस अवधि के दौरान ईंधन मूल्य आघात भी अनुकूल थे।

चार्ट 12: हेडलाइन मुद्रास्फीति का ऐतिहासिक आघात अपघटन

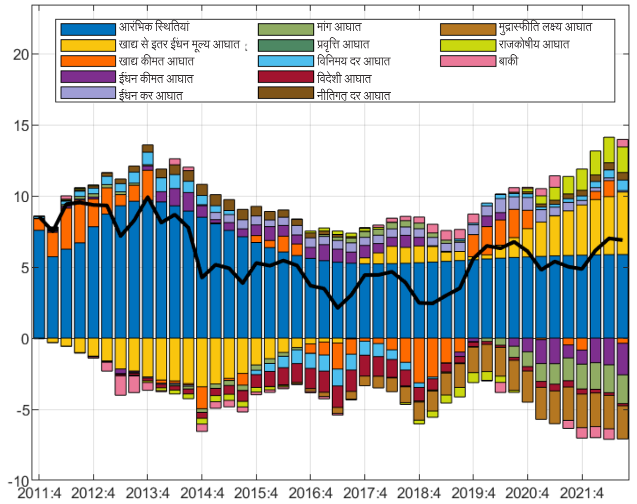

स्रोत: लेखकों के अनुमान।

चार्ट 13: जीडीपी वृद्धि का ऐतिहासिक आघात अपघटन

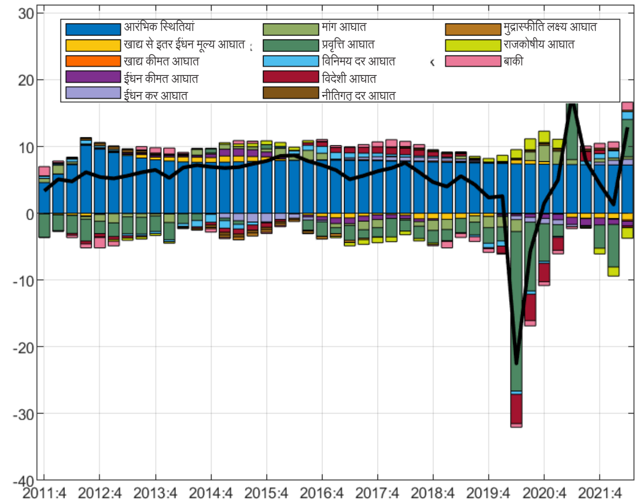

स्रोत: लेखकों के अनुमान।

वर्ष 2020-22 की अवधि के दौरान, कोविड महामारी और यूक्रेन में युद्ध के कारण लगातार आपूर्ति शृंखला व्यवधानों से उत्पन्न होने वाले खाद्य कीमत और लागत-जनित आघातों ने हेडलाइन मुद्रास्फीति पर उल्टा दबाव डाला, जो आंशिक रूप से कमजोर मांग स्थितियों द्वारा उपजा था।

V.2. जीडीपी वृद्धि

जीडीपी वृद्धि का ऐतिहासिक अपघटन (एचडी) सुझाव देता है कि 2016-19 के दौरान जीडीपी वृद्धि में मंदी के लिए अधिकांशतः संभावित उत्पादन आघात और संरचनात्मक कारक जिम्मेदार थे (चार्ट 13)। महामारी-जन्य लॉकडाउन, आपूर्ति शृंखला की बाधाओं और कमजोर बाहरी मांग ने 2020-22 के दौरान घरेलू उत्पादन और मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

V.3. नीतिगत रेपो दर

2014-16 की अवधि में, विनिमय दर में स्थिरता, हितकारी लागत-जनित आघातों और एक अनुकूल बाहरी वातावरण ने नीतिगत दर में ऋणात्मक योगदान दिया। एफआईटी अवधि (2016-2019) के दौरान, अनुकूल खाद्य और ईंधन कीमतों के आघातों, बाह्य विकास और राजकोषीय विवेक ने एक निम्न नीति दर वातावरण का समर्थन किया (चार्ट 14)। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एफआईटी द्वारा निर्धारित नॉमिनल एंकर ने इस चरण के दौरान नीति दर में ऋणात्मक योगदान दिया। दूसरे शब्दों में, नॉमिनल एंकर के अभाव में, मुद्रास्फीति के समान स्तर को प्राप्त करने के लिए नीति दर अधिक हो सकती थी। यह इंगित करता है कि एक स्पष्ट नॉमिनल एंकर के साथ, मौद्रिक नीतिगत दरों को अर्थव्यवस्था को अवस्फीत करने के लिए अन्यथा से कम बढ़ाया जा सकता है।

चार्ट 14: नीतिगत रेपो दर का ऐतिहासिक आघात अपघटन

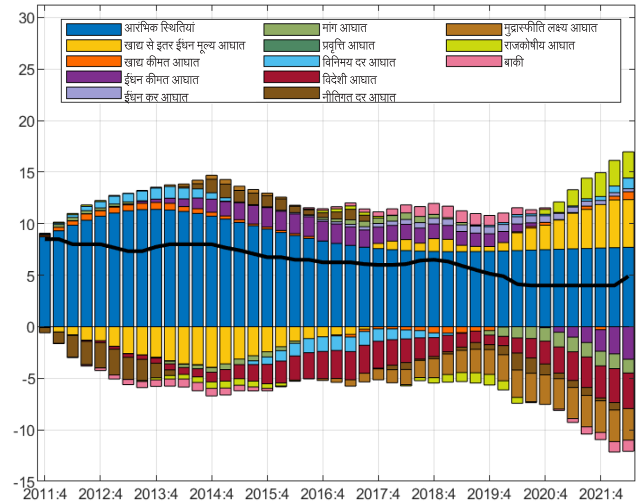

स्रोत: लेखकों के अनुमान।

2020-22 के दौरान, महामारी के कारण एक बड़े ऋणात्मक उत्पादन अंतराल के कारण मौद्रिक नीति को समायोजनकारी रुख का पालन करना पड़ा। उच्च मूल मुद्रास्फीति के साथ-साथ हेडलाइन मुद्रास्फीति के लक्ष्य से ऊपर रहने के मद्देनजर, मई 2022 से नीतिगत रेपो दर को एक सुविचारित तरीके से बढ़ाया गया है।

V.4 मूल मुद्रास्फीति

मूल मुद्रास्फीति का ऐतिहासिक अपघटन (एचडी) हेडलाइन मुद्रास्फीति के समान है। एफआईटी प्रणाली का प्रारंभ, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, राजकोषीय विवेक और अनुकूल बाहरी वातावरण ने 2016-19 के दौरान मूल मुद्रास्फीति को सहारा प्रदान किया, जो ईंधन करों में वृद्धि से ऊर्ध्वगामी दबाव को ऑफसेट करने से कहीं अधिक था (चार्ट 15)। 2020-22 में महामारी-जन्य आपूर्ति शृंखला व्यवधान और लागत-जन्य आघातों के कारण मूल मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई।

चार्ट 15: मूल मुद्रास्फीति का ऐतिहासिक आघात अपघटन

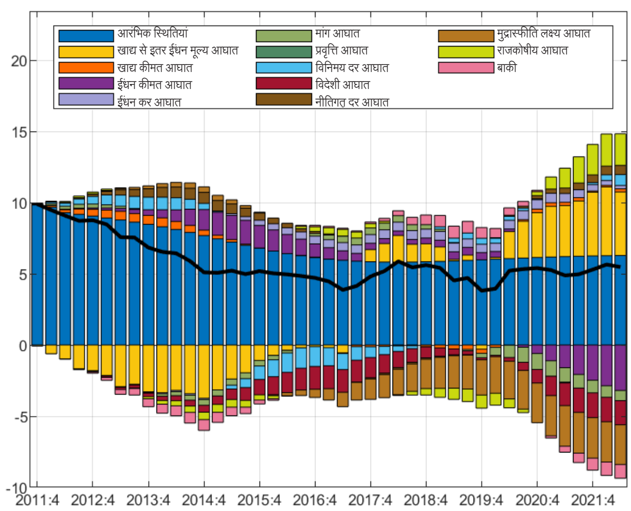

स्रोत: लेखकों के अनुमान।

VI. पूर्वानुमान प्रदर्शन

यह खंड 8 तिमाहियों तक सूडो आउट-ऑफ-सैंपल पूर्वानुमान उत्पन्न करके क्यूपीएम 2.0 के पूर्वानुमान प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और वर्ष 2011 से 2019 तक की अवधि के लिए प्रमुख समष्टि-आर्थिक चरों के सूडो आउट-ऑफ-सैंपल रूट माध्य वर्ग त्रुटियों (आरएमएसई) की गणना करता है (चार्ट 16)।

चार्ट 16: वास्तविक बनाम छद्म आउट-ऑफ-सैंपल पूर्वानुमान (प्रतिशत)

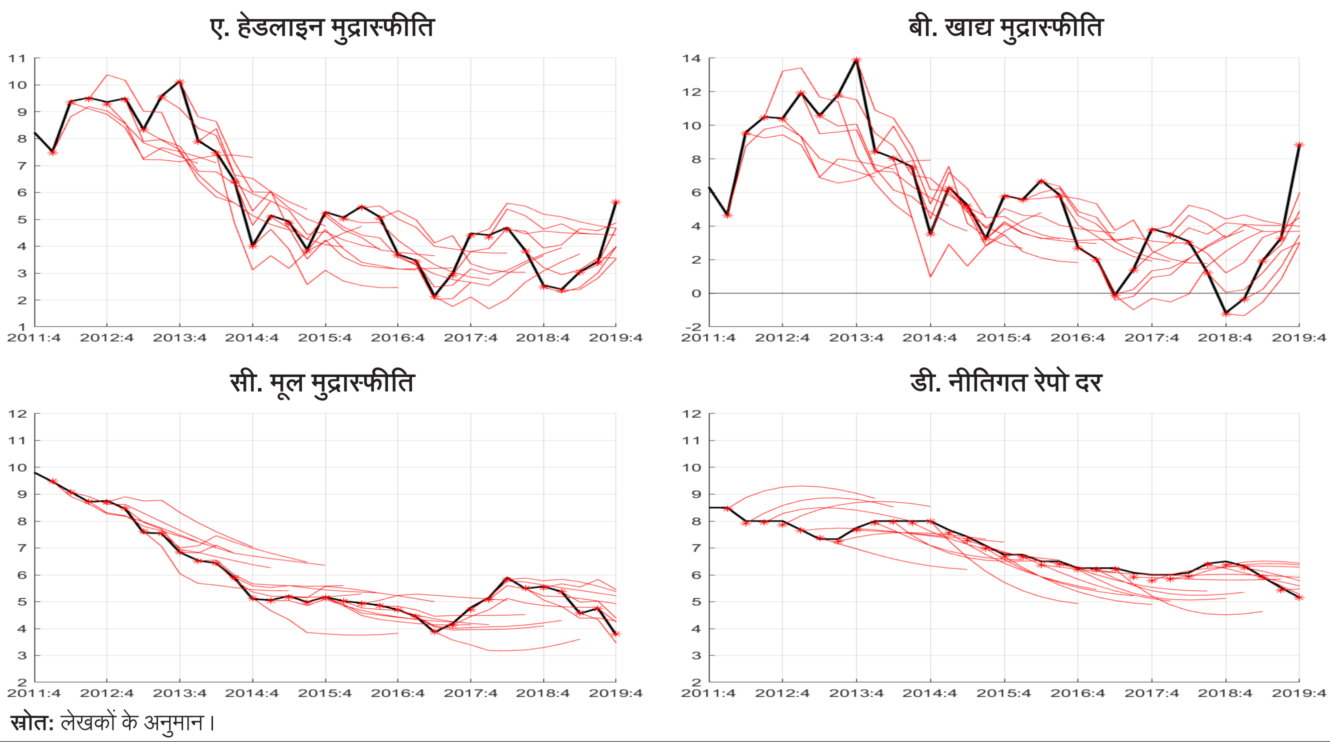

स्रोत: लेखकों के अनुमान।

हेयरलाइन चार्ट संकेत देते हैं कि खाद्य मुद्रास्फीति और हेडलाइन मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान प्रत्यक्ष रूप से सुसंगत प्रतीत होते हैं। मूल मुद्रास्फीति और नीतिगत दर के पूर्वानुमान खाद्य और हेडलाइन मुद्रास्फीति के पूर्वानुमानों की तुलना में कम उतार-चढ़ाव वाले प्रतीत होते हैं।

विभिन्न पूर्वानुमान हॉरीजॉन पर सूडो आउट-ऑफ-सैंपल आरएमएसई उत्पन्न करके पूर्वानुमान का एक औपचारिक मूल्यांकन किया जाता है (सारणी 2)।

लघु से मध्यम हॉरीजॉन (1-4 तिमाहियों) में हेडलाइन मुद्रास्फीति के पूर्वानुमानों के आरएमएसई, समय शृंखला के पूर्वानुमानों की तुलना में मामूली रूप से अधिक हैं और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के सर्वेक्षण (एसपीएफ) के साथ तुलनीय हैं (जॉन और अन्य, 2020; राज और अन्य, 2020)। सर्वोत्तम समय शृंखला पूर्वानुमानों के आरएमएसई 1-4 तिमाहियों में 0.2 से 0.6 प्रतिशत अंक कम हैं। ऐसा व्यवहार अपेक्षित है क्योंकि समय शृंखला और पूर्ण सूचना मैट्रिक्स के आधार पर मॉडल के सापेक्ष बड़े समष्टि-आर्थिक मॉडल अल्पावधि में बड़ी त्रुटियां उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि क्यूपीएम अपनी प्रारंभिक स्थिति के रूप में अल्पकालिक पूर्वानुमानकर्ताओं के पूर्वानुमानों का उपयोग करता है। मध्यम हॉरीजॉन (5-8 तिमाहियों) में पूर्वानुमान प्रदर्शन में काफी सुधार होता है, जो मौद्रिक नीति निर्णय के लिए मायने रखता है। आगे की आठ-तिमाही के पूर्वानुमानों में, क्यूपीएम ने समय शृंखला मॉडल से काफी बेहतर प्रदर्शन किया (जॉन और अन्य, 2020)।

मूल मुद्रास्फीति पूर्वानुमानों के आरएमएसई वस्तुतः हेडलाइन मुद्रास्फीति की तुलना में काफी कम हैं। जैसा कि हेडलाइन मुद्रास्फीति के मामले में, क्यूपीएम से मूल मुद्रास्फीति पूर्वानुमानों के आरएमएसई समय शृंखला पूर्वानुमानों की तुलना में अधिक हैं और 1-4 तिमाही हॉरीजॉन पर एसपीएफ पूर्वानुमानों के साथ तुलनीय हैं (जॉन और अन्य, 2020)। हालांकि, मध्यम हॉरीजॉन में, क्यूपीएम 2.0 की पूर्वानुमान सटीकता, समय शृंखला मॉडल पूर्वानुमानों से काफी बेहतर है (जॉन और अन्य, 2020)।

तालिका 2: सौडो आउट-ऑफ-सैंपल आरएमएसई

(प्रतिशत बिंदु)

चर/ होराइजन (चौथाई)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
मुख्य मुद्रास्फीति (प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)	0.05	0.80	1.07	1.40	1.61	1.50	1.34	1.30	1.21
खाद्य मुद्रास्फीति (प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)	0.05	1.60	2.04	2.59	2.91	2.63	2.48	2.55	2.32
कोर मुद्रास्फीति (प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)	0.03	0.32	0.54	0.73	0.96	0.98	0.99	0.99	0.96
पॉलिसी दर (प्रतिशत)	0.09	0.34	0.58	0.73	0.82	0.91	0.92	0.88	0.79

स्रोत: लेखकों का अनुमान.

VII. निष्कर्ष

उत्पादन और मुद्रास्फीति पर मौद्रिक नीति के प्रभाव की विशेषता दर्शाने वाले संक्रमण अंतराल को देखते हुए, अपेक्षित मुद्रास्फीति और उत्पादन के लिए भविष्योन्मुख प्रतिक्रियाएं, अधिकतम कल्याण करने के लिए आवश्यक हैं। मुद्रास्फीति और उत्पादन, दोनों ही भावी ब्याज दरों की प्रत्याशाओं के साथ-साथ परिवारों और फर्मों की मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं से भी प्रभावित होते हैं। इस प्रकार, मुद्रास्फीति और उत्पादन, अर्थव्यवस्था में पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया तंत्र के एक जटिल जाल का परिणाम हैं। तदनुसार, मुद्रास्फीति और उत्पादन के सुसंगत और विश्वसनीय पूर्वानुमान महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे मौद्रिक नीति के मध्यवर्ती लक्ष्य की भूमिका निभाते हैं। यह इस संदर्भ में है कि देश-विशिष्ट विशेषताओं को अपनाने वाले सैद्धांतिक रूप से सुसंगत और अनुभवजन्य रूप से अच्छी तरह से स्थापित मॉडल आधुनिक केंद्रीय बैंकों के बीच मौद्रिक नीति निर्माण के केंद्र में हैं।

भारत में, एक लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे को अपनाने में एक त्रैमासिक पूर्वानुमान मॉडल द्वारा सहारा लिया गया है, जो अर्ध-वार्षिक मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) में 6-18 महीनों के लिए मुद्रास्फीति पूर्वानुमान निर्धारित करने के लिए आरबीआई अधिनियम की धारा 45जेडएम में निर्धारित आवश्यकता को पूरा करता है।

क्यूपीएम 2.0 उस प्रयास को अगले स्तर तक ले जाता है, मौजूदा नए-कीनेसियन मौद्रिक मॉडल (क्यूपीएम 1.0) को निम्न के साथ समृद्ध किया: राजकोषीय-मौद्रिक नीति विचार-विमर्श, भारत-विशिष्ट ईंधन मूल्य निर्धारण की एक अधिक सूक्ष्म मॉडलिंग, पूंजी प्रवाह, विनिमय दर गतिशीलता और केंद्रीय बैंक के विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप। क्यूपीएम 2.0 इस प्रकार मौद्रिक नीति मॉडलिंग को एक सामान्य संतुलन ढांचे के करीब ले जाता है जो भारत की समष्टि-आर्थिक गतिशीलता को अधिक बेहतर तरीके से दर्शाती है और आंतरिक रूप से सुसंगत पूर्वानुमान और नीति परिदृश्य उत्पन्न करने में मदद करता है। यह नीति निर्माताओं को

अधिक सूचित निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक जानकारी और परिदृश्य प्रदान करता है।

क्यूपीएम 2.0 से उत्पन्न ऐतिहासिक अपघटन से पता चलता है कि महामारी और यूक्रेन में युद्ध के मद्देनजर मुद्रास्फीति की वृद्धि लगातार आपूर्ति के आघातों से शुरू हुई थी, लेकिन जैसे-जैसे उनके प्रभाव कम हुए, घरेलू सुधार को मजबूत करने से बढ़ती मांग ने बढ़ी हुई इनपुट लागत के प्रभाव-विस्तार को सक्षम किया एवं बढ़े हुए मुद्रास्फीतिक दबावों में निरंतरता आई (पात्र एवं अन्य, 2022)। इस अवधि के दौरान अपनाई गई अवस्फीति रणनीति को प्रतिस्पर्धी मॉडलों के सापेक्ष क्यूपीएम 2.0 द्वारा उत्पन्न पूर्वानुमानों में बेहतर सटीकता द्वारा दृढ़ता से समर्थन दिया गया है।

संदर्भ

बेहरा, एच.के., पटनायक, एस., एंड कावेडिया, आर. (2017)। नैचुरल इंटरेस्ट रेट: असेससिंग दि स्टांस ऑफ इंडियास मॉनेटरी पॉलिसी अंडर अनसर्टेनिटी। जर्नल ऑफ पॉलिसी मॉडलिंग, 39(3), 482-498।

बेन्स, एम.जे., क्लिंटन, के., जॉर्ज, ए., जॉन, जे., कामेनिक, ओ., लैक्सटन, एम.डी., मित्रा, पी., नथनएल, जी.वी., वांग, एच. और झांग, एफ. (2016ए)। इंफ्लेशन-फोरकास्ट टार्गेटिंग फॉर इंडिया: ऐन आउटलाइन ऑफ दि एनालिटिकल फ्रेमवर्क। आरबीआई वर्किंग पेपर सीरीज नंबर 7/2016।

बेन्स, एम.जे., क्लिंटन, के., जॉर्ज, ए., गुप्ता, पी., जॉन, जे., कामेनिक, ओ., लैक्सटन, एमडी, मित्रा, पी., नथनएल, जी.वी., पोर्टिलो, आर. और वांग, एच (2016बी)। क्वार्टरली प्रॉजेक्शन मोडेल फॉर इंडिया: की एलिमंट्स एंड प्रॉपर्टीज। आरबीआई वर्किंग पेपर सीरीज नंबर 8/2016।

ब्लैंचर्ड, ओ., और पेरोटी, आर. (2002)। अन एम्पिरिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ़ दि डायनामिक इफेक्ट्स ऑफ़ चंगेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेज ऑन आउटपुट। दि क्वार्टरली जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का त्रैमासिक जर्नल, 117(4), 1329-1368।

ब्लैंचर्ड, ओ., ओस्ट्री, जेडी, घोष, एआर, और चेमोन, एम. (2016)। कैपिटल फ्लोज: एक्सपैंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी? अमेरिकन इकनोमिक रिव्यू, 106(5), 565-569।

कैनज़ोनेरी, एम., क्यूम्बी, आर., और दीबा, बी (2010)। दि इंटरेक्शन बिटवीन मोनेटरी एंड फिस्कल पालिसी। हैंडबुक ऑफ़ मोनेटरी इकोनॉमिक्स, 3, 935-999।

फ्लेमिंग, जेएम (1962)। डोमेस्टिक फाइनेंसियल पॉलिसीस अंडर फिक्स्ड एंड अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स। स्टाफ पेपर्स-इंटरनेशनल मोनेटरी फण्ड, 369-380।

एंगेल, सी. (1996)। दि फॉरवर्ड डिस्काउंट अनोमोली एंड दि रिस्क प्रीमियम: ए सर्वे ऑफ़ रीसेंट एविडेंस. जर्नल ऑफ़ एम्पिरिकल फाइनेंस, 3(2), 123-192।

एस्कोलानो, जे. (2010)। ए प्रैक्टिकल गाइड टू पब्लिक डेब्ट डायनामिक्स, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, एंड सिक्लिसाल एडजस्टमेंट ऑफ़ बजटरी अग्रेगेट्स नं (2010/002)। वाशिंगटन डीसी: इंटरनेशनल मोनेटरी फण्ड।

फ्रूट, केए, और थेलर, आरएच (1990)। अनोमालिएस: फॉरेन एक्सचेंज. जर्नल ऑफ़ इकनोमिक पर्सपेक्टिव्स, 4(3), 179-192।

गली, जे., और मोनासेली, टी। (2005)। मोनेटरी पालिसी एंड एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी इन अ स्माल ओपन इकॉनमी. थे रिव्यु ऑफ़ इकनोमिक स्टडीज, 72(3), 707-734।

घोष, ए.आर., ओस्ट्री, जेडी, और चामोन, एम. (2016)। टू टारगेट्स टू इंस्ट्रूमेंट्स: मोनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसीस इन इमर्जिंग मार्केट इकनोमीज। जर्नल ऑफ़ इंटरनेशनल मनी एंड फाइनेंस, 60, 172-196।

गोपीनाथ, जी., बोज़, ई., कास, सी., डायज़, एफजे, गौरिनचास, पीओ, और प्लागबोर्ग-मोलर, एम. (2020)। डोमिनेंट करेंसी पैराडाइम। अमेरिकन इकनोमिक रिव्यू, 110(3), 677-719।

गोयल, ए., और परब, पी. (2019)। इन्फ्लेशन कन्वर्जेन्स एंड एंकरिंग ऑफ़ एक्सपेक्टेशन्स इन इंडिया (नं. 2019-23)। इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ़ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई इंडिया।

जॉन, जे., कुमार, डी., और पात्र, एमडी (2022)। मोनेटरी पालिसी: कोंफ्रोंटिंग सप्लाई-ड्रिवेन इन्फ्लेशन, आरबीआई बुलेटिन, जून।

जॉन, जे., सिंह, एस., और कपूर, एम. (2020)। इन्फ्लेशन फोरकास्ट कॉम्बिनेशंस – दि इंडियन एक्सपीरियंस, आरबीआई वर्किंग पेपर सीरीज नंबर 11/2020।

खुंद्रकपम, जेके, और जैन, आर. (2012) मोनेटरी पालिसी ट्रांसमिशन इन इंडिया: ए पीप इनसाइड दि ब्लैक बॉक्स। भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर संख्या 11/2012 ।

लुईस, केके (1995)। पज़ल्स इन इंटरनेशनल फाइनेंसियल मार्केट्स। हैंडबुक ऑफ़ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, 3, 1913 1971 ।

मिरांडा-एग्रिपिनो, एस., और रे, एच. (2022)। ग्लोबल फाइनेंशियल साइकिल, एडिटर: गोपीनाथ, जी., हेल्पमैन, ई., और रोगॉफ, के. हैंडबुक ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, एल्सेवियर, 1-43,

मिश्रा, एस., और त्रिवेदी, पी. (2016)। स्ट्रक्चरल फिस्कल बैलेंस: ऐन एम्पिरिकल इन्वेस्टीगेशन फॉर इंडिया। आरबीआई ओकेसनल पेपर, 35 ।

मुंडेल, आरए (1963)। कैपिटल मोबिलिटी एंड स्टेबिलाइजेशन पालिसी अंडर फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स। कैनेडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, 29(4), 475-485।

ओब्स्टफेल्ड, एम., और रोगॉफ, के. (2000)। नई डिरेक्शंस फॉर स्टचास्तिक ओपन इकॉनमी मॉडल्स. जर्नल ऑफ़ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, 50(1), 117-153।

पात्र, एम.डी., बेहरा, एच.के., और जॉन, जे. (2021)। इस दि फिलिप्स कर्व इन इंडिया डेड इनर्ट एंड स्टिररिंग टू लाइफ ऑर अलाइव एंड वेल? आरबीआई बुलेटिन, नवंबर।

पात्र, एम.डी., जॉर्ज, एटी, नथनएल, जी., और जॉन, जे. (2022)। एनाटोमी ऑफ़ इन्फ्लेशन'स एसेंट इन इंडिया। आरबीआई बुलेटिन, दिसंबर।

पात्र, एमडी, खुंद्रापकम, जे एंड जॉन, जे (2018)। नॉन-लीनियर, असिमेट्रिक एंड टाइम-वारयिंग एक्सचेंज रेट पास-थ्रू: रीसेंट एविडेंस फ्रॉम इंडिया। आरबीआई वर्किंग पेपर सीरीज नंबर 2/2018 ।

पटनायक, एस., बेहरा, एच.के., और शर्मा एस. (2022)। रेविसिटिंग इंडिया'स नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आरबीआई बुलेटिन, जून।

कपूर, एम. (2018)। मैक्रोइकॉनॉमिक पॉलिसीस एंड ट्रांसमिशन डायनामिक्स इन इंडिया। एसएसआरएन 3253802 पर उपलब्ध है।

राज, जे., कपूर, एम., दास, पी., जॉर्ज, एटी, वाही, जी. और कुमार, पी. (2019)। इन्फ्लेशन फोरेकास्ट्स: रीसेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया एंड ए क्रॉस-कंट्री असेसमेंट। मिंट स्ट्रीट मेमो नंबर 19, भारतीय रिज़र्व बैंक।

राज, जे., पटनायक, एस., भट्टाचार्य, आई., और अभिलाषा। (2018)। फोरेक्स मार्किट ऑपरेशन्स एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट, आरबीआई बुलेटिन, अगस्त।

आरबीआई. (2018), मैक्रोइकॉनॉमिक्स ऑफ़ क्रूड आयल प्रिसेंस। बॉक्स I.1, मौद्रिक नीति रिपोर्ट, अक्टूबर।

आरबीआई. (2019), आउटपुट गैप और कोर इन्फ्लेशन। बॉक्स I.1, मौद्रिक पॉलिसी रिपोर्ट, अप्रैल।

आरबीआई. (2021), कैपिटल फ्लो एंड एक्सचेंज रेट शॉक्स: मैक्रोइकॉनॉमिक इम्प्लिकेशन्स। बॉक्स I.1, मौद्रिक पॉलिसी रिपोर्ट, अक्टूबर।

वुडफोर्ड, एम. (2001)। फिस्कल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्राइस स्टेबिलिटी। जर्नल ऑफ मनी, क्रेडिट एंड बैंकिंग, 33(3), 669-728।

अनुबंध

बैंक-ऋण (बीएल) की स्थिति

बीएल चर[11], बैंक-ऋण (बीएल) की आपूर्ति स्थितियों के कारण मौद्रिक नीति के संचरण तंत्र में घर्षण को दर्शाता है। बीएल न केवल उत्पादन अंतराल (आउटपुट गैप) को प्रभावित करता है बल्कि उससे प्रभावित भी होता है। इसलिए, इसके संतुलन स्तर से बीएल के विचलन को भावी उत्पादन अंतराल ($\hat{y}_{t+4}^{nag}$) के लिए आनुपातिक रूप से तैयार किया जाता है और आघात (ε_t^{BL}) के लिए समायोजित किया जाता है:

$$BL_t - \overline{BL}_t = -\kappa_1 \cdot \hat{y}_{t+4}^{nag} + \varepsilon_t^{BL}.$$

$$\kappa_1 = 5. \qquad ...(33)$$

उत्पादन अंतराल ε_t^{BL} द्वारा दर्शाए गए η_t^{BL} के वितरित अंतराल से प्रभावित होता है, जो निम्नलिखित रूप लेता है:

$$\eta_t^{BL} = \theta \cdot (0.04\varepsilon_{t-1}^{BL} + 0.08\varepsilon_{t-2}^{BL} + 0.12\varepsilon_{t-3}^{BL} + 0.16\varepsilon_{t-4}^{BL} + 0.20\varepsilon_{t-5}^{BL}$$

$$+0.16\varepsilon_{t-6}^{BL} + 0.12\varepsilon_{t-7}^{BL} + 0.08\varepsilon_{t-8}^{BL} + 0.04\varepsilon_{t-9}^{BL}).$$

$$\theta = 1. \qquad ...(34)$$

मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएं

मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा निर्धारित की जाती हैं:

$$E_t^{\,h}(\pi 4_{t+1}^{core}) = (1 - c_t) * \pi 4_{t-1}^{core} + c_t * \pi 4_{t+1}^{core} + \eta_t^{E(\pi 4^{core})}$$

$$\eta_t^{E(\pi 4^{core})} = \rho^{\eta^{E(\pi 4^{core})}} \cdot \eta_{t-1}^{E(\pi 4^{core})} + \varepsilon_t^{E(\pi 4^{core})}.$$

$$\rho^{\eta^{E(\pi 4^{core})}} = 0.4. \qquad ...(35)$$

मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएं एक तिमाही पिछड़ी हुई वर्ष-दर-वर्ष मूल मुद्रास्फीति और वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति की एक तिमाही आगे की मॉडल-आधारित तर्कसंगत प्रत्याशा का भारित योग है। भार, नीति विश्वसनीयता (c_t) के स्टॉक पर निर्भर करता है। c_t, 0 (कोई विश्वसनीयता नहीं) जिसमें प्रत्याशाएं पूरी तरह से पिछड़ी दिख रही हैं, से लेकर, 1 (पूर्ण विश्वसनीयता) तक, जिस स्थिति में मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएं पूरी तरह से आगे दिख रही हैं, हो सकता है।

[11] बीएल (बैंक-ऋण) चर में वृद्धि, बैंक ऋण स्थिति को कड़ा करने और इसके विलोमतः को दर्शाती है।

विश्वसनीयता स्टॉक बिल्डिंग

विश्वसनीयता, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, को 0 और 1 के बीच मापे गए स्टॉक (c_t) के रूप में तैयार किया गया है। विश्वसनीयता गैर-रैखिक रूप से बदलती है, यानी विश्वसनीयता के निचले स्तर पर, मौद्रिक नीति को अवस्फीति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से आक्रामक होने की आवश्यकता होती है। हालांकि, जैसे-जैसे विश्वसनीयता स्टॉक बढ़ता है, वैसे-वैसे अवस्फीति की समान मात्रा हासिल करने के लिए नीतिगत प्रतिक्रियाएं कम हो सकती हैं।

विश्वसनीयता में धीरे-धीरे, समय के साथ ही सुधार हो सकता है, विशेषकर एफआईटी के शुरुआती दौर में। विश्वसनीयता एक संकेत (ξ_t) पर प्रतिक्रिया करती है, जो कि अच्छी है - यदि मुद्रास्फीति लक्ष्य (अच्छे) में परिवर्तित हो रही है, और यह खराब है – यदि उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति (खराब) की ओर बढ़ रही है। (π^{bad}).

$$c_t = \rho^c \cdot c_{t-1} + (1 - \rho^c) \cdot \xi_t.$$

$$\rho^c = 0.95. \qquad ...(36)$$

विश्वसनीयता संकेत मुद्रास्फीति के लक्ष्य में परिवर्तित होने की सापेक्ष संभावना का भार करता है। यह अधिक है, यदि वर्तमान वास्तविक मुद्रास्फीति लक्ष्य के करीब है। खराब (अच्छे) रेजाइम के तहत त्रुटि को, वास्तविक मुद्रास्फीति और खराब (अच्छे) रेजाइम के तहत प्रत्याशित मुद्रास्फीति के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है।

$$\xi_t = \frac{(\epsilon_t^{bad})^2}{(\epsilon_t^{bad})^2 + (\epsilon_t^{good})^2}. \qquad ...(37)$$

$$\epsilon_t^{bad} = \pi 4_t - [\rho^\epsilon \cdot \pi 4_{t-1} + (1 - \rho^\epsilon) \cdot \pi^{bad}]. \qquad ...(38)$$

$$\epsilon_t^{good} = \pi 4_t - [\rho^\epsilon \cdot \pi 4_{t-1} + (1 - \rho^\epsilon) \cdot \pi^{good}].$$

$$\rho^\epsilon = 0.5;\ \pi^{bad} = 8.0;\ \pi^{good} = 4.0\,. \qquad ...(39)$$

खराब (अच्छी) रेजाइम के तहत, पिछली और प्रत्याशित मुद्रास्फीति के लिए समान भार मानते हुए ρ^ϵ को 0.5 माना जाता है। अच्छे रेजाइम की विशेषता 4.0 प्रतिशत मुद्रास्फीति है और खराब रेजाइम की विशेषता मुद्रास्फीति का उच्च स्तर (8 प्रतिशत) है।

दीर्घकालीन ब्याज दरें

अल्पकालिक दर ($\breve{\iota}_t$) और दीर्घकालिक दर (i_t^m) के बीच का संबंध (i_t^4) के साथ-साथ सावधि प्रीमियम (जोखिम) पर निर्भर करता है। (i_t^{RISK}).

$$i_t^m = \rho^{i^m} . i_{t-1}^m + \left(1 - \rho^{i_t^m}\right) \cdot (i_t^4 + i_t^{RISK}) + \varepsilon_t^{i^m}$$

$$\rho^{i^m} = 0.1. \quad ...(40)$$

ब्याज दर की अवधि संरचना (i_t^4) अल्पकालिक दरों का चार तिमाही आगे का औसत है और सावधि प्रीमियम पिछले मान के भारित औसत के साथ-साथ i_t^{RISK} के लिए स्टेडी स्टेट मान है।

दीर्घकालिक दर (i_t^m) से प्रत्याशित मुद्रास्फीति $(E_t{}^h(\pi 4_{t+1}^{core})$ घटाने पर दीर्घकालिक वास्तविक ब्याज दर (r_t^m) मिलती है और वास्तविक ब्याज दर अंतराल $(\hat{r}_t^m)$ ब्याज की मूल दर (r_t^m) से वास्तविक ब्याज दर $(\bar{r}_t^m)$ का विचलन है।.

$$r_t^m = i_t^m - E_t{}^h(\pi 4_{t+1}^{core}) \quad ...(41)$$

$$\hat{r}_t^m = r_t^m - \bar{r}_t^m \quad ...(42)$$

सापेक्ष खाद्य कीमत प्रवृत्तियां

$$\overline{rp}_t^{food} = \rho^{\overline{rp}^{food}} \overline{rp}_{t-1}^{food} + (1 - \rho^{\overline{rp}^{food}}) \overline{rp}^{food^*} + \eta_t^{\overline{rp}^{food}} + \theta \cdot \varepsilon_t^{MSP} + \varepsilon_{1,t}^{\overline{rp}^{food}} \quad ...(43)$$

$$\eta_t^{\overline{rp}^{food}} = \rho^{\eta^{\overline{rp}^{food}}} \cdot \eta_{t-1}^{\overline{rp}^{food}} + \left(1 - \rho^{\eta^{\overline{rp}^{food}}}\right) \cdot \varepsilon_{2,t}^{\overline{rp}^{food}}. \quad ...(44)$$

$$\rho^{\overline{rp}^{food}} = 0.9;\ \theta = 0.4;\ \rho^{\eta^{\overline{rp}^{food}}} = 0.9.$$

सापेक्ष खाद्य कीमत प्रवृत्तियां $(\overline{rp}_t^{food})$ इसके पिछले $(\overline{rp}_{t-1}^{food})$, स्थिर स्टेट लेवेल $(\overline{rp}^{food^*})$, चल औसत प्रक्रिया $(\eta_t^{\overline{rp}^{food}})$, एमएसपी को आघात (ε_t^{MSP}) और अटपटे आघातों $(\varepsilon_{1,t}^{\overline{rp}^{food}})$ पर निर्भर करती है।

*केंद्रीय बजट 2023-24: एक आकलन**

सक्षम सूद, इप्सिता पाढ़ी, अनूप के. सुरेश, बिचित्रानंद सेठ और समीर रंजन बेहरा द्वारा

केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजीगत व्यय को विकास के प्रमुख संवाहक के रूप में परिकल्पित किया गया है और यह समष्टि-स्थिरता को मजबूत करने के लिए विश्वसनीय राजकोषीय समेकन के लिए प्रतिबद्ध है। सार्वजनिक ऋण के स्तर में कमी आई है क्योंकि सरकार ने महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का सहारा लिया है। बुनियादी ढांचे के निर्माण, डिजिटलीकरण, हरित संक्रमण और युवा सशक्तिकरण के बजट प्रस्तावों से अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को बढ़ाकर निकट भविष्य में लाभांश मिलने की उम्मीद है।

परिचय

केंद्रीय बजट 2023-24 ऐसे समय में आया है जब एक अन्यथा निर्जन वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत को वैश्विक स्तर पर एक उज्ज्वल स्थान के रूप में देखा जा रहा है। यह समष्टि-आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देते हुए विकास और रोजगार सृजन को गति देने के उद्देश्य से उपायों के माध्यम से सही तालमेल बिठाता है। बजट में सात प्राथमिकताओं को अपनाया गया है जो एक-दूसरे के पूरक हैं यथा समावेशी विकास, बुनियादी ढांचा और निवेश, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, क्षमता का उपयोग करना, हरित विकास, युवा शक्ति और अपने नीतिगत उद्देश्यों का मार्गदर्शन करने के लिए वित्तीय क्षेत्र। ये पहल लंबी अवधि में उत्पादकता लाभ प्रदान करते हुए अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाएगी।

यूरोप में युद्ध के कारण आपूर्ति में बड़े पैमाने पर व्यवधान उत्पन्न होने के बावजूद केंद्र सरकार राजकोषीय समझदारी पर पर्याप्त ध्यान देते हुए 2022-23 (आरई) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.4 प्रतिशत के बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का प्राप्त करने में कामयाब रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9 प्रतिशत पर पहुंचने का अनुमान है। सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है, जिसकी घोषणा पहली बार केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी।

बजट में कर दाताओं के अनुपालन बोझ को कम करने और कर आधार को व्यापक बनाने, आपूर्ति शृंखलाओं को औपचारिक रूप देने और कारोबार सुगमता में सुधार के उद्देश्य से कर ढांचे को सरल बनाने के उपायों का प्रस्ताव किया गया है। व्यक्तिगत आयकर स्लैब को फिर से तैयार करने से खपत को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, विषेशरूप से ऐसे समय में जब वैश्विक मंदी की आशंका बनी हुई है। व्यय के दृष्टिकोण से राजस्व व्यय वृद्धि को 1.2 प्रतिशत पर सीमित रखा गया है, जबकि पूंजीगत व्यय 2010-20 के दौरान औसतन 1.7 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 (बीई) में जीडीपी का 3.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसके अलावा, राज्यों को पूंजीगत व्यय करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत व्यय[1] के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को 1.3 लाख करोड़ रुपये के बढ़े हुए आवंटन के साथ 2023-24 (बीई) तक बढ़ा दिया गया है।[2]

इस पृष्ठभूमि के साथ, शेष आलेख को सात खंडों में विभाजित किया गया है। खंड II राजकोषीय घाटे की अंतर्निहित गतिशीलता पर चर्चा करता है। खंड III और IV केंद्र सरकार की प्राप्तियों और व्यय में रुझानों का आकलन करते हैं। खंड V केंद्र सरकार की बकाया देयताओं को दर्शाता है। खंड VI राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोतों पर चर्चा करता है जबकि खंड VII राज्यों को संसाधनों के हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करता है। खंड VIII निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

---

* लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं। लेखक डॉ. देब प्रसाद रथ और डॉ. जी वी नथनएल को उनके मूल्यवान इनपुट के लिए और सुप्रिया अभिनव सुतार को डेटा समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

[1] पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत, केंद्र सरकार पूंजीगत निवेश परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है।

[2] विस्तृत बजट प्रस्तावों के लिए कृपया अनुबंध 2 देखें।

II. राजकोषीय घाटा - अंतर्निहित गतिशीलता

सरकार ने 2022-23 (संशोधित अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.4 प्रतिशत के बजटीय राजकोषीय लक्ष्य का पालन किया।[3] हालांकि, संपूर्णता में देखें तो सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) बजट अनुमानों को 94,123 करोड़ रुपये से अधिक कर गया क्योंकि राजस्व व्यय में वृद्धि उच्च प्राप्तियों से अधिक थी। राजस्व व्यय ने बजट अनुमानों को 2.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर दिया, जबकि पूंजीगत व्यय 21,972 करोड़ रुपये कम हो गया, जिसके परिणामस्वरूप कुल व्यय में 2.4 लाख करोड़ रुपये की निवल वृद्धि हुई। प्राप्तियों के मामले में निवल कर राजस्व बजट लक्ष्य से 1.5 लाख करोड़ रुपये अधिक रहा और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां बजट अनुमान से 4,209 करोड़ रुपये अधिक होने का अनुमान है। इसकी आंशिक भरपाई कम गैर-कर संग्रह से हुई, जिसमें 7,900 करोड़ रुपये की कमी देखी गई (चार्ट 1)।

2023-24 के लिए, जीएफडी का बजट जीडीपी[4] के 5.9 प्रतिशत पर रखा गया है - 2022-23 (आरई) की तुलना में 51

चार्ट 1: 2022-23 के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्ति में बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान का योगदान

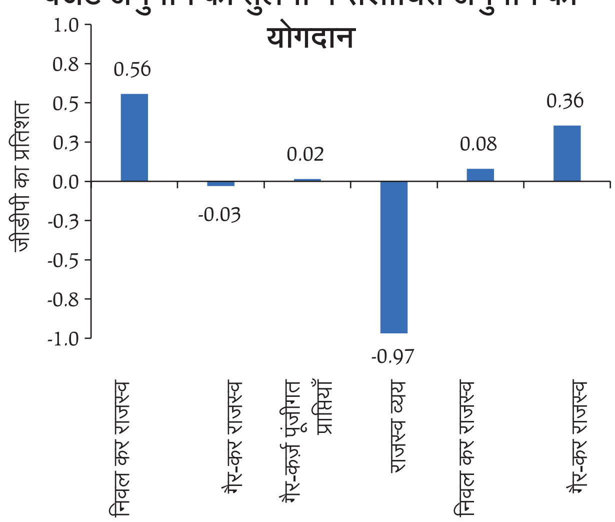

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज; और आरबीआई कर्मचारियों के अनुमान।

चार्ट 2: चक्रीय रूप से समायोजित राजकोषीय घाटा

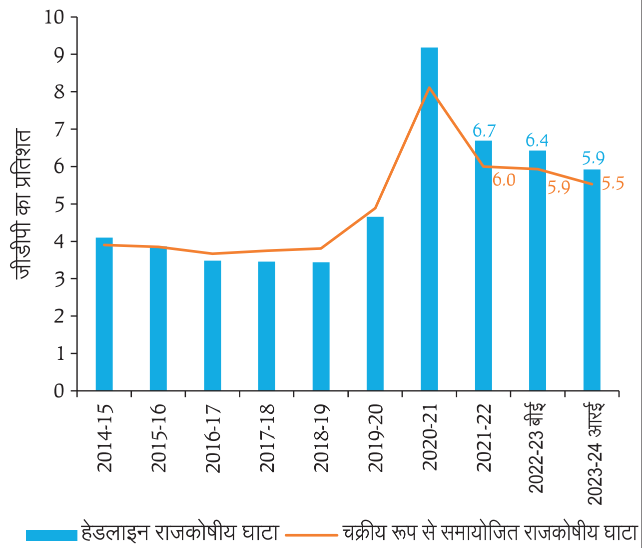

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज; और आरबीआई कर्मचारियों के अनुमान।

आधार अंकों की वृद्धि । अंतर्निहित आर्थिक चक्र को ध्यान में रखते हुए, 2023-24 के लिए चक्रीय रूप से समायोजित राजकोषीय घाटा 5.5 प्रतिशत (चार्ट 2)[5] पर कम रहा है। इसके अलावा, सरकार 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे जीएफडी प्राप्त करने के मध्यम अवधि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2023-24 में सुदृढ़ीकरण को राजस्व व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 11.6 प्रतिशत तक सीमित करके हासिल करने का प्रयास किया जाना है, भले ही पूंजीगत व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत के उच्च स्तर तक बढ़ाने का बजट है (सारणी 1)। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण निजी क्षेत्र के लिए उत्पादक संसाधनों को मुक्त कर सकता है और पूंजी की लागत को कम करने में योगदान दे सकता है, जिससे 2023-24 में अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ सकती है।

जीएफडी का वितरण

2018-19 से 2020-21 के दौरान राजस्व घाटा जीएफडी का लगभग 70 प्रतिशत था, जिसे 2022-23 (संशोधित अनुमान)

---

3 2016-17 में, केंद्र सरकार द्वारा बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य (जीडीपी का 3.5 प्रतिशत) को प्राप्त किया गया। हालांकि, 2017-18 से 2020-21 तक केंद्र सरकार अपने बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ रही ।

4 2023-2024 (बीई) के लिए अवास्तविक जीडीपी 3,01,75,065 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (अर्थात 06 जनवरी, 2023 को भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 2022-23 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2,73,07,751 करोड़ रुपये)।

5 चक्रीय रूप से समायोजित राजकोषीय घाटा वह राजकोषीय घाटा है जो प्रबल होगा अगर अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पर काम करती है। इसकी गणना चक्रीय रूप से समायोजित व्यय (E^*) और चक्रीय रूप से समायोजित राजस्व जैसे कि $R^* = R\left(\frac{Y^*}{Y}\right)^{\epsilon_r}$, $E^* = E\left(\frac{Y^*}{Y}\right)^{\epsilon_e}$ के रूप में की जाती है। जहां (R^*) और E वास्तविक राजस्व और व्यय हैं; Y वास्तविक आउटपुट है; Y* संभावित आउटपुट है ϵ_r और ϵ_e, आउटपुट अंतराल के संबंध में राजस्व और व्यय का लचीलापन हैं (फेडेलिनो एवं अन्य 2009)। कर राजस्व के लचीलेपन को 1.5 पर अनुमानित और व्यय से संबंधित स्वचालित स्टेबलाइजर्स की अनुपस्थिति में व्यय लचीलेपन का अनुमान शून्य माना जाता है।

सारणी 1: प्रमुख संकेतक 6

(जीडीपी का प्रतिशत)

	2021-22	2022-23		2023-24
	वास्तविक	बीई	आरई	बीई
1	2	3	4	5
1. राजकोषीय घाटा	6.7	6.4	6.4	5.9
2. राजस्व घाटा	4.4	3.8	4.1	2.9
3. प्राथमिक घाटा	3.3	2.8	3.0	2.3
4. सकल कर राजस्व	11.4	10.7	11.1	11.1
5. गैर-कर राजस्व	1.5	1.0	1.0	1.0
6. राजस्व व्यय	13.5	12.4	12.7	11.6
7. पूंजीगत व्यय	2.5	2.9	2.7	3.3
जिसका कि: पूँजी परिव्यय	*2.3*	*2.4*	*2.3*	*2.8*
8. कर्ज	59.6	61.0	57.8	57.8
9. प्रभावी राजस्व घाटा	3.3	2.6	2.9	1.7

नोट: 1. पूंजी परिव्यय का तात्पर्य है पूंजीगत व्यय में से ऋण और अग्रिम को घटा दिया जाए।

2. प्रभावी राजस्व घाटा का तात्पर्य राजस्व घाटे और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान राशि के बीच का अंतर है।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

में घटकर 63.3 प्रतिशत और 2023-24 (बजट अनुमान) में 48.7 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। दूसरी ओर, विकास-प्रेरित पूंजी परिव्यय का योगदान 2010-11 से 2019-20 के दौरान जीएफडी के औसत 36.5 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 46.9 प्रतिशत होने का अनुमान है (चार्ट 3)।

III. प्राप्तियाँ

चूंकि कर राजस्व बजट अनुमानों को पार कर गया, जिससे गैर-कर प्राप्तियों में कमी को पूरा करता है अतः निवल कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों सहित कुल प्राप्तियां 2022-23 (संशोधित अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 8.91 प्रतिशत रहीं, जो 8.85 प्रतिशत के बजटीय स्तर से मामूली अधिक है। 2023-24 के लिए कुल प्राप्तियों को सकल घरेलू उत्पाद के 9.0 प्रतिशत तक बढ़ाने का बजट अनुमान है।

कर राजस्व

यूक्रेन में युद्ध के समष्टि-आर्थिक परिणामों के बावजूद सकल कर राजस्व ने 2022-23 (आरई) में बेहतर प्रदर्शन किया। निगम कर, आयकर और जीएसटी में बजटीय प्रावधान से अधिक संग्रह के कारण सकल कर राजस्व बजट अनुमान से 2.9 लाख करोड़ रुपये अधिक हो गया। 2023-24 के लिए सकल कर राजस्व में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जिसमें 0.99 की बजटीय उछाल है जो प्रवृत्ति स्तर के करीब है (2010-11 से 2018-19 के औसत से प्रॉक्सी किया गया) [सारणी 2]।

चार्ट 3: जीएफडी का अपघटन

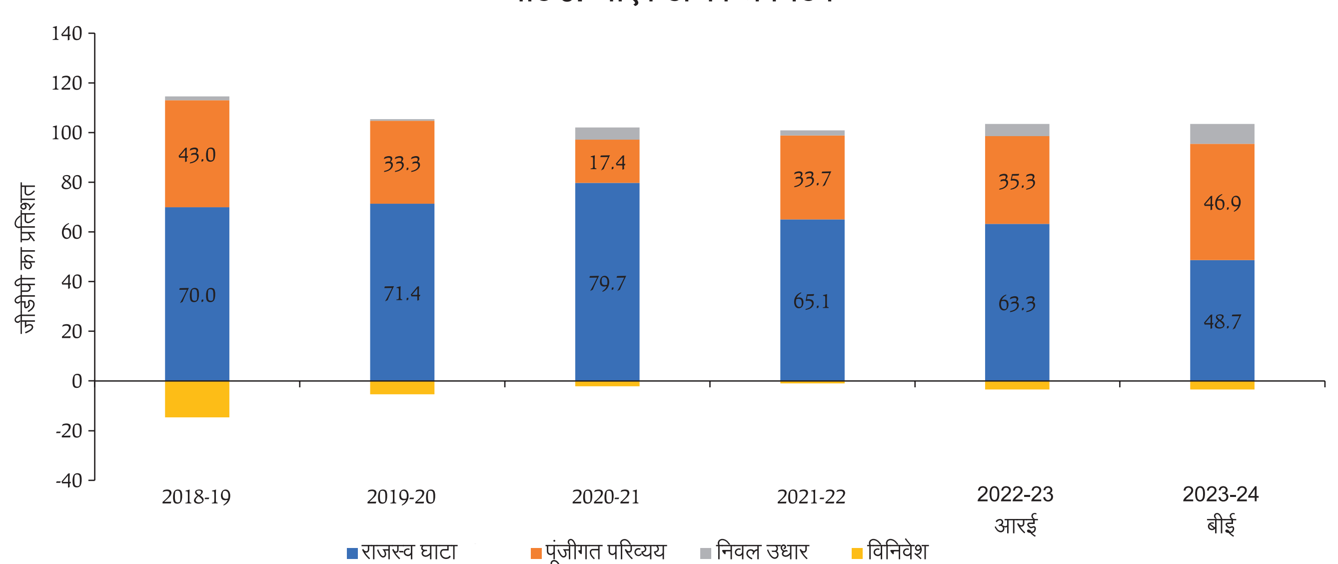

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

6 विवरण के लिए कृपया अनुबंध 1 देखें।

सारणी 2: कर में वृद्धि

	औसत कर वृद्धि (2010-11 से 2018-19)	2021-22	2022-23 (बीई)	2022-23 (आरई)	2023-24 (बीई)
1	2	3	4	5	6
1. सकल कर राजस्व	1.11	1.72	0.86	0.80	0.99
2. प्रत्यक्ष कर	1.03	2.51	1.22	1.11	1.00
(i) निगम कर	0.92	2.85	1.20	1.12	1.00
(ii) आयकर	1.27	2.21	1.28	1.13	1.00
3. अप्रत्यक्ष कर	1.25	1.04	0.51	0.46	0.99
(i) जीएसटी	-	1.39	1.40	1.45	1.14
(ii) सीमा शुल्क	0.31	2.47	1.14	0.33	1.05
(iii) उत्पाद शुल्क	0.91	0.04	-1.34	-1.23	0.57

नोट: '-': लागू नहीं। कर वृद्धि को सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन और कर नीतियों में विवेकाधीन परिवर्तनों के लिए कर राजस्व की जवाबदेही के रूप में परिभाषित किया गया है; 2022-23 (बीई) के लिए गणना 2021-22 (आरई) से अधिक की गई है।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेजों के आधार पर आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 4: कर-जीडीपी अनुपात

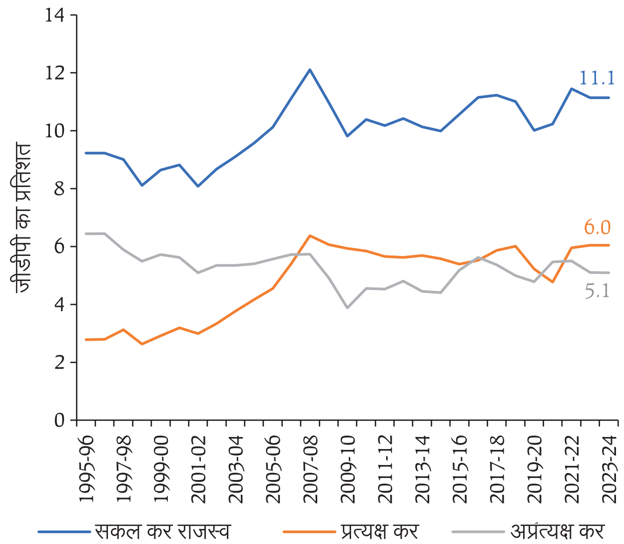

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेजों के आधार पर आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

प्रत्यक्ष कर

2022-23 (संशोधित अनुमान) में 17.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने के बाद, प्रत्यक्ष करों में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2023-24 में जीडीपी के 6.0 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है (चार्ट 4)। विभिन्न प्रावधानों को सरल और तर्कसंगत बनाने, अनुपालन बोझ को कम करने और नागरिकों को कर राहत प्रदान करने के लिए बजट में कई प्रत्यक्ष कर परिवर्तनों का प्रस्ताव किया गया है। व्यक्तिगत आयकर के तहत, बजट में नई कर व्यवस्था में निम्नलिखित प्रमुख बदलावों का प्रस्ताव है - (i) छूट सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करना, (ii) स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच करना और कर छूट सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करना और (iii) वेतनभोगी वर्ग और पेंशनभोगियों के लिए मानक कटौती लाभ का विस्तार नई कर व्यवस्था में करना। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को भी 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिकतम कर की दर मौजूदा 42.74 प्रतिशत की दर से घटकर 39 प्रतिशत हो जाएगी।

अप्रत्यक्ष कर

2022-23 (संशोधित अनुमान) में अप्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान से 55,247 करोड़ रुपये अधिक हो गया, क्योंकि जीएसटी संग्रह बजट अनुमान से 74,000 करोड़ रुपये अधिक हो गया, जिससे सीमा शुल्क (3,000 करोड़ रुपये) और उत्पाद शुल्क संग्रह (15,000 करोड़ रुपये) में हुई कमी की भरपाई हुई। मई 2022 में ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती ने 2022-23 (संशोधित अनुमान) में उत्पाद शुल्क संग्रह को जहाँ कम कर दिया, वहीं जीएसटी संग्रह में 1.45 की उछाल दर्ज की गई, जो आर्थिक गतिविधियों में सुधार और कर आधार बढ़ाने तथा अनुपालन में सुधार के प्रयासों के प्रभाव को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रत्यक्ष करों में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है जबकि जीएसटी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में क्रमश: 12.0 प्रतिशत, 11.0 प्रतिशत और 5.9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

बजट में प्रस्तावित कर परिवर्तन (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) से उपभोग्य आय में 35,000 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे व्यक्तिगत उपभोग[7] को बढ़ावा मिलने से 2023-24 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि में 15 आधार अंक की वृद्धि होने का अनुमान है।

गैर-कर राजस्व

गैर-कर स्रोतों से प्राप्तियां 2022-23 (संशोधित अनुमान) में बजटीय लक्ष्यों से 7,900 करोड़ रुपये कम हो गईं, क्योंकि रिज़र्व बैंक द्वारा अवास्तविक निर्धारित बजटीय अधिशेष से कम हस्तांतरण को आंशिक रूप से उच्च ब्याज प्राप्तियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश और स्पेक्ट्रम राजस्व (चार्ट 5) द्वारा भरपाई की गई थी। वित्त वर्ष 2023-24 में गैर-कर राजस्व 15.2 प्रतिशत बढ़कर 3.0 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

[7] विवरण के लिए, आरबीआई बुलेटिन (फरवरी 2023) में आलेख "अर्थव्यवस्था की स्थिति" देखें।

चार्ट 5: स्पेक्ट्रम राजस्व - बीई की तुलना में वास्तविक

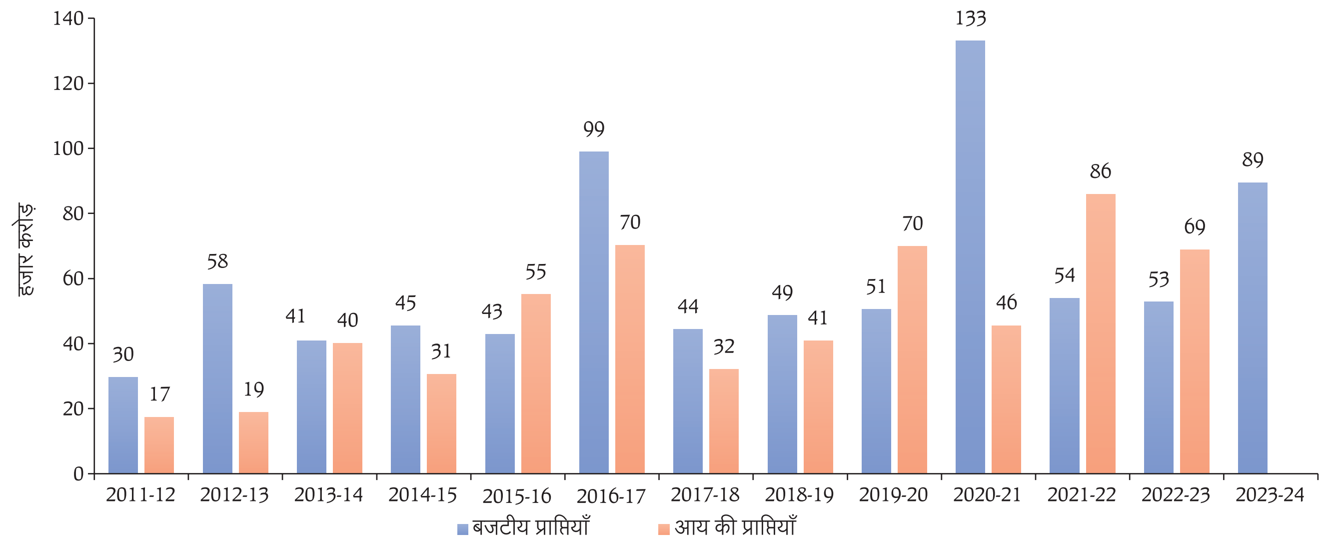

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

वित्त वर्ष 2022-23 में विनिवेश[8] से 60,000 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि बजटीय लक्ष्य 65,000 करोड़ रुपये का था, जिसमें से दिसंबर 2022 के अंत तक केवल 38,671 करोड़ रुपये ही जुटाए जा सके हैं। 2023-24 (बजट अनुमान) में, विनिवेश लक्ष्य ₹ 61,000 करोड़ (चार्ट 6) पर रखा गया है। 2022-23 (संशोधित अनुमान) में ऋण और अग्रिम की वसूली बजट अनुमान से 9,209 करोड़ रुपये अधिक रही, जो विनिवेश प्राप्तियों में कमी से अधिक है। 2023-24 में ऋण वसूली में 2022-23 (संशोधित अनुमान) की तुलना में 2.1 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है।

चार्ट 6: विनिवेश - बीई की तुलना में वास्तविक

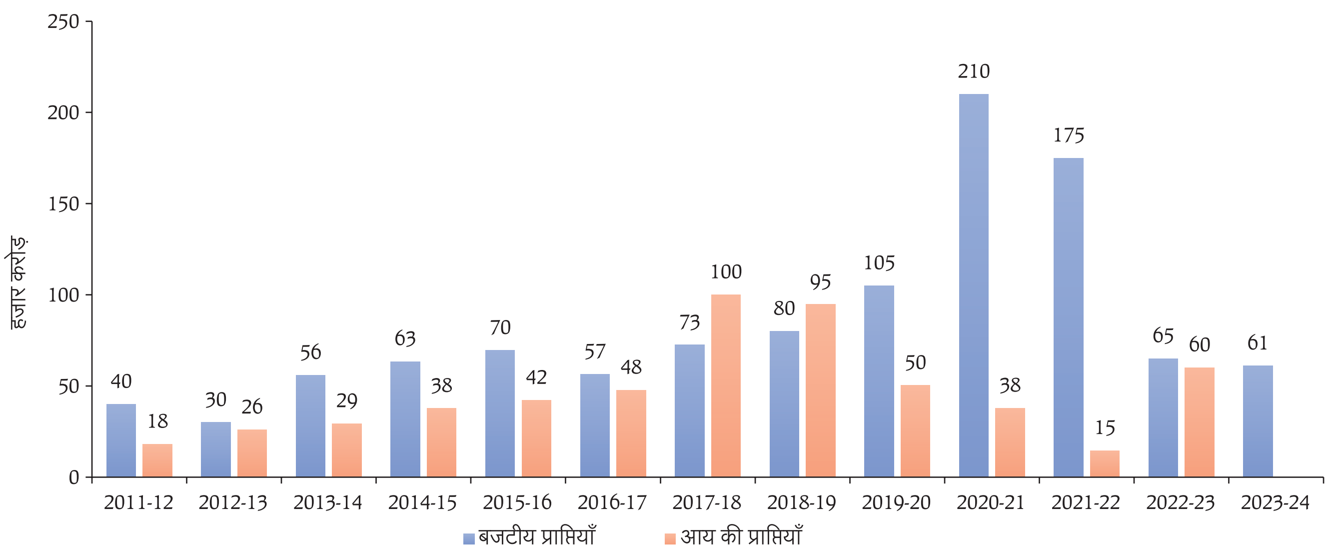

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

8 विनिवेश प्राप्तियों से तात्पर्य विविध पूंजीगत प्राप्तियों से है, जिसमें विनिवेश और अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।

IV. व्यय

2023-24 में कुल व्यय में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जो 2022-23 (संशोधित अनुमान) की 10.4 प्रतिशत की वृद्धि से कम है। 2023-24 में राजस्व व्यय में केवल 1.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है क्योंकि खाद्य सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने और यूरिया की कीमतों में कमी के कारण प्रमुख सब्सिडी पर व्यय में 28.2 प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है। निवेश और वृद्धि को पुनर्जीवित करने के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय महामारी के बाद की अवधि में पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर दिया गया है क्योंकि पूंजीगत व्यय को 2010-20 के दौरान औसतन 1.7 प्रतिशत से 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत तक बढ़ाने का बजट है (सारणी 3)।

2023-24 में, पूंजीगत व्यय का बजट ₹10 लाख करोड़ है, जो 2019-20 में खर्च की गई राशि का लगभग तीन गुना है। पूंजीगत व्यय का मंत्रालय-वार आवंटन इंगित करता है कि रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2023-24 के लिए बजटीय पूंजीगत व्यय का लगभग आधा हिस्सा है (चार्ट 7)। प्रभावी पूंजीगत व्यय (पूंजीगत व्यय और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान) में वृद्धि, इसके गुणक प्रभाव के माध्यम से, 2023-27 के दौरान 10.3 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन उत्पन्न करेगी, जिसमें रेलवे और राज्यों को ऋण सहायता का योगदान 43 प्रतिशत होगा, जबकि रसद में निवेश का योगदान 19 प्रतिशत होगा [9]।

इसके बाद, हम केंद्र सरकार के कुल व्यय को नियत व्यय में विघटित करते हैं, जिसमें संस्थानों पर व्यय[10], ब्याज भुगतान, वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान और राज्यों को जीएसटी मुआवजा; और विवेकाधीन व्यय जिसमें केंद्रीय योजनाएं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं और राज्यों को हस्तांतरण शामिल हैं (वित्त आयोग अनुदान और जीएसटी मुआवजे को छोड़कर)। महामारी से पहले, नियत व्यय का हिस्सा विवेकाधीन व्यय से अधिक था। हालांकि, जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था की समाप्ति और पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण की शुरुआत के साथ,

सारणी 3: केंद्र सरकार का व्यय

	₹ हजार करोड़				विकास दर (प्रतिशत)		
	2021-22	2022-23 (बीई)	2022-23 (आरई)	2023-24 (बीई)	2022-23 (बीई)	2022-23 (आरई)	2023-24 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. कुल व्यय	3,794	3,945	4,187	4,503	4.0	10.4	7.5
2. राजस्व व्यय *(जिसमें से)*	3,201	3,195	3,459	3,502	-0.2	8.1	1.2
(i) ब्याज भुगतान	805	941	941	1,080	16.8	16.8	14.8
(ii) प्रमुख सब्सिडी	446	318	522	375	-28.8	16.9	-28.2
खाना	289	207	287	197	-28.4	-0.6	-31.3
उर्वरक	154	105	225	175	-31.6	46.5	-22.3
पेट्रोलियम	3	6	9	2	69.8	167.9	-75.4
(iii) मनरेगा	98	73	89	60	-25.9	-9.2	-32.9
(iv) पीएम-किसान	67	68	60	60	1.8	-10.2	0.0
(v) रक्षा (राजस्व)	229	233	260	270	1.9	13.5	4.1
3. पूंजीगत व्यय	593	750	728	1,001	26.5	22.8	37.4
(i) पूंजी परिव्यय	534	610	620	837	14.2	16.0	35.0
4. प्रभावी पूंजीगत व्यय	836	1,068	1,054	1,371	27.8	26.1	30.1

नोट: प्रभावी पूंजीगत व्यय पूंजीगत व्यय और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए सहायता अनुदान का योग है।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

[9] विवरण के लिए, आरबीआई बुलेटिन (फरवरी 2023) में आलेख "अर्थव्यवस्था की स्थिति" देखें।
[10] स्थापना व्यय में वेतन, मजदूरी, पेंशन और कार्यालय संचालन व्यय शामिल है।

चार्ट 7: मंत्रालय-वार पूंजीगत व्यय

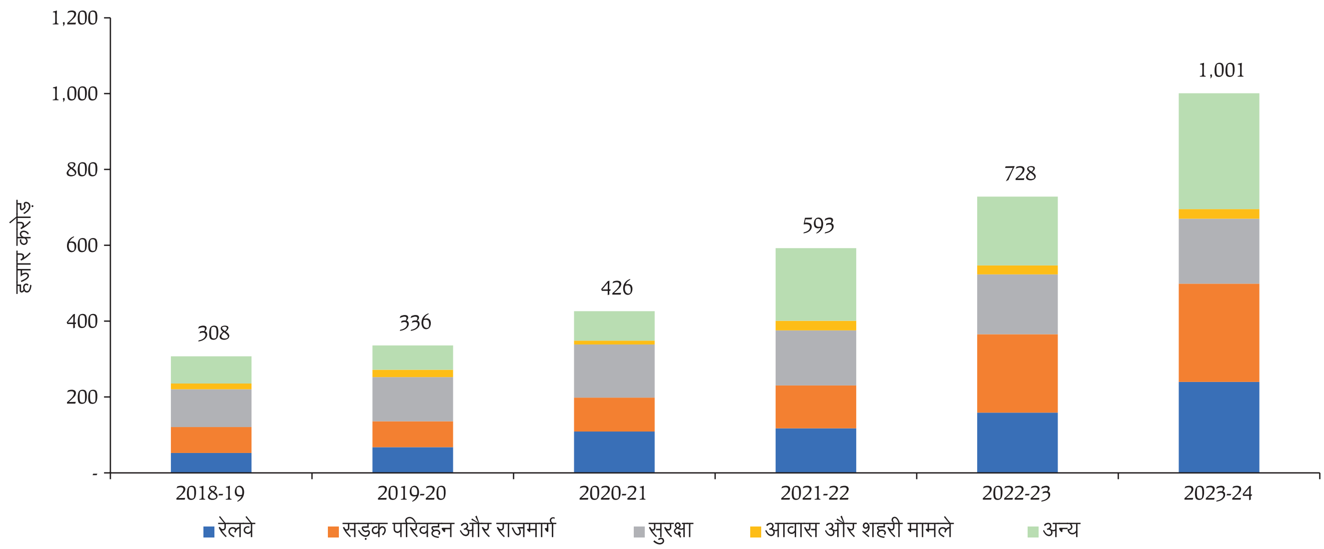

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

नियत व्यय का हिस्सा 2023-24 (बजट अनुमान) में कुल व्यय का 45.1 प्रतिशत हो गया है (चार्ट 8)।

V. बकाया ऋण

महामारी के प्रभाव के कारण 2020-21 में जीडीपी के 62.8 प्रतिशत पर पहुंचने के बाद, केंद्र सरकार के कुल बकाया ऋण को 2023-24 (बजट अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद के 57.8 प्रतिशत तक समेकित करने का बजट है। हालांकि, राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान का अनुपात 41.0 प्रतिशत तक बढ़ाने का बजट है (चार्ट 9 ए)। ब्याज दर वृद्धि अंतर (आईआरजीडी), ऋण स्थिरता का एक संकेतक, अनुकूल बना हुआ है, भले ही हाल के वर्षों में इसकी परिमाण में गिरावट आई है (चार्ट 9 बी)।

चार्ट 8: प्रतिबद्ध की तुलना में विवेकाधीन व्यय

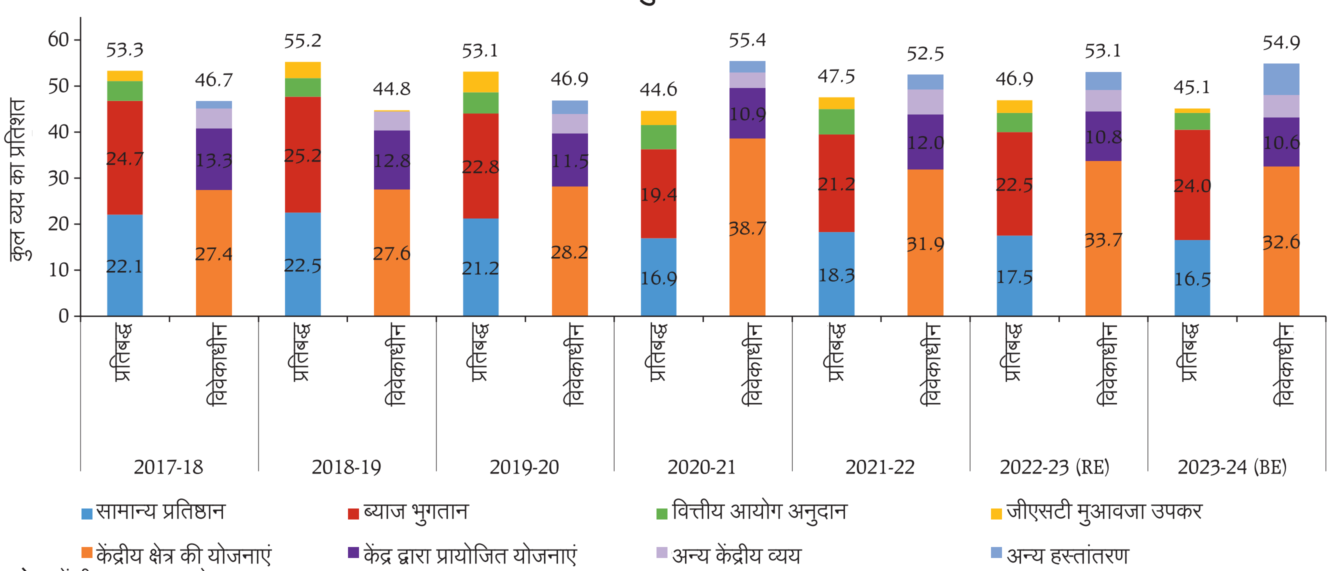

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

चार्ट 9: बकाया देयताएं और ब्याज दर वृद्धि अंतर

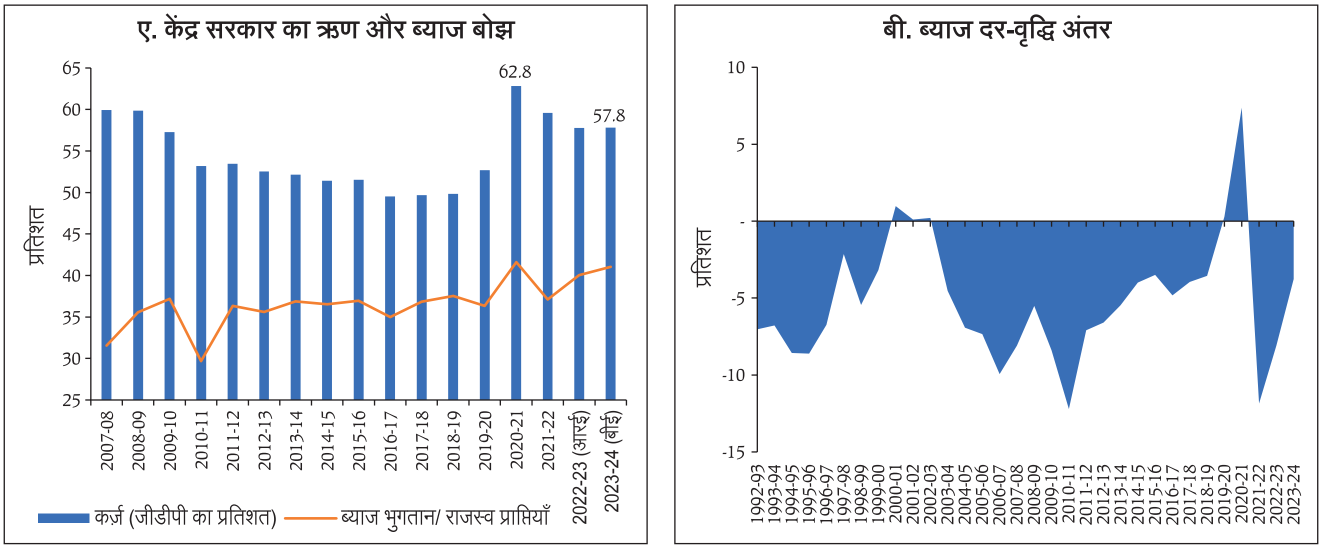

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और स्टाफ की गणना।

हालांकि, चूंकि केंद्र सरकार का ऋण अभी भी महामारी से पहले की प्रवृत्ति की तुलना में अधिक बना हुआ है, इसलिए राजकोषीय समेकन के रास्ते पर बने रहने की आवश्यकता है।

6. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

2022-23 के संशोधित अनुमानों (आरई) के अनुसार, राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 प्रतिशत तक सीमित रखने के बजट लक्ष्य को हासिल किए जाने की संभावना है। वित्त वर्ष 2023-24 में सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) जीडीपी का 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बाजार उधार केंद्र सरकार के लिए जीएफडी के वित्तपोषण का मुख्य स्रोत है, इसके बाद अल्प बचत के बदले जारी प्रतिभूतियां हैं (चार्ट 10)। 2023-24 में, सकल और निवल बाजार उधारी का बजट ₹15.4 लाख करोड़ और ₹11.8 लाख करोड़ है, जो 2022-23 (संशोधित

चार्ट 10: सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

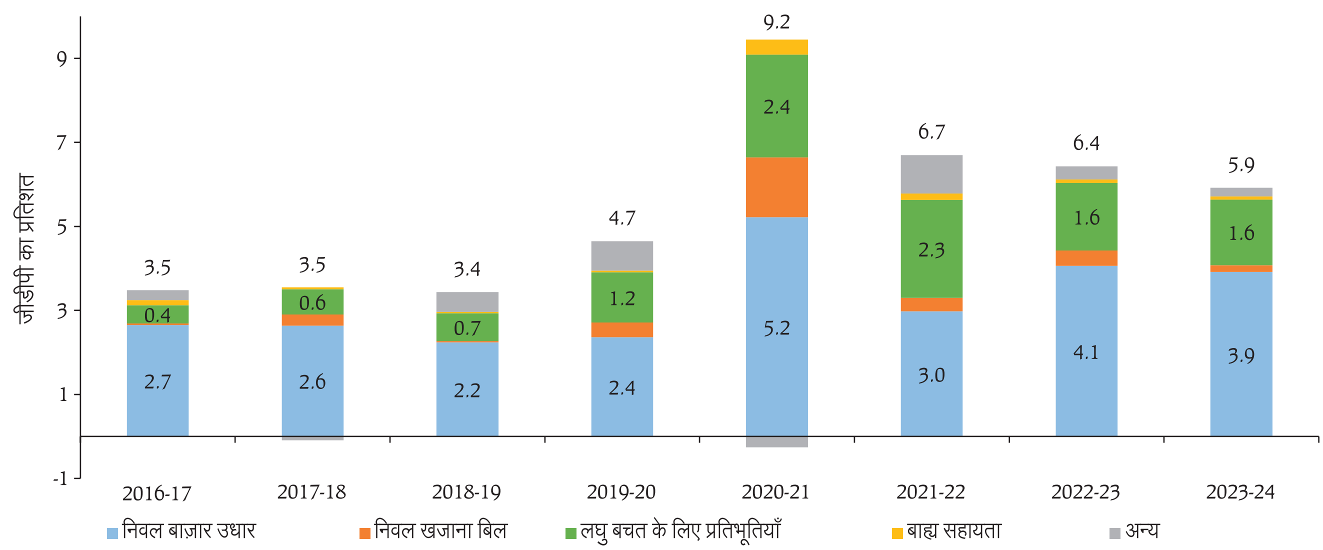

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

सारणी 4: केंद्र सरकार के बाजार उधार

(₹ करोड़)

	सकल बाज़ार उधार	निवल बाज़ार उधार
2018-19	5,71,000 (3.0)	4,22,735 (2.2)
2019-20	7,10,000 (3.5)	4,73,968 (2.4)
2020-21	12,60,116 (6.4)	10,32,907 (5.2)
2021-22	9,68,382 (4.1)	7,04,097 (3.0)
2022-23 (आरई)	14,21,000 (5.2)	11,08,183 (4.1)
2023-24 (बीई)	15,43,000 (5.1)	11,80,911 (3.9)

नोट: कोष्ठक के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में हैं।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

अनुमान) में क्रमशः ₹14.2 लाख करोड़ और ₹11.1 लाख करोड़ था (सारणी 4)। महामारी से पहले के स्तर की ओर केंद्र सरकार की बाजार उधार आवश्यकताओं (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) में धीरे-धीरे कमी से निजी निवेश के लिए जगह बनेगी।

7. केंद्र से राज्यों को संसाधन हस्तांतरण

केंद्र ने 2023-24 के लिए राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य देशी उत्पाद (जीएसडीपी) का 3.5 प्रतिशत तय किया है, जिसमें से 0.5 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा होगा। राज्यों को सकल हस्तांतरण को 2023-24 (बीई) में बढ़ाने का बजटीय अनुमान है, जिसका मुख्य कारण कर हस्तांतरण में वृद्धि और पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए आवंटन में वृद्धि है (चार्ट 11, अनुबंध 3)। वित्त आयोग अनुदान में 2023-24 में गिरावट आने की उम्मीद है, मुख्य रूप से हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान के तहत कम हस्तांतरण के कारण, जबकि स्थानीय निकायों और स्वास्थ्य क्षेत्र में हस्तांतरण में तेजी से वृद्धि देखी गई है (चार्ट 12)।

अवसंरचना में राज्यों के निवेश को बढ़ावा देने और उन्हें पूरक नीतिगत कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्र ने 1.3 लाख करोड़ रुपये के बढ़े हुए आवंटन के साथ राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण को एक और वर्ष के लिए जारी रखने का फैसला किया है।[11] 2023-24 के दौरान ही ऋण की

चार्ट 11: राज्यों को संसाधन हस्तांतरण

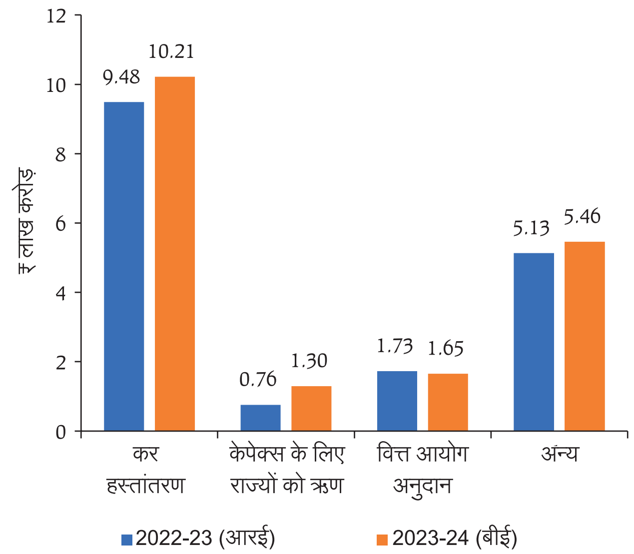

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

राशि को खर्च करना होगा। जबकि अधिकांश ऋण राज्यों के विवेक पर होगा, इसका एक हिस्सा राज्यों द्वारा अपने वास्तविक पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने पर निर्भर करेगा। परिव्यय का एक हिस्सा पुराने सरकारी वाहनों को खत्म करने, शहरी नियोजन

चार्ट 12: 2023-24 में वित्त आयोग अनुदान में व-द-व परिवर्तन (बीई)

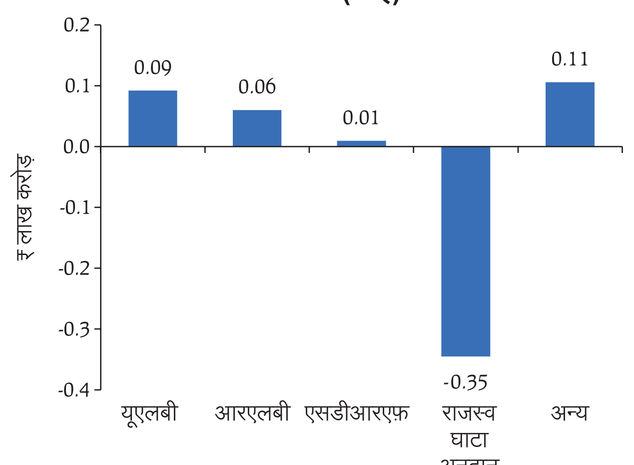

टिप्पणी: यूएलबी: शहरी स्थानीय निकाय; आरएलबी: ग्रामीण स्थानीय निकाय; एसडीआरएफ: राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

[11] 2022-23 (बीई) में, इस राशि को ₹ 1 लाख करोड़ पर बजट किया गया था, हालांकि 2022-23 (आरई) के मुताबिक आबंटन ₹ 76,000 करोड़ रहा।

सुधारों और कार्यों, शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों के वित्तपोषण (उन्हें नगरपालिका बॉण्ड के लिए ऋण योग्य बनाने के लिए), पुलिस स्टेशनों के ऊपर या हिस्से के रूप में पुलिस कर्मियों के लिए आवास, यूनिटी मॉल, बच्चों और किशोरों के पुस्तकालयों और डिजिटल अवसंरचना के निर्माण और केंद्रीय योजनाओं के पूंजीगत व्यय में राज्यों के हिस्से से भी जुड़ा होगा। केंद्रीय बजट में संपत्ति कर अभिशासन सुधारों और शहरी अवसंरचना पर रिंग-फेंसिंग उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से नगरपालिका बॉण्ड के लिए उनकी ऋण-योग्यता में सुधार करने के लिए शहरों को प्रोत्साहित करने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, एक शहरी अवसंरचना विकास कोष (यूआईडीएफ) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाएगा।

VIII. निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2023-24 का उद्देश्य वृद्धि की गति (उच्च पूंजीगत व्यय के माध्यम से) को मजबूत करना और राजकोषीय समेकन की प्रतिबद्धता के साथ आर्थिक नींव को मजबूत करके समष्टिआर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। जबकि उच्च पूंजीगत व्यय से कई गुना प्रभाव और निजी निवेश बढ़ेगा, राजकोषीय समेकन निजी क्षेत्र के लिए उत्पादक संसाधनों को उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा, एकीकृत और समन्वित योजना, डिजिटलीकरण और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उपायों और जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने के लिए कौशल पहलों द्वारा समर्थित अवसंरचना के विकास से निकट अवधि से परे लाभांश प्राप्त होने और मध्यम-अवधि में अर्थव्यवस्था की वृद्धि क्षमता में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जैसा कि इसके साथ के आलेख “अर्थव्यवस्था की स्थिति” में बताया गया है।

अनुबंध 1: केंद्रीय बजट 2023-24: प्रमुख राजकोषीय संकेतक

	₹ हज़ार करोड़					जीडीपी का प्रतिशत		वृद्धि दर	
	2020-21	2021-22	2022-23 (बीई)	2022-23 (आरई)	2023-24 (बीई)	2022-23 (आरई)	2023-24 (बीई)	2022-23 (आरई)	2023-24 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. प्रत्यक्ष कर	945	1,408	1,420	1,650	1,823	6.0	6.0	17.2	10.5
(i) कॉर्पोरेशन	458	712	720	835	923	3.1	3.1	17.3	10.5
(ii) आय	470	673	680	790	873	2.9	2.9	17.4	10.5
2. अप्रत्यक्ष कर	1,082	1,301	1,338	1,393	1,538	5.1	5.1	7.1	10.4
(i) जीएसटी	549	698	780	854	957	3.1	3.2	22.3	12.0
(ii) सीमा-शुल्क	135	200	213	210	233	0.8	0.8	5.1	11.0
(iii) उत्पाद शुल्क	392	395	335	320	339	1.2	1.1	-18.9	5.9
3. सकल कर राजस्व (1+2)	2,027	2,709	2,758	3,043	3,361	11.1	11.1	12.3	10.4
4. राज्यों को दिया जाने वाला	595	898	817	948	1,021	3.5	3.4	5.6	7.7
5. एनसीसीडी हस्तांतरण	6	6	6	8	9	0.0	0.0	30.5	9.7
6. निवल कर राजस्व (3-4-5)	1,426	1,805	1,935	2,087	2,331	7.6	7.7	15.6	11.7
7. गैर-कर राजस्व	208	365	270	262	302	1.0	1.0	-28.3	15.2
(i) लाभांश और लाभ	97	161	114	84	91	0.3	0.3	-47.7	8.4
(ii) ब्याज प्राप्तियां	17	22	18	25	25	0.1	0.1	12.6	0.7
8. राजस्व प्राप्तियां (6+7)	1,634	2,170	2,204	2,348	2,632	8.6	8.7	8.2	12.1
9. गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	58	39	79	84	84	0.3	0.3	112.1	0.6
(i) विनिवेश प्राप्तियां	38	15	65	60	61	0.2	0.2	309.9	1.7
(ii) ऋणों की वसूली	20	25	14	24	23	0.1	0.1	-5.0	-2.1
10. कुल प्राप्तियां (उदा. उधार) (8+9)	1,692	2,209	2,284	2,432	2,716	8.9	9.0	10.1	11.7
11. राजस्व व्यय	3,084	3,201	3,195	3,459	3,502	12.7	11.6	8.1	1.2
(i) ब्याज भुगतान	680	805	941	941	1,080	3.4	3.6	16.8	14.8
(ii) प्रमुख सब्सिडी	708	446	318	522	375	1.9	1.2	16.9	-28.2
खाद्य	541	289	207	287	197	1.1	0.7	-0.6	-31.3
उर्वरक	128	154	105	225	175	0.8	0.6	46.5	-22.3
पेट्रोल	38	3	6	9	2	0.0	0.0	167.9	-75.4
12. पूंजीगत व्यय (i + ii)	426	593	750	728	1,001	2.7	3.3	22.8	37.4
(i) पूंजी परिव्यय	316	534	610	620	837	2.3	2.8	16.0	35.0
(ii) ऋण और अग्रिम	110	58	140	108	164	0.4	0.5	85.1	51.6
13. कुल व्यय (11+12)	3,510	3,794	3,945	4,187	4,503	15.3	14.9	10.4	7.5
14. राजस्व घाटा (13-10)	1,818	1,585	1,661	1,755	1,787	6.4	5.9	10.8	1.8

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

अनुबंध 2: केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं

बजट में पेश की गई आर्थिक कार्यसूची तीन विषयों पर केंद्रित है: पहला, नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना; दूसरा, वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना; और तीसरा, समष्टि-आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। उल्लिखित विषयों में सहायता के लिए निम्नलिखित चार अवसर परिवर्तनकारी हो सकते हैं।

1. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण: बड़े उत्पादक उद्यमों या समूहों के गठन के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के अगले स्तर को प्राप्त करने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम (आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) द्वारा जुटाए गए महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सुविधा सेवा।
2. पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास): पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों (एमएसएमई) कीमत श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने की योजना।
3. पर्यटन: राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अभिसरण के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा देना।
4. हरित वृद्धि: विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती और हरित गतिशीलता के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

बजट में सात प्राथमिकताओं की घोषणा की गई है। प्रत्येक प्राथमिकता के तहत बजट द्वारा प्रस्तावित प्रमुख नीतिगत कार्रवाइयां नीचे सूचीबद्ध हैं।

प्राथमिकता 1: समावेशी विकास

कृषि और सहयोग

- नवोन्मेषी और किफायती समाधान प्रदान करने, आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष की स्थापना।
- कृषि क्षेत्र के लिए एक खुले-स्रोत, ओपन स्टैंडर्ड और इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रस्तावित है जो समावेशी, किसान केंद्रित समाधान और कृषि-टेक उद्योग और स्टार्ट-अप के विकास के लिए समर्थन को सक्षम करेगा।
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपये के लक्षित कृषि ऋण।
- उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त, गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम की स्थापना।
- भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में समर्थन दिया जाएगा ताकि भारत बाजरा का वैश्विक केंद्र बन सके।
- भंडारण क्षमता का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण ताकि किसानों को उचित समय पर बिक्री के माध्यम से लाभदायक कीमत हासिल करने में मदद मिल सके।

स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल

- 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
- 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा।
- उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा।
- चयनित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) प्रयोगशालाओं के माध्यम से संयुक्त सार्वजनिक और निजी चिकित्सा अनुसंधान की सुविधा।
- अभिनव शिक्षाशास्त्र और पाठ्यक्रम लेनदेन के माध्यम से शिक्षकों के प्रशिक्षण की पुन: कल्पना। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को इस उद्देश्य के लिए उत्कृष्टता के जीवंत संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा।

अनुबंध 2: केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं

- भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं, शैलियों और स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता और डिवाइस अज्ञेय पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। राज्यों को पंचायत और वार्ड स्तर पर भौतिक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्तीय साक्षरता को विकसित करने के लिए, वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों और संगठनों को इन पुस्तकालयों को आयु-उपयुक्त पठन सामग्री प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्राथमिकता 2: अंतिम छोर तक पहुंचना

- कई क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की संतृप्ति के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करने वाले आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ।
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधान मंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा।
- आदिवासी छात्रों की देखभाल करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती।
- कर्नाटक के सूखाग्रस्त मध्य क्षेत्र के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई के लिए 5,300 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न का प्रावधान।
- पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66 प्रतिशत की वृद्धि।

प्राथमिकता 3: अवसंरचना और निवेश

- पूंजी निवेश परिव्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष पूंजी निवेश राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए किए गए प्रावधान से पूरक है; केंद्र के 'प्रभावी पूंजीगत व्यय' को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत तक ले जाना है।
- 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता 1.3 लाख करोड़ रुपये के बढ़े हुए परिव्यय के साथ एक और वर्ष के लिए जारी रहेगी।
- अवसंरचना वित्त सचिवालय अवसंरचना में अधिक निजी निवेश के लिए सभी हितधारकों की सहायता करेगा।
- बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए शुरू से अंत तक कनेक्टिविटी, पहले से आखिर तक कनेक्टिविटी के लिए एक सौ महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाएगा।
- क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए पचास अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्टों, जल हवाई अड्डों और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुत्थान किया जाएगा।

शहरी विकास

- शहरों को नगरपालिका बांड के लिए अपनी ऋण योग्यता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। संपत्ति कर अभिशासन सुधारों और शहरी अवसंरचना पर उपयोगकर्ता शुल्क की घेराबंदी के माध्यम से।
- एक शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) की स्थापना प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण की कमी के लिए की जाएगी जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाएगा और इसका उपयोग सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए किया जाएगा।
- मैनहोल से मशीन-होल मोड में परिवर्तन के लिए सभी शहरों और कस्बों के सेप्टिक टैंक और सीवर की मशीनों से सफाई को 100 प्रतिशत तक सक्षम किया जाएगा।

प्राथमिकता 4: क्षमता को उजागर करना

- मिशन कर्मयोगी के तहत, सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को अपने कौशल में और सुधार करने के लिए निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच, आईजीओटी कर्मयोगी भी लॉन्च किया है।

अनुबंध 2: केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं

- 'मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया' के विजन को साकार करने के लिए, शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- स्टार्ट-अप और शिक्षाविदों द्वारा नवोन्मेष और अनुसंधान को उजागर करने के लिए, एक राष्ट्रीय डेटा अभिशासन नीति लाई जाएगी। यह अनाम डेटा तक पहुंच को सक्षम करेगा।
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रक्रिया को 'एक आकार सभी के लिए फिट बैठता है' दृष्टिकोण के बजाय 'जोखिम-आधारित' दृष्टिकोण को अपनाते हुए सरल बनाया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों को डिजिटल इंडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए केवाईसी प्रणाली को पूरी तरह से सक्षम बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
- विभिन्न सरकारी एजेंसियों, विनियामकों और विनियमित संस्थाओं द्वारा रखे जा रहे व्यक्तियों की पहचान और पते के मिलान और अपडेशन के लिए सर्व समाधान डिजीलॉकर सेवा और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में उपयोग करके स्थापित किया जाएगा।
- व्यावसायिक संस्थानों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) रखना आवश्यक है, पैन का उपयोग विनिर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। इससे व्यापार करने में आसानी होगी; और इसे कानूनी जनादेश के माध्यम से लाया जाएगा।
- विभिन्न सरकारी एजेंसियों को एक ही जानकारी अलग-अलग प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए, 'एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया' की एक प्रणाली स्थापित की जाएगी।
- विवाद से विश्वास I योजना का उद्देश्य एमएसएमई के लिए कम कठोर संविदा निष्पादन है।
- विवाद से विश्वास II योजना का उद्देश्य एमएसएमई के लिए सरकारी उपक्रमों और सरकार के संविदा संबंधी विवादों का आसानी से निपटान करना है।
- प्रतिस्पर्धी विकास आवश्यकताओं के लिए दुर्लभ संसाधनों को बेहतर ढंग से आवंटित करने के लिए, पायलट आधार पर, चुनिंदा योजनाओं के वित्तपोषण को 'इनपुट-आधारित' से 'परिणाम-आधारित' में बदल दिया जाएगा।
- न्याय के कुशल प्रशासन के लिए, ई-कोर्ट परियोजना का चरण -3 ₹ 7,000 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया जाएगा।
- भारत में फिनटेक सेवाओं को आधार, पीएम जन धन योजना, वीडियो केवाईसी, इंडिया स्टैक और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) सहित हमारे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना द्वारा सुविधाजनक बनाया गया है। ज़्यादा फिनटेक नवोन्मेषी सेवाओं को सक्षम करने के लिए, व्यक्तियों के डिजीलॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों के दायरे का विस्तार किया जाएगा।
- एमएसएमई, बड़े व्यवसाय और धर्मार्थ न्यास द्वारा उपयोग के लिए एक डिजीलॉकर संस्था स्थापित की जाएगी। यह विभिन्न प्राधिकरणों, विनियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के साथ जब भी आवश्यक हो, दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन संग्रहीत और साझा करने की दिशा में होगा।
- 5जी सेवाओं का उपयोग करके ऐपलिकेशन को विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में एक सौ प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी ताकि अवसरों, व्यापार मॉडल और रोजगार की क्षमता की एक नई श्रृंखला का उपयोग किया जा सके।

प्राथमिकता 5: हरित संवृद्धि

- अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में बदलने और जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन हाल ही में 19,700 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था।
- बजट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा संक्रमण और निवल शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता पूंजी निवेश के लिए ₹ 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 4,000 मेगावाट की क्षमता के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के साथ समर्थित किया जाएगा।

अनुबंध 2: केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं

- लद्दाख से 13 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्य संचारण प्रणाली का निर्माण ₹20,700 करोड़ रुपये के निवेश के साथ किया जाएगा, जिसमें ₹8,300 करोड़ की केंद्रीय सहायता भी शामिल है।
- कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों द्वारा पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और उत्तरदायी कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत एक हरित ऋण कार्यक्रम अधिसूचित किया जाएगा।
- वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए धरती माता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम) शुरू किया जाएगा।
- ₹10,000 करोड़ के कुल निवेश के साथ, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना के तहत 500 नए 'वेस्ट टू वेल्थ' संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
- अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सुविधा के लिए 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- मैंग्रोव वनों के लिए वनीकरण पहल 'तटरेखा पर्यावास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल' (मिष्टि) नामक शुरू की जाएगी।
- आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने और जैव-विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण-पर्यटन के अवसरों को बढ़ाने और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन करने के लिए अगले तीन वर्षों में एक नई योजना, अमृत धरोहर लागू की जाएगी।
- व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के साथ पीपीपी मोड के माध्यम से माल ढुलाई और यात्रियों दोनों के लिए तटीय शिपिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।

प्राथमिकता 6: युवा शक्ति

कौशल निर्माण

- अगले तीन वर्षों के भीतर लाखों युवाओं को कुशल बनाने के लिए प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। यह योजना उद्योग 4.0 के लिए कोडिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), 3 डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी कवर करेगी। अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कुशल बनाने के लिए, 30 स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए एक एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा।
- अगले 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को लाभान्वित करने के लिए अखिल-भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा।

पर्यटन

- राज्यों को अपने स्वयं के ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद), भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पूर्ण पैकेज के रूप में कम से कम 50 गंतव्यों का चयन और विकास किया जाएगा।

प्राथमिकता 7: वित्तीय क्षेत्र

- एमएसएमई के लिए संशोधित ऋण गारंटी योजना के तहत ₹9,000 करोड़ के विस्तारित कोष का प्रस्ताव किया गया है ताकि ₹2 लाख करोड़ के अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त गारंटी ऋण लिया जा सके।
- वित्तीय और सहायक जानकारी के केंद्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। यह ऋण के कुशल प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा, और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा। एक नया विधायी ढांचा इस सार्वजनिक

अनुबंध 2: केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं

ऋण अवसंरचना को नियंत्रित करेगा, और इसे रिज़र्व बैंक के परामर्श से डिजाइन किया जाएगा।

- अमृत काल की आवश्यकताओं को पूरा करने और वित्तीय क्षेत्र में इष्टतम विनियमन की सुविधा के लिए, सार्वजनिक परामर्श, आवश्यकतानुसार और व्यवहार्य रूप से, विनियमन बनाने और सहायक निर्देश जारी करने की प्रक्रिया में लाया जाएगा।
- अनुपालन की लागत को सरल बनाने, आसान बनाने और कम करने के लिए, वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से मौजूदा विनियमों की व्यापक समीक्षा करने का अनुरोध किया जाएगा। इसके लिए वे सार्वजनिक और विनियमित संस्थाओं के सुझावों पर विचार करेंगे। विभिन्न विनियमों के तहत आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की जाएगी।
- गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्तीय टेक-सिटी (जीआईएफ़टी) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफ़एससी): जीआईएफ़टी आईएफ़एससी में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:
  - o दोहरे विनियमन से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम के तहत शक्तियां प्रदान करना।
  - o अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए), एसईजेड प्राधिकरणों, माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) से पंजीकरण और अनुमोदन के लिए एकल खिड़की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली की स्थापना।
  - o विदेशी बैंकों की आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों द्वारा अधिग्रहण वित्तपोषण की अनुमति।
  - o व्यापार पुनर्वित्त-पोषण के लिए निर्यात आयात (एक्जिम) बैंक की सहायक कंपनी की स्थापना।
  - o मध्यस्थता, सहायक सेवाओं के लिए सांविधिक प्रावधानों के लिए आईएफएससीए अधिनियम में संशोधन करना और एसईजेड अधिनियम के तहत दोहरे विनियमन से बचना।
  - o अपतटीय व्युत्पन्नी साधनों को वैध संविदा के रूप में पहचानना।
- बैंक अभिशासन में सुधार लाने और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं।
- प्रतिभूति बाजार में कार्यकर्ताओं और पेशेवरों की क्षमता का निर्माण करने के लिए, सेबी को राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान में शिक्षा के मानकों को बनाए रखने का अधिकार दिया जाएगा।
- कंपनी अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्यों को तेजी से किए जाने के लिए एक केंद्रीय डेटा प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण से बिना दावे वाले शेयरों और अवैतनिक लाभांश को पुनः प्राप्त करने के लिए निवेशकों के लिए एक एकीकृत आईटी पोर्टल स्थापित किया जाएगा।
- डिजिटल भुगतान को व्यापक स्वीकृति मिलना जारी है। 2022 में, उन्होंने लेनदेन में 76 प्रतिशत और मूल्य में 91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इस डिजिटल अवसंरचना के लिए राजकोषीय समर्थन 2023-24 में जारी रखा जाएगा।
- एक बार की नई लघु बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, मार्च 2025 तक दो साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर पर 2 साल की अवधि के लिए महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर ₹2 लाख तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा।
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख की जाएगी। मासिक आय

अनुबंध 2: केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं

खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए ₹ 4.5 लाख से बढ़ाकर ₹ 9 लाख और संयुक्त खाते के लिए ₹ 9 लाख से ₹ 15 लाख तक बढ़ा दी जाएगी।

राजकोषीय प्रबंधन

- राज्यों को पचास साल का ब्याज मुक्त ऋण: राज्यों को दिए जाने वाले पूरे पचास साल के ऋण को 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना है। इसमें से अधिकांश राज्यों के विवेक पर होगा, लेकिन एक हिस्सा राज्यों द्वारा अपने वास्तविक पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने पर सशर्त होगा। परिव्यय के कुछ हिस्सों को निम्नलिखित उद्देश्यों से भी जोड़ा जाएगा, या आवंटित किया जाएगा:
- पुराने सरकारी वाहनों को हटाना।
- शहरी नियोजन सुधार और कार्रवाई।
- शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों का वित्तपोषण करना ताकि उन्हें नगरपालिका बॉण्ड के लिए ऋण योग्य बनाया जा सके।
- पुलिस स्टेशनों के ऊपर या हिस्से के रूप में पुलिस कर्मियों के लिए आवास।
- यूनिटी मॉल बनाना।
- बच्चों और किशोरों के पुस्तकालय और डिजिटल अवसंरचना।
- केंद्रीय योजनाओं के पूंजीगत व्यय में राज्य की हिस्सेदारी।
- राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3.5 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी, जिसमें से 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा होगा।

कर प्रस्ताव

अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

- केंद्रीय बजट में वस्त्र और कृषि को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 करने का प्रस्ताव है। नतीजतन, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नेफ्था सहित कुछ वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क, उपकर और अधिभार में मामूली बदलाव हैं।

क्षेत्र विशेष अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

- हरित गतिशीलता: बजट में मिश्रित संपीड़ित प्राकृतिक गैस में निहित जीएसटी भुगतान वाली संपीड़ित बायोगैस पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है। इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के लिए लिथियम-आयन सेल के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट को और बढ़ाया जा रहा है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स: बजट में कैमरा लेंस जैसे कुछ पुर्जों और कच्चे माल के आयात पर सीमा शुल्क में राहत देने और बैटरी के लिए लिथियम आयन सेल पर रियायती शुल्क को एक और वर्ष के लिए जारी रखने का प्रस्ताव है। टेलीविजन पैनलों के ओपन सेल के पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क 2.5 प्रतिशत कम कर दिया गया है।
- इलेक्ट्रिकल: इलेक्ट्रिक किचन चिमनी पर मूल सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है और हीट कॉइल पर इसे 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
- रसायन और पेट्रोरसायन: ऊर्जा संक्रमण को सुविधाजनक बनाने और इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए, डीनेचर्ड ईथाइल अल्कोहल को मूल सीमा शुल्क छूट दी गई है। एसिड ग्रेड फ्लोरस्पार और क्रूड ग्लिसरीन पर भी मूल सीमा शुल्क कम किया जा रहा है।
- समुद्री उत्पाद: समुद्री उत्पादों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, झींगा के लिए चारा के घरेलू निर्माण के लिए प्रमुख आदानों पर शुल्क में कमी का प्रस्ताव है।
- प्रयोगशाला में बने हीरे: हीरे को तराशने और पॉलिशिंग में भारत के वैश्विक नेतृत्व को बनाए रखने के लिए, बजट में प्रयोगशाला में बनने वाले हीरे (एलजीडी) के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले सीड पर मूल सीमा शुल्क को कम करने का प्रस्ताव किया गया है।

अनुबंध 2: केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं

- कीमती धातुएं: बजट में सोने और प्लैटिनम से बनी वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है। चांदी के डोरे, बार और वस्तुओं पर आयात शुल्क भी बढ़ाया गया है।
- मिश्रित रबर: मिश्रित रबर पर मूल सीमा शुल्क दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर '25 प्रतिशत या ₹30/किग्रा' जो भी कम हो, की जा रही है।
- सिगरेट: विनिर्दिष्ट सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) को लगभग 16 प्रतिशत तक संशोधित करने का प्रस्ताव है।

प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

- एमएसएमई और पेशेवर: बजट में सूक्ष्म उद्यमों के लिए अनुमानित कराधान की सीमा को बढ़ाकर ₹3 करोड़ और 5 प्रतिशत से कम नकद भुगतान वाले पेशेवरों के लिए ₹75 लाख करने का प्रस्ताव है।
- सहकारी समितियां: नई विनिर्माण कंपनियों के अनुरूप, विनिर्माण गतिविधियों को शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को भी 15 प्रतिशत की कम कर दर से लाभ होगा। सहकारी समितियों के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के बिना नकदी निकालने की सीमा बढ़ाकर ₹3 करोड़ कर दी गई है।
- चीनी की सहकारी समितियों को आकलन वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इससे उन्हें लगभग 10,000 करोड़ रुपये की राहत मिलने की उम्मीद है।
- प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) द्वारा नकद जमा और नकद में ऋण की जुर्माना छूट के लिए प्रति सदस्य ₹2 लाख की उच्च सीमा के लिए प्रस्ताव किया गया है।
- स्टार्ट-अप: स्टार्ट-अप को आयकर लाभ के लिए निगमन की तारीख 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है। स्टार्ट-अप की शेयरधारिता को निगमन के सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष किए जाने पर होने वाले घाटे को आगे बढ़ाने का लाभ प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।
- अपील: लंबित अपीलों को कम करने के लिए, छोटी अपीलों के निपटान के लिए लगभग 100 ज्वाइंट कमिश्नर को तैनात करने का प्रस्ताव है।
- कर रियायतों का बेहतर लक्ष्यीकरण: बजट में धारा 54 और 54 एफ के तहत आवासीय घर में निवेश पर पूंजीगत लाभ से कटौती को 10 करोड़ रुपये तक सीमित करने का प्रस्ताव है।
- युक्तिकरण: आवास, शहरों, कस्बों और गांवों के विकास और किसी गतिविधि को विनियमित और विकसित करने के उद्देश्य से संघ या राज्य की विधियों द्वारा स्थापित प्राधिकरणों, बोर्डों और आयोगों की आय को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव है।

वैयक्तिक आय कर

- नई कर व्यवस्था में छूट सीमा को बढ़ाकर ₹7 लाख करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार, नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए कोई आयकर नहीं है।
- बजट में नई वैयक्तिक आयकर व्यवस्था के तहत कर संरचना में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है जिसके तहत स्लैब की संख्या घटाकर पांच कर दी गई है और कर छूट की सीमा बढ़ाकर ₹3 लाख कर दिया गया है। संशोधित नई कर व्यवस्था इस प्रकार है:
- नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी लोगों के लिए ₹50,000 की मानक कटौती और पेंशनभोगियों के लिए ₹15,000 तक की कटौती।
- नई कर व्यवस्था में अधिभार की उच्चतम दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव है। इससे अधिकतम कर की दर 42.74 प्रतिशत से घटकर 39 प्रतिशत

अनुबंध 2: केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं

रह जाएगी।

- गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा को मौजूदा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख करने का प्रस्ताव है।
- नई आयकर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जाएगा। हालांकि, नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प जारी रहेगा।

अनुबंध 3: विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को केंद्र से संसाधन हस्तांतरण

		2021-2022	2022-2023 (आरई)	2023-2024 (बीई)	2021-2022	2022-2023 (आरई)	2023-2024 (बीई)	2021-2022	2022-2023 (आरई)	2023-2024 (बीई)
		₹ करोड़			सकल हस्तांतरण के प्रतिशत के अनुसार			वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)		
I	करों में राज्यों के हिस्से का न्यागमन	898,392	948,406	1,021,448	52.7	55.4	54.8	51.0	5.6	7.7
II	हस्तांतरण की कुछ महत्वपूर्ण मदें	202,808	125,177	183,613	11.9	7.3	9.9	23.0	-38.3	46.7
	जिनमें:									
	1. जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के बदले राज्यों को एक के बाद एक ऋण	147,866	-	-	8.7	0.0	0.0	34.2	-	-
	2. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं- ऋण	23,083	29,580	24,550	1.4	1.7	1.3	-13.8	28.1	-17.0
	3. पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता	14,186	76,000	130,000	0.8	4.4	7.0	19.9	435.7	71.1
III	वित्त आयोग अनुदान	207,435	173,257	165,480	12.2	10.1	8.9	12.7	-16.5	-4.5
	जिनमें:									
	1. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान – शहरी निकाय	16,147	15,026	24,222	0.9	0.9	1.3	-39.5	-6.9	61.2
	2. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान - ग्रामीण निकाय	40,312	41,000	47,018	2.4	2.4	2.5	-33.6	1.7	14.7
	3. एसडीआरएफ के लिए सहायता अनुदान	17,747	18,635	19,573	1.0	1.1	1.1	-20.3	5.0	5.0
	4. न्यागमन के बाद राजस्व घाटा अनुदान	118,452	86,201	51,673	6.9	5.0	2.8	59.3	-27.2	-40.1
IV	राज्यों को कुल हस्तांतरण [I +II +III के अलावा]	345,847	395,334	426,996	20.3	23.1	22.9	6.3	14.3	8.0
	1. केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत (राजस्व)	334,581	346,992	364,270	19.6	20.3	19.6	8.5	3.7	5.0
	2. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत (राजस्व)	9,994	46,687	60,942	0.6	2.7	3.3	-38.1	367.2	30.5
	3. व्यय की अन्य श्रेणियों के अंतर्गत (राजस्व)	1,270	1,552	1,681	0.1	0.1	0.1	26.6	22.2	8.3
	4. पूंजी हस्तांतरण	2	102	103	0.0	0.0	0.0	-5.0	5268.4	1.0
V	दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर में हस्तांतरण	51,128	68,654	65,337	3.0	4.0	3.5	0.9	34.3	-4.8
VI	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सकल हस्तांतरण (I+II+III+IV+V)	1,705,610	1,710,828	1,862,874	100.0	100.0	100.0	29.2	0.3	8.9
VII	ऋण और अग्रिम की कम वसूली	17,569	9,105	8,296	1.0	0.5	0.4	9.1	-48.2	-8.9
VIII	निवल हस्तांतरण (VI-VII)	1,688,041	1,701,723	1,854,578	99.0	99.5	99.6	29.5	0.8	9.0
IX	सकल हस्तांतरण/सकल घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	7.2	6.3	6.2	-	-	-	-	-	-
X	निवल हस्तांतरण/सकल घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	7.1	6.2	6.1	-	-	-	-	-	-

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

ईएसजी प्रकटीकरण और प्रदर्शन: अंतर-देशीय साक्ष्य*

द्वारा - सौरभ घोष^ और सिद्धार्थ नाथ ^

हम एक समग्र अनुभवजन्य विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं जो यह बताता है कि पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) सूचकांकों ने अपने व्यापक बाजार समकक्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। इस विषय पर लिखी जाने वाली सामग्री में इस बात पर चर्चा है कि क्या ईएसजी गतिविधियां शेयरधारकों के हित में हैं या एजेंसी की समस्याओं के परिणाम हैं। हमारा आलेख इस चर्चा के केंद्र में सटीक बैठता है और यह इंगित करता है कि ईएसजी सूचकांकों ने व्यापक बाजार सूचकांकों की तुलना में अप्रत्याशित आघात (कोविड19) का बेहतर सामना किया। इन निष्कर्षों की पृष्ठभूमि में हमने कुछ नीतिगत विकल्प प्रस्तुत किए हैं जो भारतीय कॉर्पोरेट्स के इन ईएसजी पहलों में शामिल होने को प्रोत्साहित किए जाने से संबंधित हैं।

परिचय

"पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी)" जोखिम का संबंध उन जोखिमों से है जिनका सामना जलवायु परिवर्तन, संसाधन की कमी, जनसांख्यिकीय बदलाव आदि जैसे बड़े पैमाने में होने वाले परिवर्तनों के कारण सरकारों, कॉर्पोरेट्स और वित्तीय संस्थानों को करना पड़ता है। कॉर्पोरेट वित्त के संदर्भ में ईएसजी संबंधी चर्चा में अक्सर यह बात शामिल होती है कि कंपनियां अपने व्यवसाय मॉडल के हिस्से के रूप में इन जोखिमों को कैसे शामिल और प्रबंधित करती हैं, और किस हद तक निवेशक उन्हें अपने निर्णयों में शामिल करते हैं। दुनिया भर के सरकारी प्राधिकरणों का ईएसजी जोखिमों पर बढ़ता ध्यान, यह दर्शाता है कि धारणीय विकास प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इन जोखिमों के प्रबंधन का सर्वोपरि महत्व का है। इस प्रथा को संस्थागत बनाने का सबसे प्रभावी तरीका इन सिद्धांतों को निवेश नीति और प्रथाओं में शामिल करना होगा।

दुनिया भर के सरकारी प्राधिकरण अपने विनियामकीय ढांचे (बीआईएस, 2021) में इन सिद्धांतों को शामिल करने पर ध्यान दे रहे हैं। जलवायु से संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण (टीसीएफडी) पर गठित कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय धारणीयता मानक बोर्ड (आईएसएसबी) ने टिप्पणी मंगवाने के लिए प्रस्तावित धारणीयता मानकों की अपनी पहली रूपरेखा जारी की। इन मानकों में धारणीयता लेखा मानक बोर्ड (एसएएसबी) से प्राप्त उद्योग-आधारित प्रकटीकरण आवश्यकताएं भी शामिल हैं। भारत सहित दुनिया भर की अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने पहले ही सूचीबद्ध कंपनियों के लिए धारणीयता प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाकर इस संबंध में काफी कार्य किया है। तथापि, इन प्रकटीकरणों की पारदर्शिता और रिपोर्टिंग मानक इस नीति को व्यापक आधार पर लागू किए जाने के लिए एक चुनौती बने हुए हैं (बोये एवं अन्य)।

हालांकि इस बात पर लगभग एकमत है कि बेहतर प्रकटीकरण मानकों से विनियामकों को दीर्घकालिक लाभ होगा, लेकिन उनके कुछ अल्पावधिक मुद्दे हैं। एक बड़ी उपलब्ध सामग्री (काय एवं अन्य 2016), लियांग और रेनेबूग (2017 ए और 2017 बी)) 1 से पता चलता है कि किसी देश में कार्पोरेशन्स द्वारा ईएसजी से संबंधित प्रदर्शन देश के आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली कानूनी प्रणालियों, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक अधिकारों, सद्भाव, स्वायत्तता आदि से जुड़े हैं। फर्म-स्तर पर, उच्च ईएसजी अंगीकरण बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन, उच्च संस्थागत स्वामित्व, बोर्ड के सदस्यों के संतुलित जेंडर-पॉलिटिकल झुकाव आदि से जुड़े हैं, (गिलन एवं अन्य(2021))। व्यवसाय के संदर्भ में, बढ़ते ईएसजी अंगीकरण को आम तौर पर सद्भावना, प्रतिष्ठा और सकारात्मक उपभोक्ता धारणा (शिलर (2018), दाई एवं अन्य (2020)) से जुड़ा हुआ पाया जाता है। यह किसी कंपनी को उचित औचित्य प्रदान करता है कि वह इन सिद्धांतों को अपने व्यवसाय मॉडल में क्यों शामिल करे। ईएसजी अंगीकरण के पक्ष में इन सबूतों के बावजूद, इस बात पर बहस होती है कि क्या ईएसजी गतिविधियां शेयरधारकों के व्यापक हित में हैं या एजेंसी की समस्याओं के परिणाम हैं (गिलन एवं अन्य, (2021))। इसके अलावा, कार्पोरेशन्स द्वारा, खासकर, पूंजी की कमी वाली छोटी

^ लेखक, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं।

* इस आलेख में व्यक्त विचार केवल लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

[1] साहित्य की विस्तृत समीक्षा के लिए, गिलन और अन्य (2021) देखें।

संस्थाओं के मामले में, ईएसजी पहल करने में संदेह स्थिति भी हो सकती है। दरअसल, अध्ययन की एक शाखा से पता चलता है कि ईएसजी जोखिमों के उच्च प्रकटीकरण और प्राधिकारियों द्वारा सख्त स्क्रीनिंग से स्टॉक की कीमतें कम हो सकती हैं और किसी फर्म के लिए पूंजी जुटाने की लागत उच्च हो सकती है (हेंकेल एवं अन्य, (2001), चावा (2014), एनजी और रेजाई (2015) आदि), जिससे वे ईएसजी प्रकटीकरण और पहल करने के लिए हतोत्साहित हो सकते हैं।

हमारा आलेख इस बहस के केंद्र में सटीक बैठता है। आलेख में प्रस्तुत सबूत बताते हैं कि ईएसजी पहल में अग्रणी कंपनियों के शेयर मूल्य सूचकांकों ने आम तौर पर अधिकांश उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में लंबी अवधि में व्यापक बाजार सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया है। अर्थात्, इसे इस बात से जोड़ा जा सकता है कि ईएसजी अंगीकरण को विचार में न लेने पर मिलने वाले प्रतिलाभ की तुलना में ईएसजी अंगीकरण को विचार में लेने से बेहतर वित्तीय बाजार प्रतिलाभ मिलते हैं।

इस आलेख के बाकी हिस्सों को निम्नानुसार रखा गया है: खंड 2 में हमारे विश्लेषण के लिए प्रयुक्त डेटा के बारे में बताया गया है, इसके बाद खंड 3 में समग्र खोजपूर्ण डेटा विश्लेषण है। खंड 4 में हमने दो अनुभवजन्य मॉडल (अंतर-और-अंतर तथा बाजार मॉडल) का उपयोग यह साबित करने के लिए किया है कि ईएसजी अंगीकरण करने वाली कंपनियों ने कोविड-19 महामारी के दौरान बाज़ार में अच्छा प्रदर्शन किया। आलेख के अंत में खंड 5 है।

II. डेटा

हमने अपने विश्लेषण के लिए मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) ईएसजी सूचकांकों का उपयोग किया है। हमने अपने विश्लेषण के लिए 18 देशों को चुना - 10 उभरती अर्थव्यवस्थाएं, अर्थात् ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान और थाईलैंड: और 8 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, जापान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके और यूएसए। हमारे विश्लेषण के लिए नमूना अवधि सितंबर 2010 से अगस्त 2021 तक है।

एमएससीआई ईएसजी लीडर्स के सूचकांक एमएससीआई द्वारा दी गई कंपनियों के लिए ईएसजी रेटिंग के आधार पर बनाए गए हैं। कंपनियों की एमएससीआई ईएसजी रेटिंग उन दीर्घकालिक ईएसजी जोखिमों के लिए कंपनी के जोखिम और लचीलापन को मापती है जो वित्तीय रूप से प्रासंगिक हैं। एमएससीआई ईएसजी रेटिंग को कुछ ऐसे जोखिमों को चुनने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें वित्तीय जोखिमों के पारंपरिक मूल्यांकन में शामिल नहीं किया गया किंतु जो उनके उभरने[2] पर वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ जोखिमों के प्रति कंपनी के एक्सपोज़र के साथ-साथ, एमएससीआई ईएसजी रेटिंग यह भी देखती है कि कंपनी उन जोखिमों का प्रबंधन कैसे कर रही है[3]। कंपनियों को इन पहलुओं के आधार पर रेटिंग प्रदान की जाती है और ईएसजी रेटिंग उन कंपनियों की पहचान करने में मदद करती है जो अपने उद्योग के साथियों के भीतर अग्रणी हैं या पिछड़ रही हैं। अंततः, एमएससीआई ईएसजी सूचकांकों को निवेशक के निवेश निर्णयों में ईएसजी अंगीकरण के एकीकरण की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ईएसजी से संबंधित जोखिमों के लिए कंपनियों और क्षेत्रों के जोखिम और प्रबंधन का आकलन करने के लिए, एमएससीआई विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करता है जो ज्यादातर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होते हैं, जैसे, शिक्षाक्षेत्र, सरकार, एनजीओ डेटाबेस, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यूएस ईपीए और विश्व बैंक (एमएससीआई, 2022)। कंपनियों से विभिन्न प्रकटीकरणों, ईएसजी अनुपालन और विवादों पर सरकारी डेटाबेस, मीडिया रिपोर्टों, गैर सरकारी संगठनों, हितधारक स्रोतों आदि से कंपनी विशिष्ट जानकारी एकत्र की जाती है। एमएससीआई ने सभी स्तंभों; पर्यावरण, सामाजिक और शासन को शामिल करने वाले 10 व्यापक विषयों के तहत 35 'प्रमुख मुद्दों' की पहचान की (सारणी 1 अनुलग्नक में) है। किसी कंपनी की अंतिम ईएसजी रेटिंग को व्यक्तिगत प्रमुख मुद्दों पर रेटिंग के भारित औसत के रूप

[2] उदाहरण के लिए, निकट भविष्य में पानी की कमी एक खनन कंपनी के लिए कैसे खतरा पैदा कर सकती है, यह ईएसजी रेटिंग द्वारा संकेतित किया जाता है, लेकिन इसे पारंपरिक वित्तीय संकेतकों, या स्टॉक की कीमतों द्वारा कैप्चर नहीं किया जाता है।

[3] यूरोपीय संघ, चीन और भारत सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए बड़ी विनिर्माण कंपनियों के लिए 3 ईएसजी प्रकटीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट/निदेशक की रिपोर्ट में खुलासे के अलावा, एमएससीआई ईएसजी रेटिंग बनाते समय कई स्वतंत्र स्रोतों जैसे, समाचार लेख, विवादों पर रिपोर्ट, अन्य व्यवसाय/अकादमिक रिपोर्ट आदि से कंपनी के जोखिमों के बारे में जानकारी एकत्र करता है। इससे 'नैतिक खतरे' आदि के कारण उत्पन्न होने वाले पूर्वग्रहों की संभावना कम होने की उम्मीद है।

में परिभाषित किया गया है। कंपनी की रेटिंग को तब उनके उद्योग के साथियों के सापेक्ष सामान्य किया जाता है। पर्यावरण और समाज पर उस उद्योग के संचालन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों और जिस समयरेखा के भीतर इन प्रभावों को मूर्त रूप देने की उम्मीद है, पर विचार करके किसी उद्योग के लिए भार को परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए, "उच्च प्रभाव" और "अल्पकालिक" के रूप में पहचाने जाने वाले एक प्रमुख मुद्दे को "कम प्रभाव" और "दीर्घकालिक" के रूप में पहचाने जाने वाले प्रमुख मुद्दे की तुलना में तीन गुना अधिक भारित किया जाएगा। उद्योग भार उस कंपनी का समग्र प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रमुख मुद्दों पर प्रत्येक कंपनी के स्कोर पर लागू किया जाता है, जिसे बाद अपने स्वयं के उद्योगक्षेत्र के भीतर उसे सामान्यीकृत किया जाता है, और सर्वश्रेष्ठ (एएए) और सबसे खराब (सीसीसी) के बीच रेटिंग प्रदान की जाती है। नमूना देशों के लिए एमएससीआई ब्रॉड और एमएससीआई ईएसजी लीडर्स इंडेक्स दोनों में घटकों/कंपनियों की संख्या और शीर्ष घटकों के भारांक अनुबंध में सारणी 2 में दिए गए हैं।

एक प्रतिवाद है जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए। अधिकांश देशों के लिए ब्रॉड एमएससीआई सूचकांक आम तौर पर सुपरसेट होता है, क्योंकि उनमें ज्यादातर ऐसी कंपनियां शामिल हैं जो एमएससीआई ईएसजी लीडर्स सूचकांक में हैं। इस कमी के बावजूद, हमने इस अध्ययन को जारी रखा, क्योंकि केवल ईएसजी लीडर्स या गैर-ईएसजी-लीडर्स के साथ कड़े विभागीकृत सूचकांकों को प्राप्त करना मुश्किल है। इसके अलावा यह हमारे किसी भी निष्कर्ष को नहीं बदलता है।

एमएससीआई मूल्य और बाजार पूंजीकरण, दोनों सूचकांक प्रदान करता है जिसमें वे कंपनियां शामिल होती हैं जो ईएसजी अंगीकरण के संदर्भ में नेतृत्व करती हैं। इन कंपनियों को देशों के भीतर ईएसजी लीडर्स के रूप में भी जाना जाता है[4]। ईएसजी सूचकांकों के साथ, हमने इस आलेख में बाजार पूंजीकरण और कीमतें, दोनों के आधार पर एमएससीआई व्यापक बाजार सूचकांकों का भी उपयोग किया है। हमारे नमूने में सभी देशों के लिए, ईएसजी बाजार पूंजीकरण सूचकांकों में वृद्धि ईएसजी लीडर्स के मूल्य सूचकांक में वृद्धि से अधिक थी (चार्ट 1)। इन अंतरालों से पता चलता है कि सभी देशों (मलेशिया और ब्राजील को छोड़कर) में मात्रा में या उनके देशों में ईएसजी लीडर्स द्वारा जारी शेयरों की संख्या में वृद्धि हुई है। तथापि, हम दो कारणों से इस

चार्ट 1 : यौगिक औसत वार्षिक प्रतिलाभ : सितंबर 2010 – अगस्त 2021 : ईएसजी लीडर सूचकांक (प्रतिशत)

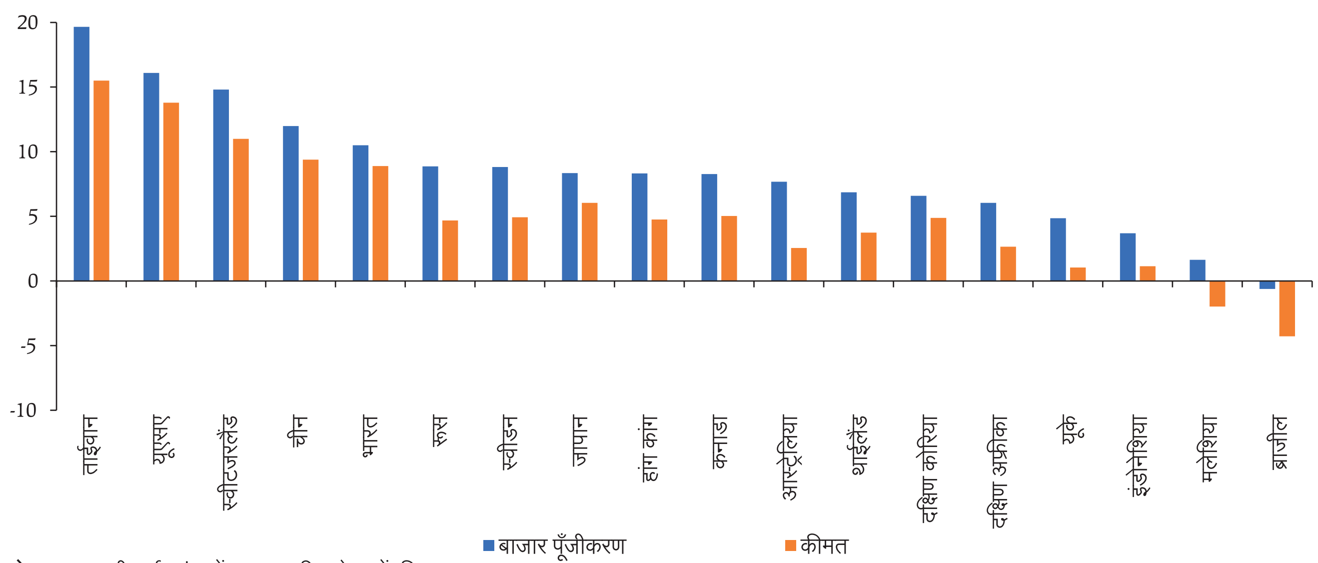

स्रोत : एमएससीआई आंकड़ों पर आधारित लेखकों की गणना।

[4] बाजार पूंजीकरण, या ईएसजी सकल सूचकांक बाजार के समग्र आकार को मापता है, यानी, प्रत्येक बकाया शेयर को प्रत्येक अवधि के लिए उनके संबंधित बाजार मूल्यों से गुणा किया जाता है, और फिर सभी शेयरों में एकीकृत किया जाता है। ईएसजी लीडर के मूल्य सूचकांक ईएसजी लीडर के लिए कंपनी-स्तरीय बाजार पूंजीकरण भारित कुल मूल्य सूचकांक हैं। ईएसजी बाजार पूंजीकरण और ईएसजी मूल्य सूचकांक उन उद्योगों के समूह के लिए बाजार पूंजीकरण और मूल्य सूचकांक का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ईएसजी विचारों में अग्रणी हैं।

चार्ट 2: औसत वार्षिक प्रतिलाभ सितंबर 2010 – अगस्त 2021

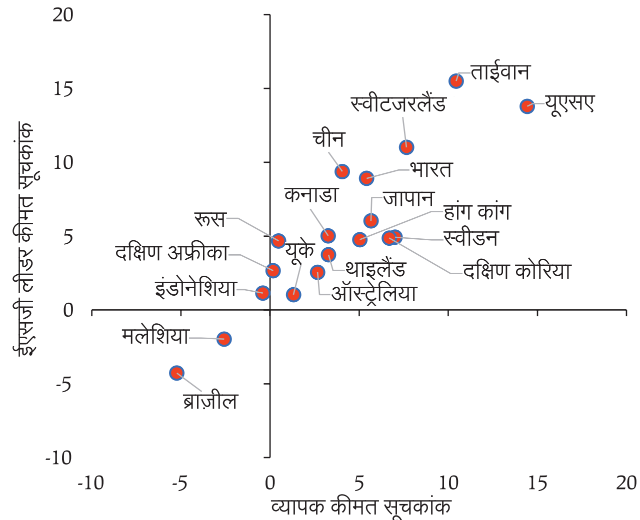

स्रोत : एमएससीआई आंकड़ों पर आधारित लेखकों की गणना।

चार्ट 3: व्यापक कीमत सूचकांक की तुलना में ईएसजी कीमत सूचकांक (2010=1)

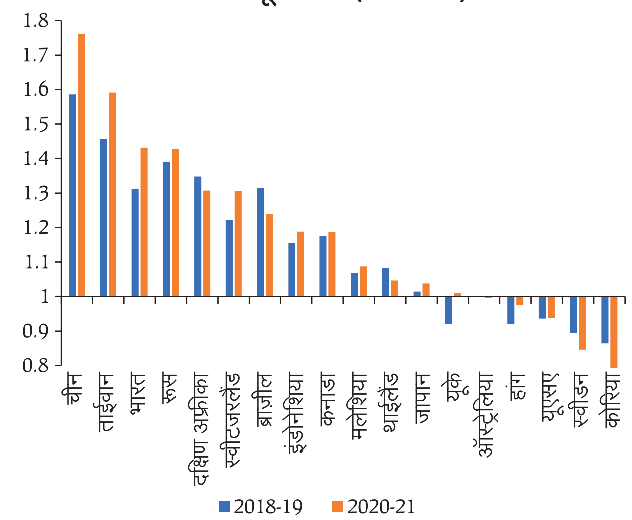

स्रोत : एमएससीआई आंकड़ों पर आधारित लेखकों की गणना।

आलेख के शेष भाग में ईएसजी मूल्य सूचकांकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला, ईएसजी बाजार पूंजीकरण और ईएसजी मूल्य सूचकांक नमूना देशों (चार्ट 1) के बीच काफी निकटता से चले, और दूसरा, मूल्य में उतार-चढ़ाव ईएसजी लीडर्स के बारे में भविष्य की ओर देखने वाले निवेशकों की अपेक्षाओं को दर्शाता है।

III. अन्वेषणात्मक डेटा विश्लेषण

अंतर-देशीय साक्ष्य

ईएसजी मूल्य सूचकांकों में औसत वार्षिक प्रतिलाभ व्यापक मूल्य सूचकांक में प्रतिलाभ के अनुरूप थे (चार्ट 2)। ईएसजी लीडर्स सूचकांकों ने हमारे नमूने में अधिकांश देशों में व्यापक सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया (चार्ट 3)। चार्ट 3 में हमने 2010 के संबंध में प्रत्येक संकेतक को सामान्य किया, और फिर ईएसजी सूचकांक और व्यापक बाजार सूचकांकों के बीच अनुपात लिया। उच्च अनुपात इंगित करता है कि ईएसजी लीडर्स सूचकांक ने व्यापक सूचकांक से बेहतर प्रदर्शन किया है। इससे पता चलता है कि जिन कंपनियों ने अपने ईएसजी से संबंधित जोखिमों को बेहतर ढंग से प्रबंधित और प्रकट किया, उनकी इक्विटी की कीमतें सूचीबद्ध कंपनियों के एक बड़े समूह की तुलना में उच्च थीं।

ईएसजी लीडर्स इंडेक्स में सापेक्ष प्रतिलाभ के मामले में भारत चीन और ताइवान को छोड़कर सभी देशों से आगे है। भारत के ईएसजी सूचकांक में सापेक्ष वृद्धि भी हमारे नमूने में 18 देशों के समूह के भीतर इस अवधि के दौरान शीर्ष पर थी, जैसा कि चार्ट 4 में दिखाया गया है, जहां ऑरेंज लाइन भारत के व्यापक बाजार सूचकांक के सापेक्ष भारत के ईएसजी लीडर्स के सूचकांक को इंगित करती है। दोनों 2010[5] पर पुन:आधारित हैं। छायांकित

चार्ट 4 : भारत में ईएसजी कीमत सूचकांक में सापेक्ष वृद्धि : वैश्विक परिप्रेक्ष्य

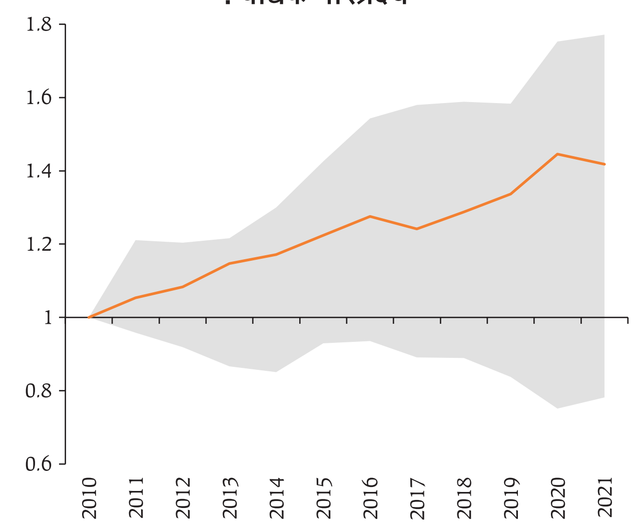

स्रोत : एमएससीआई आंकड़ों पर आधारित लेखकों की गणना।

5 वर्ष 2010 वह वर्ष है जब से हम अपने नमूने में सभी देशों के लिए ईएसजी सूचकांक प्राप्त कर सके। एमएससीआई ने 2010 से पहले इनमें से केवल कुछ देशों में ही ईएसजी सूचकांकों की सूचना दी थी। इसलिए, बेहतर तुलना के लिए, हमने सभी देशों के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में 2010 का उपयोग किया है।

चार्ट 5 : ईएसजी लीडर कीमत सूचकांक में प्रतिलाभ बनाम जोखिम : सितंबर 2010 - अगस्त 2021

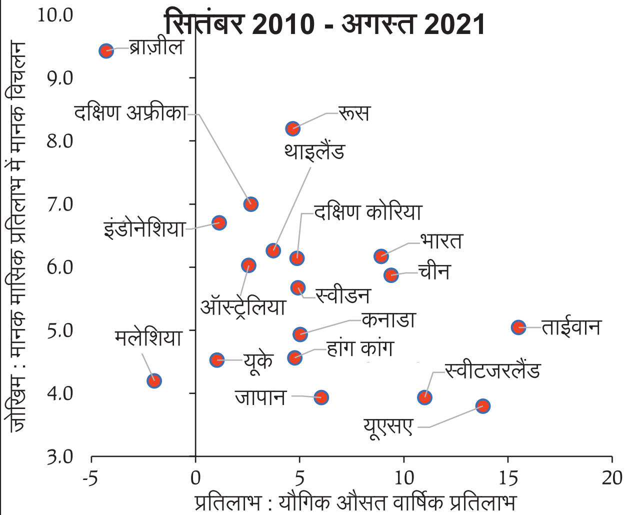

स्रोत : एमएससीआई आंकड़ों पर आधारित लेखकों की गणना।

चार्ट 6 : कीमत सूचकांक के मासिक प्रतिलाभ में मानक विचलन (प्रतिशत) : सितंबर 2010 – अगस्त 2021

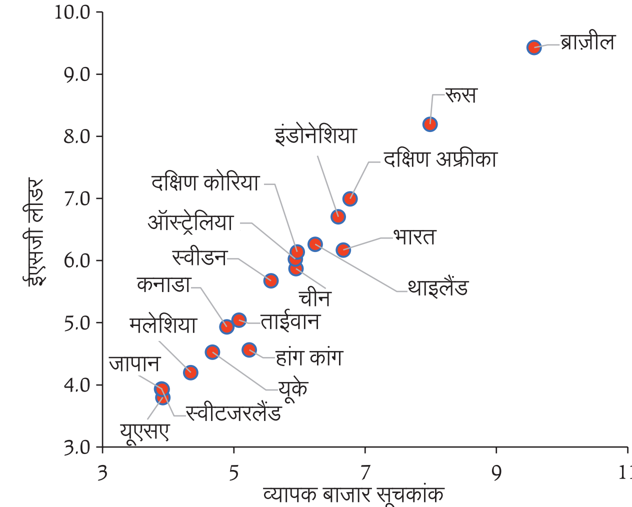

स्रोत : एमएससीआई आंकड़ों पर आधारित लेखकों की गणना।

सीमाओं का निचला छोर नमूना देशों के बीच इस माप के न्यूनतम मूल्य को इंगित करता है और छायांकित सीमाओं का ऊपरी छोर अधिकतम मूल्य को इंगित करता है।

नमूना अवधि के दौरान, देशों के समूह के बीच ईएसजी लीडर्स के मूल्य सूचकांकों में औसत वार्षिक प्रतिलाभ और औसत जोखिमों के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं है (चार्ट 5)।

हालांकि, ईएसजी सूचकांकों में जोखिम मोटे तौर पर देशों में व्यापक सूचकांकों में जोखिमों के अनुरूप थे (चार्ट 6)। सामान्य तौर पर, एई की तुलना में ईएमई में व्यापक सूचकांक और ईएसजी सूचकांक दोनों में जोखिम अधिक था। भारत अपवाद नहीं है, जहां ईएसजी और व्यापक सूचकांक दोनों में जोखिम अधिकांश देशों की तुलना में अधिक थे (चार्ट 6)। भारत के लिए मासिक ईएसजी प्रतिलाभ के लिए कर्नेल डेंसिटी प्लॉट, और हमारे नमूने में अन्य सभी देशों (भारत को छोड़कर) से पता चलता है कि भारत के मासिक ईएसजी प्रतिलाभ में आम तौर पर बनी दाहिनी आकृति उच्च प्रतिलाभ की बड़ी संभावना को दर्शाती है (चार्ट 7)। भारत के लिए प्रतिलाभ वितरण दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में प्लैटीकुर्टिक था, जो बताता है कि मासिक ईएसजी इंडेक्स प्रतिलाभ का मानक विचलन भारत के लिए अधिक क्यों था। हमने जीएआरसीएच (1,1) समीकरण का उपयोग करके व्यापक और ईएसजी सूचकांकों के अस्थिरता क्लस्टरिंग का भी विश्लेषण किया। हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि सामान्य रूप से, ब्रॉड और ईएसजी सूचकांकों, दोनों में ईएमई की तुलना में एई में अस्थिरता कम थी। भारत के मामले में ईएसजी इंडेक्स की जीएआरसीएच अस्थिरता ब्रॉड इंडेक्स प्रतिलाभ (चार्ट 8) में अस्थिरता की तुलना में कम थी, जबकि क्लस्टरिंग पैटर्न दोनों शृंखलाओं में समान थे।

चार्ट 7 : मासिक ईएसजी सूचकांक प्रतिलाभ के लिए कर्नेल डेंसिटी प्लॉट

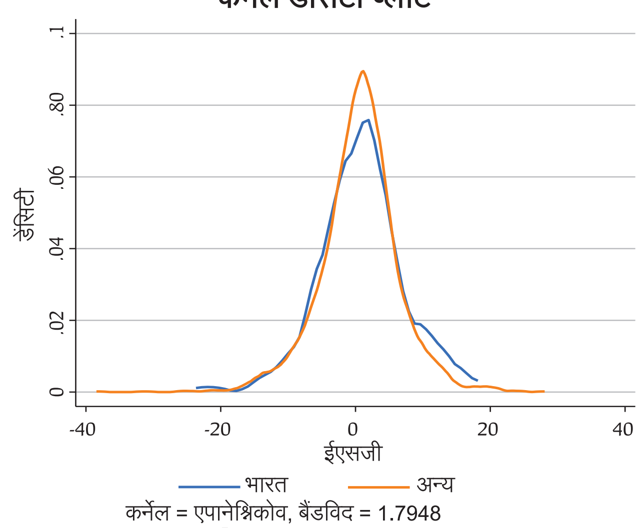

स्रोत : एमएससीआई आंकड़ों पर आधारित लेखकों की गणना।

चार्ट 8 : जीएआरसीएच अस्थिरता उपाय

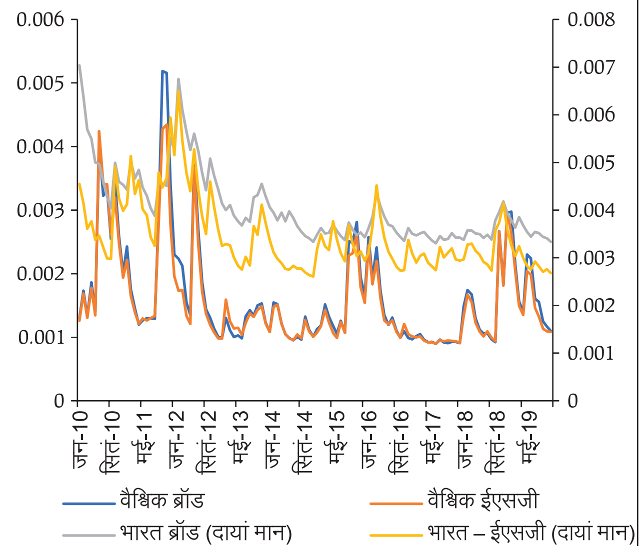

स्रोत : एमएससीआई आंकड़ों पर आधारित लेखकों की गणना।

अस्थिरता क्लस्टरिंग के अनुरूप, हमने ईएसजी लीडर्स के मूल्य सूचकांकों के लिए व्यापक बाजार जोखिमों के प्रसारण की मात्रा निर्धारित करने का प्रयास किया। सारणी 1 में, हमने पहले व्यापक बाजार प्रतिलाभ को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया, "चरम" और "सामान्य" जैसा कि पहले कॉलम में दिखाया गया है। ऐसा करने के लिए, पहले हम सितंबर 2010 और अगस्त 2021 के बीच किसी एक देश के व्यापक बाजार सूचकांक में मासिक प्रतिलाभ का निरीक्षण करते हैं और प्रत्येक देश के लिए अलग-अलग अवधि के लिए औसत और मानक विचलन दोनों का निरीक्षण करते हैं। हम मासिक प्रतिलाभ को "चरम" कहते हैं यदि किसी अवधि के लिए प्रतिलाभ उस देश के औसत के आसपास एक-मानक विचलन बैंड से ऊपर या नीचे है। इसी तरह, हम प्रतिलाभ को ईएसजी लीडर्स इंडेक्स में वर्गीकृत करते हैं। इसके बाद, हम ऐसे अवसरों की गणना करते हैं जिनमें व्यापक बाजार सूचकांक की कोई "चरम" घटना ईएसजी लीडर्स के सूचकांक की "चरम" घटनाओं के साथ भी मेल खाती हो। उदाहरण के लिए, भारत के मामले में, व्यापक सूचकांक की 78 प्रतिशत (अर्थात 30 में से 23) "चरम" घटनाएं ईएसजी लीडर्स सूचकांक की "चरम" घटनाओं में परिवर्तित हुई हैं। यह व्यापक बाजार सूचकांक से ईएसजी लीडर्स के सूचकांक में जोखिम संचरण के माप के रूप में

सारणी 1 : व्यापक और ईएसजी लीडर सूचकांकों में इवेंट के बीच संगति

(प्रतिशत)

व्यापक सूचकांक में ईवेंट	चरम		सामान्य		व्यापक सूचकांकों में 'चरम' इवेंट का प्रतिशत ईएसजी सूचकांकों में 'चरम' घटनाओं में परिवर्तित
ईएसजी सूचकांक में ईवेंट	**चरम**	**सामान्य**	**चरम**	**सामान्य**	
ब्राज़िल	29	2	2	68	95
चीन	25	5	4	67	85
भारत	**23**	**7**	**2**	**68**	**78**
इंडोनेशिया	27	2	2	70	95
दक्षिण कोरिया	25	7	5	64	79
मलेशिया	22	4	8	66	85
रूस	20	3	5	71	87
दक्षिण अफ्रीका	30	5	5	61	87
ताइवान	24	5	1	70	84
थाईलैंड	23	5	0	72	81
ऑस्ट्रेलिया	19	3	4	74	86
कनाडा	20	5	2	73	82
हांगकांग	22	8	5	66	74
जापान	24	2	0	73	91
स्वीडन	23	2	2	73	91
स्विट्ज़रलैंड	27	2	2	70	95
यूके	24	3	4	69	89
अमेरीका	22	2	2	74	91

टिप्पणियाँ:

नमूना कवर सितंबर 2010 से अगस्त 2021 के बीच का है।

'चरम' इवेंट औसत मासिक प्रतिलाभ के ऊपर और नीचे 1 मानक विचलन हैं। अन्यथा इवेंट को 'सामान्य' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कार्य करता है। सारणी 1 बताती है कि जोखिम संचरण का यह माप चयनित देशों में भारत के मामले में सबसे कम था। व्यापक सूचकांकों में 'चरम' घटनाओं का प्रतिशत जो ईएसजी सूचकांकों में 'चरम' घटनाओं में परिवर्तित हो गया, हमारे देशों के नमूना सेट के लिए औसतन लगभग 86 प्रतिशत है। इससे पता चलता है कि एसएससीआई-ईएसजी सूचकांक में शामिल कंपनियां कुछ हद तक व्यापक बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव से अछूती थीं। भारत के मामले में, यह अनुपात 78 प्रतिशत है, जो अन्य देशों के औसत से कम है, यह दर्शाता है कि ईएसजी-इंडेक्स में स्टॉक कुछ हद तक व्यापक बाजारों में चरम मूल्य उतार-चढ़ाव से सुरक्षित थे।

इस खंड के प्रमुख निष्कर्ष यह हैं कि ईएसजी प्रकटीकरण वाली कंपनियों ने सभी देशों की कंपनियों के व्यापक समूह की तुलना में, प्रतिफल और अस्थिरता की दृष्टि से, आम तौर पर बेहतर प्रदर्शन किया है।

IV. अनुभवजन्य निष्कर्ष

अब तक प्रस्तुत किए गए स्टाइलाइज्ड तथ्यों से पता चलता है कि ईएसजी लीडर्स के लिए स्टॉक मूल्य सूचकांक का प्रतिलाभ आम तौर पर लंबी अवधि में व्यापक बाजार से अधिक रहा है। अनुभवजन्य रूप से इस तथ्य की एक दृढ़ पुष्टि के लिए हमें यह देखने की आवश्यकता है कि कोविड-19 महामारी जैसे विशुद्ध रूप से बाहरी आघात के समय प्रतिलाभ क्या था। हम इसे दो अलग-अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से करते हैं; पहला, अंतर में अंतर या 'दोहरे अंतर' मॉडल का आकलन करना और दूसरा, सितंबर 2010 और अक्टूबर 2020 के बीच ईएसजी लीडर्स और व्यापक बाजार सूचकांकों में देशवार प्रतिलाभ पर 'मार्केट मॉडल' से संचयी औसत प्रतिलाभ (सीएआर) का अनुमान लगाना।

(क) अंतर में अंतर मॉडल

दोनों अंतरों से दोनों प्रकार की कंपनियों को प्रभावित करने वाले आघातों को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के बाद गैर-ईएसजी लीडर्स की तुलना में ईएसजी लीडर्स के प्रतिलाभ में अंतर का पता चलता है। इस क्रम में, हमने सितंबर 2010 और अक्टूबर 2020 के बीच व्यापक बाजार सूचकांक (नियंत्रण समूह) के साथ देश-ईएसजी लीडर्स (हमारा अभ्यास समूह जो ईएसजी का अनुसरण और उससे संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण करता है) पर मासिक प्रतिलाभ से युक्त एक पूल डेटासेट का उपयोग किया। नमूना देश डेटा खंड में की गई चर्चा के अनुसार बने रहे। हमने "ईएसजी" नामक एक डमी चर बनाया, जिसने अवलोकन के अनुरूप ईएसजी लीडर्स इंडेक्स प्रतिलाभ के लिए मूल्य 1 लिया, और व्यापक बाजार प्रतिलाभ के लिए 0 लिया।

हमने निम्नलिखित कारणों से इस प्रभाव विश्लेषण के लिए कोविड प्रकोप के बाद की अवधि जनवरी-अक्टूबर 2020 को चुना : जनवरी-मई 2020 के बीच दुनिया भर के लगभग सभी प्रमुख देशों में कोविड -19 के प्रारंभिक प्रकोप और संबंधित लॉकडाउन के बाद, दूसरी बड़ी लहर यूरोप और यूएसए के अधिकांश हिस्सों में अक्टूबर 2020 के अंत के आसपास आई। हालांकि इस लहर की वास्तविक तारीखें पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के देशों के बीच थोड़ी भिन्न हो सकती हैं, नवंबर 2020 से पहले की अवधि मोटे तौर पर दुनिया भर में पहली लहर के प्रभाव के लिए एक उचित समयरेखा है। अक्टूबर 2020 के बाद अधिकांश देशों में संक्रमण की कई लहरें आईं, लेकिन उनका समय अलग-अलग था, जिससे शुद्ध महामारी के आघात का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया। दूसरी ओर, हमने जनवरी 2020 को कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रकोप के शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया और एक और डमी वैरिएबल, "कोविड" बनाया, जिसने जनवरी 2020 के बाद से सभी महीनों के अनुरूप मूल्य 1 ग्रहण किया, और उससे पहले के महीनों के लिए शून्य।

यह शोध डिजाइन हमें यह पहचानने में मदद करेगा कि क्या ईएसजी नियमों का पालन करने और उनका खुलासा करने वाली फर्में सभी देशों की अन्य फर्मों की तुलना में अप्रत्याशित झटकों का बेहतर सामना कर सकती हैं। इस प्रभाव का अनुभवजन्य अनुमान निम्नलिखित प्रतिगमन मॉडल का अनुमान लगाकर किया गया है:

$$\Delta \log(Index_{itk}) = ESG + COVID + \beta * ESG * COVID + \sum_{i=2}^{n} Country_i + u_{itk} \ \ldots (1)$$

ईएसजी*कोविड शब्द का गुणांक β मापेगा कि कोविड-19 से पहले की अवधि की तुलना में ईएसजी सूचकांकों में प्रतिलाभ

कोविड-19 अवधि के दौरान व्यापक सूचकांकों में प्रतिलाभ से कितना भिन्न हो सकता है। β शब्द अंतर-अंतर सेट-अप में ईएसजी प्रकटीकरण के कारण हुए प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। सबस्क्रिप्ट i, t और k देश, महीने और सूचकांक (ईएसजी या व्यापक) का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुमान के परिणाम सारणी 2 में प्रस्तुत किए गए हैं।

इससे ज्ञात होता है कि ईएसजी सूचकांकों में मासिक प्रतिलाभ आम तौर पर अप्रत्याशित आघात (जैसे, कोविड) के दौरान व्यापक सूचकांकों से अधिक होता है, क्योंकि ईएसजी * कोविड गुणांक सकारात्मक है और वह पारंपरिक सांख्यिकीय स्तरों पर महत्वपूर्ण है। इस परिणाम को इस तरह देखा जा सकता है कि ईएसजी नियमों का पालन और प्रकटीकरण करने से स्टॉक प्रदर्शन बेहतर बन सकता है। संक्षिप्तता के लिए, हम देश के निश्चित डमी गुणांक को रिपोर्ट नहीं करते हैं, जिसे हमने विभिन्न देशों में अनुमानों के लिए नियंत्रित करने हेतु उपयोग में लाया था। कोविड डमी का गुणांक नकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है जो इंगित करता है कि ईएसजी लीडर्स और व्यापक सूचकांकों, दोनों पर मासिक प्रतिलाभ औसतन कोविड-19 महामारी के दौरान पूर्व-महामारी की अवधि की तुलना में कम था। ईएसजी गुणांक सकारात्मक और महत्वपूर्ण है, जो इंगित करता है कि औसतन ईएसजी सूचकांक व्यापक बाजार सूचकांक की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

सारणी 2 : कोविड-19 के दौरान ईएसजी प्रतिलाभ डिफरेंशियल्स का अंतर – अंतर अनुमान

	क्लस्टर: वर्ष	क्लस्टर: देश	क्लस्टर: वर्ष- देश
	(1)	(2)	(3)
ईएसजी	0.11*	0.11**	0.11***
	(0.048)	(0.045)	(0.037)
कोविड	-1.41***	-1.41***	-1.41***
	(0.41)	(0.42)	(0.39)
ईएसजी*कोविड	0.24***	0.24*	0.24**
	(0.048)	(0.11)	(0.12)
स्थिर	-0.12	-0.12**	-0.12
	(0.81)	(0.042)	(0.74)
प्रेक्षणों की संख्या	4392	4392	4392
रूट एमएसई	5.85	5.85	5.85

मानक त्रुटियाँ कोष्ठक में हैं।

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

(ख) बाजार मॉडल

उपर्युक्त अंतर-अंतर अनुमानों की कुछ सीमाएं हो सकती हैं। पहली बात यह कि हमारे पास कोई स्पष्ट सूचकांक नहीं है जो केवल गैर-ईएसजी लीडर्स की जानकारी दर्शाए। इसलिए, ईएसजी लीडर्स के सूचकांकों में मौजूद कुछ कंपनियां व्यापक बाजार सूचकांकों में भी मौजूद हैं। दूसरा, पहले प्रस्तुत किए गए कुछ स्टायलाइज़्ड तथ्यों में, हम दिखाते हैं कि ईएसजी लीडर्स के सूचकांकों ने व्यापक बाजार सूचकांकों से व्यापक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है और यह अंतर देशों में काफी भिन्न है, और इसलिए यह धारणा कि नियंत्रण समूह और ट्रीटमेंट समूह ने कोविड-19 महामारी से पहले सामान्य रुझानों का अनुसरण किया था, पूरी तरह संतुष्ट नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम एक दूसरी पद्धति अपनाते हैं जहां हम बाजार मॉडल का उपयोग करके परीक्षण करते हैं कि ईएसजी सूचकांक ने कोविड-19 के आघात का सामना कैसे किया (बाजार मॉडल पर विस्तृत चर्चा के लिए, मैककिनले (1997) देखें)।

महामारी का समय ईएसजी सूचकांकों के लिए प्रतिकूल आघातों के प्रति उनकी समुत्थानशीलता के लिए परीक्षा का समय था। इसका परीक्षण करने के लिए, इस उप-खंड में, हम व्यापक सूचकांकों में प्रतिफल की तुलना में ईएसजी मूल्य सूचकांकों में संचयी प्रतिफल का अनुमान लगाते हैं। वास्तव में, हम सितंबर 2010 और दिसंबर 2019 के बीच एमएससीआई व्यापक बाजार सूचकांकों के मासिक प्रतिफल पर एमएससीआई ईएसजी लीडर्स के मूल्य सूचकांकों में मासिक प्रतिफल का प्रतिगमन करते हैं। हम सभी 18 देशों के लिए ईएसजी लीडर्स और व्यापक सूचकांक दोनों के मासिक प्रतिफल के पैनल डेटा का उपयोग करते हैं। हमारा प्रतिगमन डमी चर के माध्यम से देश के निश्चित प्रभावों और वर्ष विशिष्ट अनदेखे आघात के लिए नियंत्रण होता है। देश-विषमता के लिए, हम एमएससीआई व्यापक बाजार सूचकांक और देश-विशिष्ट डमी चर में मासिक प्रतिफल के बीच की गतिविधियों को भी शामिल करते हैं। आकलन परिणाम अनुबंध में सारणी 3 में प्रस्तुत किए गए हैं। अनुमानित मॉडल निम्न रूप लेता है:

$$\Delta \log(ESG_{it}) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i D_i + \beta_1 \Delta \log(Broad_{it}) + \sum_{i=1}^{n} \beta_i \Delta \log(Broad_{it}) D_i + u_{it} \qquad ...(2)$$

जहां ESG_{it} और $Broad_{it}$ महीने t में देश i के लिए एमएससीआई ईएसजी लीडर्स सूचकांक और एमएससीआई व्यापक सूचकांक हैं। D_i देश के लिए डमी चर का प्रतिनिधित्व करता है, n देशों की संख्या है, और u_{it} प्रतिगमन के त्रुटि शब्द का प्रतिनिधित्व करता है। हौसमैन (1978) अनुसरण हौसमैन विनिर्देश परीक्षण इस तथ्य को अस्वीकार करने में विफल रहता है कि यादृच्छिक प्रभाव मॉडल से सुसंगत अनुमानक ऊपर उल्लिखित मॉडल (1) द्वारा प्रदान किए गए एक निश्चित प्रभाव अनुमानक से प्रणालीगत रूप से अलग नहीं है।

हमारे अनुमान में हमने दिसंबर 2019 तक के डेटा का उपयोग किया जो वैश्विक स्तर पर कोविड -19 महामारी के प्रकोप से पहले का अंतिम महीना है। मॉडल अनुमानों और एमएससीआई व्यापक सूचकांकों के पाए गए मूल्य का उपयोग करते हुए, हमने जनवरी और अक्टूबर, 2020 के बीच प्रत्येक देश के लिए एमएससीआई ईएसजी लीडर्स सूचकांकों में मासिक प्रतिलाभ के निश्चित किए गए मूल्य प्राप्त किए। निश्चित किए गए मूल्यों का उपयोग करके हमने अनुमानित ईएसजी लीडर्स के सूचकांक का निर्माण किया। संचयी औसत प्रतिलाभ (सीएआर) अवलोकन / वास्तविक ईएसजी लीडर्स के सूचकांक और अनुमानित ईएसजी लीडर्स के सूचकांक के मूल्यों के बीच प्रतिशत अंतर है।

हमारे अनुमान बताते हैं कि भारत के ईएसजी लीडर्स का सीएआर बाजार मॉडल (चार्ट 9) द्वारा बताए गए अनुमान की तुलना में 4 प्रतिशत अंक से अधिक था। यह आंकड़ा चीन, हांगकांग और ब्रिटेन के बाद दूसरे स्थान पर है। इससे पता चलता है कि कोविड-19 के शुरुआती आघात के बाद, ईएसजी लीडर्स ने कई अर्थव्यवस्थाओं में बाकी बाजारों से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, और भारत इस मानदंड के आधार पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है।

ईएसजी प्रकटीकरण के लिए कंपनियों को वित्तीय जोखिमों के अपने पारंपरिक मूल्यांकन से परे अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए कंपनियों को जोखिमों पर अतिरिक्त जानकारी, और कंपनियां उन्हें कैसे प्रबंधित कर रही हैं उसका खुलासा करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, अंतर-अंतर और 'बाजार मॉडल' दोनों से अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि निवेशकों के लिए अतिरिक्त जोखिमों का खुलासा करने के बावजूद, बड़ी संख्या में देशों के लिए ईएसजी लीडर्स को हुआ लाभ (चार्ट 9) अच्छा है। वास्तव में समग्र साक्ष्य बताते हैं कि ईएसजी को अपनाने और उसके उचित प्रकटीकरण को शुरू करने से बेहतर वित्तीय लाभ हो सकता है और सूचना विषमताओं में कमी आ सकती है।

चार्ट 9 : संचयी औसत प्रतिलाभ (वास्तविक घटाव पूर्वानुमानित) दिसंबर-19 और अक्तूबर- 20 के बीच

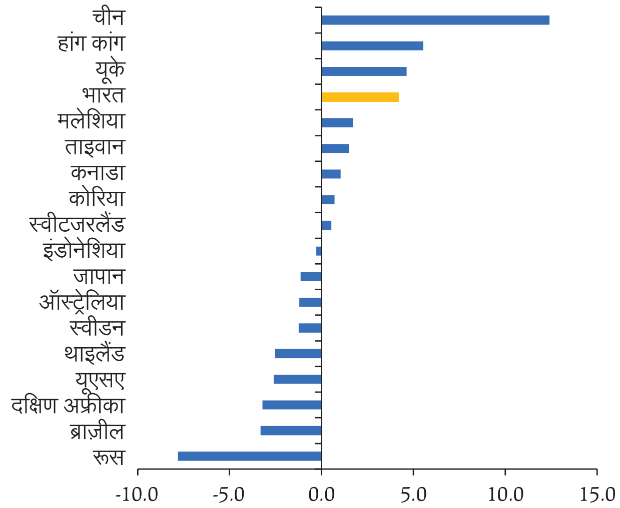

स्रोत : एमएससीआई आंकड़े और लेखकों की गणना।

V. निष्कर्ष

दुनिया भर के सरकारी प्राधिकरण ईएसजी जोखिमों पर जोर दे रहे हैं, जो दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित करने में उनके महत्व को दर्शाता है। निवेश प्रथाओं और नीति में इन सिद्धांतों को शामिल करना इस प्रथा को और अधिक स्थायी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। भारत सहित कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने पहले ही सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए धारणीयता प्रकटीकरण को एक आवश्यकता बना दिया है, और कंपनियों तथा व्यापक बाजार, दोनों के लिए ईएसजी रेटिंग

विकसित की है। इस अध्ययन में हमें देशों से संबंधित अनुभवजन्य सबूत मिले जो यह दर्शाते हैं कि ईएसजी प्रकटीकरण का संबंध बेहतर स्टॉक प्रतिलाभ और स्टॉक की कीमतों में कम अस्थिरता से है।

कोविड-19 का अप्रत्याशित आघात के रूप में प्रयोग करने पर अंतर-अंतर अनुसंधान डिजाइन के हमारे निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि ईएसजी लीडर्स के सूचकांक ने 18 देशों के नमूने के लिए व्यापक सूचकांक से बेहतर प्रदर्शन किया। बाजार मॉडल भी, एक वैकल्पिक विनिर्देश के रूप में, अधिकांश देशों के लिए अप्रत्याशित आघात के दौरान ईएसजी सूचकांकों के बेहतर प्रदर्शन का समर्थन करता है। बाजार मॉडल ढांचा ईएसजी सूचकांक प्रदर्शन के संदर्भ में देशों की रैंकिंग तय करता है, और भारत, नमूना देशों में उच्च स्थान पर है। ये निष्कर्ष मोटे तौर पर इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि ईएसजी प्रकटीकरण अल्पावधि और लंबी अवधि दोनों में बेहतर कॉर्पोरेट दृष्टिकोण से जुड़े हो सकते हैं।

इन निष्कर्षों से बड़ी संख्या में नीतिगत निहितार्थ हो सकते हैं। ईएसजी मैट्रिक्स और प्रभाव आकलन की गणना के लिए डेटा की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। सार्वजनिक नीति निगमों के लिए ईएसजी रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आने वाले वर्षों में, हरित बॉन्ड और हरित वित्त संसाधन आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। इन बॉन्डों के लिए उच्च प्रतिफल (या यहां तक कि कम ग्रीन प्रीमियम) डेटा, जानकारी और तरलता की कमी के कारण देखा जा सकता है। एक विश्वसनीय ईएसजी डेटाबेस, रेटिंग और संचार तंत्र विकसित करके इस अंतर को कम करना संभव है। यदि इस तरह के डेटाबेस को ठीक से लागू किया जाता है तो किसी विश्वसनीय ईएसजी प्रदर्शनकर्ता को कम विश्वसनीय ईएसजी प्रदर्शनकर्ता की तुलना में कम दर पर बॉन्ड बाजार से पूंजी प्राप्त हो सकती है। अत:, उभरते बाजारों में सभी औद्योगिक, सेवा गतिविधियों और बड़े अनौपचारिक क्षेत्र में ईएसजी प्रकटीकरण को धीरे-धीरे लागू किया जा सकता है।

भारत सहित उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में बैंक विषम जानकारी को कम करने और वित्तीय मध्यस्थता में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कोविड-19 के बाद के दौर में ईएसजी से संबंधित जोखिमों को बैंकों के जोखिम प्रबंधन ढांचे के साथ एकीकृत किया जा सकता है और प्रमाणित प्रकटीकरण इसके लिए पहली शर्त होगी। चूंकि प्रामाणिक डेटा प्रकटीकरण मानकीकरण, अंतःक्रियाशीलता और विश्लेषण में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा, ईएसजी जोखिमों पर निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की प्रभावी निगरानी विश्वसनीयता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस तरह के प्रकटीकरण से ऐसे डेटाबेस तैयार होंगे जो प्रभावी निगरानी, तनाव परीक्षण और अग्रगामी विश्लेषण को सक्षम करेंगे। हमने उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए एक प्रारंभिक प्रयास किया, ईएसजी लीडर्स की समुत्थानशीलता के अनुभवजन्य सबूत पाए, और नीतिगत सुझावों पर टिप्पणी तैयार की जिससे डेटा संचालित और राष्ट्रीय आवश्यकता पर निर्णय लेने की सुविधा होगी।

संदर्भ:

BIS (2021), "Sustainable finance data for central banks", Irving Fisher Committee (IFC) on Central Bank Statistics, Report No. 14, December.

Bouye, E., Klingebiel, D., Ruiz, M. (2021), "Environmental, Social, and Governance Investing: A Primer for Central Banks' Reserve Managers", World Bank, Washington, DC. © World Bank

Cai, Y., Pan, C.H., Statman, M., 2016. Why do countries matter so much in corporate social performance? J. Corp. Finan. 41, 591–609.

Chava, S., 2014. Environmental externalities and cost of capital. Manag. Sci. 60 (9), 2223–2247.

Dai, R., Liang, H., Ng, L., 2020. Socially responsible corporate customers. J. Finan. Econ. forthcoming. In press.

Gillan, S. L., Koch, A. and Starks, L. T., (2021), "Firms and social responsibility: A review of ESG and CSR research in corporate finance", Journal of Corporate Finance 66, 101889

Hausman, J. A. (1978), "Specification Tests in Econometrics", Econometrica. 46 (6):, November, 1251–1271.

Heinkel, R., Kraus, A., Zechner, J., 2001. The effect of green investment on corporate behavior. J. Financ. Quant. Anal. 36 (4), 431–449

Liang, H., Renneboog, L., 2017a. Corporate donations and shareholder value. Oxf. Rev. Econ. Policy 33 (2), 278–316.

Liang, H., Renneboog, L., 2017b. On the foundations of corporate social responsibility. J. Financ. 72 (2), 853–910.

MacKinlay, A. C. (1997), "Event Studies in Economics and Finance", *Journal of Economic Literature*, *35*(1), 13–39.

MSCI (2022), "ESG Ratings Methodology", April.

Ng, A.C., Rezaee, Z., 2015. Business sustainability performance and cost of equity capital. J. Corp. Finan. 34, 128–149.

Schiller, C., 2018. Global Supply-Chain Networks and Corporate Social Responsibility. Unpublished working paper

अनुबंध

सारणी 1 : एमएससीआई प्रमुख मुद्दे

3 स्तंभ	10 विषय	35 ईएसजी प्रमुख मुद्दे	
पर्यावरण	**जलवायु परिवर्तन**	कार्बन उत्सर्जन उत्पाद कार्बन फुटप्रिंट	वित्तपोषण पर्यावरणीय प्रभाव जलवायु परि-वर्तन भेद्यता
	प्राकृतिक पूंजी	जल संकट जैव विविधता और भूमि उपयोग	कच्चे माल के स्रोत
	प्रदूषण एवं अपशिष्ट	विषाक्त उत्सर्जन और अपशिष्ट पैकेजिंग सामग्री और अपशिष्ट	इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट
	पर्यावरणीय अवसर	क्लीन टेक में संभावना ग्रीन बिल्डिंग में संभावना	अक्षय ऊर्जा में अवसर
सामाजिक	**मानव पूंजी**	श्रम प्रबंधन स्वास्थ्य और सुरक्षा	मानव पूंजी विकास आपूर्ति शृंखला श्रम मानक
	उत्पाद देयता	उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता रासायनिक सुरक्षा उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण	गोपनीयता और डेटा सुरक्षा जिम्मेदार निवेश स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय जोखिम
	हितधारक विरोध	विवादास्पद सोर्सिंग सामुदायिक संबंध	
	सामाजिक अवसर	संचार तक पहुंच वित्त तक पहुंच	पोषण और स्वास्थ्य में, उपचार के अवसरों तक पहुंच
अभिशासन	**कॉर्पोरेट अभिशासन**	स्वामित्व और नियंत्रण बोर्ड	वेतन लेखांकन
	कॉर्पोरेट व्यवहार	बिजनेस एथिक्स टैक्स पारदर्शिता	

स्रोत: एमएससीआई ईएसजी रेटिंग पद्धति, अप्रैल 2022।

सारणी 2 : एमएससीआई सूचकांकों की व्यापक संरचना

देश/क्षेत्र	घटकों की संख्या		शीर्ष 10 घटकों का सूचकांक भार (प्रतिशत में) (दोनों सूचकांकों में सामान्य)	
	ईएसजी लीडर्स	ब्रॉड	ईएसजी लीडर्स	ब्रॉड
ब्राज़ील	28	49	60.52	24.02
चीन	163	739	68.98	36.98
भारत	40	106	72.78	39.50
इंडोनेशिया	8	23	100.00*	35.27
मलेशिया	26	35	67.92	51.38
दक्षिण अफ्रीका	27	37	65.25	53.04
दक्षिण कोरिया	42	111	65.31	18.82
ताइवान	45	86	75.90	59.39
उभरते बाजार	**469**	**1,393**	**37.94**	**20.26**
ऑस्ट्रेलिया	36	61	63.84	30.61
कनाडा	42	88	60.42	31.26
जापान	134	699	30.88	14.19
स्विट्ज़रलैंड	41	41	74.56	73.65
यूके	44	81	68.64	31.48
अमेरिका	268	626	33.89	16.87
यूरोप	**202**	**429**	**31.08**	**15.70**
विश्व	**711**	**1,540**	**23.03**	**11.52**

टिप्पणी : 31 मई 2022 तक.*: केवल 8 घटकों के लिए।

सारणी 3 : व्यापक सूचकांकों पर ईएसजी सूचकांकों में मासिक प्रतिलाभ के गुणांक

	(1)	(2)
आश्रित चर: Δlog (ईएसजी सूचकांक)		
Δlog (व्यापक सूचकांक)	0.96*** (0.016)	
व्यापक सूचकांक का देश के डमी के साथ तालमेल		
ब्राज़िल		0.97*** (0.0016)
चीन		0.93*** (0.0038)
भारत		0.89*** (0.0020)
इंडोनेशिया		1.00*** (0.0027)
दक्षिण कोरिया		0.97*** (0.0022)
मलेशिया		0.95*** (0.0029)
रूस		0.91*** (0.0015)
दक्षिण अफ्रीका		1.04*** (0.0016)
ताइवान		0.91*** (0.0021)
थाईलैंड		0.99*** (0.0017)
ऑस्ट्रेलिया		1.03*** (0.0022)
कनाडा		1.01*** (0.0022)
हांगकांग		0.75*** (0.0039)
जापान		1.00*** (0.0045)
स्वीडन		1.01*** (0.0027)
स्विट्ज़रलैंड		0.97*** (0.0046)
यूके		0.96*** (0.0038)
अमेरिका		0.97*** (0.0042)
एन	2016	2016
आर^2	0.9220	0.9262
आरएमएसई	1.54	1.51

टिप्पणी: रिग्रेशन में देश-निश्चित प्रभाव, प्रत्येक वर्ष के लिए डमी चर और 12 अलग-अलग डमी चर शामिल हैं, जो 12 महीनों में इंगित करते हैं, जो प्रतिलाभ में संभावित बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं।

* मानों के अर्थ: * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

ऋण- मांग पर बैंकरों के रुख - महामारी के बाद सुधार*

हरिद्वार यादव और सुप्रिया मजूमदार द्वारा

बैंक ऋण सर्वेक्षण, प्रमुख क्षेत्रों में निकट अवधि में ऋण की मांग, ऋण की शर्तों और उनके दृष्टिकोण पर बैंकों के रुख को बयां करता है जो वास्तविक ऋण वृद्धि के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करता है। यह आलेख महामारी के दौरान भारत में बैंकरों की भावनाओं के विकास का अध्ययन करता है। भले ही महामारी के दौरान, विशेष रूप से पहली और दूसरी लहर (क्रमशः अप्रैल-जून 2020 और अप्रैल-जून 2021) के समय, ऋण की शर्तों पर बैंकरों की भावना काफी प्रभावित हुई थी, इसके बाद इसमें तेजी से सुधार हुआ। विनिर्माण क्षेत्र में ऋण वृद्धि और उधारकर्ताओं की धारणाओं के साथ उधारदाताओं की भावना भी महत्वपूर्ण रूप से साथ-साथ चलती है।

भूमिका

बैंकों के प्रभुत्व वाली भारत जैसी अर्थव्यवस्था में नीति निर्माण के लिए ऋण मांग दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण इनपुट है। बैंक ऋण, अन्य बातों के साथ-साथ समष्टि-आर्थिक दृष्टिकोण, चलनिधि की स्थिति, उधारकर्ताओं की साख, संबंधित क्षेत्र से जुड़ी अनिश्चितता, जोखिम प्रीमियम सहित अपेक्षित रिटर्न, पोर्टफोलियो मिश्रण और जोखिम प्रबंधन क्षमताओं जैसे कई कारकों पर निर्भर होता है। इनमें से कई प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं और इसलिए समर्पित बैंक ऋण सर्वेक्षण (बीएलएस)[1] के माध्यम से एकत्र की गई ऋण मांग तथा नियमों और शर्तों पर बैंकरों की धारणा, आमतौर पर बैंक ऋण पर जानकारी का पूरक होती है। बीएलएस धनात्मक रूप से ऋण बाजार की स्थितियों पर ऋणदाताओं का दृष्टिकोण प्रदान करता है, विशेष रूप से ऋण की मांग पर बदलती आर्थिक या वित्तीय स्थितियों के प्रभाव और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बैंकों द्वारा निर्धारित ऋण के नियम और शर्तों पर।

कोविड-19 संकट के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने फर्मों और हाउसहोल्ड को समर्थन देने के लिए कई तरह के ऋण उपाय/ योजनाएं शुरू कीं। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने कई उपायों की घोषणा की, जैसे नीतिगत दर और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कमी, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) उधार में सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करना, नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं, राज्यों की उधार सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने जैसे कई अन्य उपाय किए हैं। इन नीतिगत उपायों ने अर्थव्यवस्था को रोजगार और खपत में तेजी से बदलाव लाने में मदद की, जिससे ऋण मांग में भी वृद्धि हुई।

नीति निर्माण में बैंक ऋण सर्वेक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनका उपयोग अधिकांश केंद्रीय बैंकों द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों की ऋण मांग एवं नियमों और शर्तों पर ऐसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान रुख का पता लगाने के लिए किया गया था, जब विश्वसनीय डेटा में कमी थी। सर्वेक्षण ने महामारी के प्रभाव के मापन के साथ-साथ बैंकों द्वारा अपेक्षित सुधार प्रक्रिया के समय और गति के मूल्यांकन की सुविधा प्रदान की। इस आलेख में, हम देखते हैं कि महामारी के दौरान एक-के-बाद-एक लहरों में बैंकरों की भावना कैसे विकसित हुई।

शेष आलेख को निम्नलिखित खंडों में संरचित किया गया है। खंड II सर्वेक्षण का नमूना ढांचा, प्रश्नावली और कार्यप्रणाली प्रस्तुत करता है। खंड III 2019-22 के दौरान सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष प्रदान करता है। खंड IV आधिकारिक आंकड़ों और अन्य सर्वेक्षणों के साथ इसके संबंध पर चर्चा करता है और खंड V कोविड के बाद की सुधार प्रक्रिया पर बैंकों की धारणाओं को प्रस्तुत करता है। खंड VI आलेख का समापन करता है।

^ लेखक सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग से हैं।

* इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं। सर्वेक्षण के आंकड़ों का नवीनतम चरण 8 फरवरी 2023 को बैंक की वेबसाइट (https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=21736) पर जारी किया गया था। पिछला आलेख, बैंक ऋण सर्वेक्षण पर पहला आलेख था जो इसकी पृष्ठभूमि, अंतरराष्ट्रीय अनुभव समय शृंखला डेटा और पद्धतिगत पहलुओं पर जानकारी प्रदान करते हुए आरबीआई बुलेटिन के दिसंबर 2020 के अंक (https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?id=19963) में प्रकाशित किया गया था।

1 इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ ऋण अधिकारियों के सर्वेक्षण या ऋण स्थिति सर्वेक्षण के रूप में भी जाना जाता है।

II. नमूना फ्रेम, प्रश्नावली और कार्य-पद्धति

रिज़र्व बैंक, दुनिया भर के अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए इसी तरह के सर्वेक्षणों के अनुरूप व्यापक रूप से बैंक ऋण सर्वेक्षण आयोजित करता है। यह सर्वेक्षण भविष्य की ऋण मांग पर वरिष्ठ ऋण अधिकारियों की प्रत्याशा के साथ-साथ इसके नियमों और शर्तों में समायोजन के अलावा, मौजूदा ऋण बाजार की स्थितियों पर प्रतिक्रिया भी मांगता है। इसमें शीर्ष 30 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का एक पैनल शामिल है, जिनका सभी एससीबी के कुल बकाया ऋण में 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया ऋण के आधार पर बैंकिंग कारोबार/ विलय में फैक्टरिंग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए यह पैनल अद्यतन किया जाता है। लक्षित उत्तरदाता विभिन्न ऋण विभागों के प्रमुख या बैंकों में विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ ऋण अधिकारी हैं। जिस तिमाही के लिए मूल्यांकन किया जाना है, उस तिमाही के दौरान बैंकों को सर्वेक्षण प्रश्नावली ई-मेल की जाती है और आम तौर पर सर्वेक्षण का जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है। बैंक स्वेच्छा से सर्वेक्षण में भाग लेते हैं और प्रतिक्रिया की दर आम तौर पर 90 प्रतिशत से अधिक होती है।

सर्वेक्षण दो तिमाहियों के लिए बैंकों के दृष्टिकोण को ट्रैक करता है - ऋण मांग का मूल्यांकन और मौजूदा तिमाही के लिए नियम और शर्तें जिसमें पिछली तिमाही की तुलना में सर्वेक्षण किया जाता है एवं वर्तमान तिमाही की तुलना में आगामी तिमाही के लिए अपेक्षाएं। प्रश्नावली में व्यापक आर्थिक क्षेत्रों, यथा कृषि, खनन और उत्खनन, विनिर्माण, सेवा, इंफ्रास्ट्रक्चर और खुदरा ऋणों के साथ-साथ "सभी क्षेत्रों" को कवर करने वाले 5-बिंदु पैमाने पर उत्तर के साथ गुणात्मक प्रश्न शामिल होते हैं। ऋण की मांग के मामले में, वर्तमान तिमाही में परिवर्तन और अगली तिमाही के लिए 5-बिंदु पैमाने (परिमाण को मापने का तरीका) (यथा पर्याप्त वृद्धि, मध्यम वृद्धि, समान (अपरिवर्तित), मध्यम कमी और पर्याप्त गिरावट) की अपेक्षाओं पर प्रतिक्रियाएं मांगी जाती हैं। इसी तरह, ऋण नियमों और शर्तों पर प्रतिक्रियाओं को भी 5-बिंदु पैमाने पर चिह्नित किया जाता है (यथा काफी सुलभता, थोड़ी सुलभता, समान (अपरिवर्तित), थोड़ी सख्ती, काफी सख्ती)। ऋण नियम और शर्तें एक स्वीकृत ऋण के लिए विशिष्ट होती हैं, जो कि ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच सहमत शर्तें होती हैं और ऋण अनुबंध में निर्धारित होती हैं। इसमें कीमत और कीमत से इतर, दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है और इसमें प्रासंगिक संदर्भ/ ब्याज दर, ऋण का आकार और अन्य ब्याजेतर प्रभार (जैसे, शुल्क, संपार्श्विक या गारंटी की आवश्यकता, ऋण प्रसंविदा, सहमत ऋण परिपक्वता) पर सहमत स्प्रेड शामिल है। ऋण शर्तें उधारकर्ता की विशेषताओं पर सशर्त हैं और बैंक के ऋण अनुमोदन मानदंड के साथ बदल भी सकती हैं।

सर्वेक्षण के माध्यम से 5-बिंदु पैमाने पर एकत्र की गई प्रतिक्रियाओं को 'निवल प्रतिक्रिया (नेट रिस्पांस)' (एनआर)[2] नामक एक एकल संख्या में संकलित किया जाता है, जिसे बैलेंस स्टेटिस्टिक (बीएस) स्कोर या नेट बैलेंस के रूप में भी जाना जाता है, जो धनात्मक और ऋणात्मक प्रतिक्रियाओं के अनुपात के बीच का भारित अंतर है। एनआर -100 से +100 तक के मान ले सकता है: एनआर के धनात्मक मान मापदंड/ क्षेत्र के लिए आशावाद का संकेत देते हैं (उदाहरण के लिए, बैंकों को ऋण की मांग में वृद्धि या ऋण के नियम और शर्तों में ढील की उम्मीद है), जबकि शून्य से नीचे का मान निराशावाद को दर्शाता है (उदाहरण के लिए, निम्न ऋण मांग या ऋण के नियमों और शर्तों को सख्त करने की आशंका)। इस प्रकार, निवल प्रतिक्रिया गुणात्मक प्रतिक्रियाओं को मापने में मदद करती है जो रूखों में परिवर्तन की दिशा दर्शाती है; हालाँकि, यह परिवर्तन के परिमाण का कड़ाई से अनुमान नहीं लगाता है।

III. प्रमुख सर्वेक्षण निष्कर्ष

2017 में शुरू हुए सर्वेक्षण ने फरवरी 2023 में अपने हालिया डेटा जारी करने के साथ अपना 22वां चरण पूरा किया। कोविड-19 की दो लहरों के दौरान, ऋण की मांग और उसके नियमों और शर्तों पर बैंकरों की धारणाओं के रुझान नीचे दिए गए हैं।

---

[2] निवल प्रतिक्रिया (NR) = {1*P2 + 0.5*P1 + 0*P0 + (-0.5)*P(-1) + (-1)*P(-2)}, जहां, P2 = का प्रतिशत बैंकों ने ऋण की मांग को 'पर्याप्त वृद्धि' या ऋण के नियमों और शर्तों को 'काफी सहजता' के रूप में रिपोर्ट किया, P1 = बैंकों का प्रतिशत 'मध्यम वृद्धि' के रूप में ऋण की मांग या 'कुछ हद तक आसान' के रूप में ऋण की शर्तें, P0 = का प्रतिशत ऋण की मांग या ऋण के नियमों और शर्तों को 'समान/ कोई बदलाव नहीं' रहने की सूचना देने वाले बैंक, P(-1) = ऋण की मांग को 'मध्यम कमी' के रूप में रिपोर्ट करने वाले बैंकों का प्रतिशत या ऋण के नियम और शर्तों को 'कुछ हद तक कड़ा' और P(- 2) = ऋण मांग को 'पर्याप्त कमी' या ऋण नियमों और शर्तों को 'काफी सख्त' के रूप में रिपोर्ट करने वाले बैंकों का प्रतिशत।

III.1 ऋण मांग की शर्तें

(i) कोविड-19 की पहली लहर

कोविड-19 की पहली लहर से पहले 2019-20 की चतुर्थ तिमाही (जनवरी-मार्च 2020) के दौरान, बैंकों ने सभी क्षेत्रों के लिए ऋण मांग पर कम आशावाद का संकेत दिया था (चार्ट 1)। जनवरी-मार्च 2020 के लिए सामान्य सर्वेक्षण भारत में 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लागू होने से बहुत पहले किया गया था और इस तरह, बैंकों ने अर्थव्यवस्था में संकुचन का पहले से अनुमान नहीं लगाया था क्योंकि वे बाद में देखी गई महामारी की गंभीर और अप्रत्याशित प्रकृति के पूर्ण प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सके।

चार्ट 1: सभी क्षेत्रों के लिए ऋण की मांग

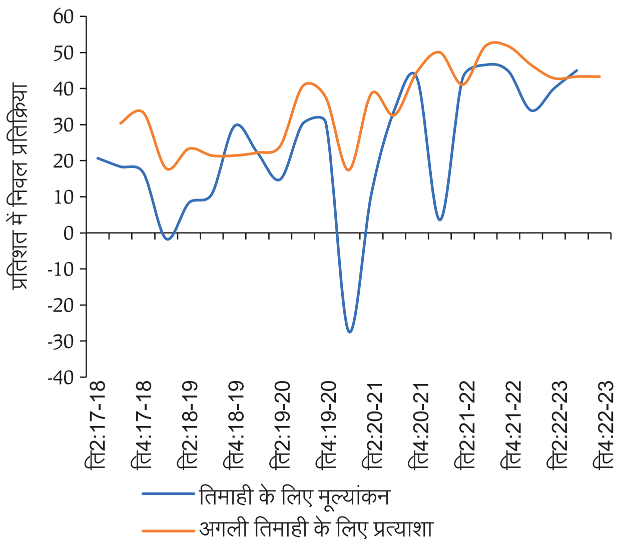

स्रोत: आरबीआई।

2020-21 (अप्रैल-जून 2020) की पहली तिमाही के दौरान कोविड-19 की पहली लहर के परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में ऋण की मांग में काफी कमी आई थी, जिससे आकलन के मामले में भारतीय बैंकों के रुख में भारी गिरावट आई थी। मूल्यांकन की गई तिमाही में सभी क्षेत्रों के लिए एनआर धनात्मक थे (चार्ट 2, अनुबंध चार्ट ए 1-ए 6)। हालांकि, अपेक्षाओं के संदर्भ में यह काफी हद तक अप्रभावित रहा। 2020-21 की दूसरी तिमाही में बैंकरों ने सभी क्षेत्रों में ऋण मांग की त्वरित बहाली का आकलन किया। खनन और उत्खनन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम आशावाद दर्ज किया गया, जबकि व्यक्तिगत ऋण खंड में अधिकतम बहाली देखी गई, जिसमें पहले सबसे तेज गिरावट देखी गई थी। बैंकों ने 2020-21 की तीसरी तिमाही के दौरान ऋण मांग में निरंतर सुधार की भी उम्मीद की। इस प्रकार, जबकि आकलन ने महामारी की पहली लहर के

चार्ट 2: कोविड-19 की पहली लहर के दौरान क्षेत्र-वार ऋण मांग

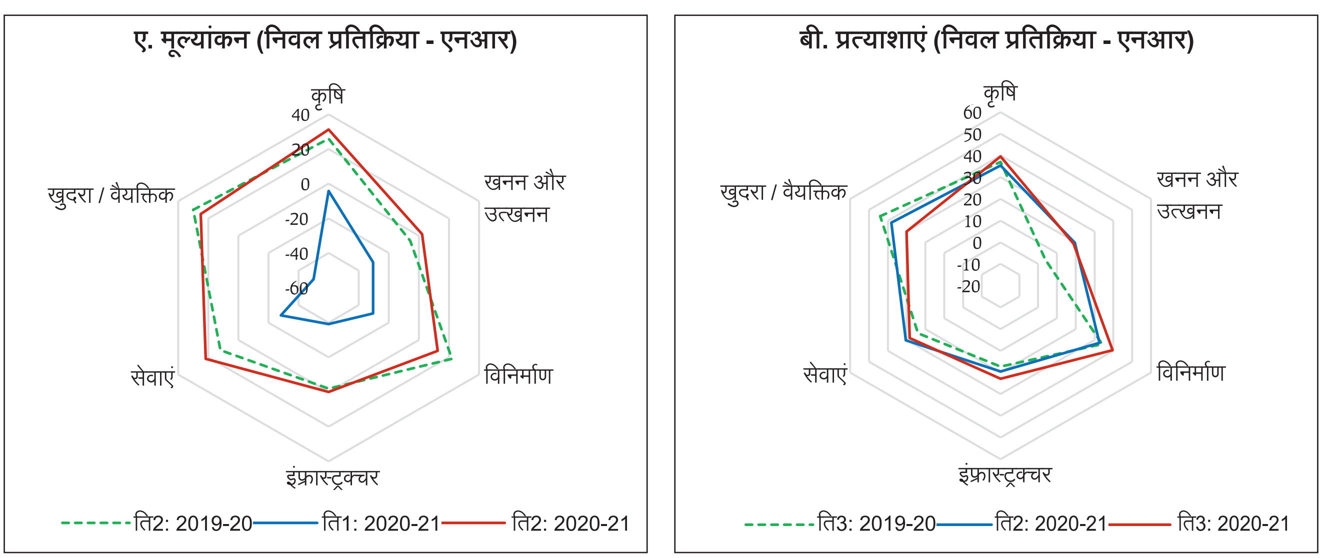

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट 3: कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान क्षेत्र-वार ऋण मांग

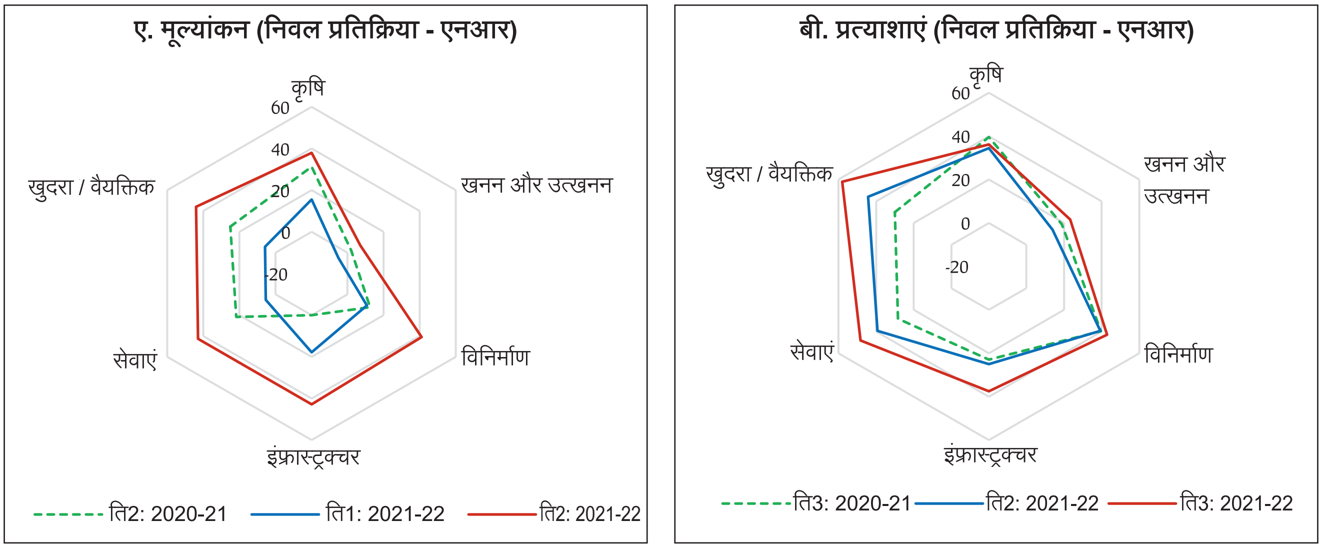

स्रोत: आरबीआई।

दौरान समग्र आर्थिक स्थितियों को प्रतिबिंबित किया, ऋण मांग की अपेक्षाएं अप्रभावित रहीं।

(ii) कोविड-19 की दूसरी लहर

2021-22 (अप्रैल-जून 2021) की पहली तिमाही में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान, सभी क्षेत्रों में ऋण मांग पर बैंकों के रुख में काफी गिरावट आई (चार्ट 3, अनुबंध चार्ट ए 1-ए 6)। हालांकि, महामारी की पहली लहर की तुलना में गिरावट की सीमा बहुत कम थी क्योंकि खनन और उत्खनन को छोड़कर सभी क्षेत्रों के लिए एनआर धनात्मक बने हुए थे। पहली लहर की तरह, अगली तिमाही (2021-22 की दूसरी तिमाही) में सभी क्षेत्रों में ऋण मांग पर बैंकरों के आकलन में तेजी से सुधार हुआ। तिमाही में वैयक्तिक ऋण खंड और सेवा क्षेत्र में तीव्र सुधार देखने को मिला। ऋण मांग पर बैंकरों की उम्मीदें 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए भी उत्साहित थीं और वास्तव में अधिकांश क्षेत्रों के लिए पिछली तिमाहियों की तुलना में अधिक थीं।

III.2 ऋण नियम और शर्तें

कोविड-19 महामारी के कारण महामारी की दोनों लहरों के दौरान विशेष रूप से मूल्यांकन के लिए भारतीय बैंकों के बीच ऋण नियमों और शर्तों के बारे में रुख में काफी गिरावट आई। हालांकि, प्रत्याशाएं काफी हद तक अप्रभावित रहीं (चार्ट 4)।

(i) कोविड-19 की पहली लहर

2020-21 की पहली तिमाही में कोविड-19 की पहली लहर में कृषि, खुदरा ऋण और विनिर्माण क्षेत्र के लिए नियम और शर्तों पर एनआर सकारात्मक थे, जो इन क्षेत्रों में आसान

चार्ट 4: 'सभी क्षेत्रों' के लिए ऋण के नियम और शर्तें

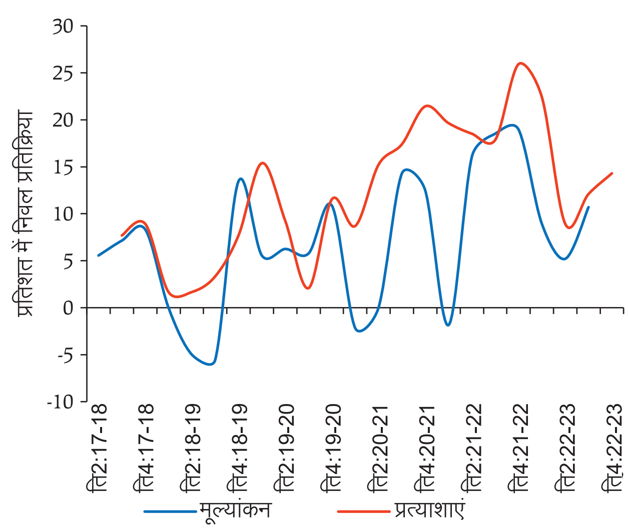

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट 5: कोविड-19 की पहली लहर के दौरान क्षेत्र-वार ऋण के नियम और शर्तें

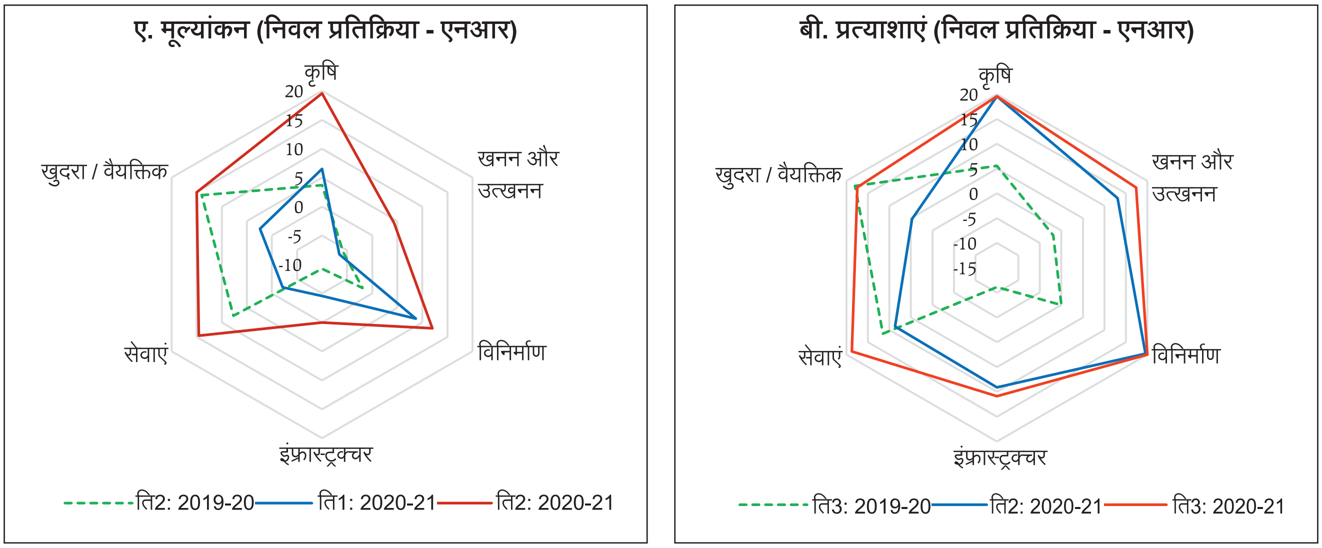

स्रोत: आरबीआई।

ऋण नियमों और शर्तों को दर्शाता है। हालांकि, अधिक बैंकों ने इंफ्रास्ट्रक्चर और खनन और उत्खनन क्षेत्र के लिए, ऋण शर्तों में कुछ सख्ती की सूचना दी। सभी क्षेत्रों के लिए ऋण नियमों और शर्तों पर रुख ने 2020-21 की दूसरी तिमाही में नरमी का संकेत दिया। बैंकरों ने 2020-21 की तीसरी तिमाही के दौरान ऋण के नियमों और शर्तों में और ढील की उम्मीद की (चार्ट 5)।

(ii) कोविड-19 की दूसरी लहर

भले ही दूसरी लहर के दौरान ऋण शर्तों पर बैंकरों के रुख में गिरावट आई, जैसा कि सभी ऋण क्षेत्रों के लिए एनआर के मूल्य में गिरावट में परिलक्षित होता है, लेकिन महामारी की दूसरी लहर के दौरान यह सकारात्मक रहा, जो पहली लहर की तुलना में आसान नियम और शर्तों का संकेत देता है (चार्ट 6)। इसके अलावा, सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए अगली

चार्ट 6: कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान क्षेत्र-वार ऋण के नियम और शर्तें

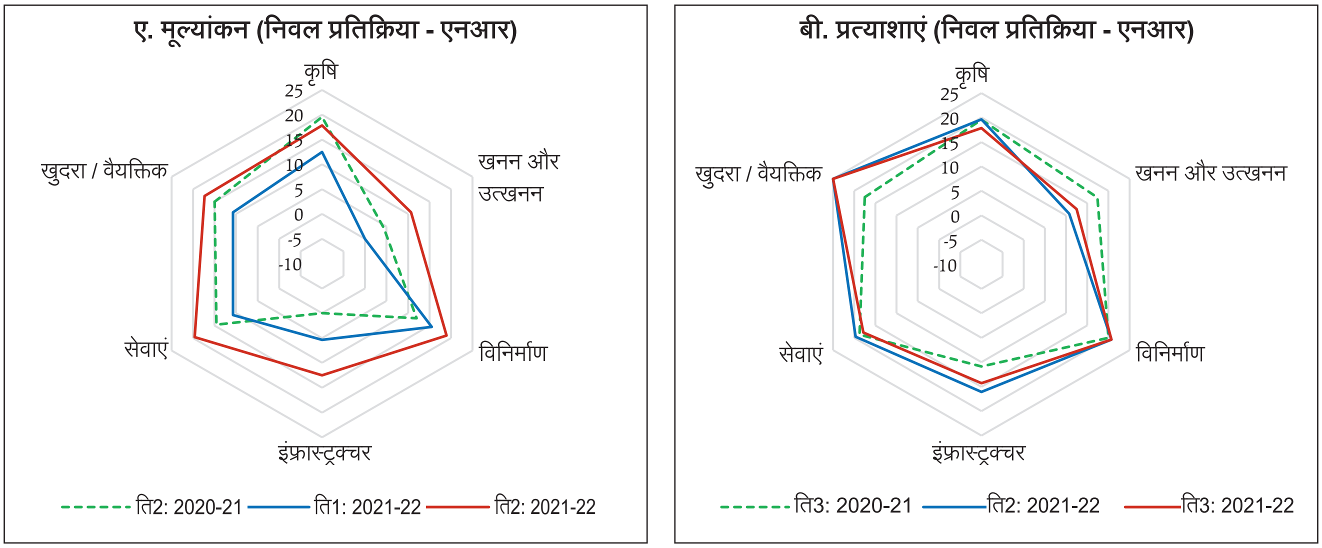

स्रोत: आरबीआई।

तिमाही 2021-22 की दूसरी तिमाही में बैंकों द्वारा ऋण नियमों और शर्तों संबंधी रुख में कमी दर्ज की गई।

IV. आधिकारिक सांख्यिकी और अन्य सर्वेक्षणों के साथ बीएलएस का संबंध

यह खंड वास्तविक ऋण के साथ-साथ अन्य सर्वेक्षणों के रुझानों के साथ सर्वेक्षण परिणामों की तुलना करता है ताकि यह समझा जा सके कि क्या इन सर्वेक्षणों से उपलब्ध जानकारी नीति निर्माताओं को प्रमुख जानकारी प्रदान कर सकती है।

IV.1 बैंक ऋण सर्वेक्षण और वास्तविक बैंक ऋण

शुद्ध प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में ऋण मांग में परिवर्तन का बैंकरों का आकलन एससीबी द्वारा दिए गए वास्तविक ऋण में वृद्धि को बारीकी से ट्रैक करता है। हालांकि, मूल्यांकन की तुलना में, उनकी प्रत्याशाएं आम तौर पर अधिक उत्साहित रही हैं (चार्ट 7)। मूल्यांकन के लिए एनआर और वास्तविक ऋण वृद्धि के बीच सहसंबंध गुणांक 0.49 है, जबकि यह प्रत्याशाओं और वास्तविक ऋण वृद्धि के लिए एनआर के बीच 0.23 है।

IV.2 विनिर्माण क्षेत्र - उधारकर्ताओं और उधारदाताओं द्वारा ऋण शर्तों का आकलन

बीएलएस ऋण की मांग और उसके नियमों और शर्तों के बारे में ऋणदाता के दृष्टिकोण (आपूर्ति पक्ष के दृष्टिकोण) को ग्रहण करता है, जबकि आरबीआई का त्रैमासिक औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण (आईओएस) [3] बैंकों और अन्य घरेलू स्रोतों से वित्त की उपलब्धता पर निर्माताओं के मांग पक्ष के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है। आईओएस 3-पॉइंट स्केल (सुधार / खराब / कोई बदलाव नहीं) पर वित्त की उपलब्धता पर मूल्यांकन और अपेक्षाओं को एकत्र करता है और इसके परिणाम निवल प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। बीएलएस में बैंकरों द्वारा मूल्यांकन किए गए विनिर्माण क्षेत्र से ऋण मांग और आईओएस में निर्माता द्वारा मूल्यांकन किए गए बैंकों और अन्य स्रोतों से वित्त की उपलब्धता अध्ययन अवधि में समान दिशात्मक परिवर्तनों का संकेत देती है (चार्ट 8)।

चार्ट 7: 'सभी क्षेत्रों' के लिए बीएलएस ऋण की मांग और वास्तविक ऋण वृद्धि

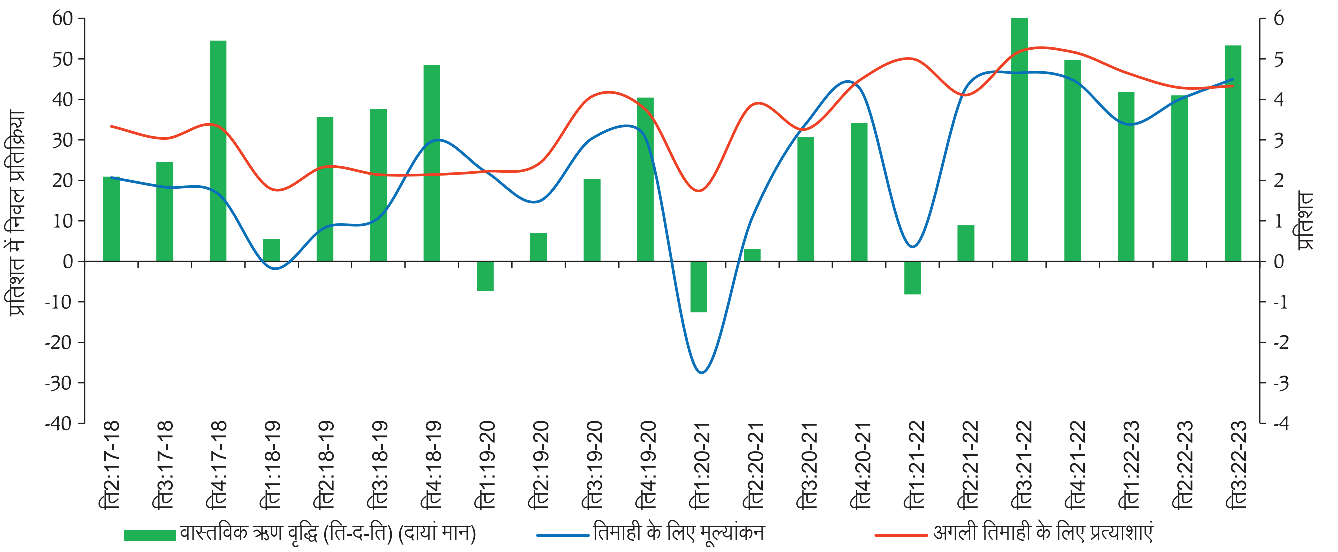

स्रोत: आरबीआई।

[3] आईओएस डेटा, आरबीआई की वेबसाइट (https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=21734) पर तिमाही आधार पर जारी किए जाते हैं, नवीनतम डेटा 8 फरवरी 2023 को जारी किया गया था)।

[4] आईओएस में विनिर्माताओं के बीच प्रचारित मापदंड हैं: 'वित्त की उपलब्धता (बैंकों और अन्य घरेलू स्रोतों यथा, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजार आदि)', 'वित्त की उपलब्धता (आंतरिक संसाधनों से)' और 'वित्त की उपलब्धता (विदेशों से)'।

चार्ट 8: बीएलएस-विनिर्माण क्षेत्र की ऋण मांग और आईओएस - वित्त की उपलब्धता

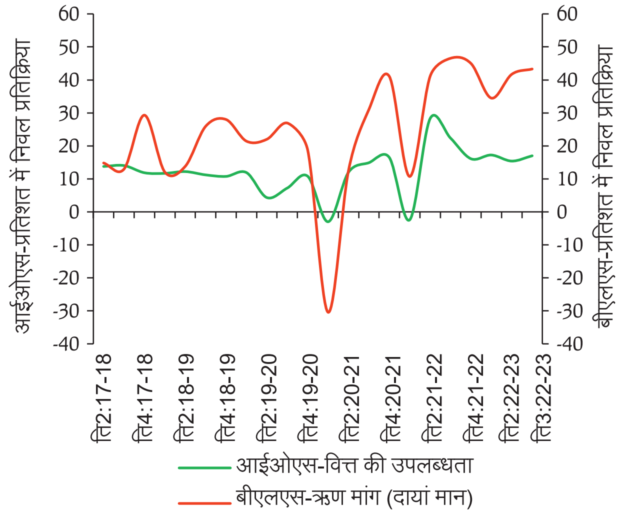

स्रोत: आरबीआई।

विनिर्माण क्षेत्र के लिए ऋण नियमों और शर्तों का बैंकरों का आकलन आम तौर पर वित्त की उपलब्धता पर निर्माताओं के रुख के अनुरूप होता है (चार्ट 9)। इन दोनों सर्वेक्षणों से उत्पन्न निवल प्रतिक्रिया के सह-संचलन से संकेत मिलता है कि ऋण अधिकारियों का आकलन काफी हद तक उद्योग की प्रत्याशाओं के अनुरूप है।

चार्ट 9: बीएलएस-विनिर्माण क्षेत्र के नियम और शर्तें एवं आईओएस - वित्त की उपलब्धता

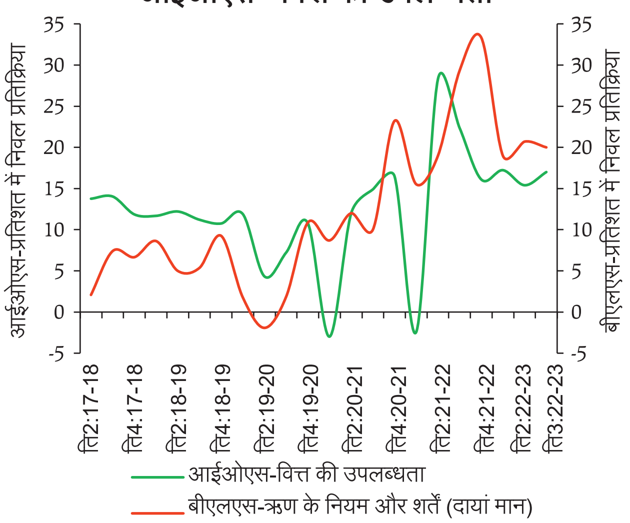

स्रोत: आरबीआई।

V. कोविड-19 के बाद के सुधार के संबंध में बैंकों की धारणा

V.1 देश व्यापी अनुभव[5]

चूंकि बैंक ऋण सर्वेक्षण मौद्रिक नीति निर्णयों का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने इन सर्वेक्षणों का उपयोग कोविड-19 प्रभाव पर बैंकों की भावनाओं का पता लगाने के लिए उपकरणों के रूप में किया। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व ने सर्वेक्षण के अप्रैल 2020 के दौर में बताया - "कई बैंकों ने मानकीकृत सर्वेक्षण प्रश्नों का उत्तर देने के अलावा कोरोना वायरस (कोविड -19) महामारी के बारे में लिखित टिप्पणियां भी प्रदान कीं। इन टिप्पणियों में, बैंकों ने बताया कि पहली तिमाही के लिए रिपोर्ट किए गए ऋण श्रेणियों में मानकों और मांग में बदलाव मार्च के अंत में हुआ क्योंकि कोविड-19 के तेजी से वैश्विक प्रसार के बारे में खबरें सामने आने पर आर्थिक दृष्टिकोण बदल गया। यूरो क्षेत्र के बैंक ऋण सर्वेक्षण के नतीजों से पता चला है कि 2020-21 और 2021-22 की पहली तिमाहियों में ऋण मांग और ऋण नियम और शर्तों पर रुख गर्त में पहुंच गए, जो भारत में कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के समान है। बड़े जापानी बैंकों में बैंक ऋण प्रथाओं पर बैंक ऑफ जापान के वरिष्ठ ऋण अधिकारी राय सर्वेक्षण ने यह भी दर्शाया कि कोविड-19 महामारी की विभिन्न लहरों के दौरान बैंकों के रुख निम्नतम स्तर पर पहुंच गए। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने क्रेडिट कंडीशन सर्वे में दर्शाया कि सुरक्षित और असुरक्षित ऋण मांग पर बैंकों की धारणा अगली तिमाहियों में पुनर्जीवित होने से पहले 2020 की दूसरी तिमाही के दौरान गर्त में पहुंच गई।

V.2 भारतीय संदर्भ

2020-21 की पहली तिमाही के सर्वेक्षण चरण के बाद से, ऋण पर बैंकों के दृष्टिकोण और बाद की दो और तिमाहियों के लिए इसके नियमों और शर्तों का आकलन करने के लिए एक अलग ब्लॉक पेश किया गया था। इस प्रकार, प्रत्याशाओं पर डेटा कुल तीन तिमाहियों के लिए एकत्र किया गया था जो अनिश्चित समय के दौरान नीतिगत निर्णयों के लिए बेहद उपयोगी बन गया। इसके अलावा, लगातार सर्वेक्षण चरणों में उसी तिमाही के लिए प्रत्याशाओं को भी हासिल किया गया था, जिससे नीति निर्माताओं

5 केंद्रीय बैंकों की संबंधित वेबसाइटें (संदर्भों में दी गई हैं)

को गतिशील रूप से विकसित महामारी और आर्थिक परिदृश्य के जवाब में प्रत्याशाओं में बदलाव का निरीक्षण करने में मदद मिली। इस अतिरिक्त ब्लॉक का उपयोग करते हुए, हम ऋण मांग और ऋण की शर्तों पर उम्मीदों को देखते हैं और देखते हैं कि कोविड रिकवरी के बाद उन्हें कैसे आकार दिया गया।

(i) ऋण मांग की स्थिति

भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेजों और उपायों ने महामारी की पहली दो लहरों के दौरान ऋण मांग पर बैंकों के रुख में सुधार को बढ़ावा दिया। हालांकि पहली लहर के बाद रुख मजबूत होने लगे, लेकिन दूसरी लहर के कारण ये फिर से कमजोर हो गए, हालांकि वे जल्दी से वापस आ गए (चार्ट 10)[6]। बैंकों के रुख एससीबी की वास्तविक ऋण वृद्धि के अनुरूप भी देखे गए। यह देखा गया है कि बैंकर दो और तीन तिमाही आगे की प्रत्याशाओं के संदर्भ में अधिक आशावादी होते हैं और एक तिमाही आगे की प्रत्याशाएं वास्तविक ऋण वृद्धि का अधिक बारीकी से पता लगाने में सक्षम थीं।

हाल की अवधि में हम देखते हैं कि बैंकर आने वाली तिमाहियों में सभी मुख्य क्षेत्रों में ऋण मांग के बारे में अत्यधिक आशावादी हैं, अर्थात्, 2022-23 की चौथी तिमाही से 2023-24 की दूसरी तिमाही जैसा कि उनके उच्च एनआर (अनुबंध चार्ट ए1-ए6) में परिलक्षित होता है।

(ii) ऋण नियम और शर्तें

ऋण नियमों और शर्तों के संदर्भ में, पहली लहर के दौरान गिरावट के बाद, प्रत्याशाओं ने ऋण नियमों और शर्तों को आसान बनाने का संकेत दिया। हालांकि, दूसरी लहर के कारण रुख फिर से नीचे आ गया, यद्यपि इसमें त्वरित सुधार हुआ। हाल की अवधि के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि बैंकर आगे चलकर ऋण के लिए आसान नियम और शर्तों की उम्मीद कर रहे हैं (चार्ट 11)।

चार्ट 10: विभिन्न चरणों में ऋण मांग का मूल्यांकन और प्रत्याशाएं

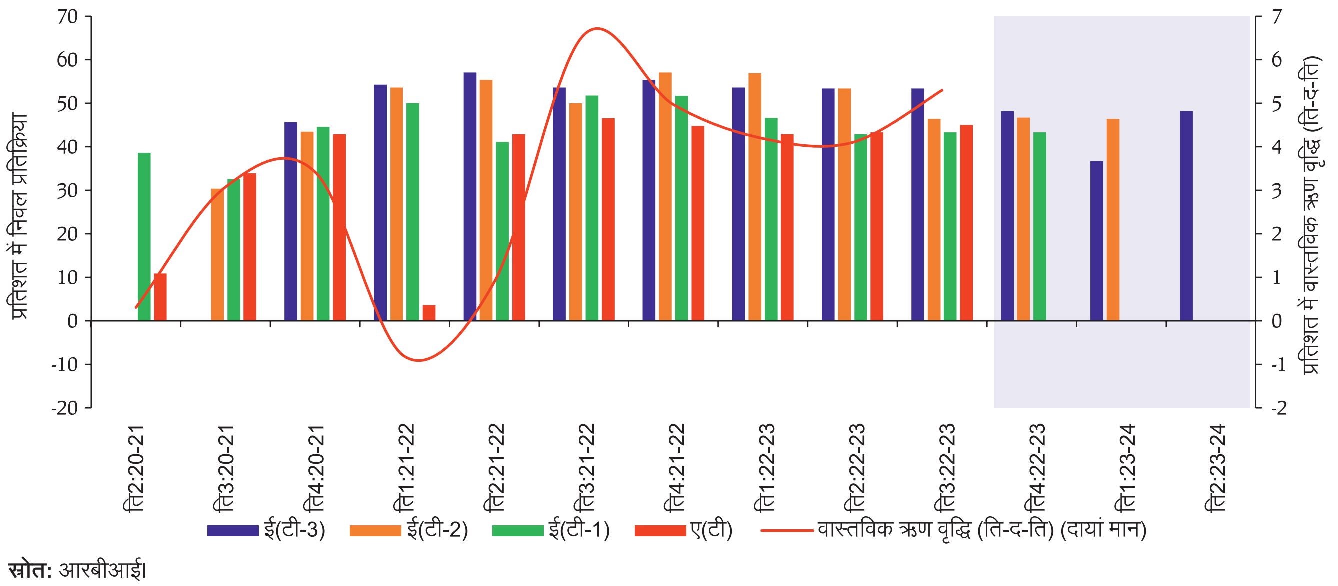

स्रोत: आरबीआई।

[6] ए(टी): मौजूदा तिमाही (टी), ई(टी-1)/ई(टी-2)/ई(टी-3) के लिए आकलन; तिमाही (टी) के लिए प्रत्याशाएं एक (-1) / दो (-2)/ तीन (-3) तिमाही पहले का पता लगाती है।

चार्ट 11: विभिन्न चरणों में नियम और शर्तों पर मूल्यांकन और प्रत्याशाएं

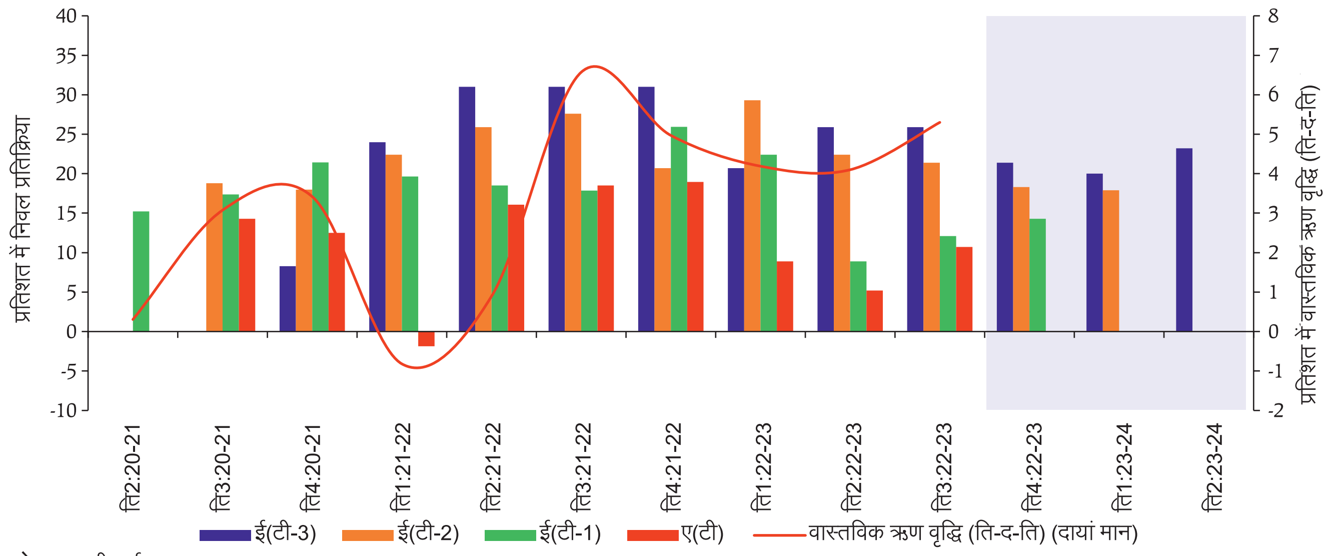

स्रोत: आरबीआई।

VI. निष्कर्ष

यह आलेख बैंक ऋण सर्वेक्षण के लगातार चरणों के परिणामों का अवलोकन करता है ताकि यह समझा जा सके कि महामारी की अवधि के दौरान विभिन्न आघातों पर रूखों ने कैसे प्रतिक्रिया दी। हम पाते हैं कि पहली और दूसरी लहर के दौरान उधार देने की स्थितियों के मूल्यांकन ने महामारी के प्रति निराशावादी तरीके से प्रतिक्रिया की। हालांकि, एक तिमाही के भीतर ऋण स्थितियों के मूल्यांकन में काफी सुधार हुआ है, जो दर्शाता है कि अनिश्चितता के दौरान नीतिगत उपाय विश्वास पैदा करने में प्रभावी थे। क्षेत्रों में, महामारी की दोनों लहरों के दौरान खुदरा/ वैयक्तिक ऋण पर दृष्टिकोण सबसे गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था, लेकिन उन्होंने मजबूत पकड़ दिखाते हुए तेजी से सुधार दर्ज किया।

बैंक ऋण सर्वेक्षण (बैंक लेंडिंग सर्वे) की जानकारी उचित सटीकता के साथ वास्तविक ऋण वृद्धि को ट्रैक करती है और बड़े बदलावों का पता लगाती है। इसलिए, यह नीति निर्माताओं के लिए ऋण बाजार में अंतर्निहित प्रवृत्तियों को मापने के लिए एक उपयोगी जरिया हो सकता है, क्योंकि सर्वेक्षण के परिणाम अग्रिम रूप से लगभग एक तिमाही पहले उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही, बीएलएस में उधारदाताओं की धारणा व्यापक रूप से औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण में उधारकर्ताओं की धारणाओं के साथ पुष्टि करती है, जो इंगित करती है कि आपूर्तिकर्ताओं का मूल्यांकन - ऋण शर्तों के मांग पक्ष के साथ समन्वयित है, जो फिर से इसकी उपयोगिता साबित करता है।

भविष्य में बैंकर आगामी तिमाहियों में ऋण मांग को लेकर सकारात्मक हैं। ऋण के लिए नियम और शर्तों पर प्रत्याशाएं भी क्रमिक तिमाहियों में सहजता की ओर इशारा करती हैं।

संदर्भ

Bank of England (2022), "Bank of England Credit Conditions Survey", Quarterly Bulletin, Q1. https://www.bankofengland.co.uk/credit-conditions-survey/2022/2022-q1

Bank of Japan, "Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices at Large Japanese Banks". https://www.boj.or.jp/en/statistics/dl/loan/loos/index.htm/#p01.

Berg, Jesper., Van Rixtel, Adrian A.R.J.M., Ferrando, Annalisa., de Bondt, Gabe and Scopel, Silvia., (2005), "The Bank Lending Survey for the Euro Area". ECB Occasional Paper No. 23, February 2005. https://ssrn.com/abstract=752072.

Board of Governors of the Federal reserve (2022), "Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices", July. https://www.federalreserve.gov/data/sloos.htm.

Cunningham, Thomas J., (2006), "The Predictive Power of the Senior Loan Officer Survey: Do Lending Officers Know Anything Special?", Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper, November.

European Central Bank (2022), "The Euro Area Bank Lending Survey - First Quarter of 2022", Q1. *https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/bank_lending_survey/html/ecb.blssurvey2022q1~fd61911ffd.en.html.*

Faruqui, Umar, Paul Gilbert, and Wendy Kei., (2008), "Bank of Canada's Senior Loan Officer Survey", Bank of Canada Review, Autumn, https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/06/faruqui.pdf.

Filardo, Andrew J. and Siklos, Pierre L., (2020), "The cross-border credit channel and lending standards surveys", Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol.67.

Köhler-Ulbrich, Petra., Hempell, Hannah S., Scopel, Silvia., (2016), "The euro area bank lending survey: Role, development and use in monetary policy preparation", European Central Bank Occasional Paper Series, No.179, September.

Reserve Bank of India, Database on Indian Economy, https://dbie.rbi.org.in.

Reserve Bank of India (2009), "Report of the Working Group on Surveys", Reserve Bank of India Bulletin, September.

Reserve Bank of India (2021), "Annual Report of the RBI for the Year 2020-21", May.

Reserve Bank of India (2022), "Annual Report of the RBI for the Year 2021-22", May.

अनुबंध

चार्ट ए1: 'कृषि' के लिए बीएलएस ऋण मांग और वास्तविक ऋण वृद्धि

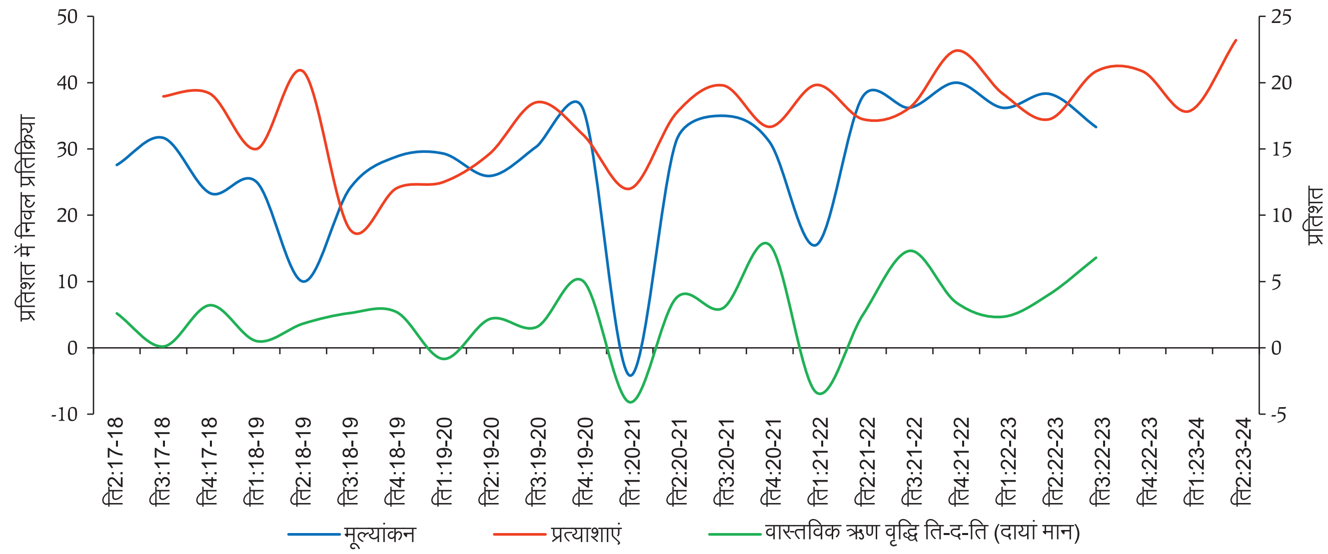

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट ए2: 'खनन और उत्खनन' के लिए बीएलएस ऋण मांग और वास्तविक ऋण वृद्धि

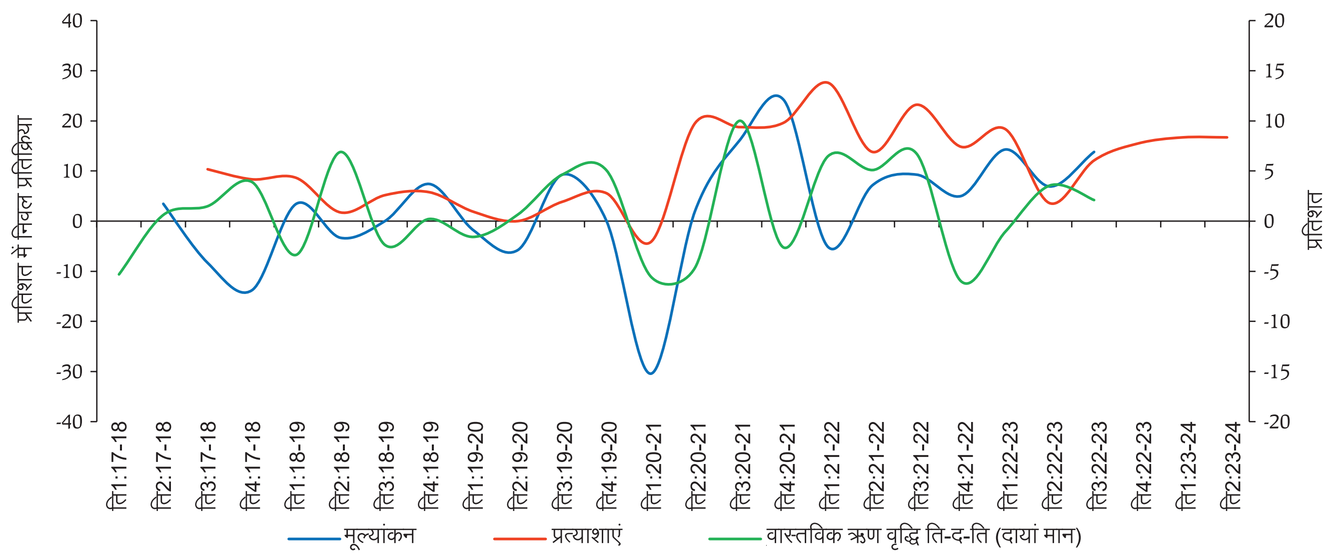

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट ए3: 'विनिर्माण' के लिए बीएलएस ऋण मांग और वास्तविक ऋण वृद्धि

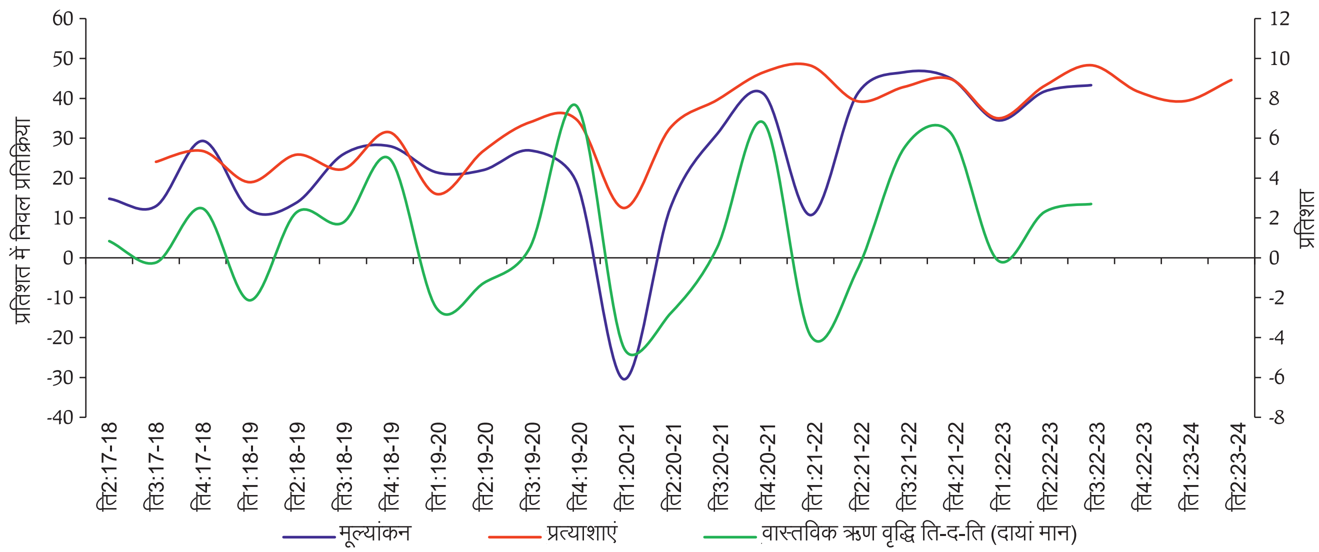

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट ए4: 'इंफ्रास्ट्रक्चर' के लिए बीएलएस ऋण मांग और वास्तविक ऋण वृद्धि

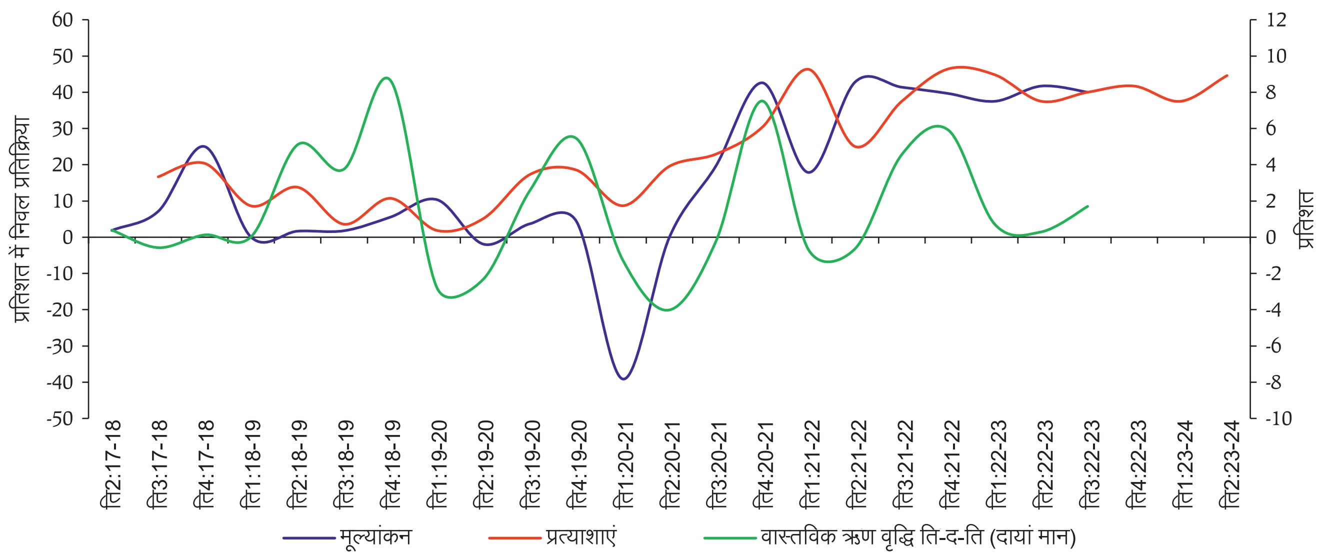

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट ए5: 'सेवाओं' के लिए बीएलएस ऋण मांग और वास्तविक ऋण वृद्धि

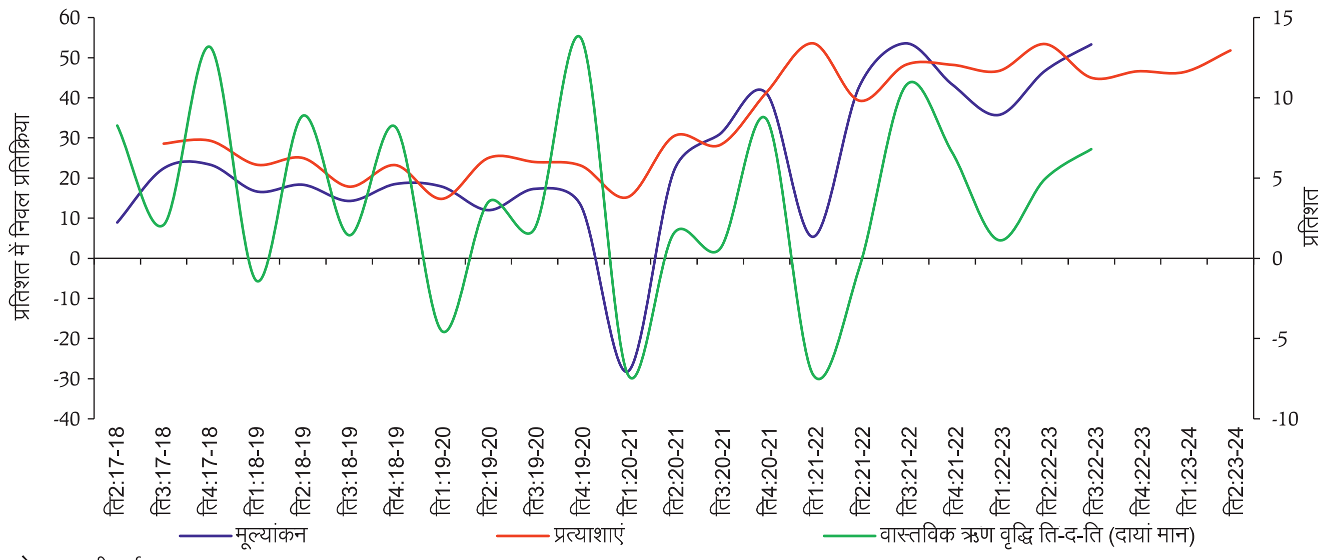

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट ए6: 'वैयक्तिक ऋण' के लिए बीएलएस ऋण मांग और वास्तविक ऋण वृद्धि

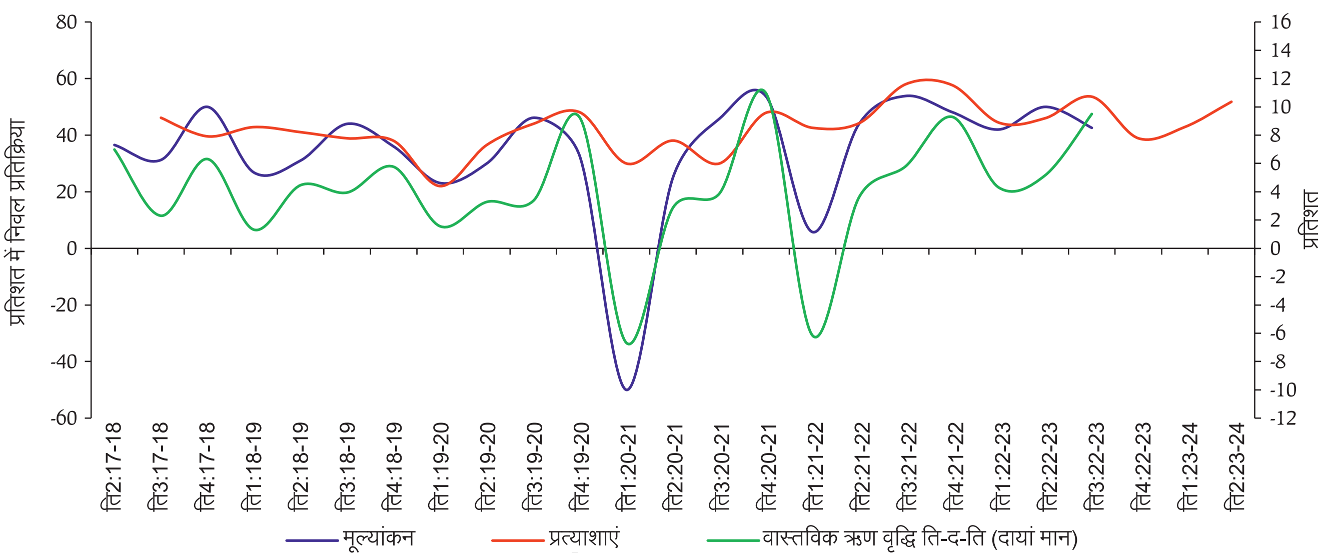

स्रोत: आरबीआई।

*फेडरल रिज़र्व की कार्रवाइयों का दीर्घ प्रभाव: मौद्रिक नीति और भारत में अनिश्चितता का प्रभाव-विस्तार**

भानु प्रताप^ और सोना थांगजासोन ^ द्वारा

यह अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक मौद्रिक नीति के आघातों के संचरण का विश्लेषण करता है। अमेरिकी मौद्रिक नीति (एमपी) के आघातों की पहचान करने के लिए एक साइन-रीस्ट्रिक्टिड वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (एसआरवीएआर) ढांचे का उपयोग करते हुए, हम पाते हैं कि अमेरिकी मौद्रिक नीति में अचानक परिवर्तन घरेलू उत्पादन और मुद्रास्फीति को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इस तरह के आघातों की समय-बदलती प्रकृति को रेखांकित करते हुए, अमेरिकी मौद्रिक नीति में अचानक परिवर्तनों को 2008 के बाद एक बड़ी मांग-गिरावट प्रभाव की तुलना में 2008 से पहले की अवधि में लागत-वृद्धि प्रभाव के रूप में देखा गया। इसके अलावा, अमेरिकी मौद्रिक नीति अनिश्चितता भी घरेलू सकल मांग को कम करती है। ये निष्कर्ष प्रमुख केंद्रीय बैंकों के लिए अपनी मौद्रिक नीति का रुख निर्धारित करने में महत्वपूर्ण प्रभावों को इंगित करते हैं।

I. परिचय

परस्पर जुड़े वित्तीय बाजारों और वैश्वीकृत वित्त की दुनिया में, एक बाजार या क्षेत्र से दूसरे बाजार में आघातों का संचरण लगभग तुरंत होता है। इस तरह के वित्तीय बाजार संबद्धता परस्पर जुड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं को जन्म देते हैं जहाँ समष्टि आर्थिक अवधारणाएँ, जैसे कि व्यापार चक्र और मुद्रास्फीति, एक साथ चलते हैं। इसके अलावा, एक देश/क्षेत्र में समष्टि आर्थिक नीति के रुख में बदलाव, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों को आश्रय देने वाले, सीमाओं के पार भी प्रभाव का संचरण करते हैं।

सदी में एक बार आने वाली महामारी के बाद मौजूदा वैश्विक स्थिति ऐसे समष्टि आर्थिक और नीतिगत घटनाक्रमों की जटिलता को रेखांकित करती है, जिनके सीमा पार प्रभाव हो सकते हैं। यद्यपि, आर्थिक सुधार जोर पकड़ रहा था, तथापि, निरंतर मुद्रास्फीति के दबाव ने प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंकों द्वारा अति-उदार मौद्रिक नीति को वापस लेने और पलटने के लिए मजबूर किया है। सभी लाभों को पूर्ववत करने की क्षमता वाले यूक्रेन-रूस युद्ध के रूप में एक विशाल भू-राजनीतिक आघात ने दुनिया को एक सख्त मौद्रिक नीति व्यवस्था में बदलाव में तेजी लाने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिकी फेडरल रिज़र्व (यूएस फेड) और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) के नेतृत्व में केंद्रीय बैंकों ने एक आक्रामक और समकालिक नीतिगत सख्ती शुरू की, जो मुद्रास्फीति को कम करने और उनकी विश्वसनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से एक नीतिगत रुख को दर्शाता है (आरबीआई, 2023)।

भारत में वित्तीय बाजार अब वैश्विक वित्तीय प्रणाली के साथ इतनी निकटता से जुड़े हुए हैं कि पिछले एक दशक में वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था के बीच तालमेल मजबूत हुआ है। अतीत में, जैसे कि "टेपर टैंट्रम" प्रकरण के दौरान, भारत ने पूंजी प्रवाह में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव, अत्यधिक विनिमय दर दबाव, वित्तीय बाजार में अस्थिरता और जीडीपी वृद्धि में मंदी, सीमा पार व्यापार और घरेलू निवेश देखा।

इस पृष्ठभूमि में, यह अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था पर यूएस फेड के मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के प्रभाव का विश्लेषण करता है। यूएस फेड की नीतिगत कार्रवाइयों का दुनिया भर में वित्तीय स्थितियों पर इसके प्रभाव के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी मौद्रिक नीति में अनिश्चितता भी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) को प्रभावित करती है। यद्यपि, अधिकांश अनुभवजन्य साहित्य उन्नत और ईएमई के बीच नीतिगत प्रभाव-विस्तार का विश्लेषण करने के लिए बहु-देशीय पैनल डेटा का उपयोग करता है, तथापि, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में काफी विविधता और उपयुक्त नीतियों को डिजाइन करने की आवश्यकता को देखते हुए वैश्विक नीतिगत आघातों के देश-विशिष्ट संचरण का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। इसलिए, हमारे अध्ययन का उद्देश्य घरेलू समष्टि-आर्थिक आधारभूत मदों अर्थात् उत्पादन वृद्धि और मुद्रास्फीति पर अमेरिकी फेडरल रिज़र्व के नीतिगत रुख के प्रभाव पर प्रकाश

^ लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं।

* लेखक संपादकीय बोर्ड और एक अनाम समीक्षक को आलेख पर उपयोगी टिप्पणियों और सुझावों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। इस पेपर में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करें।

डालकर भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक प्रभाव-विस्तार के संचरण पर उपलब्ध साहित्य को समृद्ध करना है।

ऐसा करने के लिए हम 1997-2019 की अवधि के लिए अमेरिका और भारतीय अर्थव्यवस्था पर त्रैमासिक समष्टि-आर्थिक डेटा का उपयोग करते हैं। हम एक *साइन-रीस्ट्रिक्टिड वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (एसआरवीएआर)* मॉडल का उपयोग करके अमेरिकी मौद्रिक नीति के आघातों की पहचान करते हैं और अमेरिकी मौद्रिक नीति प्रभाव-विस्तार पर प्रकाश डालने के लिए आवेग प्रतिक्रिया विश्लेषण का उपयोग करते हैं। हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिका में मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव से महत्वपूर्ण प्रभाव-विस्तार का खतरा है; हालांकि, प्रभाव की प्रकृति पिछले कुछ वर्षों में बदल गई है। विशेष रूप से, हम पाते हैं कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) से पहले, अमेरिकी मौद्रिक नीति के आघातों ने घरेलू उत्पादन वृद्धि और मुद्रास्फीति में वृद्धि को कम कर दिया, जो वैश्विक प्रभाव-विस्तार के विनिमय दर चैनल के अनुरूप घरेलू अर्थव्यवस्था पर लागत-वृद्धि प्रभाव का संकेत देता है। हालांकि, 2008 के बाद की अवधि में, अमेरिकी मौद्रिक नीति में आश्चर्यजनक परिवर्तन घरेलू सकल मांग को कम करते हैं जिससे भारत में विकास और मुद्रास्फीति में कमी होती है। हालांकि, 2008 के बाद की अवधि - अपरंपरागत मौद्रिक नीति की खोज का दौर - में यूएस फेड की नीति का समग्र प्रभाव अपेक्षाकृत कम और अस्थाई रहा है। अंत में, हम अमेरिका में मौद्रिक नीति में अनिश्चितता के कारण प्रभाव-विस्तार के प्रमाण भी पाते हैं। इससे पता चलता है कि यह न केवल यूएस फेड की नीतिगत कार्रवाई है, बल्कि उन कार्रवाइयों में अनिश्चितता भी है जो घरेलू अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकती हैं।

इस आलेख को पांच खंडों में विभाजित किया गया है। इस संक्षिप्त परिचय के बाद, खंड II नीतिगत प्रभाव-विस्तार पर वैश्विक और भारतीय साहित्य का एक संक्षिप्त सारांश प्रदान करता है। खंड III हमारे डेटा और अनुभवजन्य पद्धति का वर्णन करता है। खंड IV में, हम एसआरवीएआर मॉडल से प्राप्त आवेग प्रतिक्रियाओं और विचरण अपघटन के आधार पर अपने मुख्य परिणाम प्रस्तुत करते हैं। अंत में, प्रमुख परिणामों के आधार पर, हम भविष्य के अनुसंधान के लिए नीतिगत निहितार्थ और रूपरेखा तैयार करके खंड V में निष्कर्ष का वर्णन करते हैं।

II. साहित्य की संक्षिप्त समीक्षा

वित्तीय प्रभाव-विस्तार को होना तब माना जाता है जब एक देश (या क्षेत्र) में किसी आस्ति की कीमत में उतार-चढ़ाव दूसरे देश (या क्षेत्र) में उसी आस्ति या अन्य आस्तियों की कीमतों में परिवर्तन को प्रभावित करता है। पारंपरिक चैनल जिनके माध्यम से वित्तीय प्रभाव-विस्तार को आम तौर पर माना जाता है, उनमें वित्तीय कीमतों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्तन; सीमा पारीय तुलन पत्र एक्सपोजर; सूचना या आत्मविश्वास प्रभाव (अपेक्षाओं में आधारभूत -संचालित परिवर्तनों सहित); व्यापार संबंध; तथा मौद्रिक और राजकोषीय नीति से संबंधित प्रभाव-विस्तार शामिल हैं (डी'ऑरिया एवं अन्य, 2014, एजनर एवं अन्य, 2018; एजेनर और परेरा दा सिल्वा, 2022)।

ये चैनल आपस में जुड़े हो सकते हैं और एक प्रभाव पैदा करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं जो प्रत्येक चैनल के स्वतंत्र रूप से काम करने पर प्राप्त किए जा सकने वाले प्रभाव से अलग हो सकते हैं। मूल और मेजबान अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर सीमा पारीय प्रभाव-विस्तार का प्रभाव अक्सर विषम होता है। सीमा पार वित्तीय प्रभाव-विस्तार का प्रभाव इस प्रकार आघात के प्रकार पर निर्भर करता है जो मूल देश में आस्ति की कीमतों में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है; वास्तविक और / या वित्तीय, आर्थिक चैनल, जिसके माध्यम से आघात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होता है; मूल और प्राप्तकर्ता देशों में संचालित प्रवर्धन या शमन तंत्र; मूल और प्राप्तकर्ता देशों में समष्टि-आर्थिक और समष्टि-विवेकपूर्ण नीति व्यवस्था की प्रकृति; और प्राप्तकर्ता देशों में नीति निर्माताओं के लिए समय पर प्रतिक्रिया की गुंजाइश हो (एजनर एवं अन्य, आरबीआई, 2010)।

II.1 वैश्विक संदर्भ

वैश्विक वित्तीय चक्र को प्रभावित करने में अग्रणी अर्थव्यवस्था (एई) मौद्रिक नीति की पूर्व-प्रतिष्ठा, विशेष रूप से यूएस फेड के नेतृत्व में अच्छी तरह से शोध और प्रलेखित किया गया है (रे, 2015 और 2018; राजन और मिश्रा, 2015)। चूंकि अमेरिकी डॉलर एक वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में कार्य करता है, इसलिए उभरते बाजारों में वित्तीय स्थितियों पर अन्य व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति कार्रवाइयों का प्रभाव अमेरिकी फेड की तुलना में मामूली रहा है। उपलब्ध साहित्य ने

यह भी दर्शाया है कि इन प्रभावों की तीव्रता समय के साथ और विभिन्न देशों में विषम होती है - जीएफसी के बाद की अवधि में मजबूत और उन देशों के लिए बड़ी होती है जिन्हें जोखिम भरा निवेश माना जाता है (आईएमएफ, 2021)।

अध्ययनों में यह पाया गया है कि अमेरिकी मौद्रिक नीति के आघात मुख्य रूप से वैश्विक आस्तियों की कीमतें और पूंजी प्रवाह के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की प्रमुख मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी मौद्रिक नीति में एक विशेष भूमिका निभाता है (मिरांडा-एग्रीपिनो और रे, 2020; मिरांडा-एग्रीपिनो और रे, 2020; जॉर्डा एवं अन्य, 2019; हबीब और वेंदीट्टी, 2019)। अक्सर, अमेरिकी मौद्रिक नीति में संकुचन के बाद वैश्विक वित्तीय मध्यस्थों, विशेष रूप से ईएमई में, कुल जोखिम विमुखता में वृद्धि, वैश्विक आस्तियों की कीमतों और वैश्विक ऋण में संकुचन, कॉरपोरेट बॉण्ड स्प्रेड में वृद्धि और सकल पूंजी प्रवाह में गिरावट होती है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि अमेरिकी मौद्रिक नीति के आघात प्राप्तकर्ता देश की विनिमय दर व्यवस्था के बावजूद सीमा पार संचरित होते हैं (डीस और गेलसी, 2021; जॉर्जियाडिस, 2017)।

2013 के "टेपर टैंट्रम" प्रकरण के दौरान, तत्कालीन यूएस फेड अध्यक्ष बेन एस बर्नांके के अमेरिकी फेड द्वारा आस्ति खरीद में कटौती की संभावना पर केवल घोषणा से न केवल घरेलू ब्याज दरों में वृद्धि हुई, बल्कि उभरते बाजारों की प्रतिफल में भी वृद्धि हुई, पोर्टफोलियो बहिर्वाह हुआ, और उभरते बाजारों की मुद्राओं[1] का अवमूल्यन हुआ।

उभरते बाजार के घरेलू प्रतिफल में लगभग सभी बदलावों को अवधि प्रीमियम में बदलाव से जोड़ा जा सकता है, जो यह सुझाव देता है कि अमेरिकी मौद्रिक नीति (आईएमएफ, 2021) के आश्चर्यजनक सख्त होने के बाद उभरते बाजार के बॉण्ड को धारित करने का कथित जोखिम बढ़ जाता है। यह इस निष्कर्ष के अनुरूप है कि उच्च सरकारी जोखिम वाले देश सीमा पारीय प्रभाव-विस्तार के प्रति अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील हैं (एड्रियन एवं अन्य, 2013)। इन निष्कर्षों से जोखिम की अवधारणा का पता चलता है अर्थात जोखिम चैनल, प्रभाव-विस्तार के संचरण में एक महत्वपूर्ण चैनल के रूप में उभरा है। दूसरी ओर, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छी खबर जारी करना, भले ही यह सख्त अमेरिकी मौद्रिक नीति की उम्मीदों के साथ हो, उभरते बाजारों में वित्तीय स्थितियों के लिए अपेक्षाकृत अच्छा है। (आईएमएफ़, 2021)।

इस विचार को ध्यान में रखते हुए, हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि अमेरिकी ब्याज दर में वृद्धि के सभी उदाहरण ईएमई (उदाहरण के लिए होक एवं अन्य 2021 देखें) में वित्तीय संकट का कारण नहीं बनते हैं। ईएमई पर अमेरिकी मौद्रिक नीति परिवर्तनों के इस अंतर प्रभाव को दो प्रमुख कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। सबसे पहले, अमेरिकी नीति दर में वृद्धि का कारण। ईएमई के दृष्टिकोण से, यदि अमेरिकी ब्याज दरों में वृद्धि बेहतर विकास संभावनाओं से प्रेरित है, तो प्रभाव सकारात्मक होने की संभावना है क्योंकि उच्च अमेरिकी जीडीपी से निर्यात मांग में वृद्धि और निवेशकों का विश्वास अधिक ब्याज लागत के कारण अधिक व्यय की स्थिति में भी मजबूत होगा। हालांकि, मुद्रास्फीति के बारे में चिंताओं से प्रेरित 'आक्रामक' नीतिगत परिवर्तन अर्थात दरों में वृद्धि ईएमई के लिए अत्यधिक विघटनकारी हो सकती है। दूसरा, यह प्रभाव घरेलू सुभेद्यताओं पर इस प्रकार निर्भर है, कि समष्टि-आर्थिक कमजोरियों के लिए अति संवेदनशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थितियां अमेरिकी ब्याज दरों में वृद्धि के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं (होक एवं अन्य)।

इसके विपरीत, ऐसे अध्ययन भी हुए हैं जिनमें पाया गया है कि बेहतर मूल सिद्धांतों ने, विशेष रूप से, 2013 के "टेपर टॉक" की स्थिति में रोधन प्रदान नहीं किया। इसमें किसी देश के वित्तीय बाजार का आकार एक अधिक महत्वपूर्ण निर्धारक इस प्रकार रहा है कि बड़े बाजारों वाले देशों ने विनिमय दर, विदेशी आरक्षित निधि और इक्विटी कीमतों पर अधिक दबाव का अनुभव किया (ईचेनग्रीन और गुप्ता, 2015)। दूसरी ओर, मजबूत विनिर्माण क्षेत्र वाले एई पण्य की कीमतों और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (मिरांडा-एग्रीपिनो एवं अन्य, 2020) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चैनल के कारण प्रभाव-विस्तार के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। अंत में, एई और ईएमई के बीच बढ़ती परस्पर-आश्रितता भी रही है। आमतौर पर, एई से दुनिया के शेष भागों में संचरित होने वाले प्रभाव-विस्तार को वैश्विक प्रभाव-विस्तार के रूप में जाना जाता है, जबकि दुनिया के शेष भागों से निकलने वाले और एई को

[1] 22 मई, 2013 को संयुक्त आर्थिक समिति, अमेरिकी कांग्रेस, वाशिंगटन, डीसी के समक्ष अध्यक्ष बेन एस बर्नांके की गवाही देखें: https://www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/bernanke20130522a.htm.

प्रभावित करने वाले को आमतौर पर वैश्विक स्पिलबैक के रूप में जाना जाता है। इस तरह से देखा जाए तो पिछले 25 वर्षों में वैश्विक स्पिलबैक की मात्रा एई से ईएमई तक संचरित होने वाले वैश्विक प्रभाव-विस्तार का लगभग पांचवां हिस्सा है। हालांकि, इन दो ब्लॉकों के बीच विकसित परस्पर-आश्रितता के कारण समय के साथ इस तरह के स्पिलबैक प्रभावों में काफी वृद्धि हुई है। (अरेज़की और यांग, 2020)[2]

II.2 भारतीय संदर्भ

हाल के दिनों में, भारतीय संदर्भ में अमेरिकी मौद्रिक नीति प्रभाव-विस्तार के प्रभाव पर कई अनुभवजन्य अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों में भारत में सीमा पार प्रभाव-विस्तार के संचरण का विश्लेषण किया गया है, जो इस तरह के संचरण के लिए महत्वपूर्ण चैनलों का विश्लेषण करता है और वैश्विक प्रभाव-विस्तार प्राप्त करने और उससे निपटने में नीतिगत अनुभव का विश्लेषण करता है।

उदाहरण के लिए, पात्र एवं अन्य (2016 ए) के अनुसार यूएस फेड द्वारा की गई मात्रात्मक सहजता (क्यूई) ने भारत में मौद्रिक स्थितियों को प्रभावित किया, विशेष रूप से, क्यूई 1 ने जिसका प्रभाव सबसे अधिक था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि क्यूई से संबंधित प्रभाव-विस्तार मुख्य रूप से पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन चैनल तत्पश्चात चलनिधि चैनल के माध्यम से प्रभावित करता है। इसके अलावा, मौद्रिक नीति के घरेलू संचरण पर अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों के प्रभाव का आकलन करते हुए, पात्र और अन्य (2016 बी) ने देखा कि मुद्रा और ऋण बाजारों के माध्यम से मौद्रिक नीति संचरण वैश्विक प्रभाव-विस्तार से प्रभावित नहीं होता है। हालांकि, कर्ज़ बाजार के माध्यम से संचरण प्रभावित हुआ था। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि भारतीय विदेशी मुद्रा और इक्विटी बाजार वैश्विक प्रभाव-विस्तार के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थे, लेकिन इस तरह के प्रभाव-विस्तार के कारण घरेलू मौद्रिक नीति की नरमी को खोने का कोई मजबूत सबूत नहीं था।

इसी तरह, मोहंती और बनर्जी (2021) का मानना है कि अमेरिकी मौद्रिक सख्ती घरेलू कंपनियों के निवल मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और बाह्य ऋण के सापेक्ष घरेलू ऋण को कम करती है। वे यह भी पाते हैं कि संकुचन वाली अमेरिकी मौद्रिक नीति, मुख्य रूप से विनिमय दर के वित्तीय चैनल के माध्यम से काम करती है, जो भारत में घरेलू ऋण और व्यापार चक्र में महत्वपूर्ण गिरावट का कारण बनती है। लकड़ावाला (2021) ने टाइम-वैरिंग पैरामीटर मॉडल फ्रेमवर्क में उच्च आवृत्ति वाले वित्तीय बाजार के आंकड़ों का उपयोग करते हुए यह पाया कि अमेरिकी मौद्रिक नीति के निर्णयों का भारतीय इक्विटी बाजारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव समय के साथ मजबूत होता जा रहा है। अध्ययन में नीतिगत दर में आश्चर्यजनक बदलावों के साथ-साथ अनिश्चितता अर्थात- बड़े पैमाने पर आस्ति खरीद (क्यूई) के बारे में घोषणाएं - दोनों को ऐसे चैनल के रूप में पहचाना गया है जिसके माध्यम से प्रभाव-विस्तार प्रसारित होते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि अमेरिकी मौद्रिक नीति के प्रति भारतीय शेयर प्रतिक्रिया विदेशी संस्थागत निवेशकों के पोर्टफोलियो निर्णयों के प्रति समान रूप से संवेदनशील थी, साथ ही विनिमय दर अमेरिकी मौद्रिक नीति और अस्थिरता तथा जोखिम विमुखता के माध्यम से काम करने वाले वैश्विक वित्तीय चक्र के प्रति संवेदनशील थी।

वर्तमान नीतिगत माहौल, विशेष रूप से अग्रणी देशों में, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने या अभूतपूर्व मुद्रास्फीति से निपटने के मामले में नीति निर्माताओं की दुविधा को दर्शाता है। बढ़ती अनिश्चितता के बीच मौजूदा नीतिगत परिदृश्य में एक अच्छा नीतिगत संतुलन बनाए रखना मुश्किल होने की संभावना है। अग्रणी देशों के नीति निर्माताओं को भी अपने देश में समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के अपने विकल्प और बाकी दुनिया के लिए प्रभाव-विस्तार पैदा करने में सावधानी बरतनी चाहिए।

III. डेटा और अनुभवजन्य पद्धति

III.1 डेटा

हम अपने विश्लेषण के लिए अमेरिका और भारतीय अर्थव्यवस्था पर तिमाही आंकड़ों का उपयोग करते हैं। घरेलू ब्लॉक के लिए, आर्थिक गतिविधि को स्थिर कीमतों में व्यय को रखकर जबकि सभी वस्तुओं के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति के माप के रूप में लेकर सकल घरेलू उत्पाद

---

[2] उदाहरण के लिए, जबकि प्रमुख एई से चीन पर बड़े प्रभाव-विस्तार प्रभाव हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह वैश्विक आपूर्ति शृंखला का एक प्रमुख घटक है, चीन से इन अर्थव्यवस्थाओं पर भी स्पिलबैक प्रभाव हैं। इसलिए, चीन में कोई भी दुर्घटना, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान बार-बार देखा गया है, वैश्विक आपूर्ति बाधाएं पैदा कर सकती है।

(जीडीपी) द्वारा परोक्षित (प्रॉक्सिड) किया जाता है। दोनों को वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर मापा जाता है। हम अपने अनुभवजन्य मॉडल के घरेलू ब्लॉक में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी 50 इंडेक्स और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की नाममात्र विनिमय दर को भी शामिल करते हैं।

विदेशी ब्लॉक के लिए, यूएस सीबीओई VIX इंडेक्स के रूप में निहित शेयर बाजार की अस्थिरता को अमेरिका में जोखिम अवधारणा के लिए एक परोक्षी (प्रॉक्सी) के रूप में लिया जाता है। मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण से, दिसंबर 2008 से दिसंबर 2015 तक और कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान फेडरल निधि दर शून्य के करीब रही। इन दोनों उदाहरणों में, यूएस फेड ने दीर्घकालिक ब्याज दरों को प्रभावित करने और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मात्रात्मक सहजता कार्यक्रमों और वायदा दिशानिर्देश के अंतर्गत बड़े पैमाने पर आस्ति खरीद जैसे अपरंपरागत नीतिगत साधनों पर भरोसा किया। नीतिगत दर को शून्य को न्यूनतम सीमा मानते हुए, साहित्य यह बताते हैं कि यूएस फेड की मौद्रिक नीति के रुख को चिह्नित करने के लिए आभासी नीति दरों का उपयोग किया जाए। इस संदर्भ में, वू और जिया (2016) ने यूएस फेड के मौद्रिक नीति रुख को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए एक शैडो दर का प्रस्ताव दिया। प्रस्तावित आभासी दर जिसे 1/4, 1/2, 1, 2, 5, 7 और 10 वर्षों के लिए एक महीने की अग्रिम दरों का उपयोग करके बनाया गया है, 0 प्रतिशत से नीचे नहीं है। चूंकि छाया दर मौद्रिक नीति के समग्र रुख के लिए जिम्मेदार है, जिसमें 2008-2015 के दौरान अपरंपरागत मौद्रिक नीति की अवधि भी शामिल है, इसलिए हम यूएस फेड (चार्ट 1 ए) के मौद्रिक नीति रुख के परोक्षी के रूप में वू और जिया (2016) की आभासी ब्याज दर का उपयोग करते हैं। अंत में, अमेरिकी मौद्रिक नीति से संबंधित अनिश्चितता के लिए, हम बेकर एवं अन्य (2016) द्वारा प्रस्तावित समाचार-आधारित अमेरिकी मौद्रिक नीति अनिश्चितता संकेतक का लाभ उठाते हैं। मौद्रिक नीति के लिए अनिश्चितता में वृद्धि आम तौर पर अमेरिका में जोखिम धारणा को बढ़ाती है (चार्ट 1 बी देखें)।

चार्ट 1: संयुक्त राज्य अमेरिका में मौद्रिक नीति और जोखिम धारणा

(ए) अमेरिकी फेडरल रिज़र्व का नीतिगत रुख

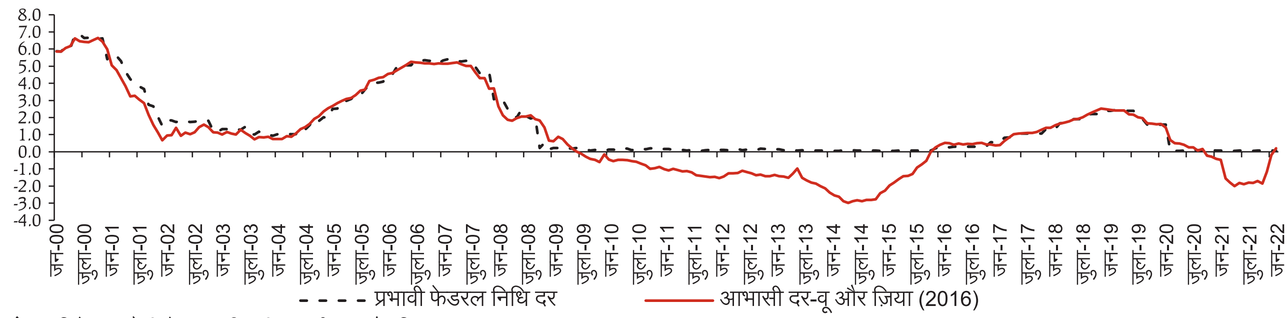

स्रोत : निदेशक बोर्ड, फेडरल रिज़र्व प्रणाली; वू और ज़िया (2016)।

(बी) अमेरिका में मौद्रिक नीति की अनिश्चितता और अंतर्निहित अस्थिरता

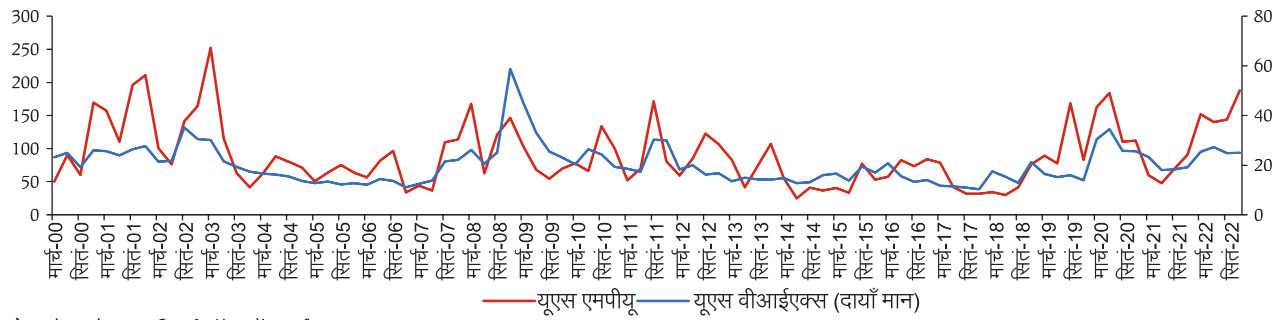

स्रोत: फ्रेड, फेडरल रिज़र्व ऑफ सेंट लुई।

यह डेटा फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ सेंट लुई के फेडरल रिज़र्व इकनॉमिक डेटाबेस (एफ़आरईडी), सीईआईसी डेटाबेस और वू और ज़िया (2016) से लिया गया है। हमारे अध्ययन में उपयोग किए गए चर और डेटा का विवरण सारणी 1 में दिया गया है।

III.2 साइन-रेस्ट्रिक्टेड वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (एसआरवीएआर) मॉडल

विकसित अर्थव्यवस्थाओं (एई), विशेष रूप से अमेरिका से मौद्रिक नीति के आघातों के संचरण को समझने के लिए, हम एक साइन-रेस्ट्रिक्टेड वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (एसआरवीएआर) मॉडल का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, निम्नानुसार निर्दिष्ट n अंतर्जात चर के साथ छोटे वीएआर (1) मॉडल पर विचार करें:

$$y_t = A \cdot y_{t-1} + \varepsilon_t \; for \; t = 1, 2, 3 \ldots, T.$$

जहां, y_t चर का वेक्टर $n \times 1$ है, A गुणांक का एक $n \times n$ मैट्रिक्स है और ε_t शून्य औसत के साथ त्रुटियों का एक सेट है, कोई क्रमिक सहसंबंध और विचरण-सहप्रसरण मैट्रिक्स नहीं है $\sum = E[\varepsilon_t \varepsilon_t^{'}]$ चूंकि घटाई हुई पूर्वानुमान त्रुटि संरचनात्मक नवोन्मेष से संबंधित है, जैसे $B\varepsilon_t = e_t$ जहां B एक संरचनात्मक पैरामीटर का $n \times n$ मैट्रिक्स है और e_t सामान्य रूप से वितरित संरचनात्मक आघात हैं जिनका शून्य औसत और इकाई विचरण है, $B^{'} = \sum = E[\varepsilon_t \varepsilon_t^{'}]$ के द्वारा संरचनात्मक पैरामीटर को पुन: प्राप्त किया जा सकता है। अनुमानित $\hat{\varepsilon}_t$, के माध्यम से संरचनात्मक आघात से उबरने के लिए, हम ब्याज की आवेग प्रतिक्रिया पर विभिन्न चिन्हित-प्रतिबंध लगाते हैं। आवेग प्रतिक्रिया पर अपेक्षाकृत कमजोर पूर्व विश्वास ज्यादातर ' x पर आघात m माह के लिए आघात के बाद y को बढ़ाता/घटाता नहीं है'।

हमारे मामले में, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एसआरवीएआर मॉडल का अनुमान लगाने के लिए 1997 की पहली तिमाही से 2019 की चौथी तिमाही के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। हम मार्कोव चेन मोंटे कार्लो (एमसीएमसी) नमूना तकनीक का उपयोग करके मॉडल का अनुमान लगाते हैं, जिसमें पीछे से लिए गए 5000 ड्रॉ, 1000 बर्न-इन ड्रॉ और 4000 सबड्रॉज़ हैं, जिस पर आवेग प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं जिन पर जुर्माना एल्गोरिदम लागू होता है। इष्टतम लंबाई बायेसियन सूचना मानदंड (बीआईसी) का उपयोग करके चुनी जाती है।

अमेरिका से मौद्रिक नीति के आघातों की पहचान करने के लिए न्यूनतम संकेत प्रतिबंध लगाते हुए, हम घरेलू अर्थव्यवस्था के प्रमुख समष्टिआर्थिक बुनियादी सिद्धांतों की प्रतिक्रिया के बारे में अज्ञेयवादी बने रहना चाहते हैं। साइन- रेस्ट्रिक्टशन के आधार पर हमारी पहचान विधि एक बायेसियन फ्रेमवर्क[3] के भीतर लागू उहलिग (2005) दंड प्रकार्य दृष्टिकोण का उपयोग करती है।

मौजूदा साहित्य के अनुरूप, हम मानते हैं कि अमेरिकी मौद्रिक नीति के आघात से यूएस वीआईएक्स सूचकांक में वृद्धि होती है, घरेलू इक्विटी बाजारों में गिरावट आती है और रुपये-डॉलर विनिमय दर में गिरावट आती है। हम यह भी मानते हैं कि मौद्रिक नीति के आघात, आघात के बाद चार तिमाहियों तक प्रभावी रहता है, जबकि घरेलू उत्पादन और कीमतों की दिशात्मक प्रतिक्रियाओं के प्रति अज्ञेयवादी रहता है। हमारे मॉडल में अमेरिकी मौद्रिक नीति के आघातों की पहचान करने के लिए साइन-रेस्ट्रिक्टशन को सारणी 2 में संक्षेपित किया गया है।

सारणी 1: चर और डेटा स्रोत

क्र. सं.	चर	विवरण	स्रोत
	घरेलू ब्लॉक		
1.	वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद	व-द-व (%)	फ्रेड, सेंट लुइस
2.	उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति	व-द-व (%)	फ्रेड, सेंट लुइस
3.	इक्विटी सूचकांक (निफ्टी 50)	व-द-व (%)	सीईआईसी डेटाबेस
4.	विनिमय दर (आईएनआर-यूएसडी)	लॉग में	सीईआईसी डेटाबेस
	विदेशी ब्लॉक		
1.	अमेरिकी मौद्रिक नीति	आभासी दर	वू और ज़िया (2016)
2.	अमेरिका निहित अस्थिरता	सीबीओई वीआईएक्स सूचकांक	फ्रेड, सेंट लुइस
3.	अमेरिकी मौद्रिक नीति अनिश्चितता	अमेरिकी एमपीयू	फ्रेड, सेंट लुइस

सारणी 2: अमेरिकी मौद्रिक नीति आघात की पहचान के लिए साइन-रेस्ट्रिक्शन

चर	विदेशी ब्लॉक		घरेलू ब्लॉक			
	यूएस एमपी	यूएस वीआईएक्स	उत्पादन	मुद्रास्फीति	इक्विटी की कीमतें	आईएनआर-यूएसडी
प्रतिबंध	≥ 0	≥ 0	?	?	≤ 0	≥ 0

स्रोत : लेखकों की गणना।

[3] वीएआरसाइनआर (VARSignR) पैकेज (डेन, 2015) का उपयोग करके मॉडल आकलन और पहचान को लागू किया गया।

4. अनुभवजन्य परिणाम

अमेरिका जैसे प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण देशों में घरेलू मौद्रिक और राजकोषीय निर्णयों के कारण उत्पन्न प्रभाव विस्तार, वित्तीय बाजारों, बैंक ऋण और अन्य अर्थव्यवस्थाओं में वास्तविक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। भले ही ये परिवर्तन अमेरिकी घरेलू अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य से इष्टतम हों, लेकिन विदेशी अर्थव्यवस्थाओं पर उनके अवांछनीय प्रभाव हो सकते हैं। यह तर्क दिया गया है कि यूएस फेड के कार्यों ने चाहे अपेक्षित हो या अनपेक्षित वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्रेडिट और आस्ति मूल्य में तेज़ी लाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। इसी तरह, जीएफसी के बाद से प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई अति-उदार मौद्रिक नीति के विभिन्न रूपों ने अन्य देशों की ब्याज दरों और ऋण स्थितियों को प्रभावित करके उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इस खंड में, हम आवेग प्रतिक्रिया विश्लेषण और हमारे एसआरवीएआर मॉडल से पूर्वानुमान त्रुटि भिन्नता अपघटन का उपयोग करके भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी मौद्रिक नीति आघातों के प्रभाव पर अपने परिणाम प्रस्तुत करते हैं।

IV.1 अमेरिकी मौद्रिक नीति से प्रभाव विस्तार

उहलिग (2005) जुर्माना प्रकार्य दृष्टिकोण के आधार पर, अमेरिका में मौद्रिक नीति आघातों के लिए घरेलू समष्टिआर्थिक चर की गतिशील प्रतिक्रियाएं चार्ट 2 में नीचे दी गई हैं। चार्ट घरेलू आर्थिक गतिविधि और मुद्रास्फीति (गहरी लाल रेखा) की आवेग प्रतिक्रियाओं के लिए औसत अनुमान को अमेरिकी नीति दर के

चार्ट 2: अमेरिकी मौद्रिक नीति आघातों के प्रभाव-विस्तार का प्रभाव - पूर्ण नमूना

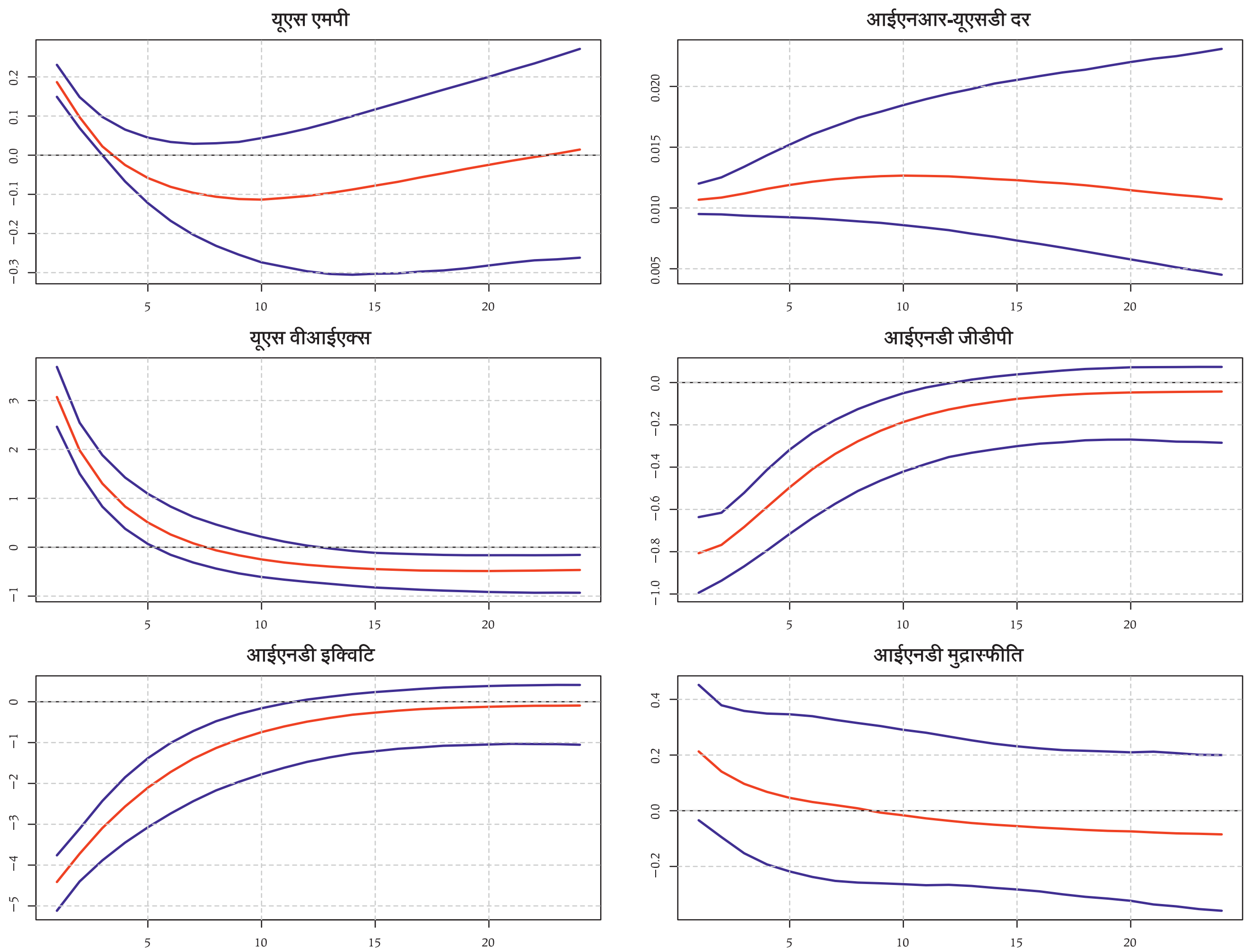

स्रोत : लेखकों की गणना।

लिए एक मानक विचलन आघात की तुलना में दिखाता है। नीली रेखाएं 68 प्रतिशत आत्मविश्वास बैंड का संकेत देती हैं। ये परिणाम पूर्ण डेटा नमूने पर अनुमान के अनुरूप हैं *यानी,* 1997 की पहली तिमाही से 2019 की चौथी तिमाही तक। आवेग प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट है कि अमेरिकी मौद्रिक नीति आघात के संकुचन के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था को उत्पादन में तत्काल गिरावट का सामना करना पड़ता है। यह प्रभाव लगभग 12 तिमाहियों तक बना हुआ पाया गया है। उत्पादन में कमी घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि के साथ होती है, हालांकि, प्रभाव सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि संकुचनकारी अमेरिकी मौद्रिक नीति के आघातों से वैश्विक जोखिम विचलन (वीआईएक्स सूचकांक) में वृद्धि होती है, जो बदले में घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास के साथ घरेलू इक्विटी कीमतों में गिरावट का कारण बनता है।

इसके बाद, हम अपने नमूने को दो अवधियों में विभाजित करते हैं, 1997 की पहली तिमाही से 2007 की चौथी तिमाही तक और 2008 की पहली तिमाही से 2019 की चौथी तिमाही तक। पूर्व अवधि जीएफसी से पहले की अवधि और मुख्य रूप से पारंपरिक नीतिगत साधनों के उपयोग को दर्शाती है। दूसरी ओर, बाद की अवधि में यूएस फेड द्वारा दोनों पारंपरिक और अपरंपरागत नीतिगत साधनों के उपयोग की विशेषता है। ध्यान दें कि, वू और ज़िया (2016) अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों के प्रभावों का अनुमान लगाने के लिए 2008-09 से 2013-14 तक के मासिक डेटा का उपयोग करते हैं। हालांकि, डेटा की कमी को देखते हुए, हम अपने मॉडल का अनुमान एक बड़े पैमाने पर लगाते हैं, जिसमें अति-उदार मौद्रिक नीति रुख की अवधि शामिल है, जिसके बाद अमेरिका में नीति का सामान्यीकरण होता है। हम इन दो मॉडलों के लिए अलग-अलग अपने मॉडल का अनुमान लगाते हैं और नीचे आवेग प्रतिक्रियाओं को प्रस्तुत करते हैं।

चार्ट 3 और 4 क्रमशः दो उप-नमूनों, 1997 की पहली तिमाही: 2007 की चौथी तिमाही और 2008 की पहली तिमाही: 2019 की चौथी तिमाही पर आवेग प्रतिक्रियाओं को प्रस्तुत करते हैं। 2008 से पहले के नमूने के अनुमान बताते हैं कि एक संकुचनकारी अमेरिकी मौद्रिक नीति के आघात से घरेलू उत्पादन में गिरावट और मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। इसके अलावा, हम पाते हैं कि घरेलू उत्पादन और मुद्रास्फीति की प्रतिक्रियाएं, सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण होने के अलावा, पूर्ण नमूने की तुलना में 2008-पूर्व नमूने के लिए ज़्यादा हैं। हालांकि, घरेलू उत्पादन की प्रतिक्रिया इस मामले में कम स्थिर है क्योंकि यह 8-9 तिमाहियों के बाद सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन हो जाता है। मुद्रास्फीति में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन में गिरावट से पता चलता है कि अमेरिकी मौद्रिक नीति के आघातों का सीमा पार संचरण 2008 से पहले की अवधि में विनिमय दर चैनल द्वारा संचालित था (कैलडारा एवं अन्य देखें)। यह देखते हुए कि अधिकांश वैश्विक व्यापार अमेरिकी डॉलर में किया जाता है, घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन से भारतीय फर्मों के लिए पूंजी की लागत में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, कच्चा तेल भी महंगा हो जाएगा जो एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में कार्य करता है, जिससे लागत में तात्कालिक वृद्धि होगी। कुल मिलाकर, घरेलू फर्मों के लिए पूंजी की लागत में इस तरह की वृद्धि अमेरिकी मौद्रिक नीति के अप्रत्याशित सख्त होने के लागत-दबाव प्रभावों को उजागर करती है।

दूसरी ओर, 2008 के बाद के नमूने के मामले में, हम पाते हैं कि अमेरिकी मौद्रिक नीति आघात घरेलू आर्थिक गतिविधि के साथ-साथ घरेलू मुद्रास्फीति में गिरावट का कारण बनते हैं। उत्पादन वृद्धि और मुद्रास्फीति में गिरावट सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण और लगातार है, जिसमें उत्पादन वृद्धि और मुद्रास्फीति चार तिमाहियों से अधिक समय से घट रही है। जैसा कि साहित्य में सुझाव दिया गया है, अमेरिकी मौद्रिक नीति का ईएमई के लिए प्रभाव विस्तार, विशेष रूप से अपरंपरागत नीतियों से, मुख्य रूप से वित्तीय चैनल द्वारा संचालित किया गया है। यह चैनल यूएस फेड द्वारा नीतिगत सख्ती के साथ अमेरिका में दीर्घकालिक ब्याज दरों की सख्ती का पता लगाता है। उच्च दीर्घकालिक प्रतिफल वैश्विक निवेशकों को विदेशी आस्तियों से अमेरिकी आस्तियों में स्विच करने की अनुमति देता है, जिससे विदेशी वित्तीय स्थितियों में वृद्धि होती है, जिसके बाद सकल घरेलू उत्पाद में कमी और ईएमई में मुद्रास्फीति होती है। इसलिए, जीएफसी के बाद की अवधि में घरेलू उत्पादन वृद्धि और मुद्रास्फीति की प्रतिक्रियाएं वित्तीय चैनल के माध्यम से वैश्विक नीति प्रभाव विस्तार के संचरण का समर्थन करती हैं। कुल मिलाकर, हमारे परिणाम बताते हैं कि जीएफसी के बाद अमेरिकी मौद्रिक नीति घरेलू अर्थव्यवस्था में कुल मांग को प्रभावित करती है।

चार्ट 3: अमेरिकी मौद्रिक नीति से प्रभाव-विस्तार- 2008 के पहले का नमूना

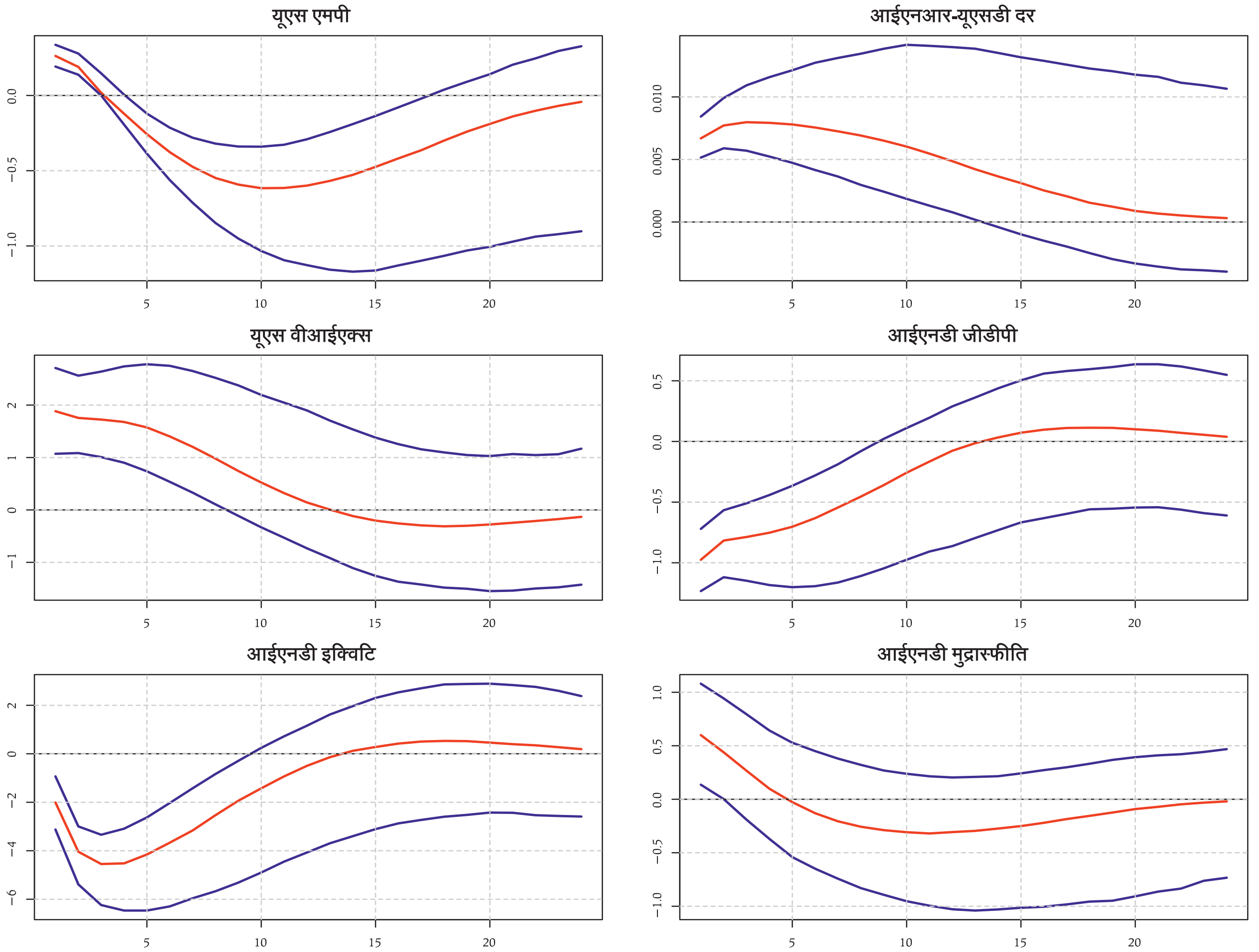

स्रोत : लेखकों की गणना।

चार्ट 3 और चार्ट 4 में प्रस्तुत आवेग प्रतिक्रियाएं भारतीय अर्थव्यवस्था में अमेरिकी मौद्रिक नीति के आघातों की बदलती प्रकृति और संचरण को रेखांकित करती हैं। 2008 से पहले की अवधि के मामले में, जो अमेरिका में पारंपरिक मौद्रिक नीति साधनों के उपयोग का पर्याय है, यूएस फेड के नीतिगत रुख में अप्रत्याशित परिवर्तन ने उत्पादन वृद्धि को कम कर दिया और घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि की, जिससे विनिमय दर चैनल के माध्यम से घरेलू अर्थव्यवस्था को लागत- दबाव आघात लगा। 2008 के बाद की अवधि में, जिसे अमेरिका में अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों की तलाश के रूप में देखा गया, भारत में नीतिगत प्रभाव विस्तार एक समग्र मांग के आघात का रूप ले लिया, जिससे घरेलू उत्पादन वृद्धि और मुद्रास्फीति में वैश्विक प्रभाव विस्तार के वित्तीय चैनल के क्रम में कमी आई।

IV.2 अमेरिकी मौद्रिक नीति अनिश्चितता से प्रभाव विस्तार

सीमा-पार नीतिगत प्रभाव विस्तार को बाजार प्रतिभागियों की आर्थिक बुनियादी बातों में बदलाव की धारणा और स्रोत देश में मौद्रिक नीति के रुख से भी प्रेरित किया जा सकता है। यह इन परिवर्तनों की वास्तविक प्राप्ति के बजाय नीतिगत घोषणाओं (या उनकी कमी) से भी प्रेरित हो सकता है। नीतिगत धारणा में इस तरह के बदलावों का उन संकेतकों द्वारा पता लगाया जा सकता है जो आर्थिक नीति के आसपास अनिश्चितता को मापते हैं। इसलिए, अमेरिका में मौद्रिक नीति के आसपास अनिश्चितता के

चार्ट 4: अमेरिकी मौद्रिक नीति से प्रभाव-विस्तार- 2008 के बाद का नमूना

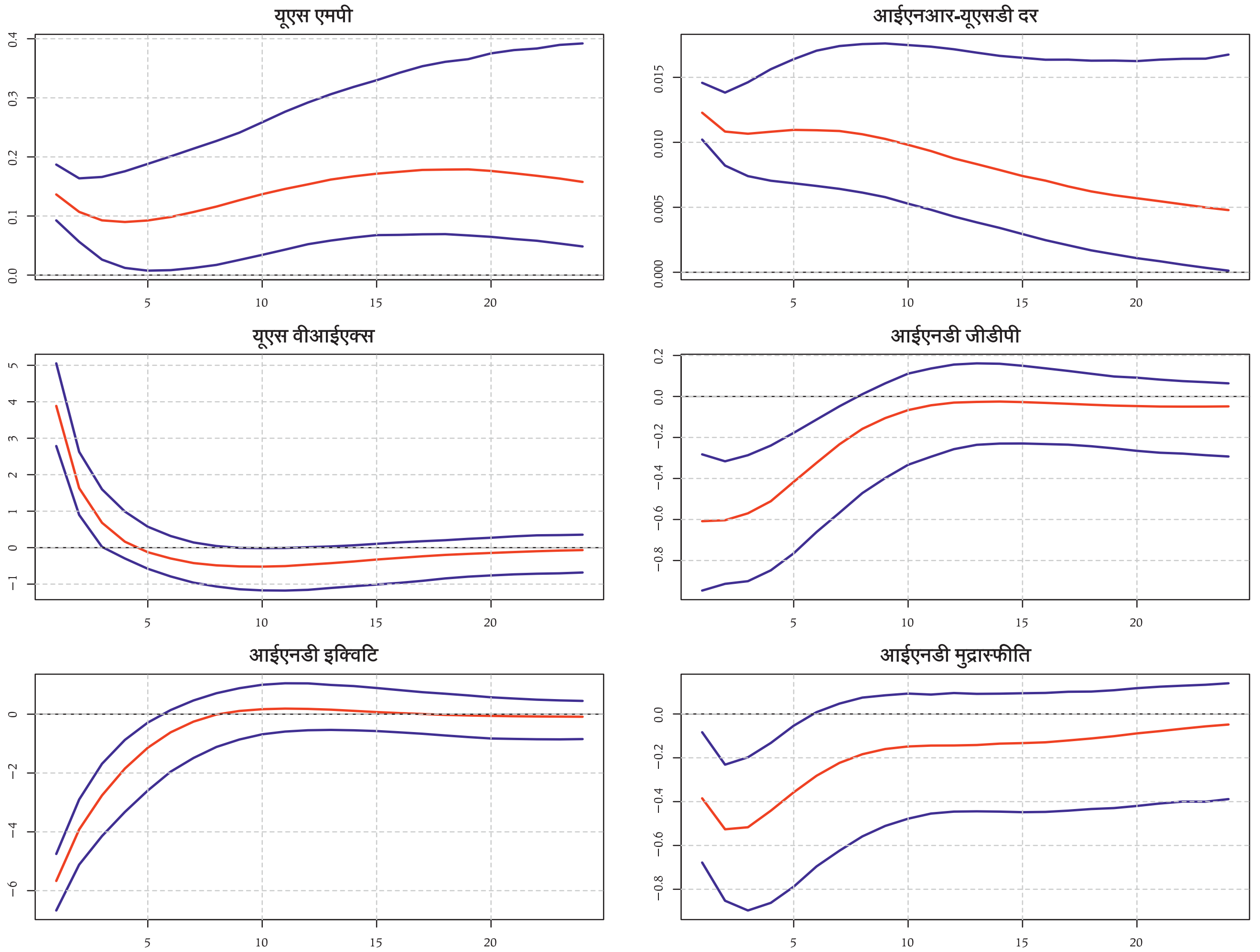

स्रोत : लेखकों की गणना।

प्रभाव का पता लगाने के लिए, हम बेकर एवं अन्य (2016) द्वारा प्रस्तावित समाचार-आधारित अमेरिकी मौद्रिक नीति अनिश्चितता (एमपीयू) सूचकांक के साथ अमेरिकी छाया ब्याज दर को बदलकर हमारे एसआरवीएआर मॉडल का अनुमान लगाते हैं। हम पहले की तरह समान साइन रेस्ट्रिक्टशन लगाते हैं और पूर्ण डेटा नमूने पर मॉडल का अनुमान लगाते हैं। यूएस एमपीयू के लिए एक मानक विचलन आघात के परिणामस्वरूप आवेग प्रतिक्रिया चार्ट 5 में दी गई है।

जैसा कि चार्ट 5 में देखा गया है, अमेरिकी मौद्रिक नीति अनिश्चितता में अप्रत्याशित वृद्धि से घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि के साथ-साथ घरेलू उत्पादन वृद्धि में गिरावट आती है। पिछले उपखंड में चर्चा की गई अमेरिकी मौद्रिक नीति के आघातों की तुलना में घरेलू जीडीपी वृद्धि और मुद्रास्फीति पर आघात का प्रभाव बड़ा और अधिक लगातार है। इससे पता चलता है कि अमेरिकी मौद्रिक नीति के संदर्भ में बढ़ी अनिश्चितता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक आपूर्ति-पक्ष के आघात के समान है जो उत्पादन वृद्धि में लगातार गिरावट के साथ त्वरित मुद्रास्फीति के रूप में दिखाई देती है। कुल मिलाकर, वैश्विक मौद्रिक नीति अनिश्चितता घरेलू मौद्रिक नीति के लिए मुद्रास्फीति-उत्पादन तालमेल को बिगाड़ देती है।

चार्ट 5: अमेरिकी मौद्रिक नीति अनिश्चितता से प्रभाव-विस्तार- पूर्ण नमूना

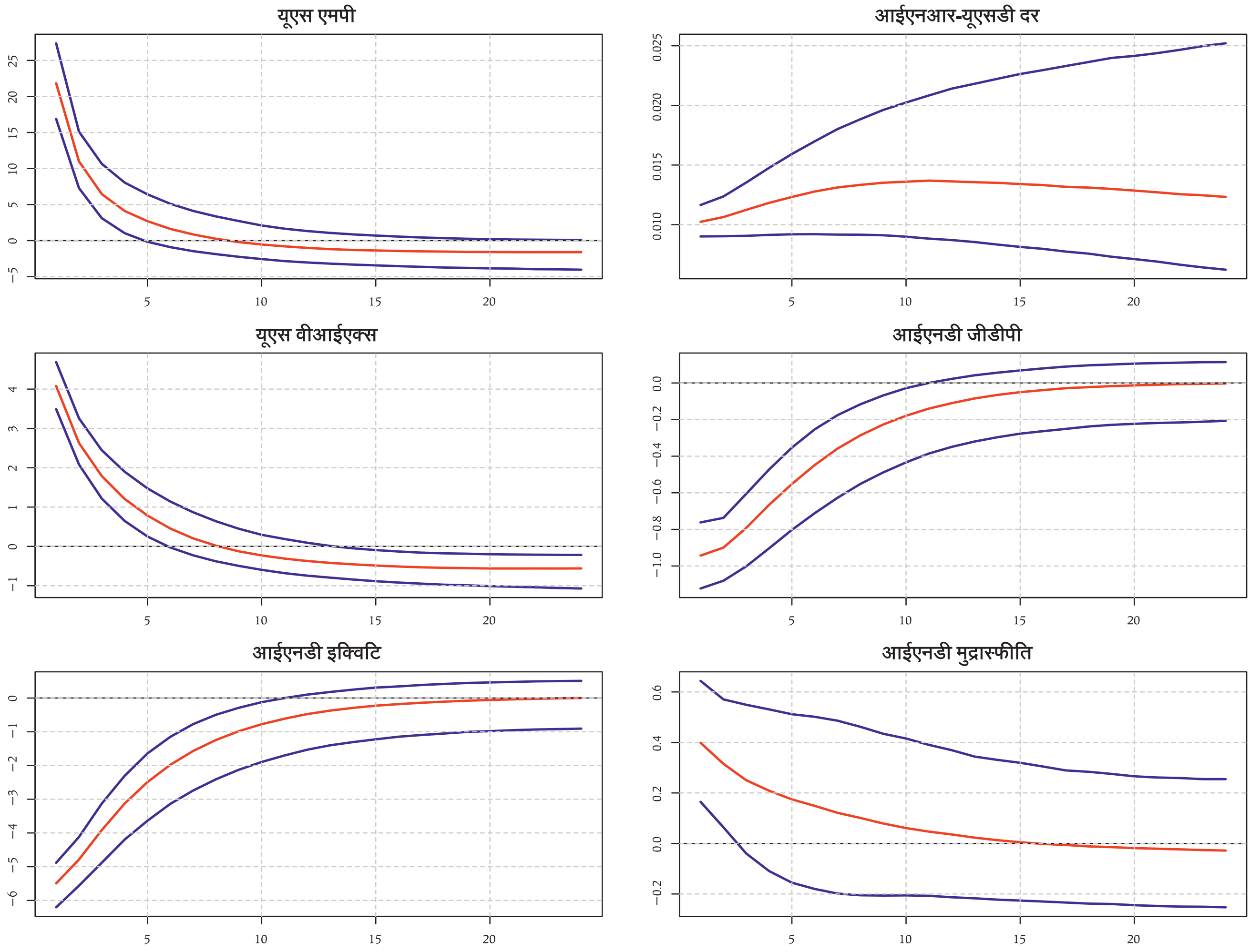

स्रोत : लेखकों की गणना।

V. निष्कर्ष

वैश्विक महामारी के बीच वैश्विक आर्थिक प्रणाली उच्च मुद्रास्फीति की वापसी, भू-राजनीतिक तनाव के कारण बढ़ी अनिश्चितता और दुनिया भर में अति-उदार नीतिगत समर्थन को वापस लिए जाने के कारण आज एक घातक तूफान झेल रही है, जिसने लाखों जीवन और आजीविका को प्रभावित किया है।

इस परिदृश्य में, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए मामले इस तथ्य से और जटिल हो जाते हैं कि उन्हें न केवल घरेलू अर्थव्यवस्था का समर्थन करना है, बल्कि एई के प्रभाव विस्तार से भी खुद को सुरक्षित रखना है। हमारा अध्ययन अमेरिकी मौद्रिक नीतिगत कार्रवाई के साथ-साथ घरेलू अर्थव्यवस्था पर मौद्रिक नीति अनिश्चितता के प्रभावों पर प्रकाश डालने के लिए अमेरिका और भारतीय अर्थव्यवस्था पर तिमाही समष्टि-आर्थिक डेटा का उपयोग करता है। महत्वपूर्ण रूप से, हम दिखाते हैं कि यूएस फेड की मौद्रिक नीति कार्रवाइयों (या अनिश्चितता) का घरेलू व्यापार चक्र पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। दुनिया भर में देखी जा रही तेज नीतिगत सख्ती के संदर्भ में, हमारे पेपर से पता चलता है कि प्रमुख केंद्रीय बैंकों को अपने नीतिगत कार्यों के साथ-साथ संचार के नकारात्मक प्रभाव से सावधान रहना चाहिए। आज की वैश्वीकृत दुनिया में, एक क्षेत्र या देशों के समूह में अस्थिरता महामारी से वैश्विक आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को पटरी से उतार सकती है। इस प्रकार, वैश्विक

अर्थव्यवस्था को और मदद मिलेगी यदि प्रमुख केंद्रीय बैंक अपने भविष्य के नीति पथ पर पारदर्शी संचार के माध्यम से अपने नीतिगत कार्रवाईयों के कारण होने वाले व्यवधानों को कम करने का प्रयास करते हैं।

संदर्भ

Adrian, T., Crump, R. K. & Moench, E. (2013). Pricing the Term Structure with Linear Regressions. Journal of Financial Economics, Pages 110-138, October.

Agénor, P. R., Alper, K., & da Silva, L. P. (2018). External shocks, financial volatility and reserve requirements in an open economy. *Journal of International Money and Finance*, *83*, 23-43.

Arezki, R., & Liu, Y. (2020). On the (Changing) asymmetry of global spillovers: Emerging markets vs. advanced economies. *Journal of International Money and Finance*, *107*, 102219.

Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Measuring economic policy uncertainty. *The quarterly journal of economics*, 131(4), 1593-1636.

Banerjee, S., & Basu, P. (2016). Indian economy during the era of quantitative easing: A dynamic stochastic general equilibrium perspective. In *Monetary Policy in India* (pp. 549580). Springer, New Delhi.

Banerjee, S., & Mohanty, M. S. (2021). *US monetary policy and the financial channel of the exchange rate: evidence from India.* BIS Working Paper No. 945, Monetary and Economic Department, Bank for International Settlements, Geneva, Switzerland.

Danne, Christian, 2015. "VARsignR: Estimating VARs using sign restrictions in R," *MPRA Paper 68429*, University Library of Munich, Germany.

D'Auria, F., Linden, S., Monteiro, D., & Zeugner, S. (2014). Cross-border spillovers in the euro area. *Quarterly Report on the Euro Area (QREA)*, *13*(4), 7-22.

Dées, S., & Galesi, A. (2021). The Global Financial Cycle and US monetary policy in an interconnected world. *Journal of International Money and Finance*, *115*, 102395.

Eichengreen, B., & Gupta, P. (2015). Tapering talk: The impact of expectations of reduced Federal Reserve security purchases on emerging markets. *Emerging Markets Review*, *25*, 1-15.

Eichengreen, B., Gupta, P., & Choudhary, R. (2022). The Taper This Time. *Indian Public Policy Review*, *3*(1 (Jan-Feb)), 1-17.

Georgiadis, G. (2017). To bi, or not to bi? Differences between spillover estimates from bilateral and multilateral multi-country models. *Journal of International Economics*, *107*, 118.

Habib, M. M. & Venditti, F. (2019). The Global Capital Flows Cycle: Structural Drivers and Transmission Channels. *Working Paper Series*, European Central Bank, May.

Hoek, J., Kamin, S. B., & Yoldas, E. (2020). When is bad news good news? US monetary policy, macroeconomic news, and financial conditions in emerging markets. *International Finance Discussion Paper* No. 1269, Board of Governors of the Federal Reserve System, USA.

Hoek, J., Yoldas, E., & Kamin, S. (2021). Are Rising US Interest Rates Destabilizing for Emerging Market Economies?. FEDS Notes June 2021, Board of Governors of the Federal Reserve System, USA.

IMF (2021). World Economic Outlook, April 2021. International Monetary Fund, Washington, USA.

Jordà, Ò., Schularick, M., Taylor, A. M., & Ward, F. (2019). Global financial cycles and risk premiums. *IMF Economic Review*, *67*(1), 109-150.

Lakdawala, A. (2021). The growing impact of US monetary policy on emerging financial markets: Evidence from India. *Journal of International Money and Finance*, *119*, 102478.

Miranda-Agrippino, S., & Rey, H. (2020). US monetary policy and the global financial cycle. *The Review of Economic Studies*, *87*(6), 2754-2776.

Miranda-Agrippino, S., Nenova, T. & Rey, H. (2020). Global Footprints of Monetary Policy. Discussion Papers, Centre for Macroeconomics (CFM).

Patra, M. D., Khundrakpam, J. K., Gangadaran, S., Kavediya, R., & Anthony, J. M. (2016). Responding to QE taper from the receiving end. *Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies*, *9*(2), 167-189.

Patra, M. D., Pattanaik, S., John, J., & Behera, H. K. (2016). Monetary policy transmission in India: Do global spillovers matter?. *Reserve Bank Occasional Papers*, *37*(1&2), Reserve Bank of India, Mumbai, India.

Patra, M.D. (2022). Taper 2022: Touchdown in Turbulence. Keynote Address at the IMC Chamber of Commerce and Industry, Mumbai, March 11, 2022, Reserve Bank of India, Mumbai.

Pierre-Richard, A., & Pereira da Silva Luiz, A. (2022). Financial spillovers, spillbacks, and the scope for international macroprudential policy coordination. *International Economics and Economic Policy*, 79-127.

RBI. (2010). Report on Currency and Finance, Reserve Bank of India, Mumbai, India.

RBI. (2023). Monetary Policy Statement delivered by Governor Shri Shaktikantha Das, Reserve Bank of India on February 08, 2023 in Mumbai, India.

Rey, H. (2013). Dilemma not Trilemma: The Global Financial Cycle and Monetary Policy Independence. Proceedings - Economic Policy Symposium - Jackson Hole, Federal Reserve of Kansas City Economic Symposium, Pages 285-333.

Rey, H. (2018). National Monetary Authorities and the Global Financial Cycle. *Lecture delivered at the Sixteenth LK Jha Memorial Lecture*, Reserve Bank of India, Mumbai.

Uhlig, H. (2005). What are the effects of monetary policy on output? Results from an agnostic identification procedure. *Journal of Monetary Economics*, *52*(2), 381-419.

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

अवसरिक श्रृंखला

विषय-वस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	143
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	144
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	145
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय	146
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	147
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	147
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	148
7	मुद्रा स्टॉक (एम$_3$) के स्रोत	149
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	150
9	कुल चलनिधि राशियां	150
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	151
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	151
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	152
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	152
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	153
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	154
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	155
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	156
	कीमत और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)	157
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	157
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	157
21	थोक मूल्य सूचकांक	158
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)	162
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	162
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	163
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	163
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	164
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	165
28	वाणिज्यिक पत्र	165
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	165
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	166

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	167
32	विदेशी मुद्रा भंडार	167
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	167
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	168
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	168
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	169
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)- पंजीकरण	170
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	171
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (₹ करोड़)	172
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	173
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (₹ करोड़)	174
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	175
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	176
	अवसरिक श्रृंखला	
44	लघु बचत	178
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	179
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	180
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	181
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	182
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	183
50 (ए)	हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार	184
50 (बी)	हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक	187

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।
– = शून्य/नगण्य
प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2021-22	2021-22		2022-23	
		ति1	ति2	ति1	ति2
	1	2	3	4	5
1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	8.1	18.1	8.3	12.7	5.6
1.1.1 कृषि	3.0	2.2	3.2	4.5	4.6
1.1.2 उद्योग	9.8	40.4	6.6	6.0	-3.1
1.1.3 सेवाएं	8.8	15.5	10.0	17.5	9.0
1.1ए अंतिम खपत व्यय	7.0	10.2	10.2	21.3	7.7
1.1बी सकल नियत पूंजी निर्माण	15.8	62.5	14.6	20.1	10.4
	2021-22	2021		2022	
		नवं.	दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	11.4	1.0	1.0	7.3	4.3
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	8.9	8.9	10.3	9.8	9.2
2.1.2 ऋण	9.6	6.9	9.3	17.3	14.9
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	9.7	7.1	9.4	17.7	15.3
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	6.0	3.6	2.8	10.7	10.6
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	13.0	12.8	14.7	11.0	10.3
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	8.8	9.5	11.4	8.9	8.7
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	4.50	4.50
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.7	4.8	5.0	5.3	5.3
3.4 ऋण-जमा अनुपात	72.2	71.0	71.3	75.0	75.0
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	77.2	37.3	56.1	128.6	111.5
3.6 निवेश-जमा अनुपात	28.7	29.0	28.4	29.3	28.7
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	19.7	17.7	12.9	39.7	28.9
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	4.00	4.00	4.00	5.90	6.25
4.2 स्थायी रिवर्स रिपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़) दर*	-	-	-	5.65	6.00
4.4 सीमांत स्थायी सुविधा दर	4.25	4.25	4.25	6.15	6.50
4.5 बैंक दर	4.25	4.25	4.25	6.15	6.50
4.6 आधार दर	7.25/8.80	7.30/8.80	7.25/8.80	8.10/8.80	8.10/9.40
4.7 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	6.45/7.00	6.50/7.00	6.50/7.00	7.05/8.05	7.30/8.15
4.8 मीयादी जमा दर>1 वर्ष	5.00/5.60	4.90/5.50	4.90/5.60	6.10/7.25	6.00/7.25
4.9 बचत जमा दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
4.10 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	3.34	3.35	3.32	6.13	6.38
4.11 91-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	3.84	3.53	3.66	6.40	6.31
4.12 182-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	4.27	3.83	3.97	6.73	6.74
4.13 364-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	4.58	4.13	4.27	6.87	6.89
4.14 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	6.86	6.33	6.47	7.29	7.34
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमियम					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	76.18	74.71	74.30	81.53	82.79
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	84.01	83.85	84.05	84.87	88.15
5.3 अमेरिकी डॉलर का वायदा प्रीमिआ 1-माह (%)	5.67	3.69	3.96	2.21	2.17
3-माह (%)	4.46	3.80	4.15	2.16	2.17
6-माह (%)	4.10	4.71	4.71	2.26	2.22
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.51	4.9	5.7	5.9	5.7
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.13	4.8	5.6	5.4	5.5
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	12.97	14.9	14.3	5.8	5.0
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	10.25	10.2	13.8	5.5	2.4
6.3.2 ईंधन और पावर	32.50	44.4	38.1	17.4	18.1
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	11.10	12.3	10.7	3.6	3.4
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	55.43	56.8	40.5	9.8	-0.2
7.2 निर्यात	44.62	34.6	44.3	9.7	-3.1

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिज़र्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसार शुरू किया है ।

*: 8 अप्रैल 2022 दिनांकित प्रेस अधिसूचना सं.2022-2023/41के अनुसार।

#: 3 दिसंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 तक सभी पखवाड़ों के लिए बैंक ऋण वृद्धि और संबंधित अनुपात को चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए समायोजित किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2021-22	2022		2023			
		जन.	दिसं. 30	जन. 6	जन. 13	जन. 20	जन. 27
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	3107637	3004604	3203051	3225329	3252059	3249112	3261992
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	15	16	15	13	10	19	19
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	**3107652**	**3004619**	**3203066**	**3225342**	**3252070**	**3249132**	**3262010**
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	128208	114864	129184	130632	131852	134029	135652
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2978927	2889257	3073515	3094378	3119720	3114638	3125922
1.2.3 रुपया सिक्का	518	498	367	333	497	465	436
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	–	–	–	–	–	–	–
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	1794574	1929291	1439225	1399746	1344611	1341640	1374659
2.1.1.1 केंद्र सरकार	101	100	100	100	101	101	101
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	683437	681336	841612	830148	800904	861612	813573
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7123	7560	8648	9055	8317	8452	8592
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4121	3766	4403	4520	4450	4443	4337
2.1.1.7 अन्य बैंक	37589	36681	45114	44305	44847	44728	44453
2.1.1.8 अन्य	988819	1139410	457383	425587	407855	350431	429497
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	73343	60395	81922	85989	78095	71830	74063
2.1.2 अन्य देयताएं	1359254	1300073	1506375	1496017	1515004	1517021	1543823
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	**3153828**	**3229365**	**2945600**	**2895763**	**2859616**	**2858662**	**2918482**
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	15	16	15	13	10	19	19
2.2.2 विदेश में रखे शेष	1243853	1387051	1075884	1040773	1020375	1021574	1052101
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.2 राज्य सरकारें	670	716	4450	17380	16688	19058	16745
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	94299	94286	127472	96723	95937	96401	121622
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.6 नाबार्ड	24927	24770	–	–	–	–	–
2.2.3.7 एक्जिम बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.8 अन्य	8077	811	17789	16125	1662	3469	9175
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	72741	30404	81790	86108	78656	72197	74372
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.4.2 सरकारी खज़ाना बिल	–	–	–	–	–	–	–
2.2.5 निवेश	1491042	1497144	1409345	1407260	1412703	1408700	1404238
2.2.6 अन्य आस्तियां	218203	194167	228855	231380	233584	237243	240211
2.2.6.1 स्वर्ण	201354	181597	212643	215026	217034	220617	223290

*: डेटा अनंतिम है।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिसं. 1, 2022	-	-	-	-	0	220379	–	790	-	-221169
दिसं. 2, 2022	-	-	-	31234	987	246265	–	1640	-	-278152
दिसं. 3, 2022	-	-	-	-	563	13987	–	-	-	-13424
दिसं. 4, 2022	-	-	-	-	7	3257	–	-	-	-3250
दिसं. 5, 2022	-	-	-	-	518	227361	-	1875	-	-228718
दिसं. 6, 2022	-	-	-	-	7	158653	-	945	-	-159591
दिसं. 7, 2022	-	-	-	-	13	229671	-5000	1125	-	-235783
दिसं. 8, 2022	-	-	-	-	29	208605	-625	-	-	-209201
दिसं. 9, 2022	-	-	-	-	5	219063	-3400	290	-	-222748
दिसं. 10, 2022	-	-	-	-	42	5790	-	-	-	-5748
दिसं. 11, 2022	-	-	-	-	59	7336	-	-	-	-7277
दिसं. 12, 2022	-	-	-	-	35	204788	–	370	-	-205123
दिसं. 13, 2022	-	-	-	-	2969	208870	–	135	-	-206036
दिसं. 14, 2022	-	-	-	-	215	177306	–	1285	-	-178376
दिसं. 15, 2022	-	-	-	-	39	162303	565	1360	-	-163059
दिसं. 16, 2022	-	-	-	13453	21103	65736	3000	-	-	-55086
दिसं. 17, 2022	-	-	-	-	930	17563	–	-	-	-16633
दिसं. 18, 2022	-	-	-	-	5	2432	–	-	-	-2427
दिसं. 19, 2022	-	-	-	-	5645	54697	3129	-	-	-45923
दिसं. 20, 2022	-	-	-	-	7091	69829	2966	-	-	-59772
दिसं. 21, 2022	-	-	-	-	2449	46987	-61	-	-	-44599
दिसं. 22, 2022	-	-	-	-	937	59487	–	-	-	-58550
दिसं. 23, 2022	-	-	-	-	2101	61426	-450	5	-	-59780
दिसं. 24, 2022	-	-	-	-	54	17846	–	-	-	-17792
दिसं. 25, 2022	-	-	-	-	25	3066	–	-	-	-3041
दिसं. 26, 2022	-	-	-	-	406	75574	–	-	-	-75168
दिसं. 27, 2022	-	-	-	-	279	82556	-505	-	-	-82782
दिसं. 28, 2022	-	-	-	-	8901	98806	–	-	-	-89905
दिसं. 29, 2022	-	-	-	-	5440	86536	506	-	-	-80590
दिसं. 30, 2022	-	-	-	27084	33224	120779	–	-	-	-114639
दिसं. 31, 2022	-	-	-	-	269	50364	-	-	-	-50095

एसडीएफ़: स्थायी जमा सुविधा, एमएसएफ़: सीमांत स्थायी सुविधा।

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/ विक्रय

i) ओटीसी सेगमेन्ट में परिचालन

मद	2021-22	2021	2022	
		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	17312	-2917	4361	3842
1.1 क्रय (+)	113991	7475	22281	12817
1.2 विक्रय (-)	96679	10392	17920	8975
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (₹ करोड़)	134629	-20809	33929	29295
3 संचयी (मार्च के के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	17312	37413	-29978	-26136
(₹ करोड़)	134629	285996	-249702	-220407
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	65791	49106	8493	10968

ii) मुद्रा वायदा खंड में परिचालन

मद	2021-22	2021	2022	
		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	2370	0	10	0
1.2 विक्रय (-)	2370	0	10	0
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	0	0	0	(-)150

सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	30 दिसंबर 2022 की स्थिति		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	1140	5473	-4333
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	3806	125	3681
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	7731	1246	6485
4. 1 वर्ष से अधिक	5135	0	5135
कुल (1+2+3+4)	**17812**	**6844**	**10968**

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(₹ करोड़)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2021-22	2022						2023
		जन. 28	अग. 26	सितं. 23	अक्टू. 21	नवं. 18	दिसं. 30	जन. 27
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	11	38	4034	9657	51134	3250	33224	27370
2 अनुसूचित बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुर्नवित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
3.2 बकाया	–	734	0	910	1022	1801	2376	1675
4. अन्य								
4.1 सीमा	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000
4.2 बकाया	32401	24401	40159	31039	20249	10850	15400	7500
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	32412	25173	44193	41606	72405	15901	51000	36545

टिप्पणी: 1. अन्य को विशेष पुनर्वित्त सुविधा अर्थात एक्ज़िम बैंक को 22 मई 2020 से पुनः शुरू कर दिया।

2. अन्य के लिए पुनर्वित सुविधा, अर्थात आरबीआई अधिनियम 1934 के नाबार्ड/ सिडबी/एनएचबी यू /एस 17 (4 एच), 17 अप्रैल 2020 से।

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा भंडार उपाय

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2021-22	2021	2022		
		दिसं. 31	नवं. 18	दिसं. 16	दिसं. 30
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	3035689	2881115	3093618	3127695	3122236
1.1 संचलन में नोट	3105703	2959237	3189066	3211867	3203037
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	27270	26921	28469	28641	28857
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	98028	105786	124807	113734	110416
2 जनता की जमाराशियां	2271436	2257098	2262770	2237429	2404868
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	2212992	2206052	2192060	2173283	2341936
2.2 रिज़र्व बैंक के पास ‘अन्य’ जमाराशियां	58444	51045	70709	64145	62932
3 एम$_1$ (1 + 2)	**5307125**	**5138213**	**5356388**	**5365124**	**5527104**
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	188433	179437	196440	196440	196440
5 एम$_2$ (3 + 4)	**5495558**	**5317650**	**5552828**	**5561564**	**5723544**
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	15186605	14975823	16043534	16119395	16332131
7 एम$_3$ (3 + 6)	**20493729**	**20114036**	**21399921**	**21484519**	**21859235**
8 कुल डाकघर जमाराशियां	1012241	969847	1088490	1088490	1088490
9 एम$_4$ (7 + 8)	**21505970**	**21083883**	**22488411**	**22573009**	**22947725**

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम$_3$) का स्रोत

(₹ करोड़)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2021	2022		
		दिसं. 31	नवं. 18	दिसं. 16	दिसं. 30
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	**6477629**	**6100716**	**6612762**	**6525131**	**6565472**
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1450596	1194335	1226047	1097957	1170253
1.1.1 सरकार पर दावे	1490991	1526753	1423456	1422205	1412098
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1489324	1520076	1417773	1410153	1407648
1.1.1.2 राज्य सरकारें	1667	6677	5683	12052	4450
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियां	40394	332418	197409	324248	241845
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	40352	332375	197366	324205	241802
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	5027033	4906381	5386715	5427174	5395219
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	**12616520**	**12290942**	**13679367**	**13888869**	**14045877**
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	16571	2094	14661	14282	19852
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	12599950	12288848	13664706	13874587	14026025
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	11891314	11582087	12947813	13154442	13305854
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	690201	688991	699569	702806	702681
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	18435	17769	17324	17339	17491
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	**4854063**	**4849508**	**4571803**	**4761560**	**4746428**
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	4442479	4550652	4316211	4505968	4490835
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	4442720	4550897	4316456	4506213	4491094
3.1.2 विदेशी देयताएं	241	245	246	246	259
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	411583	298856	255593	255593	255593
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	**28013**	**27664**	**29212**	**29384**	**29600**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	**3482496**	**3154794**	**3493223**	**3720427**	**3528143**
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1308500	1307042	1381545	1511272	1494789
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	2173996	1847752	2111678	2209154	2033355
एम$_3$ (1+2+3+4-5)	**20493729**	**20114036**	**21399921**	**21484519**	**21859235**

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2021	2022		
		दिसं. 31	नवं. 18	दिसं. 16	दिसं. 30
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	5307125	5138213	5356388	5365124	5527104
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	12081049	11814053	12512152	12550677	12807909
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	20634885	20243385	21732947	21794816	22147115
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	3035689	2881115	3093618	3127695	3122236
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	17266157	17041253	18093758	18141179	18521503
1.2.1 मांग जमाराशियां	2212992	2206052	2192060	2173283	2341936
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	15053166	14835201	15901698	15967895	16179568
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	6773925	6675840	7155764	7185553	7280805
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	176718	84894	252530	274311	291491
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	8279241	8159360	8745934	8782342	8898762
1.3 आरबीआई के पास ‘अन्य’ जमाराशियां	58444	51045	70709	64145	62932
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	274594	269971	474861	461797	440444
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	20080599	19381230	21384192	21525125	21705225
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	6477629	6100716	6612762	6525131	6565472
2.1.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1450596	1194335	1226047	1097957	1170253
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	5027033	4906381	5386715	5427174	5395219
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	13602969	13280514	14771430	14999993	15139752
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई ऋण	39581	26864	14661	14282	19852
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	13563389	13253650	14756769	14985711	15119900
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	952181	958477	1069274	1086427	1073325
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	28013	27664	29212	29384	29600
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4705191	4753021	4471445	4580773	4595397
2.3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4442479	4550652	4316211	4505968	4490835
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	262711	202369	155234	74805	104562
2.4 पूंजी खाता	3021858	2976677	3404225	3501354	3507288
2.5 अन्य मदें (निवल)	1157060	941854	747678	839112	675819

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(₹ करोड़)

समुच्चय	2021-22	2021	2022		
		दिसं.	अक्टू.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
1 एन एम$_3$	**20630753**	**20243385**	**21712620**	**21732947**	**22147115**
2 डाकघर जमाराशियां	596588	572353	594633	594633	594633
3 एल$_1$ (1 + 2)	**21227341**	**20815738**	**22307253**	**22327580**	**22741748**
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	49578	24644	58446	58400	65601
4.1 सावधि मुद्रा उधार	1824	1984	1518	1423	963
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	39170	15360	49270	49270	56570
4.3 सावधि जमाराशियां	8584	7299	7657	7706	8069
5 एल$_2$ (3 + 4)	**21276919**	**20840382**	**22365698**	**22385979**	**22807349**
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	70564	66542	..	..	78061
7 एल$_3$ (5 + 6)	**21347483**	**20906924**	..	..	**22885411**

टिप्पणी : 1. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2021	2022		
		दिसं. 31	नवं. 18	दिसं. 16	दिसं. 30
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	3133716	2986901	3218425	3241429	3232652
1.2 आरबीआई के पास बैंकरों की जमाराशियां	876726	764828	869931	867014	899777
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	823632	716432	814570	810927	841612
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियां	58444	51045	70709	64145	62932
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	4068887	3802775	4159065	4172588	4195361
2 स्रोत					
2.1 आरबीआई के देशी ऋण	906895	531501	1195188	1148509	1169715
2.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1450596	1194335	1226047	1097957	1170253
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल आरबीआई ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	1448972	1187700	1220407	1085948	1165846
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	–	–	–	–	–
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	–	–	–	–	–
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1488816	1519509	1417416	1409918	1407281
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1488816	1519509	1417416	1409918	1407281
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	508	567	357	235	367
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	40352	332375	197366	324205	241802
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल आरबीआई ऋण	1624	6634	5641	12009	4408
2.1.2 बैंकों पर आरबीआई के दावे	-583282	-689698	-45520	36270	-20391
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	-560272	-664928	-45520	36270	-20391
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई के ऋण	39581	26864	14661	14282	19852
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	–	–	1801	1741	2376
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	23010	24770	–	–	–
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	28013	27664	29212	29384	29600
2.3 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4442479	4550652	4316211	4505968	4490835
2.3.1 सोना	322213	292779	326887	336282	341827
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4120283	4257890	3989341	4169703	4149026
2.4 पूंजी खाता	1254092	1221533	1480042	1574332	1580164
2.5 अन्य मदें (निवल)	54408	85509	-98496	-63060	-85375

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	2021-22	मार्च 31 /माह के अंतिम शुक्रवारों/शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2021	2022				
		दिसं. 24	दिसं. 2	दिसं. 9	दिसं. 16	दिसं. 23	दिसं. 30
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	4068887	3744266	4150211	4144023	4172588	4174957	4195361
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	3133716	2996038	3221993	3244575	3241429	3242470	3232652
1.2 आरबीआई के पास बैंकरों की जमाराशियां	876726	697251	862988	835124	867014	868177	899777
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियां	58444	50977	65231	64325	64145	64310	62932
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1450596	1091480	1318497	1264172	1097957	1106385	1170253
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-560272	-622634	-182157	-155913	36270	21544	-20391
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	16571	2130	19799	10694	14282	19849	19852
2.4 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4442479	4595536	4403884	4479156	4505968	4497489	4490835
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	28013	27539	29384	29384	29384	29384	29600
2.6 आरबीआई की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1308500	1349785	1439196	1483470	1511272	1499694	1494789

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवारों/ माह के रिपोर्टिंग शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2021	2022		
		दिसं. 31	नवं. 18	दिसं. 16	दिसं. 30
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	16331874	16101231	17155518	17202880	17581221
1.1.1 मांग जमाराशियां	2072747	2066651	2050865	2032432	2201751
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	14259128	14034581	15104653	15170448	15379470
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	6416607	6315561	6797094	6826702	6920761
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी)	176718	84894	252530	274311	291491
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	7842520	7719019	8307559	8343746	8458708
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	274594	269971	474861	461797	440444
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	17575002	17146425	19117789	19384474	19487073
2.1.1 सरकार को ऋण	4728179	4607365	5085790	5126768	5095190
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	12846823	12539060	14031999	14257705	14391883
2.1.2.1 बैंक ऋण	11891314	11582087	12947813	13154442	13305854
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	11836304	11493407	12895573	13099868	13251881
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	11522	6589	23052	24960	20813
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	769	869	822	838	854
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	943218	949514	1060312	1077464	1064363
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	262711	202369	155234	74805	104562
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	465464	417913	367987	294204	332964
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	133439	140623	141836	151499	152563
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	69314	74921	70916	67900	75839
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	1268887	1475543	972531	876263	960618
2.3.1 आरबीआई के पास शेष	683437	716432	814570	810927	841612
2.3.2 उपलब्ध नकदी	85926	94182	112441	101606	98615
2.3.3 आरबीआई से ऋण और अग्रिम	-499524	-664928	-45520	36270	-20391
2.4 पूंजी खाता	1743595	1730974	1900013	1902851	1902953
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	756537	722161	715162	768015	627636
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	571535	557811	638855	688438	676799
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	26533	29768	17359	28347	29580

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(₹ करोड़)

मद	25 मार्च 2022 की स्थिति	2021	2022		
		दिसं. 31	नवं. 18	दिसं. 16	दिसं. 30
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	4728948	4608235	5086612	5127607	5096044
2 अन्य सरकारी प्रतिभूतियां (गैर-एसएलआर)	-	-	172062	187971	170410
3 वाणिज्यिक पत्र	55315	53140	58106	51418	54045
4 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
4.1 सरकारी उद्यम	7642	8397	9512	9420	9402
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	73814	73060	70661	70695	70997
4.3 अन्य	5152	5007	4910	4853	4881
5 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
5.1 सरकारी उद्यम	117860	115386	99952	100708	102017
5.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	326188	341692	324422	328748	326724
5.3 अन्य	148753	147470	94250	89445	98504
6 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
6.1 म्यूचुअल फंड	34404	38153	40974	46345	36748
6.2 वित्तीय संस्थाएं	174090	167086	185463	187863	190633

टिप्पणी : कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के डेटा अंतिम हैं, और कॉलम (4) एवं (5) के डेटा अनंतिम हैं।
'-' डेटा उपलब्ध नहीं हैं।

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(₹ करोड़)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2021-22	2021	2022		2021-22	2021	2022	
		दिसं.	नवं.	दिसं.		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6	7	8
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	212	212	212	212	136	136	137	137
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	**262674**	**254662**	**322059**	**329579**	**258649**	**250071**	**318826**	**326294**
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	194143	190557	200485	220832	190570	186315	197978	218463
1.2 बैंकों से उधार राशि	38369	37900	67257	51598	38317	37883	67114	51284
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	30162	26204	54317	57150	29762	25873	53734	56548
2 अन्य के प्रति देयताएं	**17832517**	**17590424**	**18946352**	**19369144**	**17380755**	**17144557**	**18508511**	**18926865**
2.1 कुल जमाराशियां	16899634	16670399	17749945	18157327	16465313	16241854	17329371	17733784
2.1.1 मांग	2117513	2109712	2123876	2245951	2072747	2066651	2078973	2201751
2.1.2 मीयादी	14782121	14560688	15626069	15911376	14392567	14175203	15250398	15532033
2.2 उधार	278985	274394	500784	445126	274594	269971	495442	440444
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	653898	645630	695623	766691	640848	632732	683697	752638
3 रिज़र्व बैंक से उधार	**94299**	**102489**	**96704**	**127472**	**94299**	**102489**	**96669**	**127472**
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अन्य	94299	102489	96704	127472	94299	102489	96669	127472
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	788725	830772	936542	962644	769363	810615	915324	940227
4.1 उपलब्ध नकदी	88732	96489	109526	101119	85926	94182	106483	98615
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	699993	734284	827015	861524	683437	716432	808841	841612
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	**315282**	**288521**	**375572**	**382420**	**243637**	**226892**	**317123**	**317527**
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	199434	192939	240469	230710	164240	156132	199953	190298
5.1.1 चालू खाते में	19733	19597	38399	23357	16691	16055	35353	19998
5.1.2 अन्य खातों में	179701	173342	202070	207353	147549	140077	164599	170301
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	36905	32002	25749	38501	6982	12048	11935	18843
5.3 बैंकों को अग्रिम	39340	30206	46031	47615	35802	28572	45530	45874
5.4 अन्य आस्तियां	39603	33373	63324	65595	36613	30139	59706	62511
6 निवेश	**4874070**	**4752766**	**5217161**	**5241312**	**4728948**	**4608235**	**5072239**	**5096044**
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	4867102	4745699	5210634	5234523	4728179	4607365	5071422	5095190
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	6968	7067	6527	6789	769	869	817	854
7 बैंक ऋण	**12259048**	**11938940**	**13386156**	**13695835**	**11891314**	**11582087**	**13002265**	**13305854**
7ए खाद्यान्न ऋण	90827	124496	100376	99690	55011	88680	54657	53972
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	12016486	11716596	13152140	13454349	11651337	11361984	12771064	13067327
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	36070	34172	33936	35326	36055	34159	33918	35310
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	155796	136359	155857	159217	154212	135027	153738	156955
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	19537	20865	16315	18911	19157	20446	16148	18727
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	31160	30947	27908	28033	30554	30471	27397	27535

टिप्पणी : कॉलम (4) एवं (8) के डेटा अनंतिम हैं।

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(₹ करोड़)

क्षेत्र	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 25, 2022	2021	2022		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		दिसं. 31	नवं. 18	दिसं. 30	2022-23	2022
	1	2	3	4	%	%
I. सकल बैंक ऋण (II+III)	**11891314**	**11582087**	**12947813**	**13304393**	**11.9**	**14.9**
II. खाद्यान्न ऋण	**55011**	**88679**	**52239**	**53972**	**-1.9**	**-39.1**
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	**11836304**	**11493408**	**12895574**	**13250421**	**11.9**	**15.3**
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां	**1461719**	**1462086**	**1595185**	**1630871**	**11.6**	**11.5**
2. उद्योग	**3156067**	**3027972**	**3294514**	**3291537**	**4.3**	**8.7**
2.1 सूक्ष्म और लघु[1]	532792	509395	556127	579070	8.7	13.7
2.2 मझौले	213996	205853	224624	237564	11.0	15.4
2.3 बड़े	2409279	2312723	2513763	2474903	2.7	7.0
3. सेवाएं	**3017258**	**2931207**	**3315747**	**3504664**	**16.2**	**19.6**
3.1 परिवहन परिचालक	155352	147467	161037	164451	5.9	11.5
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	20899	21049	21210	22404	7.2	6.4
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	64378	63457	65092	63588	-1.2	0.2
3.4 शिपिंग	8436	7475	7206	7307	-13.4	-2.2
3.5 नौवहन	23979	14420	24445	28930	20.6	100.6
3.6 पेशेवर सेवाएं	116742	112954	124321	126739	8.6	12.2
3.7 व्यापार	696301	675374	733730	768167	10.3	13.7
3.7.1 थोक व्यापार	351213	343121	353789	376414	7.2	9.7
3.7.2 खुदरा व्यापार	345088	332253	379941	391753	13.5	17.9
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	291168	294019	304276	309031	6.1	5.1
3.9 गैर -बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)[2] जिसमें से	1022399	974300	1218791	1320299	29.1	35.5
3.9.1 आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	282048	267204	307661	311071	10.3	16.4
3.9.2 सरकारी वित्तीय संस्थाएं (पीएफआई)	137084	108726	178024	181330	32.3	66.8
3.10 अन्य सेवाएं [3]	617603	620693	655639	693750	12.3	11.8
4 वैयक्तिक ऋण	**3381699**	**3274532**	**3800330**	**3935144**	**16.4**	**20.2**
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	27628	25102	35658	36640	32.6	46.0
4.2 आवास	1684424	1634687	1843862	1898411	12.7	16.1
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	78730	80026	96188	109937	39.6	37.4
4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	6161	5968	6758	6806	10.5	14.0
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	147789	141751	173424	180090	21.9	27.0
4.6 शिक्षा	82723	81933	91069	92754	12.1	13.2
4.7 वाहन ऋण	402689	388737	468088	484747	20.4	24.7
4.8 सोने के आभूषण पर ऋण	73942	75761	83755	84256	13.9	11.2
4.9 अन्य वैयक्तिक ऋण	877613	840568	1001529	1041502	18.7	23.9
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र *(मेमो)*						
(i) कृषि और संबद्ध गतिविधियां[4]	1484923	1457894	1631458	1673097	12.7	14.8
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम[5]	1377848	1372858	1457114	1526256	10.8	11.2
(iii) मध्यम उद्यम [6]	351900	340564	369403	386473	9.8	13.5
(iv) आवास	616814	587417	613395	617924	0.2	5.2
(v) शिक्षा ऋण	58118	59599	58887	58998	1.5	-1.0
(vi) नवीकरणीय ऊर्जा	3538	2112	4177	4782	35.2	126.5
(vii) सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर	2483	2650	2394	2473	-0.4	-6.7
(viii) निर्यात ऋण	23621	25954	15506	15673	-33.6	-39.6
(ix) अन्य	37159	39615	50219	52093	40.2	31.5
(x) नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1180928	1141715	1361042	1381194	17.0	21.0

टिप्पणी : 1. डेटा अनंतिम हैं। सकल बैंक ऋण और गैर -खाद्य ऋण का डाटा धारा -42 रिटर्न पर आधारित है, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (एससीबी) शामिल किया गया है, जब कि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्र-वार पर और उद्योग-वार बैंक ऋण(एसआईबीसी) रिटर्न, के आधार पर हैं। जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कुल खाद्येतर ऋण के लगभग 93 प्रतिशत के चुनिंदा बैंकों को समाविष्ट किया गया है। टिप्पणी 2: जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और वृद्धि दर में कुछ बदलाव हुए हैं। टिप्पणी 3: चुनिंदा एससीबी द्वारा पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए बैंकों की ऋण वृद्धि को समायोजित किया जाता है।

1. एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
2. अन्य सेवाओं के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
3. कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यकलापों के अंतर्गत प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल है।
4. सूक्ष्म और लघु उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋणऔर पीएसएलसी भी शामिल हैं।
5. 'मध्यम उद्यमों' में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल हैं।

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 25, 2022	2021	2022		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		दिसं. 31	नवं. 18	दिसं. 30	2022-23	2022
	1	2	3	4	%	%
2 उद्योग (2.1 से 2.19)	3156067	3027972	3294514	3291537	4.3	8.7
2.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	49135	48973	52338	53331	8.5	8.9
2.2 खाद्य प्रसंस्करण	173246	167771	159064	174703	0.8	4.1
2.2.1 चीनी	26307	21374	16868	17882	–32.0	–16.3
2.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	18246	17944	16710	18806	3.1	4.8
2.2.3 चाय	5728	5993	5985	5419	–5.4	–9.6
2.2.4 अन्य	122965	122459	119501	132596	7.8	8.3
2.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	18176	17351	20057	19974	9.9	15.1
2.4 वस्त्र	224026	217149	211566	217966	–2.7	0.4
2.4.1 सूती वस्त्र	90384	87516	81723	84820	–6.2	–3.1
2.4.2 जूट से बने वस्त्र	3509	2909	3731	3864	10.1	32.8
2.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	38371	37961	38689	39737	3.6	4.7
2.4.4 अन्य वस्त्र	91761	88762	87423	89544	–2.4	0.9
2.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	11573	11213	11311	11629	0.5	3.7
2.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	16294	15852	17697	18418	13.0	16.2
2.7 काग़ज़ और काग़ज़ से बने उत्पाद	40565	40244	41565	42468	4.7	5.5
2.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	107333	107041	148211	163677	52.5	52.9
2.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	196363	187453	215902	217102	10.6	15.8
2.9.1 उवर्रक	33160	30462	33894	33761	1.8	10.8
2.9.2 औषधि और दवाइयां	61093	57744	65792	66499	8.8	15.2
2.9.3 पेट्रो केमिकल्स	19622	21888	23121	21087	7.5	–3.7
2.9.4 अन्य	82486	77360	93095	95755	16.1	23.8
2.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	72013	67527	75954	77626	7.8	15.0
2.11 कांच और कांच के सामान	5952	5921	6607	7117	19.6	20.2
2.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	47910	47949	51177	53224	11.1	11.0
2.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	288531	276737	311249	329646	14.2	19.1
2.13.1 लोहा और स्टील	187584	179811	211112	223934	19.4	24.5
2.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	100946	96926	100137	105712	4.7	9.1
2.14 सभी अभियांत्रिकी	167966	158894	170101	172177	2.5	8.4
2.14.1 इलेक्ट्रानिक्स	38179	38149	40027	39743	4.1	4.2
2.14.2 अन्य	129787	120745	130074	132434	2.0	9.7
2.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	89896	85991	93061	96797	7.7	12.6
2.16 रत्न और आभूषण	80512	72065	73749	77604	–3.6	7.7
2.17 निर्माण	117724	115383	118548	117229	–0.4	1.6
2.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1195027	1137078	1234559	1197256	0.2	5.3
2.18.1 पॉवर	611410	595098	624479	609091	–0.4	2.4
2.18.2 दूरसंचार	130318	109049	128906	114852	–11.9	5.3
2.18.3 सड़क	270395	252608	283074	284203	5.1	12.5
2.18.4 हवाई अड्डा	6646	7583	9072	8956	34.8	18.1
2.18.5 बंदरगाह	8886	9441	8188	7834	–11.8	–17.0
2.18.6 रेलवे	10512	10100	11290	11201	6.6	10.9
2.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	156860	153201	169550	161119	2.7	5.2
2.19 अन्य उद्योग	253823	247379	281798	243592	–4.0	–1.5

टिप्पणी : जनवरी 2019 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(₹ करोड़)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2020-21	2021	2022						
		नवं. 26	सितं. 30	अक्टू. 07	अक्टू. 21	अक्टू. 28	नवं. 04	नवं. 18	नवं. 25
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	33	32	33	33	33	33	33	33
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	**125859.6**	**126631.3**	**124590.8**	**126562.6**	**126803.0**	**126637.1**	**126360.6**	**126894.1**	**127382.3**
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	**23736.9**	**23568.9**	**24874.3**	**26059.9**	**26251.7**	**25889.7**	**25512.5**	**25577.6**	**24931.7**
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	4896.9	5294.8	6051.1	6093.9	6012.5	6211.1	5886.2	5568.0	5197.9
2.1.1.2 अन्य	13,899.4	13473.5	12836.4	14253.5	14361.5	14276.2	14104.1	14228.8	14221.3
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	150.0	699.7	799.6	749.5	399.7	399.9	404.9	624.7
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	4940.6	4650.6	5287.2	4912.9	5128.3	5002.6	5122.2	5376.0	4887.9
2.2 मीयादी देयताएं	**179957.5**	**175629.1**	**172837.7**	**172577.1**	**171821.7**	**171886.4**	**171587.7**	**171549.2**	**172191.9**
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	65333.7	59386.8	56993.6	55836.1	54914.6	55727.0	54916.2	54040.1	54088.1
2.2.1.2 अन्य	111960.2	113157.7	111754.4	112309.1	112441.5	112360.9	112256.5	112665.3	113161.0
2.2.2 बैंकों से उधार	630.0	910.1	1580.1	2080.1	2120.1	1441.3	2016.3	2433.3	2519.3
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	2033.7	2174.4	2509.7	2351.8	2345.5	2357.3	2398.6	2410.4	2423.5
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	63559.8	62398.8	70718.0	70049.4	68792.2	76583.1	75852.3	73458.8	73686.9
4.1 मांग	15691.8	12380.4	13633.4	13623.2	16862.7	15999.9	15799.9	15528.3	15498.3
4.2 मीयादी	47868.0	50018.4	57084.6	56426.3	51929.6	60583.2	60052.4	57930.5	58188.6
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	**8151.1**	**9075.7**	**10969.0**	**10137.6**	**10492.0**	**10490.1**	**10600.3**	**10229.6**	**10166.0**
5.1 उपलब्ध नकदी	570.3	691.6	821.6	809.9	758.5	814.7	802.1	867.6	777.6
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	7580.8	8384.1	10147.4	9327.7	9733.5	9675.4	9798.1	9362.0	9388.3
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	**1148.1**	**1215.4**	**1520.6**	**1396.1**	**1352.8**	**1407.8**	**1364.8**	**1560.4**	**1557.2**
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	**64455.2**	**73814.2**	**72520.1**	**73255.5**	**73448.2**	**74182.9**	**73637.4**	**73166.1**	**72325.9**
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	**28835.7**	**21853.7**	**18267.2**	**17881.7**	**15981.1**	**21439.7**	**21003.3**	**17899.7**	**18018.5**
9 बैंक ऋण (10.1+11)	**114631.6**	**107879.4**	**121551.1**	**121730.1**	**120921.6**	**120927.0**	**120809.3**	**120186.2**	**120652.2**
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	**114612.1**	**107858.5**	**121528.1**	**121709.0**	**120901.6**	**120906.9**	**120769.5**	**120147.3**	**120612.7**
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	89429.1	99264.9	115486.6	115443.1	115130.2	117333.9	117079.2	117456.0	117682.0
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	19.5	20.8	23.1	21.1	20.1	20.1	39.7	38.8	39.5

कीमत और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)

समूह/उप समूह	2021-22			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	दिसं. '21	नवं.'22	दिसं.'22(अ)	दिसं.'21	नवं.'22	दिसं.'22(अ)	दिसं.'21	नवं.'22	दिसं.'22(अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	**162.8**	**168.7**	**165.0**	**165.8**	**176.6**	**174.4**	**172.2**	**181.3**	**178.6**	**168.2**	**178.3**	**175.9**
1.1 अनाज और उत्पाद	146.4	150.4	147.6	147.4	166.9	168.8	151.6	168.4	170.2	148.7	167.4	169.2
1.2 मांस और मछली	200.4	206.5	202.6	197.0	207.2	206.9	202.2	213.4	212.8	198.8	209.4	209.0
1.3 अंडा	173.3	176.0	174.4	176.5	180.2	189.1	180.0	183.2	192.0	177.9	181.4	190.2
1.4 दूध और उत्पाद	158.3	159.0	158.6	159.8	172.3	173.4	160.0	172.3	173.8	159.9	172.3	173.5
1.5 तेल और चर्बी	192.2	172.4	184.9	195.8	194.0	194.0	173.5	180.0	179.2	187.6	188.9	188.6
1.6 फल	155.3	163.5	159.2	152.0	159.1	156.7	158.3	162.6	159.5	154.9	160.7	158.0
1.7 सब्जी	156.1	192.8	168.5	172.3	171.6	150.2	219.5	205.5	178.7	188.3	183.1	159.9
1.8 दाल और उत्पाद	164.1	164.4	164.2	164.5	170.2	170.5	164.2	171.0	171.3	164.4	170.5	170.8
1.9 चीनी और उत्पाद	117.4	119.1	118.0	120.6	121.5	121.2	121.9	123.4	123.1	121.0	122.1	121.8
1.10मसाले	171.2	167.5	170.0	171.7	204.8	207.5	168.2	198.8	200.5	170.5	202.8	205.2
1.11गैर नशीले पेय पदार्थ	167.8	154.7	162.3	169.7	176.4	176.8	156.5	162.1	162.8	164.2	170.4	171.0
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	173.0	175.8	174.3	175.1	186.9	187.6	178.2	192.4	193.3	176.5	189.5	190.2
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	**190.3**	**196.5**	**191.9**	**190.8**	**195.5**	**195.9**	**196.8**	**200.6**	**201.0**	**192.4**	**196.9**	**197.3**
3 कपड़ा और जूते	**168.2**	**158.4**	**164.3**	**171.2**	**186.9**	**187.8**	**160.7**	**174.7**	**175.7**	**167.0**	**182.1**	**183.0**
3.1 कपड़ा	168.8	160.9	165.7	171.8	187.2	188.1	163.3	176.7	177.7	168.5	183.1	184.0
3.2 जूते	164.5	144.7	156.3	167.3	185.2	185.9	146.7	163.5	164.3	158.7	176.2	176.9
4 आवास	**--**	**163.0**	**163.0**	**--**	**--**	**--**	**163.4**	**171.8**	**170.7**	**163.4**	**171.8**	**170.7**
5 ईंधन और लाइट	**164.0**	**159.8**	**162.4**	**165.6**	**181.9**	**182.8**	**161.7**	**180.3**	**180.9**	**164.1**	**181.3**	**182.1**
6 विविध	**164.1**	**156.1**	**160.2**	**166.0**	**174.6**	**175.5**	**157.8**	**167.4**	**168.2**	**162.0**	**171.1**	**172.0**
6.1 घरेलू सामान और सेवा	161.8	153.5	157.9	163.9	175.5	176.4	156.0	166.9	167.2	160.2	171.4	172.1
6.2 स्वास्थ्य	172.0	163.3	168.6	174.0	182.3	183.5	165.1	175.8	177.2	170.6	179.8	181.1
6.3 परिवहन और संचार	157.9	150.0	153.7	160.1	167.5	167.8	151.8	158.9	159.3	155.7	163.0	163.3
6.4 मनोरंजन	162.7	154.8	158.2	164.5	170.8	171.2	157.6	166.7	167.1	160.6	168.5	168.9
6.5 शिक्षा	168.4	160.1	163.5	169.7	176.9	177.3	160.6	171.5	171.8	164.4	173.7	174.1
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	161.3	160.8	161.1	162.8	173.4	175.7	162.4	173.8	176.0	162.6	173.6	175.8
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	**164.5**	**163.1**	**163.8**	**167.0**	**177.8**	**177.1**	**165.2**	**175.0**	**174.1**	**166.2**	**176.5**	**175.7**

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अ: अनंतिम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2021-22	2021	2022	
				दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	123.6	125.4	132.5	132.3
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	1075	1097	1167	1167
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	–	1084	1106	1178	1179

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2021-22	2021	2022	
		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	47999	47890	51874	53941
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	65426	61280	60968	66698

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधारः 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2021	2022		
			दिसं.	अक्टू.	नवं. (अ)	दिसं. (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य वस्तुएँ	**100.000**	**139.4**	**143.3**	**152.9**	**152.1**	**150.4**
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	**22.618**	**160.7**	**168.4**	**181.2**	**177.7**	**172.4**
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	**15.256**	**167.3**	**176.7**	**186.1**	**180.2**	**174.5**
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	163.5	165.1	179.6	181.9	184.2
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	187.6	226.9	230.8	202.0	173.4
1.1.1.3 दूध	4.440	156.9	157.3	166.7	167.0	168.3
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	164.0	161.5	167.8	166.7	166.9
1.1.1.5 मसाले	0.529	159.8	165.9	191.2	193.0	191.5
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	168.3	170.3	180.0	182.8	181.3
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	**4.119**	**158.1**	**164.6**	**166.0**	**168.2**	**170.7**
1.1.2.1 फाइबर	0.839	158.4	164.6	193.1	193.6	188.1
1.1.2.2 तिलहन	1.115	214.4	210.1	189.0	199.7	200.0
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	119.9	123.8	127.5	131.3	134.4
1.1.2.4 पुष्पोत्पादन	0.204	217.0	309.8	298.5	247.6	288.6
1.1.3 खनिज	**0.833**	**197.2**	**204.7**	**196.8**	**196.7**	**198.7**
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	193.3	200.9	182.6	182.6	183.5
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	211.0	218.2	246.6	246.2	252.0
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	**2.410**	**110.3**	**109.3**	**170.7**	**171.2**	**152.7**
1.2 ईंधन और बिजली	**13.152**	**124.6**	**133.8**	**158.0**	**159.6**	**158.0**
1.2.1 कोल	**2.138**	**129.0**	**130.9**	**134.3**	**134.3**	**134.3**
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	143.0	143.4	143.4	143.4	143.4
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.8	119.8	119.8	119.8	119.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	170.5	212.6	294.3	294.3	294.3
1.2.2 खनिज तेल	**7.950**	**126.2**	**134.0**	**166.4**	**172.4**	**164.4**
1.2.3 बिजली	**3.064**	**117.4**	**135.3**	**152.9**	**144.0**	**157.7**
1.3 विनिर्मित उत्पाद	**64.231**	**135.0**	**136.5**	**141.9**	**141.5**	**141.1**
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	**9.122**	**157.9**	**156.6**	**163.7**	**164.6**	**163.3**
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	142.8	143.7	140.9	139.4	142.5
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस,मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	144.1	149.1	139.2	140.1	142.7
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	122.3	120.9	127.4	127.4	127.5
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	187.2	180.1	173.3	174.8	169.2
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	149.4	148.3	168.2	168.4	169.6
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	145.6	146.5	165.1	165.9	167.4
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	133.3	138.3	163.6	160.7	158.1
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	146.2	150.0	163.4	163.5	166.1
1.3.1.9 चीनी,गुड़ और शहद	1.163	122.9	125.1	127.3	128.1	127.7
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	130.5	132.0	135.4	136.4	138.3
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	136.7	131.4	162.5	159.8	148.7
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	171.1	175.4	178.5	177.0	172.7
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	157.5	157.4	178.0	178.4	181.8
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	137.0	136.3	142.9	142.0	140.4
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	153.5	153.1	183.8	182.2	181.8
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	200.9	199.5	206.5	212.4	208.8
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	**0.909**	**126.8**	**127.2**	**129.1**	**128.8**	**129.5**
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	123.6	124.1	129.7	130.0	131.4
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	130.5	131.1	135.1	133.8	134.3
1.3.2.3 शीतल पेय,मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	128.6	128.5	123.3	122.9	122.9
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	**0.514**	**160.2**	**161.9**	**164.2**	**165.4**	**164.3**
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	160.2	161.9	164.2	165.4	164.3

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक *(जारी)*

(आधारः 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2021	2022		
			दिसं.	अक्टू.	नवं. (अ)	दिसं. (अ)
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	**4.881**	**135.2**	**139.2**	**142.5**	**140.3**	**138.4**
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	128.2	133.4	132.0	128.6	125.5
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	146.8	149.7	160.1	159.5	158.9
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	125.5	127.5	132.5	130.6	127.6
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	138.7	141.1	155.2	154.1	153.2
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	168.5	167.1	156.2	151.9	151.7
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	126.2	129.3	130.4	130.6	131.5
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	**0.814**	**143.1**	**144.7**	**149.3**	**149.4**	**149.9**
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर बुने हुए तैयार वस्त्र	0.593	142.0	143.2	147.9	147.8	148.6
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉस्चिटेड वस्त्र	0.221	145.8	148.7	153.3	153.5	153.6
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	**0.535**	**119.2**	**119.8**	**122.2**	**122.6**	**121.7**
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	103.4	104.3	103.9	105.2	104.0
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	141.5	142.6	140.8	141.9	141.0
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	121.0	121.4	126.0	125.8	125.1
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	**0.772**	**141.0**	**142.5**	**142.9**	**143.3**	**143.7**
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	128.8	131.2	138.7	138.5	139.3
1.3.7.2 विनियर शीट,प्लायवुड का विनिर्माण,लॅमिन बोर्ड,पार्टिकल बोर्डऔर अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	141.9	143.1	141.1	141.0	141.3
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	193.9	194.5	205.7	206.6	206.6
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	134.1	135.9	136.0	139.2	139.2
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	**1.113**	**137.5**	**141.2**	**152.8**	**151.2**	**148.2**
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	141.4	145.3	159.3	158.3	156.6
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	137.8	139.3	150.1	148.3	145.3
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	131.0	136.5	145.2	142.7	137.8
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	**0.676**	**157.8**	**162.6**	**172.4**	**171.8**	**176.8**
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	157.8	162.6	172.4	171.8	176.8
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	**6.465**	**133.5**	**136.8**	**146.3**	**145.3**	**144.2**
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	143.8	149.3	159.9	158.3	156.2
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	129.6	131.1	148.0	148.1	147.6
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिथेंटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	140.3	142.6	140.6	137.5	136.0
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद	0.454	132.1	133.2	144.5	144.9	143.5
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	130.4	137.0	145.7	146.2	146.0
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट,सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	128.1	130.9	142.8	142.8	142.3
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	130.3	134.1	143.3	142.1	141.1
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	106.6	109.2	109.4	106.8	105.7
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	**1.993**	**135.9**	**136.6**	**141.2**	**141.6**	**141.7**
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	135.9	136.6	141.2	141.6	141.7
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	**2.299**	**124.8**	**127.1**	**129.2**	**128.5**	**128.5**
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब,रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	104.3	106.5	113.2	113.7	113.6
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	101.9	104.6	105.7	105.9	105.9
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	138.0	140.3	140.6	139.3	139.2
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	**3.202**	**123.7**	**125.1**	**133.5**	**134.2**	**134.7**
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	139.1	143.9	158.7	159.9	163.4
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	115.6	119.0	119.1	119.1	118.9
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	119.3	120.9	136.5	139.3	137.5
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	112.9	114.3	117.5	118.5	118.5
1.3.13.5 सीमेन्ट,चूना और प्लास्टर	1.645	126.4	127.1	136.7	137.3	137.6

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक *(जारी)*

(आधारः 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2021	2022		
			दिसं.	अक्टू.	नवं. (अ)	दिसं. (अ)
1.3.13.6 कंक्रीट,सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	129.2	129.8	134.3	134.8	134.9
1.3.13.7 पत्थरों को काटना,आकार देना और संवारना	0.234	122.2	120.2	125.9	126.1	127.1
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	90.6	96.6	105.4	106.6	106.6
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	**9.646**	**140.1**	**141.9**	**145.6**	**143.5**	**143.0**
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	150.8	153.6	155.8	152.6	150.4
1.3.14.2 धात्विक लौह	0.653	147.7	145.2	164.2	157.2	157.6
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	119.1	118.2	126.1	123.8	122.1
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	137.4	139.0	147.9	145.0	145.7
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	157.5	160.6	148.7	146.4	143.9
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	133.7	130.7	149.0	144.7	141.4
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	141.7	142.8	146.1	143.2	142.0
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	155.9	161.8	175.6	174.4	171.7
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	139.7	143.8	141.1	140.7	141.9
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	118.9	120.7	130.6	131.7	132.6
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	159.0	160.6	173.4	172.6	175.7
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	**3.155**	**130.5**	**133.1**	**137.7**	**138.3**	**137.9**
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	123.9	124.8	131.3	133.2	132.7
1.3.15.2 धातु से बने टैंक,जलाशय और डिब्बे	0.660	156.2	162.1	157.0	156.5	156.3
1.3.15.3 वाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर	0.145	96.1	94.8	103.1	102.7	98.7
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	117.5	122.6	135.3	135.9	134.7
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	108.2	109.6	113.2	113.3	113.3
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	136.5	138.3	144.2	144.4	144.9
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	**2.009**	**113.7**	**113.5**	**117.1**	**116.9**	**117.1**
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	106.0	107.5	115.6	115.6	115.1
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	134.7	134.9	134.9	134.9	135.0
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	121.7	120.5	129.6	129.6	130.7
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स	0.641	102.1	100.8	100.4	99.5	100.2
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	108.4	108.5	113.5	113.5	112.5
1.3.16.6 हाथ घडी और दीवार घडी	0.076	145.6	145.6	151.6	153.1	151.3
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	106.1	109.2	111.6	111.6	112.2
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	98.3	98.4	101.6	101.6	101.7
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	**2.930**	**122.3**	**123.6**	**129.2**	**128.8**	**129.5**
1.3.17.1 विद्युतमोटर्स,जनरेटर,ट्रांसफार्मरऔरबिजलीवितरणऔरनियंत्रणसंबंधीउपकरण	1.298	119.7	120.8	128.1	126.6	127.7
1.3.17.2 बैटरी और एक्युम्युलेटर	0.236	121.8	123.8	133.1	133.2	133.5
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	103.1	100.4	119.9	120.4	118.5
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रानिक और बिज़ली के वायर और केबल	0.428	140.7	143.1	141.4	142.7	144.0
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	114.5	115.6	117.5	117.9	117.8
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	128.4	130.8	134.7	134.6	133.9
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	113.2	113.9	117.5	117.8	119.7
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	**4.789**	**120.0**	**121.1**	**126.5**	**126.6**	**126.7**
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन,एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	119.2	121.4	126.9	126.6	125.7
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	122.1	123.1	127.4	128.3	129.2
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	115.1	116.4	117.1	117.1	117.5
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	118.1	119.5	124.4	123.9	124.5
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	74.2	73.0	79.9	80.9	81.2
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने –उतारने वाले उपकरण	0.285	120.0	122.7	125.9	126.1	126.4

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)

(आधारः 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2021	2022		
			दिसं.	अक्टू.	नवं. (अ)	दिसं. (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	133.4	130.6	141.7	142.6	142.5
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	128.4	130.5	138.0	138.8	138.6
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	114.2	114.6	121.2	121.1	121.1
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	78.2	78.5	85.2	85.7	86.5
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	130.1	131.0	129.8	127.8	125.3
1.3.18.13 कपड़ा,परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	125.3	125.8	132.6	132.2	133.6
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	134.7	136.2	141.2	141.6	142.2
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	66.6	66.8	70.3	70.3	69.7
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	**4.969**	**122.7**	**124.1**	**128.1**	**128.0**	**127.5**
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	122.6	123.5	125.8	126.4	125.7
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	122.7	124.7	130.6	129.8	129.4
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	**1.648**	**131.7**	**133.1**	**137.3**	**137.5**	**137.9**
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली –वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.9	158.9	163.6	163.6	163.6
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टाक	0.110	104.4	103.8	104.3	106.1	104.4
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	131.0	132.8	137.4	137.6	138.3
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाडी	0.117	137.2	138.0	140.4	140.2	139.2
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	135.9	137.4	153.4	154.3	157.7
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	**0.727**	**150.1**	**154.3**	**156.2**	**156.1**	**157.2**
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	150.1	154.3	156.2	156.1	157.2
1.3.22 अन्य विनिर्माण	**1.064**	**137.9**	**136.7**	**144.9**	**146.9**	**152.5**
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	136.0	134.8	143.4	145.7	151.7
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	192.3	195.7	194.5	193.9	182.7
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	140.4	142.5	151.7	152.0	151.9
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	150.9	151.1	159.0	159.3	159.3
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	171.8	171.1	170.5	168.0	168.0
2 खाद्य सूचकांक	**24.378**	**163.8**	**169.2**	**177.7**	**174.3**	**170.3**

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)

उद्योग	भारांक	2020-21	2021-22	अप्रैल- नवंबर		नवंबर	
				2021-22	2022-23	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	118.1	131.6	127.6	134.6	128.0	137.1
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	101.0	113.3	105.8	110.8	111.8	122.7
1.2 विनिर्माण	77.63	117.2	131.0	127.2	133.6	128.9	136.7
1.3 बिजली	7.99	157.6	170.1	170.2	186.9	147.9	166.7
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	118.1	129.5	125.0	134.6	126.5	132.5
2.2 पूंजीगत माल	8.22	75.9	88.7	83.9	96.4	82.1	99.1
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	124.7	143.9	140.2	147.2	141.3	145.6
2.4 इंफ्रास्ट्रक्चर/निर्माण वस्तुएं	12.34	124.7	148.2	143.0	153.6	141.5	159.6
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	101.2	113.8	110.3	116.6	106.6	112.0
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	142.1	146.7	144.6	141.0	147.9	161.1

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(₹ करोड़)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-नवंबर			
	2022-23 (बजट आकलन)	2022-23 (वास्तविक)	2021-22 (वास्तविक)	बजट आकलन के लिए प्रतिशत	
				2022-23	2021-22
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	**2348413**	**1769994**	**1733223**	**75.4**	**83.4**
1.1 कर राजस्व (निवल)	2086662	1555692	1473809	74.6	83.5
1.2 करेतर राजस्व	261751	214302	259414	81.9	82.7
2 गैर-कर्ज पूंजीगत प्राप्तियां	**83500**	**55106**	**28469**	**66.0**	**28.5**
2.1 ऋण की वसूली	23500	16435	19105	69.9	86.9
2.2 अन्य प्राप्तियां	60000	38671	9364	64.5	12.0
3 कुल प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	**2431913**	**1825100**	**1761692**	**75.0**	**80.9**
जिसमें से:	3458959	2328132	2129414	67.3	67.2
4 राजस्व व्यय					
4.1 ब्याज भुगतान	940651	680853	565864	72.4	69.5
5 पूंजी व्यय	728274	489944	391644	67.3	65.0
6 कुल व्यय (4+5)	**4187232**	**2818076**	**2521058**	**67.3**	**66.9**
7 राजस्व घाटा (4-1)	**1110546**	**558138**	**396191**	**50.3**	**36.4**
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	**1755319**	**992976**	**759366**	**56.6**	**47.7**
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	**814668**	**312123**	**193502**	**38.3**	**24.9**

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय बजट 2022-23।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2021-22	2021	2022					
		दिसं. 31	नवं. 25	नवं. 2	दिसं. 9	दिसं. 16	दिसं. 23	दिसं. 30
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	5310	9354	16804	14896	15637	14258	14138	14180
1.2 प्राथमिक व्यापारी	16705	26882	23433	21138	22793	21908	19208	15538
1.3 राज्य सरकारें	31320	103016	45031	43031	42231	44231	45431	47131
1.4 अन्य	72109	106541	105524	107985	106618	107950	112385	117108
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	70130	56154	68750	65891	67923	63346	63319	62858
2.2 प्राथमिक व्यापारी	63669	32988	53570	51829	52290	52369	51974	45722
2.3 राज्य सरकारें	15763	6458	27598	26098	26098	24513	23513	22513
2.4 अन्य	69259	19711	81725	79438	71875	69941	65133	68212
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	112386	115964	108145	109624	109049	104092	100142	108294
3.2 प्राथमिक व्यापारी	160461	117965	183977	179436	178688	182441	187924	187403
3.3 राज्य सरकारें	22836	21643	45396	44390	46295	46400	46500	42776
3.4 अन्य	118392	99125	136944	138787	137740	135924	135026	130815
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	289362	139739	194863	152813	123956	174753	185087	188391
4.4 अन्य	659	761	1582	390	898	763	455	1019
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	758339	715802	896896	882543	877237	867372	864693	862547

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि ₹ करोड़ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियाँ			स्वीकृत बोलियां			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2022-23										
नवं. 30	10000	146	45182	1045	29	9955	1045	11000	98.43	6.3977
दिसं. 7	10000	167	61321	6234	37	9966	6234	16200	98.42	6.4474
दिसं. 14	10000	170	64308	11239	22	9961	11239	21200	98.43	6.3977
दिसं. 21	10000	146	56943	3739	26	9961	3739	13700	98.43	6.3940
दिसं. 28	10000	129	47976	3245	15	9955	3245	13200	98.45	6.3099
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2022-23										
नवं. 30	6000	146	21712	20	36	5980	20	6000	96.76	6.7254
दिसं. 7	6000	130	19356	19	51	5981	19	6000	96.73	6.7880
दिसं. 14	6000	148	22610	379	52	5972	379	6350	96.74	6.7529
दिसं. 21	6000	137	21032	18	34	5982	18	6000	96.74	6.7599
दिसं. 28	6000	119	19738	32	17	5968	32	6000	96.75	6.7400
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2022-23										
नवं. 30	6000	156	18716	1104	54	5980	1104	7084	93.59	6.8678
दिसं. 7	6000	198	24777	1953	51	5952	1953	7905	93.55	6.9194
दिसं. 14	6000	187	31302	137	39	5967	137	6105	93.59	6.8678
दिसं. 21	6000	154	26179	124	36	5977	124	6100	93.56	6.9000
दिसं. 28	6000	161	23890	90	22	5986	90	6076	93.57	6.8907

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार		दरों का दायरा	भारित औसत दरें
		उधार लेना/उधार देना	उधार लेना/उधार देना
		1	2
दिसंबर	1, 2022	4.30-5.85	5.76
दिसंबर	2, 2022	4.30-5.85	5.79
दिसंबर	3, 2022	5.15-5.55	5.39
दिसंबर	5, 2022	4.50-5.80	5.76
दिसंबर	6, 2022	4.15-5.80	5.76
दिसंबर	7, 2022	4.30-6.15	6.07
दिसंबर	8, 2022	4.30-6.15	6.09
दिसंबर	9, 2022	4.30-6.18	6.10
दिसंबर	12, 2022	4.30-6.15	6.08
दिसंबर	13, 2022	4.30-6.20	6.08
दिसंबर	14, 2022	4.40-6.15	6.09
दिसंबर	15, 2022	4.30-6.40	6.19
दिसंबर	16, 2022	4.30-6.60	6.39
दिसंबर	17, 2022	5.10-6.10	5.81
दिसंबर	19, 2022	4.30-6.60	6.50
दिसंबर	20, 2022	4.30-6.60	6.49
दिसंबर	21, 2022	4.30-6.60	6.44
दिसंबर	22, 2022	4.30-6.60	6.49
दिसंबर	23, 2022	4.30-6.55	6.46
दिसंबर	26, 2022	4.30-6.55	6.46
दिसंबर	27, 2022	4.30-6.75	6.31
दिसंबर	28, 2022	4.30-6.50	6.29
दिसंबर	29, 2022	4.30-6.60	6.36
दिसंबर	30, 2022	4.30-6.65	6.49
दिसंबर	31, 2022	5.15-6.20	5.97
जनवरी	2, 2023	4.30-6.25	6.16
जनवरी	3, 2023	4.30-6.15	6.08
जनवरी	4, 2023	4.30-6.25	6.06
जनवरी	5, 2023	4.30-6.10	6.06
जनवरी	6, 2023	4.30-6.10	6.05
जनवरी	7, 2023	5.15-6.05	5.74
जनवरी	9, 2023	4.40-6.12	6.06
जनवरी	10, 2023	4.55-6.12	6.06
जनवरी	11, 2023	4.55-6.12	6.06
जनवरी	12, 2023	4.55-6.15	6.06
जनवरी	13, 2023	4.55-6.30	6.21

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2021	2022			
	दिसं. 31	नवं. 18	दिसं. 2	दिसं. 16	दिसं. 30
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (₹ करोड़)	84702.40	257555.16	274602.72	272570.90	293983.09
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (₹ करोड़)	17497.20	25534.76	32831.31	31706.05	35845.62
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.74-5.31	6.64-7.28	6.77-7.20	6.71-7.59	6.65-7.88

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2021	2022			
	दिसं. 31	नवं. 15	नवं. 30	दिसं. 15	दिसं. 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (₹ करोड़)	350068.65	381455.70	362307.65	363736.15	359673.30
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (₹ करोड़)	87182.55	55158.95	66918.15	65701.70	54575.60
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.50-12.31	6.21-13.78	6.50-12.01	6.34-13.75	6.58-13.75

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(₹ करोड़)

मद	2021-22	2021	2022					
		दिसं. 31	नवं. 25	दिसं. 2	दिसं. 9	दिसं. 16	दिसं. 23	दिसं. 30
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	14515	13822	19325	15885	16362	17828	18447	19107
2 नोटिस मुद्रा	2122	3125	192	4526	492	5409	164	4418
3 मीयादी मुद्रा	515	640	332	944	282	853	717	867
4 त्रिपक्षीय रिपो	618526	834645	710250	760797	579566	719115	684319	790750
5 बाजार रिपो	383844	402671	489094	550005	438455	524436	502373	600368
6 कार्पोरेट बांड में रिपो	4373	0	473	312	1723	2879	2006	208
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	75085	73613	95133	72719	84489	80619	75159
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	51300	37640	56440	66339	73928	57167	43412	33290
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	5570	6397	4989	3496	2972	2951	4207	3177
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	4690	4503	5431	2839	3878	3307	3669	2219
10.2 182-दिवसीय	3440	1706	2761	3823	1731	1530	3493	2854
10.3 364-दिवसीय	3530	2120	2061	1553	1998	1451	2998	2836
10.4 नकदी प्रबंधन बिल								
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	68530	52366	71681	78050	84508	66406	57779	44376
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	–	1662	1994	736	1131	1310	1036	34

सं. 30: गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2021-22		2021-22 (अप्रै-दिसं.)		2022-23 (अप्रै-दिसं.)*		दिसं. 2021		दिसं. 2022*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	**164**	**138894**	**124**	**130082**	**162**	**40509**	**30**	**18258**	**21**	**5235**
1ए प्रीमियम	154	136893	117	128289	150	38170	28	17906	20	5070
1.1 पब्लिक	121	112567	96	104847	122	36957	20	15681	18	5119
1.1.1 प्रीमियम	119	111314	95	103702	119	35737	20	15444	18	4989
1.2 राइट्स	43	26327	28	25236	40	3552	10	2577	3	116
1.2.1 प्रीमियम	35	25580	22	24587	31	2433	8	2462	2	80
2 अधिमान शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3 बॉण्ड और डिबेंचर	**28**	**11589**	**24**	**10717**	**24**	**6872**	**4**	**1584**	**2**	**249**
3.1 परिवर्तनीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अपरिवर्तनीय	28	11589	24	10717	24	6872	4	1584	2	249
3.1.1 पब्लिक	28	11589	24	10717	24	6872	4	1584	2	249
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4 कुल (1+2+3)	**192**	**150484**	**148**	**140799**	**186**	**47381**	**34**	**19843**	**23**	**5484**
4.1 पब्लिक	149	124157	120	115563	146	43829	24	17266	20	5368
4.2 राइट्स	43	26327	28	25236	40	3552	10	2577	3	116

टिप्पणी: 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कालम के आंकडे कुल में नहीं जुड़ सकते।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम है।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2021-22	2021	2022				
			दिसं.	अग.	सितं.	अक्टू.	नवं.	दिसं.
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड़ ₹	3147021	295989	294599	283946	260213	285453	313687
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	422004	39270	37031	35391	31602	34892	38039
1.1 तेल	करोड़ ₹	503850	50912	67589	58296	51863	66154	68885
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	67472	6755	8496	7266	6299	8086	8353
1.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	2643171	245077	227010	225650	208350	219299	244803
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	354533	32515	28535	28125	25304	26806	29686
2 आयात	करोड़ ₹	4572775	454721	493688	518793	485856	476301	496308
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	613052	60330	62056	64662	59006	58220	60185
2.1 तेल	करोड़ ₹	1207803	124324	139209	150772	149621	147700	160344
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	161810	16495	17498	18792	18171	18054	19444
2.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	3364972	330397	354479	368021	336235	328601	335964
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	451242	43835	44558	45870	40835	40166	40741
3 व्यापार शेष	करोड़ ₹	-1425753	-158731	-199089	-234847	-225644	-190848	-182621
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-191048	-21060	-25025	-29271	-27404	-23328	-22145
3.1 तेल	करोड़ ₹	-703953	-73411	-71619	-92476	-97758	-81547	-91459
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-94339	-9740	-9003	-11526	-11872	-9968	-11091
3.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	-721800	-85320	-127469	-142371	-127886	-109301	-91161
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-96709	-11320	-16023	-17745	-15531	-13360	-11055

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

मद	इकाई	2022			2023			
		जन. 28	दिसं. 23	जन. 30	जन. 6	जन. 13	जन. 20	जन. 27
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल आरक्षित निधियां	**करोड ₹**	**4727298**	**4663730**	**4656002**	**4645635**	**4652927**	**4654872**	**4702189**
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	**629755**	**562808**	**562851**	**561583**	**572000**	**573727**	**576761**
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड ₹	4249350	4130758	4121067	4106795	4112093	4108235	4149889
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	566077	498490	498188	496441	505519	506358	509018
1.2 स्वर्ण	करोड ₹	296461	339492	341827	345658	348887	354646	358942
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	39493	40969	41323	41784	42890	43712	44027
	मात्रा (मैट्रिक टन)	755.42	786.28	787.37	787.37	787.37	787.37	787.37
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	13657	13662	13662	13662	13662	13662	13662
	करोड ₹	142706	150729	150400	150698	149382	149543	150649
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	19011	18190	18182	18217	18364	18432	18478
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड ₹	38780	42751	42708	42485	42565	42447	42709
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	5174	5159	5159	5141	5227	5226	5238

* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से हैं।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2021-22	2021	2022		2021-22	2022-23
		दिसं.	नवं.	दिसं.	अप्रै.-दिसं.	अप्रै.-दिसं.
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	**139022**	**141908**	**134500**	**134485**	**3075**	**5408**
1.1 एफसीएनआर (बी)	16918	18154	16719	17558	-2319	640
1.2 एनआर (ई) आरए	100801	102916	95318	94469	2925	1813
1.3 एनआरओ	21303	20838	22463	22458	2469	2955

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2021-22	2021-22	2022-23	2021	2022	
		अप्रै-दिसं.	अप्रै-दिसं.	दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	**38587**	**24810**	**22341**	**1351**	**-2428**	**1954**
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1. 1.1.2)	**56231**	**38977**	**32492**	**2851**	**-172**	**3637**
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	**84835**	**61554**	**55274**	**6249**	**4335**	**6514**
1.1.1.1.1 इक्विटी	59684	43838	37717	3991	2491	4491
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	1698	1574	653	25	4	90
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	42932	30646	29649	3044	2089	3988
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	14143	10953	6445	842	319	333
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	910	664	971	80	80	80
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	19347	14118	14115	1691	1691	1691
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	5805	3598	3442	567	153	332
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	**28605**	**22577**	**22783**	**3397**	**4507**	**2877**
1.1.1.2.1 इक्विटी	27189	22012	20814	3312	4210	2439
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	1416	565	1969	86	297	437
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	**17644**	**14167**	**10151**	**1501**	**2255**	**1683**
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	10061	7929	6523	1022	1457	1272
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3379	2534	2574	282	282	282
1.1.2.3 अन्य पूंजी	7604	5989	3701	389	1030	342
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	3400	2285	2647	192	513	214
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	**-16777**	**-1562**	**-3238**	**-3736**	**4750**	**-436**
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	–	–	–	–	–	–
1.2.2 एफआईआई	-14071	218	-2978	-3356	4727	-554
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	–	–	–	–	–	–
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	2706	1780	260	379	-24	-119
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	**21809**	**23248**	**19103**	**-2385**	**2323**	**1519**

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2021-22	2021	2022		
		दिसं.	अक्टू.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	**19610.77**	**1773.56**	**1924.09**	**1992.70**	**2068.26**
1.1 जमाराशियां	830.05	56.64	64.28	60.72	60.49
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	112.90	10.77	15.28	17.17	13.26
1.3 इक्विटी / कर्ज में निवेश	746.57	54.30	111.41	86.58	119.58
1.4 उपहार	2336.29	214.59	208.11	220.90	202.76
1.5 दान	16.55	2.69	1.68	0.98	0.87
1.6 यात्रा	6909.04	884.10	973.50	1030.64	1137.93
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	3302.37	281.46	280.67	305.35	274.79
1.8 चिकित्सा उपचार	37.79	3.33	4.02	4.76	4.36
1.9 विदेश में शिक्षा	5165.33	253.69	217.87	211.65	237.65
1.10 अन्य	153.88	11.99	47.27	53.95	16.59

सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)

मद	2020-21	2021-22	2022		2023
			जनवरी	दिसंबर	जनवरी
	1	2	3	4	5
40- मुद्रा समूह (आधार: 2015-16=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	93.92	93.13	93.94	89.49	89.24
1.2 रीर	103.46	104.66	105.29	100.00	99.62
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	93.59	93.55	94.70	90.68	90.66
2.2 रीर	102.96	103.48	104.18	98.40	98.24
6- मुद्रा समूह (व्यापार-भारित)					
1 आधार : 2015-16=100					
1.1 नीर	88.45	87.03	87.60	83.71	83.17
1.2 रीर	101.84	102.27	102.96	99.40	99.20
2 आधार : 2020-21 =100					
2.1 नीर	100.00	98.39	99.03	94.64	94.03
2.2 रीर	100.00	100.42	101.10	97.61	97.41

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण

(अमेरिकी मिलियन डॉलर)

मद	2021-22	2021	2022	
		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1086	139	92	99
1.2 राशि	28851	4374	5203	2768
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	18	1	0	0
2.2 राशि	11035	1175	0	0
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1104	140	92	99
3.2 राशि	39886	5549	5203	2768
4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	8.00	5.30	4.70	7.20
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लाइबोर पर भारित औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.71	1.01	1.62	1.68
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-10.50	0.00-10.25	0.00-11.80	0.00-10.35
उधारकर्ता श्रेणियाँ				
I. कॉर्पोरेट विनिर्माण	12244	442	2116	522
II. कॉर्पोरेट -बुनियादी संरचना	17023	2584	2971	28
ए) परिवहन	1597	109	0	0
बी) ऊर्जा	8215	959	1192	6
सी) पानी और सफ़ाई व्यवस्था	10	0	14	0
डी) संचार	1,258	5	1,515	22
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	0	0	0	0
एफ)अन्वेषण खनन और रिफाइनरी	4691	1100	250	0
जी) अन्य उप -क्षेत्र	1252	411	0	0
III. कॉर्पोरेट सेवा क्षेत्र	1570	291	13	36
IV. अन्य संस्थाएं	609	500	0	0
ए) एसईज़ेड में इकाई	9	0	0	0
बी) सिडबी			0	0
सी) एक्जिम बैंक	600	500	0	0
V. बैंक	100	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबी एफ सी के अलावा)	4	0	0	0
VII. एनबीएफसी	7995	1690	81	2148
ए) एनबीएफसी -आई एफ सी/ए एफ सी	5621	1275	0	1418
बी) एनबी एफ सी -एमएफआई	93	17	31	3
सी) एनबीफसी - अन्य (एनजीओ)	2282	398	50	727
VIII. गैर -सरकारी संगठन	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई)	0	0	0	0
X. अन्य	341	42	22	34

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	जुला.-सितं. 2021			जुला.-सितं. 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**405412**	**374223**	**31189**	**378470**	**408849**	**-30379**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**194262**	**203996**	**-9734**	**225210**	**261601**	**-36391**
1.1 पण्य	**104769**	**149280**	**-44511**	**111973**	**195519**	**-83546**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**89494**	**54717**	**34777**	**113237**	**66082**	**47155**
1.2.1 सेवाएं	61418	35839	25579	79986	45554	34432
1.2.1.1 यात्रा	2147	3919	-1772	5775	7539	-1764
1.2.1.2 परिवहन	7581	8181	-600	9533	11337	-1804
1.2.1.3 बीमा	795	575	220	756	586	170
1.2.1.4 जीएनआईई	217	198	19	183	219	-36
1.2.1.5 विविध	50678	22965	27713	63738	25872	37866
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	29965	3184	26781	36228	3546	32681
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	13858	12457	1401	19141	13964	5178
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1303	1463	-160	2113	1600	514
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	766	275	491	803	399	403
1.2.2 अंतरण	21154	2163	18991	27462	2711	24751
1.2.2.1 आधिकारिक	18	239	-221	52	292	-240
1.2.2.2 निजी	21135	1924	19212	27410	2419	24991
1.2.3 आय	6922	16714	-9792	5789	17817	-12028
1.2.3.1 निवेश आय	5425	15960	-10535	4159	16962	-12803
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1497	754	743	1630	854	775
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**209849**	**170227**	**39622**	**153260**	**146342**	**6918**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**132472**	**119898**	**12575**	**99726**	**86757**	**12969**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	20541	11844	8697	18048	11611	6437
2.1.1.1 भारत में	19375	6475	12900	16844	7803	9041
2.1.1.1.1 इक्विटी	13806	6259	7548	10699	7111	3588
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	4668		4668	4667		4667
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	900	216	684	1478	692	786
2.1.1.2 विदेश में	1167	5369	-4203	1204	3808	-2603
2.1.1.2.1 इक्विटी	1167	2824	-1658	1204	1782	-577
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	845	-845	0	865	-865
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1700	-1700	0	1161	-1161
2.1.2 संविभाग निवेश	111931	108054	3877	81678	75146	6532
2.1.2.1 भारत में	110448	105904	4544	81375	74473	6901
2.1.2.1.1 एफआईआई	110448	105904	4544	81375	74473	6901
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	95335	94718	618	72212	66210	6003
2.1.2.1.1.2 ऋण	15112	11186	3926	9163	8264	899
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	1483	2150	-666	303	673	-370
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**25723**	**17888**	**7834**	**27520**	**22027**	**5493**
2.2.1 बाह्य सहायता	2418	1290	1129	2020	1523	497
2.2.1.1 भारत द्वारा	13	16	-3	11	22	-11
2.2.1.2 भारत को	2406	1273	1132	2009	1501	508
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	9283	4941	4342	5351	5463	-112
2.2.2.1 भारत द्वारा	282	249	33	359	100	258
2.2.2.2 भारत को	9001	4692	4309	4993	5363	-370
2.2.3 भारत को अल्पावधि	14021	11658	2364	20149	15041	5108
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	9615	11658	-2043	17152	15041	2111
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	4407	0	4407	2997	0	2997
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**20817**	**20457**	**360**	**15567**	**24013**	**-8447**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	20473	20457	17	15567	24012	-8445
2.3.1.1 आस्तियां	10097	9858	239	134	10646	-10512
2.3.1.2 देयताएं	10376	10598	-222	15433	13366	2067
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	8574	9357	-783	13993	11504	2490
2.3.2 अन्य	344	0	344	0	2	-2
2.4 रुपया कर्ज चुकौती	0	2	-2	0	1	-1
2.5 अन्य पूंजी	30837	11983	18855	10447	13543	-3096
3 भूल-चूक	**1301**	0	**1301**	0	**906**	**-906**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	**31189**	**-31189**	**30379**	0	**30379**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (वृद्धि -/ कमी +)		31189	-31189	30379	0	30379

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(₹ करोड़)

मद	जुला.-सितं. 2021			जुला.-सितं. 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**3003766**	**2772683**	**231083**	**3020039**	**3262450**	**-242411**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**1439323**	**1511443**	**-72120**	**1797085**	**2087469**	**-290384**
1.1 पण्य	**776248**	**1106039**	**-329791**	**893502**	**1560163**	**-666661**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**663075**	**405404**	**257671**	**903583**	**527306**	**376277**
1.2.1 सेवाएं	455057	265535	189522	638258	363505	274753
1.2.1.1 यात्रा	15905	29037	-13132	46081	60160	-14079
1.2.1.2 परिवहन	56168	60613	-4445	76071	90467	-14396
1.2.1.3 बीमा	5894	4263	1631	6035	4676	1360
1.2.1.4 जीएनआईई	1607	1467	141	1463	1751	-288
1.2.1.5 विविध	375483	170154	205328	508608	206451	302156
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	222016	23589	198426	289082	28298	260784
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	102675	92295	10380	152740	111423	41317
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	9652	10836	-1184	16862	12764	4098
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	5676	2035	3641	6405	3185	3219
1.2.2 अंतरण	156732	16028	140704	219132	21632	197501
1.2.2.1 आधिकारिक	137	1774	-1638	413	2327	-1914
1.2.2.2 निजी	156596	14254	142342	218719	19305	199414
1.2.3 आय	51286	123840	-72554	46193	142170	-95977
1.2.3.1 निवेश आय	40194	118251	-78057	33190	135354	-102164
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	11092	5589	5503	13003	6816	6187
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**1554807**	**1261241**	**293567**	**1222954**	**1167748**	**55206**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**981510**	**888342**	**93168**	**795775**	**692288**	**103487**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	152195	87755	64439	144014	92649	51365
2.1.1.1 भारत में	143550	47973	95577	134406	62266	72140
2.1.1.1.1 इक्विटी	102293	46371	55922	85373	56743	28630
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	34589	0	34589	37239	0	37239
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	6668	1602	5066	11795	5523	6271
2.1.1.2 विदेश में	8645	39782	-31137	9608	30382	-20774
2.1.1.2.1 इक्विटी	8645	20927	-12282	9608	14216	-4608
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	6259	-6259	0	6900	-6900
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	12596	-12596	0	9267	-9267
2.1.2 संविभाग निवेश	829315	800587	28729	651761	599639	52122
2.1.2.1 भारत में	818325	784660	33664	649339	594268	55071
2.1.2.1.1 एफआईआई	818325	784660	33664	649339	594268	55071
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	706356	701779	4577	576224	528326	47898
2.1.2.1.1.2 ऋण	111968	82881	29087	73116	65943	7173
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	10991	15927	-4936	2422	5371	-2949
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**190583**	**132537**	**58046**	**219602**	**175768**	**43834**
2.2.1 बाह्य सहायता	17919	9554	8364	16119	12152	3968
2.2.1.1 भारत द्वारा	95	120	-26	87	177	-89
2.2.1.2 भारत को	17824	9434	8390	16032	11975	4057
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	68777	36608	32169	42702	43593	-891
2.2.2.1 भारत द्वारा	2087	1844	242	2861	799	2062
2.2.2.2 भारत को	66691	34764	31927	39841	42795	-2953
2.2.3 भारत को अल्पावधि	103887	86375	17512	160781	120023	40757
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	71239	86375	-15136	136866	120023	16843
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	32649	0	32649	23914	0	23914
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**154236**	**151566**	**2670**	**124217**	**191617**	**-67400**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	151690	151566	124	124217	191604	-67387
2.3.1.1 आस्तियां	74810	73041	1769	1070	84951	-83881
2.3.1.2 देयताएं	76881	78525	-1645	123147	106652	16494
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	63530	69328	-5798	111661	91794	19867
2.3.2 अन्य	2545	0	2545	0	13	-13
2.4 रुपया कर्ज चुकौती	0	15	-15	0	10	-10
2.5 अन्य पूंजी	228478	88781	139697	83360	108064	-24704
3 भूल-चूक	**9636**	0	**9636**	0	**7233**	**-7233**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	**231083**	**-231083**	**242411**	0	**242411**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	231083	-231083	242411	0	242411

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	जुला.-सितं. 2021			जुला.-सितं. 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	**194262**	**203974**	**-9712**	**225206**	**261577**	**-36371**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**166187**	**185119**	**-18932**	**191959**	**241073**	**-49114**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**104769**	**149280**	**-44511**	**111973**	**195519**	**-83546**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	104254	133258	-29004	111660	185742	-74082
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	515	0	515	313	0	313
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		16022	-16022		9777	-9777
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**61418**	**35839**	**25579**	**79986**	**45554**	**34432**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	75	16	59	311	28	283
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	74	418	-345	50	542	-492
1.अ.ख.3 परिवहन	7581	8181	-600	9533	11337	-1804
1.अ.ख.4 यात्रा	2147	3919	-1772	5775	7539	-1764
1.अ.ख.5 निर्माण	716	715	0	858	833	26
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	795	575	220	756	586	170
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1303	1463	-160	2113	1600	514
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	202	2189	-1987	324	2224	-1900
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	30823	3651	27172	37111	4140	32971
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	13858	12457	1401	19141	13964	5178
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	713	1243	-530	917	1654	-737
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	217	198	19	183	219	-36
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	2915	813	2102	2913	889	2024
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**6922**	**16714**	**-9792**	**5789**	**17817**	**-12028**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1497	754	743	1630	854	775
1.आ.2 निवेश आय	4413	15740	-11328	3321	16856	-13535
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	2046	9816	-7770	1907	9939	-8032
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	111	2859	-2748	55	2917	-2862
1.आ.2.3 अन्य निवेश	62	3064	-3002	146	3954	-3808
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	2193	1	2193	1213	46	1167
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	1012	220	792	838	106	732
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**21153**	**2141**	**19012**	**27458**	**2688**	**24770**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	21135	1924	19212	27410	2419	24991
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	20237	1356	18881	26686	1750	24935
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	899	568	331	724	669	55
1.इ.2 सामान्य सरकार	18	217	-199	48	268	-220
2. पूंजी खाता (2.1+2.2)	**189**	**202**	**-13**	**136**	**122**	**15**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	62	132	-71	6	36	-30
2.2 पूंजी अंतरण	128	70	58	130	85	45
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**209660**	**201236**	**8424**	**183506**	**146243**	**37263**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**20541**	**11844**	**8697**	**18048**	**11611**	**6437**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	19375	6475	12900	16844	7803	9041
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	18475	6259	12216	15366	7111	8255
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	13806	6259	7548	10699	7111	3588
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	4668		4668	4667		4667
3.1.अ.2 ऋण लिखत	900	216	684	1478	692	786
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	900	216	684	1478	692	786
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	1167	5369	-4203	1204	3808	-2603
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	1167	3669	-2502	1204	2646	-1442
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	1167	2824	-1658	1204	1782	-577
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		845	-845		865	-865
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1700	-1700	0	1161	-1161
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		1700	-1700		1161	-1161
3.2 संविभाग निवेश	**111931**	**108054**	**3877**	**81678**	**75146**	**6532**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	110448	105904	4544	81375	74473	6901
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	95335	94718	618	72212	66210	6003
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	15112	11186	3926	9163	8264	899
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	1483	2150	-666	303	673	-370
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (आरक्षित निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**5367**	**5806**	**-439**	**7454**	**7308**	**145**
3.4 अन्य निवेश	**71821**	**44344**	**27478**	**45948**	**52178**	**-6230**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	8918	9357	-439	13993	11505	2488
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	344	0	344	0	2	-2
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	8574	9357	-783	13993	11504	2490
3.4.2.3 सामान्य सरकार			0			0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र			0			0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	23600	17330	6270	8945	19494	-10549
3.4.3अ भारत को ऋण	23306	17065	6241	8576	19372	-10796
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	294	265	29	369	122	247
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	55	13	42	59	1	59
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	14021	11658	2364	20149	15041	5108
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	7365	5986	1379	2801	6137	-3335
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	17862		17862	0		0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	**31189**	**-31189**	**30379**	0	**30379**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण			0			0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए		17862	-17862		0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए			0			0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	13326	-13326	30379	0	30379
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**209660**	**201236**	**8424**	**183506**	**146243**	**37263**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	121882	112614	9267	96598	83949	12649
4.2 ऋण लिखत	62552	51447	11104	53728	56158	-2430
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	25227	37175	-11947	33180	6137	27043
5. निवल भूल-चूक	**1301**		**1301**		**906**	**-906**

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़)

मद	जुला.-सितं. 2021			जुला.-सितं. 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	**1439319**	**1511278**	**-71958**	**1797054**	**2087284**	**-290229**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**1231305**	**1371574**	**-140270**	**1531760**	**1923668**	**-391908**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**776248**	**1106039**	**-329791**	**893502**	**1560163**	**-666661**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	772435	987331	-214896	891001	1482147	-591146
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	3812	0	3812	2501	0	2501
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	118708	-118708	0	78016	-78016
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**455057**	**265535**	**189522**	**638258**	**363505**	**274753**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	558	118	440	2480	223	2256
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	546	3100	-2554	396	4323	-3927
1.अ.ख.3 परिवहन	56168	60613	-4445	76071	90467	-14396
1.अ.ख.4 यात्रा	15905	29037	-13132	46081	60160	-14079
1.अ.ख.5 निर्माण	5302	5299	3	6848	6643	205
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	5894	4263	1631	6035	4676	1360
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	9652	10836	-1184	16862	12764	4098
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	1499	16220	-14721	2589	17749	-15161
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	228370	27051	201318	296127	33035	263092
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	102675	92295	10380	152740	111423	41317
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	5279	9207	-3928	7319	13197	-5878
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1607	1467	141	1463	1751	-288
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	21601	6027	15574	23247	7093	16154
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**51286**	**123840**	**-72554**	**46193**	**142170**	**-95977**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	11092	5589	5503	13003	6816	6187
1.आ.2 निवेश आय	32694	116622	-83928	26500	134507	-108007
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	15161	72730	-57569	15219	79312	-64093
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	820	21184	-20364	442	23280	-22838
1.आ.2.3 अन्य निवेश	461	22703	-22242	1162	31551	-30389
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	16251	5	16246	9677	364	9313
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	7500	1629	5871	6690	846	5843
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**156729**	**15863**	**140865**	**219101**	**21446**	**197656**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	156596	14254	142342	218719	19305	199414
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	149936	10045	139891	212941	13968	198973
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	6659	4209	2451	5779	5337	442
1.इ.2 सामान्य सरकार	133	1609	-1476	382	2141	-1759
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**1402**	**1497**	**-95**	**1089**	**971**	**118**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	457	981	-524	50	289	-239
2.2 पूँजी अंतरण	946	516	430	1039	682	357
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**1553408**	**1490992**	**62417**	**1464307**	**1166962**	**297345**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**152195**	**87755**	**64439**	**144014**	**92649**	**51365**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	143550	47973	95577	134406	62266	72140
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	136882	46371	90511	122612	56743	65869
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	102293	46371	55922	85373	56743	28630
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	34589	0	34589	37239	0	37239
3.1.अ.2 ऋण लिखत	6668	1602	5066	11795	5523	6271
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	6668	1602	5066	11795	5523	6271
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	8645	39782	-31137	9608	30382	-20774
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	8645	27186	-18541	9608	21116	-11508
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	8645	20927	-12282	9608	14216	-4608
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	6259	-6259	0	6900	-6900
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	12596	-12596	0	9267	-9267
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	12596	-12596	0	9267	-9267
3.2 संविभाग निवेश	**829315**	**800587**	**28729**	**651761**	**599639**	**52122**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	818325	784660	33664	649339	594268	55071
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	706356	701779	4577	576224	528326	47898
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	111968	82881	29087	73116	65943	7173
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	10991	15927	-4936	2422	5371	-2949
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**39762**	**43017**	**-3256**	**59477**	**58316**	**1161**
3.4 अन्य निवेश	**532137**	**328550**	**203587**	**366643**	**416358**	**-49714**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	66075	69328	-3253	111661	91807	19854
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	2545	0	2545	0	13	-13
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	63530	69328	-5798	111661	91794	19867
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	174857	128400	46456	71377	155555	-84177
3.4.3अ भारत को ऋण	172675	126436	46239	68430	154579	-86150
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	2181	1964	217	2948	975	1973
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	405	97	308	471	4	467
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	103887	86375	17512	160781	120023	40757
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	54566	44349	10217	22353	48968	-26615
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	132346	0	132346	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	**0**	**231083**	**-231083**	**242411**	**0**	**242411**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	132346	-132346	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	98737	-98737	242411	0	242411
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**1553408**	**1490992**	**62417**	**1464307**	**1166962**	**297345**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	903041	834377	68664	770814	669876	100938
4.2 ऋण लिखत	463455	381183	82272	428729	448118	-19389
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	186912	275432	-88520	264764	48968	215796
5. निवल भूल-चूक	**9636**	**0**	**9636**	**0**	**7233**	**-7233**

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2021-22		2021		2022			
			सितं.		जून		सितं.	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश में/ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	211573	521647	203814	506710	214230	517254	216834	510106
1.1 इक्विटी पूंजी*	132765	493987	128062	480743	134357	489548	135799	481956
1.2 अन्य पूंजी	78807	27660	75752	25967	79873	27706	81034	28150
2 पोर्टफोलियो निवेश	10642	270425	8578	291215	10614	246342	10983	245720
2.1 इक्विटी	1110	156381	4590	177034	8153	135476	6312	137013
2.2 कर्ज	9533	114043	3988	114181	2461	110866	4671	108707
3. अन्य निवेश	90974	486588	84498	469430	77434	483115	86995	481281
3.1 व्यापार ऋण	18561	118145	11815	104418	21146	123184	24753	128323
3.2 ऋण	10474	195245	10816	192116	6543	191557	8084	188488
3.3 मुद्रा और जमाराशि	42081	140994	42302	142904	30242	137445	33528	135621
3.4 अन्य आस्तियां/ देयताएं	19858	32203	19565	29991	19504	30929	20630	28850
4 आरक्षित निधियां	607309		635363		589155		532664	
5 कुल आस्ति/ देयताएं	920498	1278660	932253	1267355	891433	1246712	847475	1237108
6 निवल आईआईपी (आस्ति-देयताएं)	-358162		-335102		-355279		-389633	

टिप्पणी: * इक्विटी पूंजी में निवेश निधि का हिस्सा और पुनर्निवेशित अर्जन शामिल है।

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व 2021-22	2021	2022		वि.व 2021-22	2021	2022	
		दिसं.	नवं.	दिसं.		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचलित प्रणाली (1.1 से 1.3)	33.01	3.13	3.67	3.42	206873112	20703988	22488758	22326077
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	12.22	1.10	1.26	1.19	142072939	14801512	15457897	15144169
1.1.1 आउटराईट	6.22	0.48	0.66	0.60	8793301	651103	759097	711065
1.1.2 रेपो	3.08	0.30	0.36	0.36	51015712	5075401	6039868	6125370
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो	2.92	0.31	0.23	0.23	82263926	9075009	8658933	8307734
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	19.91	1.96	2.33	2.16	59775826	5516604	6577286	6670289
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	0.88	0.07	0.08	0.07	5024347	385873	453575	511620
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार आधार-संरचना (एफएमआई)	–	–	–	–	–	–	–	–
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	2078.39	192.78	206.46	215.03	128657516	12966991	12291749	13736057
1.1 ग्राहक लेनदेन	2063.73	191.50	205.30	213.80	113319292	11418233	10691727	12180091
1.2 इंटरबैंक लेनदेन	14.66	1.29	1.16	1.23	15338225	1548758	1600022	1555966
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	577934.74	56422.79	84557.58	90675.95	42728006	4076395	4527540	4928331
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	9.76	0.65	0.51	0.32	575	36	29	21
2.2 एपीबीएस $	12573.33	1082.20	1065.62	1157.66	133345	14987	9460	20670
2.3 आईएमपीएस	46625.25	4429.86	4634.80	4858.37	4171037	396411	454679	486552
2.4 एनएसीएच जमा $	18757.82	1483.71	1373.88	1515.84	1281685	113132	141901	157435
2.5 एनईएफटी	40407.29	3763.38	4388.30	4854.81	28725463	2724980	2730878	2981681
2.6 यूपीआई @	459561.30	45662.99	73094.47	78288.95	8415900	826848	1190593	1281971
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	11.99	1.12	1.79	1.92	177	16	19	21
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	12189.49	1064.54	1316.60	1357.72	1034444	91163	110181	116425
3.1 भीम आधार पे @	227.73	19.59	14.52	12.71	6113	611	475	446
3.2 एनएसीएच नामे $	10754.74	937.92	1164.17	1198.55	1026641	90426	109479	115737
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1207.02	107.03	137.91	146.46	1689	126	227	242
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	61782.93	5611.80	4955.95	5223.54	1701851	160398	170386	185149
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	22398.82	2112.59	2347.73	2556.47	971638	93907	114794	126524
4.1.1 पीओएस आधारित $	11124.59	1093.48	1319.99	1449.35	380643	36713	46296	51772
4.1.2 अन्य $	11274.23	1019.10	1027.75	1107.12	590994	57195	68498	74752
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	39384.11	3499.21	2608.22	2667.08	730213	66491	55592	58625
4.2.1 पीओएस आधारित $	22967.10	2202.51	1779.41	1859.31	451550	43062	37237	39573
4.2.2 अन्य $	16417.00	1296.71	828.81	807.77	278663	23429	18355	19052
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	65782.75	7008.04	6075.20	6354.65	279416	25878	22808	22648
5.1 वालेट	53013.86	5659.18	4730.07	5012.71	220183	21195	17342	18400
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	12768.89	1348.86	1345.14	1341.94	59233	4683	5466	4248
5.2.1 पीओएस आधारित $	1116.16	99.63	77.72	61.58	19546	1893	1039	722
5.2.2 अन्य $	11652.73	1249.23	1267.42	1280.37	39687	2790	4428	3527
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6999.12	660.33	586.94	608.13	6650333	640955	581120	621387
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6999.12	660.33	586.94	608.13	6650333	640955	581120	621387
6.2 अन्य	0.00	–	–	–	–	–	–	–
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	724689.03	70767.50	97492.27	104220.00	52394049	4994790	5412034	5873940
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	726767.42	70960.28	97698.73	104435.03	181051565	17961781	17703784	19609997
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	719768.30	70299.95	97111.79	103826.90	174401233	17320825	17122664	18988610

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व. 2021-22	2021	2022		वि. व. 2021-22	2021	2022	
		दिसं.	नवं.	दिसं.		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	506842.31	49877.80	79124.20	84909.51	14961371	1433961	1993302	2125480
1.1 इंट्रा-बैंक $	40805.69	3927.19	5342.59	5557.30	2726363	254443	355045	373813
1.2 इंटर-बैंक $	466036.62	45950.61	73781.61	79352.22	12235007	1179518	1638256	1751667
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	40726.59	3593.75	3487.32	3664.00	83159996	8602920	7808859	8591147
2.1 इंट्रा-बैंक @	9583.32	848.88	870.33	949.32	52142582	5691255	4606598	4923803
2.2 इंटर-बैंक @	31143.27	2744.87	2616.98	2714.68	31017413	2911666	3202261	3667344
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	65240.43	5923.80	5608.36	5891.49	3111946	280371	265635	280461
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना $	62.37	5.90	7.59	8.13	3130	295	367	392
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	64851.61	5889.14	5568.41	5850.03	3097739	279100	264180	278923
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	326.45	28.76	32.36	33.33	11076	977	1089	1146
4 पीओएस पर नकद निकासी $ (4.1 से 4.2)	91.17	3.78	2.30	2.38	728	35	23	24
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	79.42	3.71	2.28	2.37	557	35	23	24
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	11.75	0.07	0.02	0.02	171	0	0	0
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	11126.04	940.20	944.92	934.53	299776	25208	25541	25484
5.1 एईपीएस @	11126.04	940.20	944.92	934.53	299776	25208	25541	25484

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2022 तक	2021	2022	
		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	9912.93	10066.90	10283.34	10206.53
1.1 क्रेडिट कार्ड	736.27	689.49	806.06	811.87
1.2 डेबिट कार्ड	9176.66	9377.42	9477.28	9394.66
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	15553.69	15111.90	16098.32	16234.69
2.1 वालेट @	12787.93	12511.00	13269.83	13346.64
2.2 कार्ड @	2765.76	2600.90	2828.48	2888.05
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.52	2.45	2.55	2.57
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम $	2.20	2.15	2.20	2.20
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम $	0.31	0.30	0.36	0.37
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	9.16	7.27	13.34	14.19
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	60.70	54.98	73.52	75.50
6 भारत क्यूआर @	49.72	46.47	48.25	49.59
7 यूपीआई क्यूआर *	1727.34	1440.10	2302.87	2379.44

@: नवंबर 2019 से नया समावेश
#: दिसंबर 2021 से शामिल सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा।
$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।
* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम है।
2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिल दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रैन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

अवसरिक शृंखला

सं. 44: अल्प बचत

(₹ करोड़)

योजना		2020-21	2021		2022	
			फर.	दिसं.	जन.	फर.
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	**प्राप्तियां**	**181237**	**14405**	**18175**	**14893**	**13932**
	बकाया	**1259585**	**1224772**	**1397878**	**1412766**	**1426737**
1.1 कुल जमाराशियां	**प्राप्तियां**	**132687**	**10143**	**13855**	**10676**	**9753**
	बकाया	**867494**	**847119**	**969847**	**980523**	**990274**
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	39748	2252	4475	3018	3568
	बकाया	205888	194738	226701	229719	233287
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां					
	बकाया					
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	276	-23	-366	-15	-20
	बकाया	3419	3037	3200	3185	3165
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	166	57	2	-1	-777
	बकाया	175	40	150	149	-628
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	12211	1135	1228	1146	933
	बकाया	221379	220277	232747	233892	234825
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	21009	1950	1929	1615	1490
	बकाया	97051	94750	114134	115749	117239
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	41470	3798	3926	3438	3217
	बकाया	207557	203597	241034	244474	247690
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	108205	107099	116043	116819	117578
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7473	7418	7931	7967	7996
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7227	7267	6983	6964	6944
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	84652	81813	110077	112724	115172
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	17807	974	2662	1475	1338
	बकाया	132029	130683	151885	153359	154697
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	-1	0	4
	बकाया	-25	-24	-25	-25	-22
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	21	21	21	21	21
1.2 बचत प्रमाणपत्र	**प्राप्तियां**	**34860**	**3647**	**3978**	**3691**	**3583**
	बकाया	**286863**	**282483**	**321027**	**324713**	**328337**
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	17361	1843	1860	1626	1585
	बकाया	135348	133016	150513	152139	153724
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	-3	0	0	0	0
	बकाया	159	157	158	158	158
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-7911	-470	-426	-193	940
	बकाया	-6776	-6194	-8455	-8648	-7708
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	25340	2274	2544	2258	1019
	बकाया	147942	145422	168720	170978	171996
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	41	0	0	0	23
	बकाया	-114	-147	-114	-114	-90
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	32	0	0	0	16
	बकाया	-74	-103	-74	-74	-58
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	10378	10332	10279	10274	10315
1.3 लोक भविष्य निधि	**प्राप्तियां**	**13690**	**615**	**342**	**526**	**596**
	बकाया	**105228**	**95170**	**107004**	**107530**	**108126**

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियाँ हैं। अर्थात सकल प्राप्तियाँ माइनस सकल भुगतान
स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां

श्रेणी	2021		2022		
	सितं.	दिसं.	मार्च	जून	सितं.
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	**8235318**	**8439811**	**8529036**	**8784931**	**9098788**
1. वाणिज्यिक बैंक	37.82	35.40	35.93	36.16	36.44
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.35	0.27	0.29	0.33	0.38
3. बीमाकृत कंपनियां	24.18	25.74	25.89	26.34	25.94
4. म्यूच्युअल फंड	2.91	3.08	2.91	2.32	2.58
5. सहकारी बैंक	1.50	1.82	1.81	1.84	1.80
6. वित्तीय संस्थाएं	1.17	1.69	0.94	1.09	0.98
7. कॉरपोरेट	0.72	1.37	1.47	1.52	1.58
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	1.81	1.66	1.56	1.43	1.38
9. भविष्य निधियां	3.77	4.33	4.60	4.77	4.66
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	16.98	16.92	16.62	16.06	15.28
11. अन्य	8.79	7.73	7.97	8.18	8.98
11.1 राज्य सरकार	1.67	1.69	1.82	1.84	1.83

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां

श्रेणी	2021		2022		
	सितं.	दिसं.	मार्च	जून	सितं.
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	**4153508**	**4257578**	**4410250**	**4472011**	**4589128**
1. वाणिज्यिक बैंक	35.94	34.41	34.39	34.22	34.37
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.44	0.40	0.38	0.41	0.36
3. बीमाकृत कंपनियां	27.50	28.85	28.42	28.39	27.71
4. म्यूच्युअल फंड	1.97	1.91	1.82	1.89	2.08
5. सहकारी बैंक	3.60	4.07	4.04	4.06	3.89
6. वित्तीय संस्थाएं	1.72	1.73	1.72	1.73	1.71
7. कॉरपोरेट	1.32	1.70	1.82	1.98	1.85
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
9. भविष्य निधियां	18.27	20.66	20.79	20.52	20.18
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.85	0.83	0.80	0.79	0.79
11. अन्य	8.38	5.40	5.81	5.99	7.05
11.1 राज्य सरकार	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21

खज़ाना बिल

श्रेणी	2021		2022		
	सितं.	दिसं.	मार्च	जून	सितं.
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	**763582**	**692869**	**757198**	**1022053**	**920205**
1. वाणिज्यिक बैंक	50.22	47.01	49.04	51.37	50.91
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	1.33	1.53	4.20	2.49	2.12
3. बीमाकृत कंपनियां	4.12	6.29	6.58	5.34	5.46
4. म्यूच्युअल फंड	17.72	13.72	14.01	14.86	11.98
5. सहकारी बैंक	1.32	1.49	1.79	1.34	1.48
6. वित्तीय संस्थाएं	2.12	2.36	3.53	3.73	4.17
7. कॉरपोरेट	2.40	3.13	3.47	4.27	3.86
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.15	0.72	0.49	0.40	0.53
9. भविष्य निधियां	0.37	0.85	0.21	1.70	3.21
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	17.62	22.89	16.69	14.50	16.27
11.1 राज्य सरकार	12.64	18.92	11.54	10.99	12.27

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़)

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (सं.अ.)	2022-23 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	**4515946**	**5040747**	**5410887**	**6353359**	**7453320**	**8008684**
1.1 गतिविधियां	2635110	2882758	3074492	3823423	4489442	4761567
1.1.1 राजस्व	2029044	2224367	2446605	3150221	3444624	3536719
1.1.2 पूंजी	519356	596774	588233	550358	963856	1144725
1.1.3 ऋण	86710	61617	39654	122844	80962	80123
1.2 गैर गतिविधियां	1812455	2078276	2253027	2442941	2864084	3140466
1.2.1 राजस्व	1741432	1965907	2109629	2271637	2653832	2928102
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	814757	894520	955801	1060602	1244104	1408929
1.2.2 पूंजी	69370	111029	141457	169155	178038	209892
1.2.3 ऋण	1654	1340	1941	2148	32214	2472
1.3 अन्य	68381	79713	83368	86995	99794	106652
2. कुल प्राप्तियां	**4528422**	**5023352**	**5734166**	**6397162**	**7193029**	**7944834**
2.1 राजस्व प्राप्तियां	3376416	3797731	3851563	3688030	4894050	5497245
2.1.1 कर प्राप्तियां	2978134	3278947	3231582	3193390	4026487	4551271
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1853859	2030050	2012578	2076013	2608666	2904479
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	1121189	1246083	1216203	1114805	1414088	1642678
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	3086	2814	2800	2572	3732	4115
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	398282	518783	619981	494640	867564	945974
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	34224	36273	31137	33448	40481	46552
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	142433	140287	110094	64994	117937	90824
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	42213	44667	59515	16951	33188	19835
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	100219	95621	50578	48044	84748	70989
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	**997097**	**1102729**	**1449230**	**2600335**	**2441333**	**2420614**
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	989167	1097210	1440548	2530155	2421587	2401363
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	144792	387091	571872	890012	627255	-----
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	-144847	325987	190241	107493	350911	-----
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	844375	710119	868676	1640143	1794332	2401363
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	7931	5519	8682	70180	19746	19251
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	989167	1097210	1440548	2530155	2421587	2401363
3ख.1.1 बाज़ार उधार (निवल)	794856	795845	971378	1696012	1377060	1808401
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	71222	88961	209232	458801	565522	398870
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	42351	51004	38280	41273	45133	44731
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	18423	-18298	10411	4545	-1675	5824
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	25138	66289	-14227	25682	32945	34029
3ख.1.6 नकद शेष	-12476	17395	-323279	-43802	260291	63850
3ख.1.7 अन्य	49653	96014	548753	347643	142310	45659
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	7931	5519	8682	70180	19746	19251
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	*26.4*	*26.7*	*27.0*	*32.1*	*31.5*	*31.0*
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	*26.5*	*26.6*	*28.6*	*32.3*	*30.4*	*30.8*
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	*19.8*	*20.1*	*19.2*	*18.6*	*20.7*	*21.3*
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	*17.4*	*17.3*	*16.1*	*16.1*	*17.0*	*17.6*
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	*5.8*	*5.8*	*7.2*	*13.1*	*10.3*	*9.4*

…: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बज़ट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	दिसंबर 2022 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	299.72	31	1810.66	31	2129.80	20
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	332.38	12	780.54	7	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	201.66	4	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	817.65	25	686.88	10
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	34.57	8	704.61	8	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	-	-	209.75	30	56.55	16
17	मेघालय	68.70	12	17.45	7	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	85.27	13	-	-
19	नगालैंड	-	-	152.58	28	59.40	10
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	929.68	9	-	-	-	-
23	राजस्थान	4951.31	31	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	524.27	25	1082.18	18	355.15	5
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	35.08	1	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणियां: 1. राज्य सरकारों द्वारा एसडीएफ का लाभ समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खजाना बिल (एटीबी) शेष और सरकारी प्रतिभूतियों में अन्य निवेशों के संपार्श्विक पर लिया जाता है।
2. डब्ल्यूएमए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को अस्थायी नकदी बेमेल को पूरा करने के लिए अग्रिम है।
3. ओडी राज्य सरकारों को उनकी डब्ल्यूएमए सीमा से परे अग्रिम दिया जाता है।
4. प्राप्त किया गया औसत: कुल सहायता (एसडीएफ/ डब्ल्यूएमए/ ओडी) को दिनों की संख्या से विभाजन करने पर प्राप्त मान है जिसके लिए महीने के दौरान सहायता बढ़ाई गई थी।
5. - : शून्य।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	दिसंबर 2022 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खज़ाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	9918	976	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2193	3	0	1700
3	असम	4485	74	0	0
4	बिहार	7999	-	0	0
5	छत्तीसगढ़	6117	-	1	208
6	गोवा	816	393	0	0
7	गुजरात	9649	573	0	0
8	हरियाणा	1451	1456	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	0	0
11	झारखंड	1031	-	0	0
12	कर्नाटक	12943	311	0	33907
13	केरल	2565	-	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1097	0	0
15	महाराष्ट्र	57286	1208	0	22000
16	मणिपुर	60	120	0	0
17	मेघालय	937	65	8	0
18	मिज़ोरम	348	65	0	0
19	नगालैंड	1526	40	0	0
20	उड़ीसा	15621	1749	101	39930
21	पुदुचेरी	453	-	0	1023
22	पंजाब	6342	0	0	0
23	राजस्थान	-	-	129	9000
24	तमिलनाडु	7991	-	18	3252
25	तेलंगाना	6775	1475	0	0
26	त्रिपुरा	830	16	0	1400
27	उत्तराखंड	4222	173	0	0
28	उत्तर प्रदेश	4194	-	116	0
29	पश्चिम बंगाल	10880	796	239	0
	कुल	**176631**	**10588**	**611**	**112420**

टिप्पणियां: 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।

2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में राज्य सरकारों द्वारा निवेश किए गए 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के ट्रेजरी बिल शामिल हैं।

3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23						2022-23 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
						अक्टूबर		नवंबर		दिसंबर			
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल	निवल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	50896	40498	46443	36103	2500	1625	2913	2038	-	-437	45303	37721
2	अरुणाचल प्रदेश	767	767	563	530	-	-50	-	-	559	559	559	489
3	असम	15030	14230	12753	10753	1700	1700	2400	2400	800	800	12900	12600
4	बिहार	27285	24685	28489	24334	6000	6000	6000	3750	6000	5000	25000	20922
5	छत्तीसगढ़	13000	10500	4000	913	-	-	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	3354	3054	2000	1450	200	200	150	-	300	300	1050	550
7	गुजरात	44780	33280	31054	13554	7000	5000	3000	700	2000	1000	26000	13800
8	हरियाणा	30000	25550	30500	20683	2500	1400	3500	2950	1500	950	28000	18420
9	हिमाचल प्रदेश	6000	3755	4000	1875	-	-200	2000	2000	1000	1000	8000	6440
10	जम्मू और कश्मीर	9328	6020	8562	5373	800	660	500	500	1495	895	5545	4306
11	झारखंड	9400	8900	5000	3191	-	-500	1000	1000	2000	1500	3000	1500
12	कर्नाटक	69000	61900	59000	49000	-	-3500	16000	14000	16000	13500	32000	24000
13	केरल	28566	23066	27000	18120	2500	1500	4000	2364	1500	650	16936	7450
14	मध्य प्रदेश	45573	38773	22000	13900	2000	1500	2000	2000	-	-	12000	9500
15	महाराष्ट्र	69000	50022	68750	40790	11000	9000	-	-1000	-	-1563	45000	23753
16	मणिपुर	1302	1044	1476	1326	-	-	-	-	122	122	872	597
17	मेघालय	1777	1587	1608	1298	300	300	413	263	440	440	1753	1503
18	मिज़ोरम	944	677	747	447	100	100	100	100	150	150	990	875
19	नगालैंड	1721	1366	1727	1222	-	-	146	-54	300	300	1322	872
20	उड़ीसा	3000	500	0	-6473	-	-1000	-	-500	-	-	-	-4500
21	पुदुचेरी	1390	790	1374	841	-	-100	-	-	300	200	700	500
22	पंजाब	32995	23467	25814	12428	4650	3650	5300	4800	2245	1745	31900	22546
23	राजस्थान	57359	44273	51149	38243	4500	3230	1000	-500	1251	751	29251	19169
24	सिक्किम	1292	1292	1511	1471	200	165	277	277	-	-	877	807
25	तमिलनाडु	87977	76796	87000	72500	6000	1750	4000	3000	6000	4850	49000	34003
26	तेलंगाना	43784	38782	45716	39256	3000	2375	2500	1875	2500	2187	28000	22582
27	त्रिपुरा	1916	1631	300	0	-	-	-	-90	-	-100	-	-315
28	उत्तराखंड	75500	59185	62500	42355	9000	6024	-	-	-	-78	14000	2213
29	उत्तरप्रदेश	6200	5208	3200	1800	500	500	-	-	-	-650	500	-150
30	पश्चिम बंगाल	59680	50180	67390	45199	6000	4000	-	-2500	7000	5000	37000	20500
	कुल	798816	651777	701626	492483	70450	45330	57199	39373	53462	39071	457458	302652

- : शून्य

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं. 50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार

(राशि करोड़ में)

मद	2019-20				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**238613.6**	**476724.8**	**386450.4**	**530769.8**	**1632558.5**
जीडीपी का प्रतिशत	*4.8*	*9.8*	*7.5*	*10.3*	*8.1*
I. वित्तीय आस्तियां	**398076.7**	**567753.2**	**517351.0**	**924069.3**	**2407250.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*8.1*	*11.7*	*10.1*	*18.0*	*12.0*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	12239.0	296625.6	124015.7	451698.3	884578.5
(ए) बैंक जमाराशि	-10550.9	278124.4	116211.9	444044.6	827830.0
i. वाणिज्यिक बैंक	-13293.8	269475.4	66666.7	446006.7	768855.0
ii. सहकारी बैंक	2742.9	8649.0	49545.2	-1962.1	58975.0
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	22789.9	18501.2	7803.7	7653.7	56748.5
2. जीवन बीमा निधियाँ	117873.1	108209.1	110373.8	37714.2	374170.2
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	104681.1	98426.3	103356.1	193739.0	500202.5
4. मुद्रा	61244.1	-26104.8	86832.6	160690.2	282662.1
5. निवेश	43936.8	43018.8	22655.1	-11953.8	97656.9
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	23303.5	38382.2	19191.1	-19191.1	61685.7
(बी) इक्विटी	18648.2	2172.4	936.2	4981.0	26737.8
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	57038.5	46514.1	69053.6	91117.2	263723.4
II. वित्तीय देयताएँ	**159463.1**	**91028.5**	**130900.6**	**393299.5**	**774691.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*3.2*	*1.9*	*2.6*	*7.7*	*3.9*
ऋण (उधार)					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	159429.6	90994.9	130867.1	393266.0	774557.6
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	140261.4	58074.4	114905.9	196581.1	509822.8
जिसमें :					
वाणिज्यिक बैंक	135754.1	57135.0	87377.4	202214.2	482480.6
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	19168.2	32920.5	15961.2	196684.8	264734.8
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-519.7	22976.7	29930.7	198264.3	250652.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	17033.0	8093.1	-15710.4	-3093.1	6322.6
iii. बीमा कंपनियाँ	2655.0	1850.8	1740.9	1513.6	7760.2
2. गैर-वित्तीय कार्पोरेशन (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.8	135.1
3. सामान्य सरकार	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-1.0

सं. 50 (ए): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार *(जारी..)*

(राशि करोड़ में)

मद	2020-21				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**600422.5**	**573643.2**	**481433.5**	**719844.5**	**2375343.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*15.5*	*12.1*	*8.8*	*12.5*	*12.0*
I. वित्तीय आस्तियां	**805869.5**	**612224.3**	**651241.3**	**1092617.4**	**3161952.5**
जीडीपी का प्रतिशत	*20.8*	*13.0*	*12.0*	*19.0*	*16.0*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	297412.4	278631.7	158172.2	525550.7	1259767.1
(ए) बैंक जमाराशि	281191.3	264565.3	147096.0	527056.7	1219909.2
i. वाणिज्यिक बैंक	279010.5	262033.7	143558.6	471730.9	1156333.7
ii. सहकारी बैंक	2180.8	2531.6	3537.3	55325.8	63575.6
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	16221.1	14066.4	11076.3	-1506.0	39857.9
2. जीवन बीमा निधियाँ	123291.4	142365.7	156438.6	141120.0	563215.8
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	119666.9	110916.6	108512.2	207604.5	546700.1
4. मुद्रा	202432.7	21286.9	91456.0	66800.5	381976.1
5. निवेश	6249.8	-12956.4	67659.3	63624.0	124576.7
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	-16021.0	-28837.7	57675.4	51267.0	64083.8
(बी) इक्विटी	18599.4	8291.5	5307.1	6333.3	38531.2
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	55760.7	70924.2	67947.4	86862.2	281494.6
II. वित्तीय देयताएँ	**205447.0**	**38581.1**	**169807.8**	**372772.9**	**786608.8**
जीडीपी का प्रतिशत	*5.3*	*0.8*	*3.1*	*6.5*	*4.0*
ऋण (उधार)					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	205490.3	38624.3	169851.0	372816.9	786782.5
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	211058.8	13213.0	139622.0	284732.6	648626.4
जिसमें :					
वाणिज्यिक बैंक	211259.3	13213.8	140514.3	242476.0	607463.5
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	-5568.6	25411.3	30229.0	88084.4	138156.1
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-15450.4	21627.1	15921.2	61326.1	83424.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	10516.6	2875.1	13048.5	25336.1	51776.2
iii. बीमा कंपनियाँ	-634.8	909.2	1259.3	1422.2	2955.9
2. गैर-वित्तीय कार्पोरेशन (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.0	134.4
3. सामान्य सरकार	-77.0	-77.0	-77.0	-77.0	-308.0

सं. 50(ए): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार *(समाप्त)*

(राशि करोड़ में)

मद	2021-22				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**519781.2**	**358325.2**	**453302.7**	**636259.8**	**1967668.9**
जीडीपी का प्रतिशत	*10.1*	*6.4*	*7.2*	*9.6*	*8.3*
I. वित्तीय आस्तियां	**382780.7**	**547346.2**	**834009.6**	**796341.7**	**2560478.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*7.5*	*9.7*	*13.2*	*12.0*	*10.8*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	-84377.1	202652.1	425821.4	151374.9	695471.4
(ए) बैंक जमाराशि	-106507.3	197301.2	422819.5	140297.2	653910.7
i. वाणिज्यिक बैंक	-108037.7	195617.4	418642.9	145510.5	651733.1
ii. सहकारी बैंक	1530.4	1683.8	4176.7	-5213.3	2177.6
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	22130.2	5350.9	3001.9	11077.7	41560.7
2. जीवन बीमा निधियाँ	114617.8	127356.0	103154.9	95681.7	440810.4
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	126469.7	108777.0	91543.9	254877.2	581667.9
4. मुद्रा	128660.2	-68631.2	62793.3	146845.0	269667.4
5. निवेश	24929.6	82305.4	69760.9	50980.8	227976.7
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	14573.0	63151.3	37912.2	44963.7	160600.1
(बी) इक्विटी	4502.5	13218.5	27808.2	3084.1	48613.3
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	71423.1	93829.6	79877.9	95524.7	340655.3
II. वित्तीय देयताएँ	**-137000.5**	**189021.0**	**380706.9**	**160081.8**	**592809.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*-2.7*	*3.4*	*6.0*	*2.4*	*2.5*
ऋण (उधार)					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	-137021.8	188999.7	380685.6	160060.6	592724.1
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	-113662.5	134166.1	320160.2	153323.3	493987.0
जिसमें :					
वाणिज्यिक बैंक	-108061.2	135728.8	317452.5	152364.2	497484.4
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	-23359.3	54833.7	60525.5	6737.3	98737.1
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-31118.4	28880.1	29479.8	-31016.3	-3774.8
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	7132.0	24403.8	29494.8	37436.2	98466.8
iii. बीमा कंपनियाँ	627.1	1549.8	1550.9	317.4	4045.2
2. गैर-वित्तीय कार्पोरेशन (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.8	135.1
3. सामान्य सरकार	-12.5	-12.5	-12.5	-12.5	-50.0

टिप्पणियां: 1. हाउसहोल्ड की निवल वित्तीय बचत निवल वित्तीय आस्तियों के प्रवाह को संदर्भित करती है, जो हाउसहोल्ड द्वारा धारित वित्तीय आस्तियों में परिवर्तन को घटाकर उनकी वित्तीय देयताओं में परिवर्तन को दर्शाती है।
2. छोटी बचत और पीपीएफ में संशोधन मुख्य रूप से लेखा महानियंत्रक, भारत सरकार के मासिक डेटा से प्राप्त तिमाही आंकड़ों के कारण होता है।
3. 2021-22 के लिए बैंक जमा में संशोधन का श्रेय बीएसआर-2 के अनुसार कुल जमा में हाउसहोल्ड की कम हिस्सेदारी को दिया जाता है।
4. जीडीपी के अनुपात के रूप में डेटा की गणना 31 अग. 2022 को जारी राष्ट्रीय आय 2021-22 के अनंतिम अनुमानों के आधार पर की गई है।
5. पूर्णांकन के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़े कुल योग के बराबर नहीं हो सकते हैं।

सं. 50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक

(राशि करोड़ में)

मद	जून-2019	सितं-2019	दिसं-2019	मार्च-2020
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी)	**16315506.3**	**16632816.5**	**17010694.5**	**17180616.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*84.7*	*85.4*	*86.2*	*85.6*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	8858293.4	9136417.9	9252629.8	9696674.3
i. वाणिज्यिक बैंक	8131543.2	8401018.6	8467685.3	8913692.0
ii. सहकारी बैंक	726750.2	735399.2	784944.4	782982.3
(बी) जीवन बीमा निधि	3883609.7	3930727.6	4049902.5	3884771.5
(सी) मुद्रा	2010842.9	1984738.1	2071570.7	2232261.0
(डी) म्यूचुअल फंड	1404631.5	1412654.1	1468727.6	1197092.9
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**6370092.6**	**6461087.5**	**6591954.6**	**6985220.6**
जीडीपी का प्रतिशत	*33.1*	*33.2*	*33.4*	*34.8*
ऋण (उधार)				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	5148115.0	5206189.4	5321095.3	5517676.4
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	4668496.4	4725631.3	4813008.7	5015222.9
ii. सहकारी बैंक	478956.2	479656.9	506946.6	501074.8
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1221977.5	1254898.1	1270859.3	1467544.1
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	451922.3	474899.0	504829.7	703094.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	673312.1	681405.2	665694.8	662601.7

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक *(जारी.)*

(राशि करोड़ में)

मद	जून-2020	सितं-2020	दिसं-2020	मार्च-2021
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी)	**18039169.4**	**18606364.4**	**19333484.1**	**20168953.3**
जीडीपी का प्रतिशत	*94.9*	*98.6*	*100.8*	*101.9*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	9977865.6	10242430.9	10389526.9	10916583.6
i. वाणिज्यिक बैंक	9192702.5	9454736.2	9598294.8	10070025.7
ii. सहकारी बैंक	785163.1	787694.7	791232.1	846557.9
(बी) जीवन बीमा निधि	4102000.7	4274424.9	4551882.0	4718718.2
(सी) मुद्रा	2434693.7	2455980.6	2547436.6	2614237.0
(डी) म्यूचुअल फंड	1343752.0	1443784.4	1648999.0	1730461.0
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**7190710.8**	**7229335.1**	**7399186.1**	**7772003.0**
जीडीपी का प्रतिशत	*37.8*	*38.3*	*38.6*	*39.3*
ऋण (उधार)				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	5728735.3	5741948.3	5881570.2	6166302.8
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	5226482.2	5239696.0	5380210.4	5622686.4
ii. सहकारी बैंक	500870.2	500865.3	499968.8	542221.2
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1461975.5	1487386.9	1517615.9	1605700.3
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	687643.6	709270.7	725191.9	786518.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	673118.3	675993.4	689041.8	714377.9

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक *(समाप्त)*

(राशि करोड़ में)

मद	जून-2021	सितं-2021	दिसं-2021	मार्च-2022
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी)	**20508115.7**	**21057343.4**	**21673261.7**	**22104312.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*97.4*	*95.9*	*95.0*	*93.4*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	10810076.3	11007377.6	11430197.1	11570494.3
i. वाणिज्यिक बैंक	9961988.0	10157605.4	10576248.3	10721758.8
ii. सहकारी बैंक	848088.3	849772.1	853948.8	848735.5
(बी) जीवन बीमा निधि	4894238.5	5105262.1	5175997.5	5287980.3
(सी) मुद्रा	2742897.3	2674266.1	2737059.4	2883904.4
(डी) म्यूचुअल फंड	1855000.1	2064363.5	2126112.0	2152140.5
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**7634981.2**	**7823980.9**	**8204666.6**	**8364727.1**
जीडीपी का प्रतिशत	*36.3*	*35.6*	*36.0*	*35.3*
ऋण (उधार)				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	6052640.2	6186806.3	6506966.5	6660289.7
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	5514625.2	5650354.1	5967806.6	6120170.8
ii. सहकारी बैंक	536604.9	535027.3	537720.1	538664.3
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1582341.0	1637174.6	1697700.1	1704437.4
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	755399.6	784279.7	813759.5	782743.2
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	721510.0	745913.7	775408.5	812844.7

टिप्पणी: 1. डेटा को केवल चुनिंदा वित्तीय लिखतों के लिए संकलित किया गया है(बैंकिंग क्षेत्र, एनबीएफ़सी और एचएफ़सी से ऋण) जिसके लिए डेटा उपलब्ध है।

2. जीडीपी अनुपात के रूप में डेटा की गणना 31 अग. 2022 को जारी राष्ट्रीय आय 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमान पर आधारित है।

3. हो सकता है कि कॉलम में दिए गए अंकों को पूर्णांकन के कारण कुल योग में न जोड़ा जाए।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।

3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।

4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।

4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।

4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।

4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।

7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।

2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

http://nsdp.rbi.org.in के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्वर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्ज़िम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकडे सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।

2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

एनएम$_2$ और एनएम$_3$ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।

2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।

2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थांओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।

एल$_1$ और एल$_2$ मासिक आधार पर और एल$_3$ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।

जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकड़े अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

सारणी सं. 14
कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 17
2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।
2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।
4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24
प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30
प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।
1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।
2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32
आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अतंरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34
1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.1.4 : अनुमान
1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान
'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी सस्थांओं/शाखाओं के बीच के ऋण सबंधी लेनदेन से संबंधित है।
हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ो से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35
1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36
सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का सकेंतक। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2018-19 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37
ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -
  - बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल है।
  - जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए है, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया हैं।

सारणी सं. 45

(-): शून्य/ नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 31 मई 2021 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2020-21 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बज़ट 2020-21 से लिया गया है।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुन:चुकौती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकौती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डेटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारो में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (**https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618**) में उपलब्ध हैं।

'वर्तमान सांख्यिकी' का टाइम सीरिज डेटा https://dbie.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2023	₹350 एक प्रति ₹250 एक प्रति (रियायती दर*) ₹4,000 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,000 (एक वर्ष रियायती दर*)	15 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति 150 अमेरिकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी पुस्तिका 2021-22	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका 2021-22	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमेरिकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2021-22 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (कांउटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2021-22	₹575 एक प्रति (कांउटर पर) ₹625 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	22 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकांउट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (कांउटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
7. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (कांउटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8 अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (कांउटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयनः दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (कांउटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 42, सं. 1, 2021	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 42, सं. 2, 2021	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर्स; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (कांउटर पर)	50 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
13. नगरपालिका वित्त संबंधी रिपोर्ट	₹300 एक प्रति (कांउटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	16 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (http://dbie.rbi.org.in) ।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।

* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

सामान्य अनुदेशः

1. सभी संचार निम्न को संबोधित किए जाने चाहिए:
   निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार विभाग,
   आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीआरकेडी, डीईपीआर),
   भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर भवन, तल मंजिल,
   सर पी. एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स सं. 1036. मुंबई- 400 001
   टेलीफोन: 022-2260 3000 विस्तार: 4002, ईमेल: spsdepr@rbi.org.in

2. बिक्री के लिए प्रकाशन प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) उपलब्ध हैं।

3. प्रकाशनों को कैश-ऑन डिलीवरी के आधार पर नहीं भेजा जाएगा।

4. एक बार बेचे गए प्रकाशनों को वापस नहीं लिया जाएगा।

5. प्रकाशन के पिछले अंक आम तौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं।

6. जहां कहीं भी रियायती मूल्य का संकेत नहीं दिया गया है, भारत में छात्रों, शिक्षकों, शैक्षिक/ अकादमिक संस्थानों, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है, बशर्ते पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

7. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और भुगतानकर्ता के नाम, सदस्यता संख्या (यदि कोई हो), खाता संख्या, तारीख और राशि सहित लेनदेन विवरण spsdepr@rbi.org.in पर ईमेल किया जाना चाहिए या डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए।

   ए. एनईएफटी हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित विवरण अपेक्षित है:

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा और पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाता प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19

   बी. गैर-डिजिटल मोड के माध्यम से सदस्यता के मामले में, कृपया मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट/ चेक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के नाम पर भेजें।

8. 'प्रकाशन प्राप्त न होने' संबंधी शिकायतें दो माह की अवधि के अंदर भेजी जाएं।